



LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Monday, December 16, 2024 / Agrahayana 25, 1946 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, December 16, 2024 / Agrahayana 25, 1946 (Saka)

<u>CONTENTS</u>	<u>PAGES</u>
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 281 – 291)	1 – 30
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 292 – 300)	31 – 50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 3221 – 3450)	51 – 280



सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Monday, December 16, 2024 / Agrahayana 25, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, December 16, 2024 / Agrahayana 25, 1946 (Saka)

<u>C O N T E N T S</u>	<u>P A G E S</u>
RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	281
PAPERS LAID ON THE TABLE	281 - 306
STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 5 th and 6 th Reports	307
STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT 1 st to 3 rd Reports	307
STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS 1 st to 5 th Reports	308
STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS Action Taken Statements	309
STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL Final Action Taken Statements	310
MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	311 - 51
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	352 - 66
Shri Parshottambhai Rupala	352
Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava	352
Dr. Rabindra Narayan Behera	353
Shri Lumba Ram	353
Shri Chhatrapal Singh Gangwar	354

Shrimati Kriti Devi Debbarmann	354
Dr. Faggan Singh Kulaste	355
Dr. Vinod Kumar Bind	355
Shri Arun Govil	356
Shri Dilip Saikia	356
Shri Dulu Mahato	357
Shri Ramvir Singh Bidhuri	357
Shri Gopal Jee Thakur	358
Sushri S. Jothimani	358
Dr. Namdeo Kirsan	359
Shri S. Supongmeren Jamir	359
Shri Anto Antony	360
Shri Sukhdeo Bhagat	360
Shri Pushpendra Saroj	361
Sushri Iqra Choudhary	361
Shri Kalipada Saren Kherwal	362
Shri Kirti Azad	362
Shri Arun Nehru	363
Shri Sribharat Mathukumilli	363
Shri Sunil Kumar	364
Shri Bajrang Manohar Sonwane	364
Shri Naresh Ganpat Mhaske	365
Dr. Rajkumar Sangwan	365
Shri N.K. Premachandaran	366

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS	367 - 492
(Inconclusive)	
Shri K.C. Venugopal	368 - 376
TEXT OF CUT MOTIONS	377
...	378
Dr. Sanjay Jaiswal	379 - 82
Shri Lalji Verma	383 - 85
...	386
Prof. Sougata Ray	387 - 89
Shri D.M. Kathir Anand	390 - 93
Shri Magunta Sreenivasulu Reddy	394 - 96
Shri Anil Yeshwant Desai	397 - 98
Shrimati Supriya Sule	399 - 403
Shri Naresh Ganpat Mhaske	404 - 06
Shri Manish Tewari	407 - 08
Shri P.P. Chaudhary	409 - 13
Dr. Gumma Thanuja Rani	414 - 15
Shri Sudhakar Singh	416 - 17
Dr. M. P. Abdussamad Samadani	418 - 19
@ Shri Gurmeet Singh Meet Hayer	420
# Shri Subbarayan K.	421
Shri Raja Ram Singh	422
Shri N.K. Premachandran	423 - 27
Shri Anand Bhadauria	428 - 29

@ For English translation of the speech made by the Hon. Member, Shri Gurmeet Singh Meet Hayer in Punjabi, please see the Supplement (PP 420A to 420B).

For English translation of the speech made by the Hon. Member, Shri Subbarayan K. in Tamil, please see the Supplement (PP 421A to 421B).

Sushri Sayani Ghosh	430 - 433
Dr. K. Sudhakar	434 - 37
Shri Chamala Kiran Kumar Reddy	438 - 40
\$ Shri K. Eswarasamy	441
Shri Jugal Kishore	442 - 44
Shri Sribharat Mathukumilli	445 - 46
Shri Rajesh Ranjan	447 - 48
Adv. Francis George	449 - 51
Shri Shashank Mani	452 - 53
Shri Rahul Kaswan	454 - 56
Shri Dharmendra Yadav	457 - 58
Shri Vishaldada Prakashbapu Patil	459 - 60
Shri C. N. Annadurai	461 - 62
Shri Durai Vaiko	463 - 64
Shri Bishnu Pada Ray	465 - 68
Prof. Varsha Eknath Gaikwad	469 - 70
Shri Ravindra Dattaram Waikar	471 - 72
Adv. Chandra Shekhar	473 - 75
Shri Darshan Singh Choudhary	476 - 77
Dr. M. K. Vishnu Prasad	478 - 80
Shri Jagdambika Pal	481 - 86
Dr. Amar Singh	487 - 88
Dr. Nishikant Dubey	489 - 91
Shri Hanuman Beniwal	492

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, December 16, 2024 / Agrahayana 25, 1946 (Saka)

S U P P L E M E N T

<u>CONTENTS</u>		<u>PAGES</u>
XXX	XXX	XXX
Xxx	xxx	xxx
Xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS		420A - 21B & 441A - 41B
xxx	xxx	xxx
Shri Gurmeet Singh Meet Hayer		420A - 20B
Shri Subbarayan K.		421A - 21B
xxx	xxx	xxx
Shri Eswarasamy K.		441A - 41B

(1100/IND/NKL)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-281.

... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : अध्यक्ष जी, यदि आप विजय दिवस पर कुछ कहते तो अच्छा होता... (व्यवधान)

(प्रश्न 281)

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, गढ़ तो चित्तौड़ है, बाकी तो सब गढ़िया है। चित्तौड़गढ़ एशिया का सबसे बड़ा किला है। इसका बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। इससे मीरा, पन्ना, महारानी पद्मावति और महाराणा प्रताप का गौरवशाली इतिहास जुड़ा है। प्रधान मंत्री जी ने मीरा जी के 525वें वर्ष पर ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर बड़े कार्यक्रम किए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या चित्तौड़गढ़ में भी मीरा जी के नाम पर बड़ा स्मारक बनेगा? चित्तौड़ के दुर्ग पर एक वैकल्पिक मार्ग की लम्बे समय से मांग है। क्या इस मांग पर सरकार विचार कर रही है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। आप संक्षिप्त में प्रश्न और जवाब होने चाहिए ताकि सभी प्रश्न पूछे जा सकें।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। भक्त शिरोमणि मीरा बाई का 525वां जन्म जयंती दिवस माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में मंत्रालय ने आयोजित किया है। मीरा बाई जी के जीवन से जुड़े चार महत्वपूर्ण स्थान, उनका जन्म स्थान - मेड़ता, जहां उनकी शादी हुई - चित्तौड़गढ़, जहां उन्होंने भक्ति की - वृंदावन और जहां उनका महापरिनिर्वाण होकर ईश्वर में एकाकार हुई - द्वारका में, इन चारों स्थानों पर बड़े कार्यक्रम मीरा जी की स्मृति में करने का निश्चय हुआ था। तीन स्थानों पर कार्यक्रम हो चुके हैं और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि चित्तौड़गढ़ में आगामी 21, 22 और 23 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है।

महोदय, जहां तक स्मारक बनाने का विषय है, ऐसा कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है। वैकल्पिक मार्ग के लिए जिला कलेक्टर ने एक पत्र लिखा है। माननीय सदस्य ने भी पत्र लिखा है। हमने राज्य सरकार से उस पत्र के आधार पर एक बार अपनी तरफ से एक रजिस्ट्रार डीपीआर बनाने के लिए आग्रह किया है कि वे डीपीआर भेजें। उसके बाद मोन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप विचार करके आगे निर्णय कर पाएंगे, लेकिन अभी वह बहुत ही प्रारम्भिक अवस्था में है इसलिए इस पर अभी किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। आज माननीय सदस्य और मंत्री जी, क्या एक नया प्रयास कर सकते हैं कि संक्षिप्त में प्रश्न पूछें और संक्षिप्त में जवाब दें। हमें आज कोशिश करनी चाहिए कि कैसे 20 प्रश्न पूछ सकें।

श्री पडोले, आप सदन में इतनी बार बोलें हैं, जितनी बार कोई नहीं बोला है।

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपकी कृपा हमेशा रहेगी। मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सरकार महारानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय स्मारक उन्नयन में स्थानीय समुदायों को शामिल करने और इसे पर्यटन स्थल बना कर रोजगार सृजन के रूप में विकसित करने के लिए क्या कोई प्रयास कर रही है?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष जी, महारानी लक्ष्मीबाई जी का स्मारक ग्वालियर में बना है। वह ग्वालियर का नेशनल मोन्यूमेंट नहीं है, लेकिन ग्वालियर की नगरपालिका उसका संरक्षण करती है, लेकिन अभी इस तरह का कोई विचार मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

(इति)

(1105/RV/VR)

(प्रश्न 282)

SHRI SAGAR ESHWAR KHANDRE (BIDAR): Thank you, Speaker, Sir, for giving me an opportunity to speak. I come from the Kalyana-Karnataka region which is a very backward region. We are protected by Article 371 (J) of the Constitution, which gives us a special status in employment. A lot of job migration happens in our region. From my Lok Sabha constituency itself, a lot of youth after finishing their degree go to Hyderabad, Pune and Bangalore to work.

Sir, I would like to ask the Central Government whether it is doing anything to identify these regions, where maximum job migration is happening, to ensure that employment is given to the youth in Tier-II and Tier-III cities.

डॉ. मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान समय में रोजगार की अनेक शाखाएं भी उपलब्ध हुई हैं और अनेक प्रकार के एजुकेशन और स्किल्स भी डेवलप हुए हैं। इन स्किल्स और अपनी आवश्यकता के अनुसार देश का कोई भी नागरिक न केवल अपने देश में, बल्कि वह सारी दुनिया में जाकर रोजगार के लिए प्रयास कर सकता है और रोजगार प्राप्त कर सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कल्याण-कर्नाटक का हो, चाहे वह कर्नाटक के किसी भी भाग का हो, वह हैदराबाद जा सकता है और हैदराबाद के लोग भी कल्याण-कर्नाटक में या उसे जहां भी ऑपॉर्च्युनिटी उपलब्ध हो, वहां वे जा सकते हैं।

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): Sir, what are the schemes being given and the steps being taken up by the Government to increase the opportunities for employment for the people of Kalahandhi and Nawapara?

माननीय अध्यक्ष : जो प्रथम बार सांसद चुनकर आए हैं, आज उन सभी माननीय सदस्यों को सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा।

डॉ. मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष जी, कालाहांडी के लिए या देश के किसी शहर के लिए कोई अलग योजना नहीं बनायी जाती है, लेकिन रोजगार-सृजन के लिए भारत सरकार द्वारा जो भी योजनाएं लागू हैं, उन सारी योजनाओं का लाभ कालाहांडी को भी मिल सकता है।

(इति)

(Q.283)

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Speaker, Sir, I have received the reply. The hon. Minister has informed that 73.2 per cent of all workers engaged in the non-agriculture sector were in the informal sector during the period from July 2023 to June 2024.

There are several critical steps that the Government need to take to streamline the informal economy. Policy measures such as enhancing access to finance, providing skills training, securing property rights and extending legal protections can help transition of informal economy into formal sector.

From the reply, I understand that the Government is focused on registering and taxing workers in the informal sector. Women workers constitute a significant share of this sector. However, they lack job protection. Being largely semi-skilled or unskilled, they are in urgent need to get skill training.

Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister what measures the Government has taken to provide legal protection to workers in the informal economy. How many workers have received skill development training so far?

श्री पंकज चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा के दायरे में कवर हो रहा है। इसी कारण, उन्होंने आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा का बेहतर कवरेज मिल रहा है।

जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है कि क्या प्रयास किए गए हैं, तो अगर आप देखें तो हम 'उद्यम' पोर्टल लेकर आए, जिसमें 5.5 करोड़ एम.एस.एम.ई.जी. रजिस्टर्ड हुए और उन्हें औपचारिक सेवाओं से ऋण प्राप्ति की सुविधा प्राप्त हो रही है। वहीं हम 'ई-श्रम' पोर्टल लेकर आए, जिसमें पिछले तीन वर्षों में ही 30.46 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत किया गया। अगर आप ई.पी.एफ.ओ. के डेटा को देखें तो वर्ष 2014-15 में जहां 15.84 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, वहीं वर्ष 2022-23 में 29.88 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया।

इस प्रकार सरकार का यह लगातार प्रयास है कि लोगों को औपचारिक सेक्टर में लाया जाए।

(1110/SAN/GG)

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Speaker, Sir, since a large proportion of workers in the informal economy is women, I would like to ask the hon. Minister what measures have been taken to provide health facilities to these workers.

What steps has the Government undertaken to reduce the gender gap and increase the participation of women workers in the formal sector?

श्री पंकज चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, अगर देखें तो अनौपचारिक क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। तमाम योजनाओं के तहत, जो माननीय सदस्य ने उनके स्वास्थ्य के लिए बात की है, तो पूरे देश में प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों को भी कवर किया जा रहा है।

डॉ. आनन्द कुमार गोंड (बहराइच) : माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में पांचवे स्थान पर पहुंच गई है और जल्द ही यह तीसरे स्थान पर पहुंचने वाली है। इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का बहुत बड़ा योगदान है।

मैं माननीय वित्त राज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एमएसएमई सैक्टर के औपचारिकीकरण के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

श्री पंकज चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बताया कि हमने जो पोर्टल लॉन्च किया है, उसके तहत कहीं न कहीं भारी वृद्धि उसमें हुई है। अगर देखें तो एमएसएमई का दायरा जहां वर्ष 2015 में 21.9 लाख था, वहीं वर्ष 2024 में यह बढ़ कर के 5.5 करोड़ हो गया है।

(ends)

(Q.284)

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): Hon. Speaker, Sir, the SAMADHAN portal has been a very significant digital initiative of the Government in recording and resolving the disputes between workmen, industry management and trade unions. Additionally, there are also State-level mechanisms to address such disputes. I would like to ask the hon. Minister, in this regard, how the Ministry of Labour and Employment is collaborating with the State Labour Departments to align SAMADHAN with regional grievance redressal mechanisms for better efficiency.

डॉ. मनसुख मांडविया: अध्यक्ष महोदय, समाधान पोर्टल कंपनी, कंपनी में काम करने वाले कामगार, उसके सैलरी रिलेटिड इश्यूज, उसके ग्रेचुटी रिलेटिड इश्यूज, आदि का रोबस्ट रूप में समाधान करने के लिए वर्ष 2019 में बनाया गया था। किसी भी व्यक्ति को कोई भी ग्रीवांस है, तो वह समाधान पोर्टल पर रजिस्टर करा सकता है और समय पर ही उसका निपटान हो जाए, उसके लिए प्रयास किया जाता है और उसके साथ काउंसलिंग की जाती है। उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों साथ मिल कर काम करते हैं। एक रोबस्ट व्यवस्था और सिस्टम बना हुआ है। वहां अपनी ग्रीवांस और अपना इश्यू को रख कर उसका समाधान निकाला जा सकता है।

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): Hon. Speaker, Sir, we know that workers in the unorganised sector constitute more than 80 per cent of the total workforce. So, I would like to understand in this regard, though we have the e-Shram portal, whether we can consider the unorganised sector and try to inculcate or involve them in the new portal SAMADHAN that is available now. Can we integrate both e-Shram and SAMADHAN and ultimately have one digital platform?

By now, the upgradation of SAMADHAN portal should have been done. What are the steps the Ministry has taken to upgrade the SAMADHAN portal?

डॉ. मनसुख मांडविया : अध्यक्ष महोदय, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार का एम्प्लॉइमेंट होता है। जो इनफॉर्मल सैक्टर में होते हैं, उनका आज के दिन तक रजिस्ट्रेशन नहीं था। लेकिन मोदी गवर्मेंट ने सारे इनफॉर्मल सैक्टर में काम करने वाले कामगारों को सूचीबद्ध करने के लिए ई-श्रम पोर्टल का निर्माण किया है। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही

है कि इनफॉर्मल एक्टिविटी से जुड़े हुए 30 करोड़ से अधिक ऐसे लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उनका भी कोई गिवांस है, उनका भी कोई इश्यु है, रिड्रेसल के लिए भी वे समाधान पोर्टल पर जा सकते हैं। केवल फॉर्मल सैक्टर के लोग ही नहीं, इनफॉर्मल सैक्टर के लोग भी वहां समाधान के लिए अप्लाई कर के अपने इश्यु को रिजॉल्व कर रहे हैं।

(1115/MY/SNT)

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, एमएसएमईज के 85 हजार से अधिक मामले समाधान पोर्टल पर लंबित हैं। इसमें 26,876 करोड़ रुपये की देयता भी शामिल है। एमएसइएफसी के फैसले के बावजूद कंपनियों का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। सरकार एमएसएमई को तेजी से न्याय दिलाने के लिए और अपीलों की प्रक्रिया को जल्द करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

डॉ. मनसुख मांडविया : अगर किसी भी कंपनी और एम्प्लॉइज के बीच में इश्यू हो तो उसको रिड्रेस करने के लिए समाधान पोर्टल के तहत प्रयास हो रहा है। उसमें से भी, क्योंकि यह विवाद का विषय बन जाता है, कई बार इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते हैं तो वे ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं। ट्रिब्यूनल को तो हम इंटीमेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पिछले तीन महीने से आज तक समाधान पोर्टल के तहत जो रिड्रेसल रेट था, वह 60 से 65 परसेंट एवरेज था। पिछले तीन महीने से एक जुम्बेश के रूप में काम किया जा रहा है। पिछले तीन महीने का जो डेटा है, उसमें 80 परसेंट से ऊपर रिड्रेस हो रहा है ताकि कोई कामगार हो, कोई इस्टैब्लिशमेंट हो, कोई ट्रेड यूनियन हो, उनका इश्यू समाधान के तौर पर निपटाया जा सके और उसको समय पर भुगतान हो जाए। अगर उनका कोई इश्यू हो तो उसका भी समाधान भी हो जाए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप एक प्रयास यह भी कीजिए श्रम का विवाद न्यायालय तक कम पहुंचे, क्योंकि वहां पर विवाद काफी लंबे समय तक लंबित रहते हैं। एक बार लॉ मिनिस्टर से बात करके इसके लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि उनकी समस्या का निपटान टाइम-बाउंड हो जाए।

डॉ. मनसुख मांडविया : सर, इसके लिए हम प्रयास करेंगे।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, हम दोनों साथ बैठकर इसके लिए प्रयास करेंगे।

SHRI ANIL YESHWANT DESAI (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Thank you, Speaker Sir, for allowing me to ask a supplementary on this question.

The SAMADHAN Portal is categorised State-wise, Central-wise, and year-wise also. May I know this from the hon. Minister? Under EPFO, there are accounts of labourers from different MSMEs, and more so, from medium-size enterprises. On the SAMADHAN Portal, there are hundreds

and thousands of complaints regarding their accounts which are very essential for the labour to meet their regular requirements and in the emergencies also. The SAMADHAN Portal somehow is not answering to that. A lot of shortcomings and a lot of inadequacies are there. How will that be coordinated? How will the labour requirements be fulfilled?

डॉ. मनसुख मांडविया : अध्यक्ष जी, यह विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य कैटेगरी के एम्प्लाइज जब ईपीएफओ के दायरे में आता है, 15 हजार के अंदर जिनकी सैलरी है, वे ईपीएफओ के दायरे में आते हैं। उनका ईपीएफओ में पैसा भी कटता है और वहां उनके पैसे का हिसाब-किताब रखा जाता है। जब उनको पैसे की आवश्यकता होती है, तब वह वहां से पैसा ले लेता है। उस वक्त उनको कई ग्रीवान्सेज भी होती हैं। इस पोर्टल की वजह से कई बार उसको समस्या भी होती थी।

अध्यक्ष महोदय, उनकी समस्या को हम समझते हैं कि अपने पैसे को निकाल कर उपयोग करने के लिए उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको पैसे निकलाने के लिए सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा सारी प्रोसेस हो रही हैं। उसको और रोबस्ट करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब उसको अपना पैसा वापस लेना है, इसके लिए उसको कोई दिक्कत न हो, उसका इंट्री करना है, उसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, उसकी कोई छोटी-मोटी गलती हो तो उसे ठीक करना है। इन सारी चीजों को रोबस्ट करके बैंक लेवल का एक ईपीएफओ रिड्रेसल सिस्टम हो, ताकि ईपीएफओ की सारी गतिविधियाँ हो सकें, उसके लिए ईपीएफओ श्री जीरो वर्जन लाया जा रहा है। मार्च महीने तक उनके ग्रीवान्स को 100 परसेंट रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। आज उसमें अच्छा प्रोग्रेस भी हो रहा है। 2.1 के तहत आज लास्ट एक साल से जो शिकायतें थीं, उनमें 50 परसेंट कटौती हुई है।

(इति)

(Q. 285)

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): Thank you, Speaker Sir.

In the reply given by the hon. Minister, there is a mention about the climatic intervention project that has been in the dairy sector.

(1120/AK/CP)

This was started in the year 2016 under the rule of Telugu Desam Party, but this project could not be completed due to the inefficiency of the previous Government. This project was supposed to be completed by 2021. I would like to ask this from the hon. Minister. What steps have been taken to complete this project?

श्री भूपेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जिस क्षेत्र के बारे में पूछा है, इसमें आंध्र प्रदेश के तीन जिले अनंतपुर, नेल्लौर और विजयनगरम में, डेयरी में क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाले परिवर्तन के कारण यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग है। इस प्रोजेक्ट में टोटल टारगेटेड बेनीफिशियरीज 5,025 हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इन तीनों जिलों में विशेष रूप से जो क्लाइमेट रेगुलेशन है, कैटल के बारे में जो फॉडर और बाकी चीजों हैं, उनमें इंप्रूवमेंट किया गया है। यह प्रक्रिया जारी है और इसका काम शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): Sir, my Constituency, Nandyal, has the highest rainfall deficit, that is, about 89 per cent. Out of 29 Mandals, 28 Mandals are rainfed Mandals and 16 Mandals have been declared severely drought-hit areas. I come from Rayalaseema region where the AP Disaster Management Authority has declared about 54 Mandals from Rayalaseema region as drought-hit areas, and these unique climatic conditions and untimely rainfalls in Rayalaseema region have remained a very serious issue.

I would like to ask this from the hon. Minister. Are there any additional schemes and alternative financial benefits for the Rayalaseema region? I am asking this because we have to get our farmers out of debt-trap. Thank you.

श्री भूपेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज की बात है, इसके माध्यम से आंध्र प्रदेश में इन तीन जिलों के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगर कोई स्पेसिफिक स्टेट एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज है, तो उसे अपने राज्य सरकार के द्वारा पता कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : फर्स्ट टाइम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बहुत अच्छी तरह से सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी।

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY (BHONGIR): Speaker Sir, thank you very much for giving me this opportunity. I would like to ask this from the hon. Minister in regard to my State of Telangana, which is facing severe drought in regions such as Nalgonda, Karimnagar, Belgaum and Nizamabad. However, under the National Adaptation Fund for Climate Change, only Mahbubnagar District has received funding for drought mitigation with an allocation of Rs. 24 crore. What is the current status of expenditure of these Rs. 24 crore in Mahbubnagar? Additionally, are these plans getting into other districts which are also drought-affected like Nalgonda and Karimnagar under NAFCC in the near future? Thank you very much.

श्री भूपेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, इस एडैप्टेशन प्लान के लिए 847 करोड़ रुपये चार क्षेत्रों के लिए दिए गए थे, पहला कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, दूसरा जल प्रबंधन के लिए, तीसरा ईको सिस्टम और बायो डायवर्सिटी के लिए और चौथा फॉरेस्ट्री के लिए। उस कार्यक्रम के अंतर्गत, जहां तक तेलंगाना का विषय है, महबूब नगर में कृषि कार्य के लिए दिया गया था, जिस पर अभी कार्रवाई जारी है।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मंजूनाथ बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। कभी जरूरत होगी तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं।

डॉ. सी. एन. मंजूनाथ।

DR. C. N. MANJUNATH (BANGALORE RURAL): Many thanks to the hon. Speaker for giving this opportunity to ask a question from the hon. Minister of Environment, Forest and Climate Change.

Today, in our Constituency, a lot of elephant intrusions are happening across the segments of Bannerghatta, Sathanur and Kanakapura, and the elephants are killing the farmers and also destroying the crops. I want to ask this from the hon. Minister. How much fund is released towards preventive measures from the CAMPA Fund? The CAMPA Fund has got sufficient money. I would request the hon. Minister to release money from the CAMPA Fund to erect a barricade along the 70 kms stretch to prevent elephant intrusions so that this sort of killing and death due to trampling does not occur.

(1125/UB/NK)

The other thing is that if a Forest Department employee dies, the compensation is about Rs. 25 lakh but if a farmer dies, the compensation is only Rs. 15 lakh. There should be an equal compensation for the farmer.

Also, I request the hon. Forest Minister to immediately release some grants from the CAMPA fund to erect a barricade to prevent the elephant intrusion.

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न है, वह एडाप्टेशन के संबंध में है, वर्तमान में क्लाइमेट चेंज के कारण एडाप्टेशन में सूखा आदि का विषय है, यह उसके संबंध में है। जहां तक हाथियों का प्रश्न है, उन्होंने हाथियों के उत्पात के विषय में मानव मृत्यु के बारे में कहा है और कैम्पा फंड के बारे में डिमांड की है। वह इससे अलग विषय है। माननीय सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र का विषय लिखकर कर देंगे तो हम उसका समाधान करेंगे और मैं उनको गाइडलाइन भी उपलब्ध करा दूंगा।

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): I would like to ask the hon. Minister, what specific steps is the Government taking to ensure that Karnataka's drought-prone districts receive adequate funding and priority under the National Adaptation Fund for Climate Change (NAFCC), especially considering their vulnerability in the recent years?

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक के लिए अलग से फंड उपलब्ध कराया जा रहा है, इस फंड के अंतर्गत कोई व्यवस्था नहीं है।

SHRIMATI PRIYANKA GANDHI VADRA (WAYANAD): Sir, I would like to add to the question on the man-animal conflict.

In my constituency of Wayanad, in the past one year, 90 people have been affected by this conflict, and just yesterday, there was an attack by wild animals or wild elephant. I would like to ask the hon. Minister to increase the compensation especially for farmers and ordinary people who are being affected by this man-animal conflict.

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है, वह मूल प्रश्न से अलग है। उनका वायनाड तीन ताल्लुका क्षेत्रों में है, मानंतवाड़ी, सुल्तानबथेरी और व्यथिरी में है। मैं वहां खुद गया था, हम लोगों ने पूरी टीम बनायी थी। हमारे द्वारा वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा एकीकृत रूप से कार्य किया गया था। यह कंस्टीट्यूएंशी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का एक बड़ा क्षेत्र है, उसके संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत यह कंस्टीट्यूएंशी आती है। चूंकि यह प्रश्न मूल प्रश्न के साथ नहीं जुड़ा है, लेकिन हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्य की कॉपी मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा।

(इति)

(प्रश्न 286)

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का समाधान कारक उत्तर दिया है और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 21 ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटीज को वेबसाइट पर डाला है। जो यूनिवर्सिटीज फर्जी डिग्री उपलब्ध कराती हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज को सिर्फ धोखाधड़ी में ही रखा गया है। क्या मंत्रालय इनकी सजाओं को सख्त करने के लिए कोई सिफारिश करेगा ताकि सामान्य धोखाधड़ी श्रेणी से उठकर ऐसे बच्चे जो फर्जी डिग्री प्राप्त करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज के लिए सख्त सजा करने का प्रावधान करेंगे?

डॉ. सुकान्त मजूमदार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि शिक्षा कन्करेंट लिस्ट में आता है। लॉ एंड ऑर्डर मूलतः स्टेट का विषय है। यह स्वाभाविक है यूजीसी हर सेशन के पहले जो फेक यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी लिस्ट अपनी वेबसाइट पर जारी करता है। इसके साथ-साथ जो रिक्वनाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी भी लिस्ट यूजीसी की वेबसाइट पर रहता है। हम समय-समय पर स्टेट गवर्नमेंट्स को लेटर लिखते हैं, पिछले अक्टूबर में हमारी सचिव साहब ने सारी राज्य सरकारों को लिखा कि आपके स्टेट में फलां-फलां फेक यूनिवर्सिटीज हैं, आप इसकी व्यवस्था कीजिए।

मैं आपके माध्यम से माननीय मॅम्बर से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी सेशन की शुरूआत होती है, माननीय सदस्य बहुत रिप्यूटेड लीडर्स हैं, उनका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहता है, उसे स्टूडेंट्स भी फॉलो करते हैं।

(1130/SK/SRG)

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने सोशल मीडिया में फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट रखें ताकि उस राज्य के विद्यार्थियों को पता चले कि उनके राज्य में कौन सी फेक यूनिवर्सिटी है और वे जालसाजी में न आएं।

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर) : सर, इसे पोर्टल पर गया है लेकिन फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी दें। अगर हमें वैसे ही पता है कि ये फेक यूनिवर्सिटीज हैं तो इनको बंद करने के लिए क्या सख्त सजा नहीं दी जानी चाहिए? आपने जो पोर्टल पर डाला है, वह जिलेवार विभाजित नहीं है। पूरे देश की यूनिवर्सिटीज को बच्चे नहीं देख पाते हैं। क्या आप पोर्टल को सुधार कर उन सूचियों को जिलेवार करेंगे? क्या आप ऐसे राज्यों के नाम घोषित करेंगे जिनको आपने सूचित किया और उसके बावजूद यूनिवर्सिटीज कार्यरत हैं? आपने इसका समाधानकारक उत्तर तो दिया, लेकिन यूनिवर्सिटीज को राज्यवार विभाजित नहीं किया जो मेरे मूल प्रश्न में था।

डॉ. सुकान्त मजूमदार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सीनियर मॅम्बर को बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में लगभग अभी 21 फेक यूनिवर्सिटीज हैं। मैंने पहले ही प्रश्न का उत्तर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मैटर है। हम डायरेक्टली जाकर हस्तक्षेप करेंगे तो फिर फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रश्न आ जाएगा। मेरे पास लिस्ट है, मैं इसे स्टेटवाइज पढ़ देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या आप ऐसा करने वाले हैं?

... (व्यवधान)

डॉ. सुकान्त मजूमदार : मैं उनके सुझाव को नोट कर लेता हूँ। मेरे पास स्टेटवाइज ब्यौरा है। मैं माननीय सदस्य और बाकी सदस्यों, जिन्हें भी जानकारी चाहिए, वह उपलब्ध करा दूंगा।

मुझे लगता है कि यूजीसी टाइम टू टाइम व्यवस्था लेती है और हम रिट पेटिशन भी करते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं लेकिन मूलतः लॉ एंड आर्डर स्टेट का विषय है। हम उनसे आग्रह कर सकते हैं कि आप व्यवस्था लें। अगर स्टेट व्यवस्था लेगी तो उसके ऊपर धोखाधड़ी के केसिज होंगे।

माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, मैंने उसे नोट कर लिया है।

माननीय अध्यक्ष: श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे जी!

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दम दम) : क्या यह लिस्टेड है?

माननीय अध्यक्ष: दादा, मैं इतनी गलती नहीं करता, आप करते होंगे।

... (व्यवधान)

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री ने फेक यूनिवर्सिटीज के बारे में उत्तर दिया है। जैसा अभी सीनियर मैम्बर ने जो कहा है, मैं उनके सवाल में कुछ एड करना चाहता हूँ कि सरकार ने पिछले दस सालों में कितनी फेक यूनिवर्सिटीज पर कार्रवाई की है? ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। दूरदराज गांवों में एडवर्टाइजमेंट्स की जाती हैं और उन्हें देखकर बच्चे एनरोल कर लेते हैं। उनको पता नहीं होता कि ऑथोराइज क्या है और अनआथोराइज क्या है। इसमें क्लेरिटी लाने के लिए सरकार क्या कर रही है? अगर बच्चों ने एडमिशन लिया और पासआउट हो गए हैं तो उनके भविष्य के बारे में सरकार क्या सोच रही है?

डॉ. सुकान्त मजूमदार : मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि हम आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 फेक यूनिवर्सिटीज बंद कर चुके हैं। हमने वर्ष 2014-24 तक, दस सालों में 12 फेक यूनिवर्सिटीज बंद की हैं जबकि वर्ष 2004-2014 में सिर्फ पांच फेक यूनिवर्सिटीज ही बंद की गई थीं।

माननीय सदस्य के सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, मैंने पहले ही अवगत कराया है कि हम टाइम टू टाइम राज्यों को बोलते हैं। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को सेंसटाइज करें, सोशल मीडिया के माध्यम से करें।

माननीय अध्यक्ष: आपने इसके बारे में पहले बोल दिया है।

... (व्यवधान)

SHRI SALENG A. SANGMA (TURA): Sir, we know that it is every parents dream that their children become somebody. But the fact is that these kinds of fake institutions are destroying the future of our youths.

Mr. Speaker, Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister, whether any kind of compensation will be given to these ill-fated or unlucky children whose fate is already at stake.

SHRI SUKANTA MAJUMDAR: Sir, I think this question is quite similar to the previous one. As I mentioned, now according to the UGC Act, we recognize the universities either by Section 2F or Section 3. Other than that, sometimes some people open such kind of institutions which may either may or may not bear the name of a 'university'.

(1135 /KDS /RCP)

But from time to time, we also notify them. As you know, it is the duty of the State Government to take action because law and order is the pivotal function of the State Government. ... (*Interruptions*) The question is a repetition. So, what can I do?

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे (लातूर) : धन्यवाद स्पीकर सर, मैं लातूर चुनाव क्षेत्र से आता हूँ और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार कुछ नए केंद्रीय विद्यालय भारत में खोलने जा रहा है? यदि हां, तो लातूर जैसे पिछड़े क्षेत्र में नया केंद्रीय विद्यालय बने। माननीय प्रधान मंत्री जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूट लातूर के लिए देंगे। इसके लिए क्या कुछ कार्रवाई हो रही है?

डॉ. सुकान्त मजूमदार : सर, जैसा कि आपको पता है कि यह डायरेक्टली प्रश्न से संबंधित नहीं है। यह प्रश्न फेक यूनिवर्सिटीज से संबंधित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी तक लगभग 56 हैं, जो शिक्षा मंत्रालय के अंदर हैं। ... (व्यवधान) I think, my colleague Shri Jayant Chaudhary is there. He will answer that.

माननीय अध्यक्ष : आप कृपया ऐसे डायरेक्शन मत दिया करें कि जयंत चौधरी जी, आप उत्तर दें।

जयंत चौधरी जी।

... (व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) : अध्यक्ष जी, वैसे यह प्रश्न मुख्य सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है। यह केंद्रीय विद्यालय से संबंधित सवाल है। अभी-अभी कैबिनेट ने 85 केंद्रीय विद्यालयों के प्रस्तावों को अनुमति दी है।

(इति)

(प्रश्न 287)

श्री सौमित्र खान (बिष्णुपुर) : सर, मामला एक साल पुराना है। मेरे राज्य में बिष्णुपुर में मैंने देखा कि बाहर के राज्यों में आपने पैसा अलॉट किया है। बिष्णुपुर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है। 3 हजार 275 करोड़ रुपया देश देश के 23 राज्यों में सैंक्शनड हुआ है। बिष्णुपुर मॉन्यूमेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए शनेश्वर धाम मंदिर, रासमंच, बिष्णुपुर लालजी मंदिर आदि के लिए क्या कोई प्रावधान है? इनके लिए कुछ भी पैसा सैंक्शन नहीं हुआ है, तो इसके पीछे क्या कारण है?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का उत्तर देने से पूर्व सदन की जानकारी में एक विषय लाना चाहता हूँ कि महाभारत कालीन के सर्वाधिक सूक्ष्म प्रमाण जहां राखीगढ़ी के आर्कियोलॉजिकल एस्कवेशन से मिले हैं, उसके दो ऐसे मूल्स को अभी नए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के रूप में पिछले सप्ताह अधिसूचित किया गया है।

माननीय सदस्य ने बिष्णुपुर मंदिर ... (व्यवधान) नहीं, नहीं, मैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए निवेदन कर रहा हूँ। बिष्णुपुर मंदिर परिसर को लेकर माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीनस्थ कुल जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके रखरखाव, उनके अपकीप मेन्टीनेंस, उनके कन्जर्वेशन को लेकर प्रत्येक वर्ष एक प्रोग्राम बनाया जाता है। उसमें से जहां जितनी आवश्यकता है, उसके अनुसार फंड्स का एलोकेशन किया जाता है। हर-एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को हर साल कन्जर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब जैसी जहां आवश्यकता है, तो प्राप्त सूचनाओं के आधार पर फंड एलोकेशन उस तरह से होता है। फंड का एलोकेशन न स्टेटवइज होता है, न मॉन्यूमेंटवाइज होता है। It is requirement based. रिक्वायरमेंट के आधार पर फंड्स एलोकेट किए जाते हैं।

श्री सौमित्र खान (बिष्णुपुर) : सर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या बिष्णुपुर सिटी को नैशनल हेरिटेज सिटी घोषित किया जा सकता है? क्योंकि इससे इसको भी पब्लिसिटी मिलेगी, जो अच्छा है।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अभी तक इस तरह का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचार में नहीं है, लेकिन बिष्णुपुर मंदिर समूह को पहले से ही वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी द्वारा अधिसूचित किए जाने हेतु टेंटेटिव लिस्ट में पहले से ही भारत सरकार की तरफ से प्रस्ताव वहां भेजा जा चुका है।

(1140/MK/PS)

डॉ. संबित पात्रा (पुरी) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय की एक वार्षिक आम बैठक एजीएम में इस मुद्दे को उठाया गया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे एडविना माउंटबेटन, जगजीवन राम, और जयप्रकाश नारायण जी के मध्य पत्राचार हुआ था। मगर, वर्ष 2024 के आरंभ में इस एजीएम की मीटिंग अर्थात् कार्यवाही वृत्तांत में यह उल्लेख है कि एक व्यक्ति एम.वी.राजन, मार्च, 2008 में इस संस्थान में आए और कुछ दस्तावेजों को चिह्नित किया गया। उन चिह्नित दस्तावेजों को इस संस्थान के तत्कालीन निदेशक की अनुमति से मई, 2008 में तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष को 51 कार्टन बॉक्स में भरकर भेज दिया गया। ... (व्यवधान) सभी दस्तावेज हमारे राष्ट्र के इतिहास को समझने के लिए आवश्यक है। मैं माननीय सस्कृति मंत्री जी से चाहता हूँ कि इस मामले की सत्यता की जांच करवाएं तथा पूर्व प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े इन सभी कागजातों को वापस प्रधानमंत्री संग्रहालय में उपलब्ध कराएं।... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रोसीडिंग से एक्सपंज होना चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रश्न संदर्भित प्रश्न है। सम्माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह कहीं संबद्ध नहीं है। यह उनका सुझाव है। मैंने उनका सुझाव लिखकर रखा है और उस पर उचित कार्रवाई की जा सकती है।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर – 288, श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं माननीय सदस्य, मैंने उनको रोक दिया था।

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जो नये माननीय सदस्य हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वे प्रयास करें कि जो संबंधित प्रश्न है, उस संबंधित प्रश्न के आस-पास ही प्रश्न पूछें।

... (व्यवधान)

(प्रश्न 288)

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत (कोरबा) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के प्रदूषण की स्थिति से बदतर स्थिति मेरे लोक सभा क्षेत्र कोरबा की है। वहां एयर क्वालिटी 400 है, जो डेंजर का गंभीर लेवल है। यह पॉवर प्लांट के कारण हो रहा है। इसमें एसीसीएल, बाल्को और एनटीपीसी के वैस्ट प्रोडक्ट हैं और फ्लाई ऐश है। उनसे ब्रिक्स तो बनती हैं, लेकिन कई गुना ज्यादा राखड़ पैदा होती है और उसको हर जगह फेंक दिया जाता है। उसके कारण वहां पर बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं और वायु तथा पानी प्रदूषित हो रहा है। वहां पर कोयले का लदान और एनटीपीसी में बिजली आदि का लाभ तो सरकार ले रही है, लेकिन बदले में हमारे यहां की जनता को सिर्फ बीमारी दे रही है, जिसमें अस्थमा, टीबी, बोन टीबी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस तरह से जो हमारे यहां गंभीर समस्या है, यहां तक तक कि वहां ओपीडी में डेली 500 मरीज वायु से प्रदूषित होकर आ रहे हैं, उसके लिए सरकार की क्या सोच और उसके लिए सरकार ने क्या प्लान किया है, ताकि, हमें इस प्रकार की बीमारी और प्रदूषण से निजात मिल सके? धन्यवाद।

श्री भूपेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक वायु प्रदूषण का विषय है, हमारे यहां लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग करके उसकी पूरी सूचना जनता के बीच में रखी जाती है। शेष कार्रवाई राज्य सरकार को करनी होती है।

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत (कोरबा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बार-बार यही प्रश्न है। मैं इस प्रश्न के बारे में लोक सभा में कई बार बोल चुकी हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे क्षेत्र की जनता के लिए यह सरकार क्या करना चाहती है। यदि कुछ करना चाहती है तो उसके लिए जवाब दे।

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के 130 शहरों में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया जाता है। उसके अंतर्गत उन जिलों में जहां पर वायु प्रदूषण की समस्या है और 130 शहरों में जहां इस प्रकार की समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए हम वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं और राज्यों को प्रोत्साहित भी करते हैं। हम सभी जिलों में जहां पर वायु प्रदूषण के अनेकों कारण होते हैं, इंडस्ट्री उसका एक कारण है, व्हीकल पॉल्यूशन, डस्ट और वैस्ट मैनेजमेंट भी उसका कारण है, हम उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी कार्यक्रम चलाते हैं और जो अच्छा कार्य करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं।

(1145/SPS/SMN)

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में मेरे लोक सभा क्षेत्र नगीना में गुलदार के हमलों को रोकने के लिए सरकार ने वन्य जीव प्रबंधन और मानव वन्य जीव संघर्ष पर कितनी धनराशि

खर्च की है? इन निधियों का उपयोग किस प्रकार किया गया है और इनका क्या प्रभाव रहा है? क्या सरकार ने धन के उपयोग की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है?

माननीय अध्यक्ष जी, आप नए सदस्यों का हौसला बढ़ा रहे हैं, इसलिए आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न वायु प्रदूषण के संबंध में है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह एनीमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा है। उनके क्षेत्र में तेंदुए की समस्या है। वह मुझ से दो दिन पूर्व भी मिले हैं। यह उनके क्षेत्र की समस्या का विषय है, जो इस प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता है। उनके क्षेत्र का विषय इस प्रश्न से अलग है। हम इसको बाहर सुलझाएंगे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब ज्ञानवान मत बनिए। जब बोला है कि स्पीकर गलती नहीं करता है तो नहीं करता है।

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब) : स्पीकर साहब, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी श्री फतेहगढ़ साहिब से शुरू होकर लुधियाना शहर से होता हुआ एक बुड्ढा नाला दरिया है। वह सतलुज दरिया में जाता है। उस नाले में इतना प्रदूषण है कि कैंसर, यूरेनियम, फ्लोराइड और पता नहीं उसमें क्या-क्या मिल रहा है। उसके लिए पंजाब सरकार बहुत सालों से कोशिश कर रही है। क्या केन्द्र सरकार बुड्ढा नाला को साफ और स्वच्छ बनाने की कोशिश करेगी?

दूसरी बात यह है कि क्या केन्द्र सरकार ने पार्ट बी की एग्जम्प्लस की स्टडी कराई है या नहीं? मंत्री जी आपने उसका जवाब नहीं दिया है। क्या आप आगे स्टडी कराएंगे?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एयर पॉल्यूशन का विषय है। यह स्पेसिफिक प्रश्न आपके संसदीय क्षेत्र से संबंधित है। उसके लिए आप अतिरिक्त रूप से मिल सकते हैं।

श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान (रतलाम) : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कागज न होने के कारण वर्षों से खेती कर रहे लोगों को मध्य प्रदेश में वन भूमि के पट्टे नहीं मिले हैं। क्या उनके लिए कुछ सोचा है?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय वन भूमि के पट्टों के संबंध में है। माननीय सदस्य को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वन भूमि के पट्टे उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर वह वहां प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में वन भूमि के पट्टे उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके बारे में सामने वालों को भी पता होगा।

(इति)

(Q.289)

SHRI G. KUMAR NAIK (RAICHUR): Thank you Sir for the opportunity.

I am glad to hear from the hon. Finance Minister that banks in Karnataka are operating robustly and that the interest subvention is helping reduce farmers' interest burden by three per cent for timely repayments.

I would like to bring to your kind notice that cooperative banks in Karnataka supported by NABARD and the State Government provide around Rs. 25,000 crore in short term loans at zero per cent interest to over 35 lakh farmers annually.

In this connection, my question is this. With the short-term refinance loan limit for Karnataka reduced from Rs. 5600 crore to Rs. 2340 crore, how will the Government ensure that the cooperative banks continue to provide zero per cent interest loan to marginal farmers? Will the Ministry consider alternative mechanisms or additional financial support to prevent these farmers from resorting to high interest rates from private lenders which will severely impact their financial stability?

(1150/MM/RP)

श्री पंकज चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में ही कहा कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2023-24 में कर्नाटक में ग्राउंड लेवल क्रेडिट 2.07 परसेंट था। पिछले वर्ष की तुलना में करीब 18.26 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। जहां तक किसी लोन का सवाल है अगर आप देखें, जब से यशस्वी नरेन्द्र मोदी जी इस देश के प्रधान मंत्री हुए हैं, उनका विशेष फोकस खेती-किसानी पर रहा है। वर्ष 2014 में ग्राउंड लेवल क्रेडिट 7.3 लाख करोड़ था, वहीं वही वर्ष 2024-25 में वह बढ़कर 27.5 लाख करोड़ किया गया है।

श्री जी. कुमार नायक (रायचूर) : सर, मेरी आशंका यही है कि राज्य और राष्ट्र के स्तर पर ऊपर-ऊपर देखने से कुछ आंकड़े छिप जाते हैं। Several reports have pointed out that the PSL lending by the commercial banks are more concentrated in the urbanised regions, having higher share of branches compared to the backward and rural areas. Hence, the Rural Cooperative Banks which cater primarily to the farmers' needs need to be provided with greater

amount of low-cost funds which now has been reduced due to increase in PSL by commercial banks. I agree with what the hon. Minister has said.

Sir, I would like to know whether the Union Government has analysed the per capita PSL in aspirational districts which tend to have lower PSL credit, particularly, by private sector banks on which the Government seems to be relying now. What steps have been taken by the Government to increase PSL credit in aspirational districts? There are two aspirational districts in my constituency in Karnataka. That is why I have this specific question. What action can be taken to ensure that the aspirational districts do get the credit as desired? It is not enough to look at the national point of view, and the State point of view. Please come down to dry and arid areas of Karnataka, and the aspirational districts of Karnataka.

श्री पंकज चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बताया है कि किसानों के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि छोटे किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है, मैं बताना चाहता हूं कि छोटे और सीमांत किसानों के खातों की संख्या में पिछले तीन वर्षों से लगातार वृद्धि हो रही है। अगर वर्ष 2021-22 में देखें तो 11.67 करोड़ खाते थे, वहीं वह वर्ष 2023-24 में बढ़कर 13.6 करोड़ खाते हो गए। केवल खातों की बात नहीं है, अगर वर्ष 2021-22 में देखें तो 1059976 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे, वहीं वर्ष 2023-24 में 1439991 करोड़ रुपये के लोन छोटे और सीमांत किसानों को दिए गए।

(इति)

(प्रश्न 290)

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : धन्यवाद अध्यक्ष जी, जनजातीय क्षेत्रों में होम स्टे पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस दिशा में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक अच्छी पहल की गयी है। ऐसे गांवों में जहां पर्यटन की क्षमता है, करीब एक हजार होम स्टे को विकसित करने के लिए योजना बनायी गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि झारखंड जैसे जनजातीय बाहुल्य राज्य में ऐसे होम स्टे की कितनी संख्या है और उसके लिए कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जनजातीय क्षेत्र के लोगों की आजीविका और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए एक वृहद योजना जनजातीय उत्तम ग्राम अभियान के नाम से प्रारम्भ की गयी है। उसी के एक उपांग के रूप में, उसी को सपोर्ट करते हुए टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एक हजार होम स्टे बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें पांच लाख रुपये एक नया होम स्टे बनाने के लिए और पांच लाख रुपये एक कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर बनाने के लिए, *between the home stays* और तीन लाख रुपये अगर कोई होम स्टे किसी अपग्रडेशन के लिए आवश्यक होता है तो उसके लिए देने का हमने प्रावधान किया है। अभी राज्य सरकारों से इस तरह के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। एक बार पूरे प्रस्ताव आ जाने के बाद ही कौन से राज्य में कितने होम स्टे एलोकेट होंगे, उसके बारे में कोई ठोस वक्तव्य मैं यहां दे पाऊंगा।

(1155/YSH/NKL)

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : अध्यक्ष जी, यद्यपि पर्यटन को विकसित करने की प्राथमिक जवाबदेही राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों की है, तथापि भारत सरकार के द्वारा 'स्वदेश दर्शन स्कीम' और 'प्रसाद स्कीम' के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। झारखण्ड राज्य के इको सर्किट टूरिज्म को विकसित करने के लिए 30.44 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उस राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया? क्या पूरी राशि का उपयोग किया गया या नहीं किया गया और अगर नहीं किया गया तो उसके क्या कारण थे? इस दिशा में पूरी राशि का उपयोग हो, उसके लिए माननीय मंत्री जी क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखते हैं?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, 'स्वदेश दर्शन स्कीम' के तहत 'Development of Eco Tourism circuit at Dalma-Betla National Park' के लिए भारत सरकार से जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था, *it was one of the 76 projects sanctioned in total*, जिनकी कुल लागत लगभग 5200 करोड़ रुपये एस्टीमेट की गई थी।

इसमें से लगभग 4,994 करोड़ रुपये रिलीज किए जा चुके हैं। इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में भी 33 करोड़ 44 लाख रुपये का एस्टीमेटेड प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था, जिसमें से 28 करोड़ रुपये अब तक रिलीज किए जा चुके हैं। 76 प्रोजेक्ट्स में से 75 प्रोजेक्ट्स, 100 प्रतिशत फिजिकली कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसा राज्यों ने हमें संसूचित किया है। इसके बारे में अगर माननीय सदस्य और भी विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो उनका मेरे कार्यालय में स्वागत है। वे कभी भी आ जाएं। हम इसके बारे में बैठकर जो भी जानकारी माननीय सदस्य को चाहिए होगी, उनको उपलब्ध करवा देंगे।

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल (वलसाड) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का मेरे लोक सभा क्षेत्र वलसाड में वलसाड, नवसारी और डांग की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में तीथल, नारगोल बीच, उमरगाम बीच, विल्सन हिल्स, सापुतारा और डॉन हिल के साथ-साथ रामायण से जुड़े हुए शबरी धाम और उनाई माता जैसे पवित्र तीर्थ स्थान भी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार की इन्हें 'स्वदेश दर्शन योजना' में शामिल करने की कोई योजना है? अगर योजना है तो हमारे क्षेत्र को यह एक नई दिशा देने का काम करेगी।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्माननीय सदस्य का एक बहुत अच्छे प्रस्ताव और बहुत पोटेंशियल वाले क्षेत्र के बारे में ध्यान आकर्षित करवाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब की जानकारी में है कि टूरिज्म प्राइमरली स्टेट की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार इस पर प्रस्ताव बनाकर भेजे तो निश्चित रूप से तय प्रावधानों के तहत उस पर कार्रवाई करने का प्रयास, जो उपलब्ध संसाधन हैं, उनके तहत करने का प्रयास हम कर सकते हैं।

(इति)

(Q.291)

SHRI G. SELVAM (KANCHEEPURAM): Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity.

How many individuals have benefitted from skill development initiatives conducted through employment exchanges in the last three years?

डॉ. मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि देश में जिस तरह से मैनुफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, उस स्थिति में राज्य सरकार की ओर से, सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर से नम्बर ऑफ टाइप के इनिशिएटिव्स और आईआईटी के द्वारा उसको ट्रेनिंग दी जाती है।

वर्तमान समय में इस बजट में भी प्रधान मंत्री जी ने दो लाख करोड़ रुपये के खर्च से 4.1 करोड़ जॉब निर्माण का लक्ष्य रखा है। उसमें भी स्किल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण विषय रखा गया है। स्किल डेवलपमेंट और स्किल एनहांसमेंट के लिए हर सेक्टर में कलस्टर बेस्ड स्किलिंग हो, उसके लिए हब और स्पोक की व्यवस्था के द्वारा, जिस एरिया में जिस टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, जिस टाइप की स्किल की आवश्यकता है, वैसा ही सिलेबस बनाकर उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है।

SHRI G. SELVAM (KANCHEEPURAM): Are there any plans to expand the scope of skill development and counselling programmes through employment exchanges in tier-2 and tier-3 cities?

डॉ. मनसुख मांडविया : अध्यक्ष महोदय, स्किल डेवलपमेंट को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए हमने नेशनल करियर सर्विस पोर्टल को इंटीग्रेट किया है। उसमें हमने ई-श्रम पोर्टल को भी इंटीग्रेट किया है। उसमें स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पोर्टल को भी इंटीग्रेट किया गया है, ताकि जहां जिस टाइप की स्किल वाली मेनपावर उपलब्ध है, उसको इंटीग्रेट करके नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के द्वारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज को जोड़कर उसको अपने करियर के लिए अपॉर्च्युनिटी मिले, रोजगार के लिए अपॉर्च्युनिटी मिले, उसके लिए प्रयास किया गया है।

(1200/RAJ/VR)

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव राय, आप अपनी बात एक सेकेंड में पूछिए, अब बारह बजने वाले हैं।

श्री राजीव राय (घोसी) : सर, माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि पिछले तीन वर्षों में कितने लोगों को रोजगार मिला।

मैं यह जानना चाहता हूं कि तीन वर्षों में कितने लोगों की कटौती हुई, छंटनी हुई और कितने लोग बेरोजगार हो गए, जिसका डेटा क्या अभी सरकार के पास है और क्या संविदा पर नौकरी करने वालों को स्थायी करने का आपका कोई विचार है?

डॉ. मनसुख मांडविया : अध्यक्ष महोदय, रोजगार के साथ जुड़ना और उनके लिए और अच्छी जगहों पर रोजगार की अपॉर्च्युनिटी हो, तो वहां माइग्रेट होना, यह स्वभाविक है, लोग जुड़ते भी रहते हैं और कई लोग दूसरे जॉब्स भी ज्वाइन करते रहते हैं।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में विनिर्णय

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिन माननीय सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, प्रो. सौगत राय, श्री राजेश रंजन, श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत, डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद, श्री अरविंद गणपत सावंत, श्री बी. मणिकम टैगोर, श्री गौरव गोगोई, श्री धर्मेन्द्र यादव, डॉ. मोहम्मद जावेद, श्री कोडिकुन्नील सुरेश और श्री के. राधाकृष्णन। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए आज अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी।

THE MINISTER OF CULTURE; AND MINISTER OF TOURISM (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, Noida, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, Noida, for the year 2022-2023.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tibet House, New Delhi, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tibet House, New Delhi, for the year 2022-2023, together with audit report thereon.
- (iii) A copy of Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tibet House, New Delhi, for the year 2022-

2023.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.
- (5)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sahitya Akademi, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sahitya Akademi, New Delhi, for the year 2023-2024.
- (6)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Victoria Memorial Hall, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Victoria Memorial Hall, Kolkata, for the year 2023-2024.
- (7)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Museum, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Museum, Kolkata, for the year 2023-2024.
- (8)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Culture Fund, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958:-
 - (i) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws for Lakha Mandal temple and images in its vicinity, Village Lakha Mandal, Tehsil – Chakrata, District Dehradun, Uttarakhand
 - (ii) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws for Ancient

- Excavated Sites and Remains, Village Khawli Sera, Purola, District Uttarkashi, Uttarakhand.
- (iii) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws for Cemeteries, Mauza Kydganj, District Prayagraj, Uttar Pradesh.
- (iv) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws for the site of the Stupa and Monastery of the Sakyas at Piprahwa (Tehsil, District Siddharth Nagar, Uttar Pradesh).
- (v) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws for "Two tombs, viz., the first octagonal and known as the tomb of Muhammad Momin, the 'Ustad', now empty, and the other square and known as the tomb of Haji Jamal, his pupil; the latter contains 5 graves inside and one on a platform outside" Nakodar, District Jalandhar, Punjab.
- (vi) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws for Ancient site and Buddhist Stupa, Sanghol, District Fatehgarh Sahib, Punjab.
- (vii) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws for Imambara of Asaf-ud-Daula, Masjid connected with Asaf-ud-Daula and Rumi Darwaza close to Asaf-ud-Daula Imambara at Hussainabad, Tehsil Lucknow Sadar, District Lucknow, Uttar Pradesh.
- (viii) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws for The Dome of Shah Nawaz Khan, Burhanpur, Madhya Pradesh.
- (ix) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws for Hammam Khana, Chowk Mohalla, Burhanpur, Madhya Pradesh.
- (x) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws for The Bridge over Beta (Behta) River and the temple attached to it, Tikaitganj, (Tehsil-Malihabad, District – Lucknow, Uttar Pradesh).
- (xi) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws for Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District – Balrampur, Uttar Pradesh.

- (xii) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws The Group of Temples known as Brindaban Chandra's Math Guptipara, District – Hooghly, West Bengal.
- (xiii) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws for Lord Cornwallis Tomb, Ghazipur, Uttar Pradesh.
- (xiv) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws for Bibi Sahib's Masjid, Burhanpur, Madhya Pradesh.
- (xv) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws for Ancient Site known as Fazilnagar Ka Kot comprised in survey plot Nos 766, 782 and part of survey plot Nos 757, 758 and 759, District – Kushinagar, Uttar Pradesh.

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 12 जुलाई के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 384(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपरोक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) (एक) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) स्टार्स, मध्य प्रदेश के वर्ष 2020-2021 एवं 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) स्टार्स, मध्य प्रदेश के वर्ष 2020-2021 एवं 2021-22 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपरोक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) स्टार्स, राजस्थान के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) स्टार्स, राजस्थान के वर्ष 2022-23 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपरोक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) तेलंगाना समग्र शिक्षा, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) तेलंगाना समग्र शिक्षा, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपरोक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) समग्र शिक्षा, लद्दाख के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) समग्र शिक्षा, लद्दाख के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपरोक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31; प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (दस्तावेजों का सत्यापन) (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/212 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 30 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/213 में प्रकाशित हुए थे।
- (3) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 20 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/210 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंकर) (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 29 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/214 में प्रकाशित में हुए थे।

- (4) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सिक्का निर्माण (डॉ. पंजाबराव उर्फ भाऊसाहब देशमुख की 125वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023, जो 21 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 905(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सिक्का निर्माण (रामकृष्ण मिशन की स्थापना के 125 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023, जो 21 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 906(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सिक्का निर्माण (खरतरगच्छ सहस्राब्दी, संस्थापक जैनाचार्य श्री जिनेश्वर सूरी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023, जो 23 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 914(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) सिक्का निर्माण (डॉ. हरेकृष्ण महताब की 125वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023, जो 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 926(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) सिक्का निर्माण (कर्नाटक बैंक के 100 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023, जो 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 927 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) सिक्का निर्माण (वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष पूरा होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 02 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 4 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) सिक्का निर्माण (स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 22 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 56(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) सिक्का निर्माण (गणतंत्र दिवस समारोह के 75वें वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 23 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 60 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (नौ) सिक्का निर्माण (उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के श्री राम चंद्र जी की 125वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 31 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 80(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) सिक्का निर्माण (श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 01 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 84(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) सिक्का निर्माण (भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 23 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 127(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) सिक्का निर्माण (मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड की स्थापना के 250 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 12 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) सिक्का निर्माण (भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के 90 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 19 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 218(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) सिक्का निर्माण (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 382(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) सिक्का निर्माण (भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 383(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सोलह) सिक्का निर्माण (कल्लेगनार डॉ. एम. करुणानिधि की जन्मशती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 393(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्रह) सिक्का निर्माण (एच.एच. श्री माताजी निर्मला देवी की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो दिनांक

- 6 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 539(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (अठारह) सिक्का निर्माण (भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई मुख्य शाखा भवन शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 563(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (उन्नीस) सिक्का निर्माण (श्री स्वामीनारायण मंदिर, वडतालधाम द्विशताब्दी महोत्सव के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 564(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बीस) सिक्का निर्माण (राजभाषा के हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी किया जाना) नियम, 2024, जो दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 565(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (इक्कीस) सिक्का निर्माण (केंद्रीय रेशम बोर्ड के स्थापना वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 18 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 578(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बाईस) सिक्का निर्माण (जैन आचार्य श्रीमद बुद्धिसागर सुरीश्वरजी महाराजजी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 686(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेईस) सिक्का निर्माण (बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी की हीरक जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 685(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौबीस) सिक्का निर्माण (भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो दिनांक 12 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 700(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पच्चीस) सिक्का निर्माण (पार्श्वनाथ भगवान के 2900वें जन्म कल्याणक के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 18 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 711(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (छब्बीस) सिक्का निर्माण (पार्श्वनाथ भगवान के 2800वें निर्वाण कल्याणक के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 18 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 710(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्ताईस) सिक्का निर्माण (मैसूर मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 25 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 728(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (अट्ठाईस) सिक्का निर्माण (डॉ. हरेकृष्ण महताब की 125वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 19 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 714(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (उनतीस) सिक्का निर्माण (संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 20 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 718(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 27 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एपीजीवीबी-एसआर-संशोधन/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2023, जो दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 904/एपीजीबी/पीएचआरडी/डीएफएस में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एपीआरबी/जीएन/142/1677 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) असम ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 6 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एजीवीबी/पीईआर/ईएसटीटी-बी/01/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।

- (पाँच) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीजीवीबी/एचओ/एचआर/4637/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 10 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. बीयूपीबी/एचओ/एचआरएम/06/17631019 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) बड़ौदा यू.पी. बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीयूपीबी/1019 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 18 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीआरजीबी/ एचओ/ एचआर/1094/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 6 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. डीबीजीबी 1/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचपीजीबी/एचओ/एचआरडी/2024 में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 25 जुलाई, 2024 की अधिसूचना संख्या एचपीजीबी/एचओ/एचआरडी/2024 में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण)।
- (ग्यारह) जे एंड के ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 22 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेकेजीबी/एचओ/एचआरडीडी /2024-25/2978 में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेकेजीबी/सेवा/(संशोधन)/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) कर्नाटक ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 15 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र

- में अधिसूचना संख्या फा.स. एनबी.एचओ.आईडीडी.नीति/182/316(सेवा विनियम)/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनबी.एचओ.आईडीडी.नीति/182/316(सेवा विनियम)/ 2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) केरल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या केजीबी/सेवा विनियम (संशोधन)/1/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (सोलह) मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 14 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. एमपीजीबी/एचओ/एचआरडी/2041/सेवा(संशोधन)/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्रह) मध्यांचल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडी/2024-25/683 दिनांक 30.10.2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (अठारह) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 13 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एमजीबी/सेवा विनियम (संशोधन)/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (उन्नीस) मेघालय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एमईजीआरआरबी/ सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (बीस) मिजोरम ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 1 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एमआरबी/2024-मिजोरम ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (इक्कीस) ओडिशा ग्राम्य बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 21 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीएच/एचआरडी/831/2024-25 (संशोधन) विनियम, 2024 में प्रकाशित हुए थे।

- (बाईस) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीबीजीबी/एचओ/सीएचएम/पीएडी/300/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (तेईस) प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. पीयूपीजीबी.1/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौबीस) पंजाब ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ :एचआरडी:2024/3357 में प्रकाशित हुए थे।
- (पच्चीस) राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आरएमजीबी/एसआर संशोधन/10/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (छब्बीस) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 12 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. एचओ/एचआरएम/ डीओपी-जीओआई /84/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्ताईस) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 10 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एचआरडीडी/2024/1891 में प्रकाशित हुए थे।
- (अठ्ठाईस) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 22 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसजीबी/एचओ/पीईआर/19638/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (उनतीस) तमिलनाडु ग्राम बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 13 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या टीएनजीबी/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीस) तेलंगाना ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 21 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या टीजीबी सेवा विनियम संशोधन 2024 में प्रकाशित हुए थे।

- (इकतीस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 9 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या टीजीबी.1/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (बत्तीस) उत्कल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 15 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/242 में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 8 नवम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या पीईआर/1733 में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र।
- (तैंतीस) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 15 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. यूबीकेजीबी.1/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौंतीस) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 27 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एचआरडी/17/24-25/1151 में प्रकाशित हुए थे।
- (पैंतीस) उत्तराखंड ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 25 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या यूजीबी/एचओ/2024-25/पीईआर/661 में प्रकाशित हुए थे।
- (छत्तीस) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या वीकेजीबी/एचओ/एचआरडी/एमआरएस/2024-25/25 में प्रकाशित हुए थे।
- (सैंतीस) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 24 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. एपीजीवीबी-पीआर-संशोधन-2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (अड़तीस) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1020/एपीजीबी/पीएचआरडी/डीएफएस/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (उनतालीस) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एपीआरबी/जीएन/142/3936 में प्रकाशित हुए थे।

- (चालीस) आर्यावर्त बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 21 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आर्यावर्त बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (इकतालीस) असम ग्रामीण विकास बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 14 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एजीवीबी/पीईआर/ईएसटीटी-बी/08/03/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (बयालीस) बंगीय ग्रामीण विकास बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 21 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीजीवीबी/एचओ/एचआर/5700/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (तैंतालीस) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 10 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. बीजीजीबी/एचओ/एचआरएम/06/1763 में प्रकाशित हुए थे।
- (चवालीस) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 10 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरएम/एचओ/2024-25/252 में प्रकाशित हुए थे।
- (पैंतालीस) बड़ौदा यूपी बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 16 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. बीयूपीबी/24-25/158 में प्रकाशित हुए थे।
- (छियालीस) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 18 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीआरजीबी/एचओ/एचआर/1161/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (सैंतालीस) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीबीजीबी/2/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (अड़तालीस) एलाक्वाई देहाती बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 22 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईडीबी/714/संशोधित पेंशन विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (उनचास) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम,

2024 जो दिनांक 23 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचपीजीबी/एचओ/एचआरडी/2024/पीईएन-1 में प्रकाशित हुए थे।

- (पचास) जेएंडके ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 14 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेकेजीबी/एचओ/एचआरडीडी/2024-25/4359 में प्रकाशित हुए थे।
- (इक्यावन) झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 6 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेआरजीबी/पेंशन (संशोधन)/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (बावन) कर्नाटक ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 6 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 8/4/2024-आरआरबी में प्रकाशित हुए थे।
- (तिरपन) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 1 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या केवीजीबी/पेंशन विनियम/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौवन) केरल ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 1 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या केजीबी पेंशन विनियम (संशोधन)/1/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (पचपन) मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 14 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. एमपीजीबी/एचओ/एचआरडी/2042/पेंशन (संशोधन)/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (छप्पन) मध्यांचल ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कार्मिक (पेंशन)/डीकेएम/24-25/57 में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्तावन) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 5 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. 8/20/2010-आरआरबी में प्रकाशित हुए थे।
- (अठ्ठावन) मणिपुर ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. एमआरबी/ईपीआर/2/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (उनसठ) मेघालय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

- फा.स. एमईजीआरआरबी/पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (साठ) मिजोरम ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 1 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जीजेडटी-एमआरबी/पीएसएन-एएमएम/2024-25/01 विनियम, 2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (इकसठ) नागालैंड ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनआरबी/पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (बासठ) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. पीबीजीबी/एचओ/सीएचएम/पीएडी/301/2024-25, 2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (तिरसठ) प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 10 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. पीयूपीजीबी 2/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौसठ) पंजाब ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 10 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. एचओ:एचआरडी: 2024/4363 में प्रकाशित हुए थे।
- (पैंसठ) राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 22 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आरएमजीबी/पीआर संशोधन/19/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (छियासठ) सप्तगिरी ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 22 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एचआरएम/डीओपी-जीओआई/86//2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (सड़सठ) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 14 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एचआरडीडी/2024/2016 में प्रकाशित हुए थे।
- (अड़सठ) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 21 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसजीबी/एचओ/पीईआर/20282/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (उनहत्तर) तमिलनाडु ग्राम बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो

- दिनांक 22 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या टीएनजीबी/पेंशन(संशोधन)/041024/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्तर) तेलंगाना ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 01 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या तेलंगाना ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (इकहत्तर) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. टीजीबी.1/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (बहत्तर) उत्कल ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 15 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/252 में प्रकाशित हुए थे।
- (तिहत्तर) उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 16 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. यूबीकेजीबी.2/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौहत्तर) उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 18 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/टीबीसी/17/2024-25/646 में प्रकाशित हुए थे।
- (पिचहत्तर) उत्तराखंड ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 24 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. यूजीबी/एचओ/2024-52/पीईआर/1133 में प्रकाशित हुए थे।
- (छिहत्तर) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 01 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या वीकेजीबी/पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (6) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) बैंक ऑफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 29 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा. सं. एचओ/एचआरएम/116/2714 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक

- 4 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीओआई/एचओ/एचआर/आईआर/एमकेबी/एल-324(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा. सं. एएक्स1/एसटी/ओएसआर/119/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा. सं. आईबी/जी-10/1/2024-25(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) इंडियन ओवरसीज बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 2 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा. सं. एचआरएमडी/एसयूपी/177/01/2024-25(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 28 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडब्ल्यू पीएम 6114 2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 27 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ/एचसीएम/आईआरपी/2024-25/295 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) यूको बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 27 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/ईएसटी/2024-25/570 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 29 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा. सं. एचआरडीडी/पीओएल/ओएसआर(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 26 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा. सं. पीएसबी/एचआरडी/ओएसआर/2024-25/01 में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 27 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ/ईआरडी/पीडी/798/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (7) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (समूह 'ग' कर्मचारियों की भर्ती, वेतन तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2024, जो दिनांक 21 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक

व्याख्यात्मक ज्ञापना।

- (8) उपरोक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि.743(अ) जो दिनांक 3 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 496(अ) का निरसन किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (दो) केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 745(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (10) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 744(अ) जो दिनांक 3 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 500(अ) का निरसन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (11) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 5063(अ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3048(अ) और दिनांक 29 नवम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5128(अ) में प्रकाशित उसके शुद्धिपत्र में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (दो) का.आ. 3048(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 109 की उप-धारा (1), (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए (एक) 1.9.2023 से माल और सेवा कर अपीलिय अधिकरण (जीएसटीएटी) की स्थापना, (दो) नई दिल्ली में जीएसटीएटी की प्रधान पीठ के गठन, और (तीन) जीएसटीएटी की कई राज्य पीठ के गठन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (तीन) सा.का.नि. 729(अ) जो दिनांक 25 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 02/2017-केंद्रीय कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं

तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

- (चार) का.आ 5091(अ) जो दिनांक 27 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसका आशय डीजीजीआई द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के लिए समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नियुक्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (पांच) सा.का.नि.735(अ) जो दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यापार का प्रधान स्थान पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अक्तूबर, 2024 के माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की नियत तारीख बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (12) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.749(अ) जो दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 751(अ) में प्रकाशित उसके शुद्धिपत्र जिनका आशय अधिसूचना की तारीख से 06 माह की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य तथा वियतनाम से “टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड तथा अनकोटेड ग्लास” के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (13) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2024, जो 29 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 739(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (14) सामान्य बीमा कारबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1972 के अध्याय-पांच के खंड 17 के अंतर्गत सामान्य बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का युक्तिकरण) संशोधन योजना, 2024 जो दिनांक 6 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 5257 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (वाणिज्य)- वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 12 (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां) की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (16) (एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष

2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (17) वर्ष 2023-2024 के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यक्रम की सरकार द्वारा की गई समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Notification No. S.O. 353(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29th January, 2024 making certain amendments in the Notification No. S.O. 489(E) dated 1st May, 2003, issued under sub-section (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3) A copy of the State Pollution Control Board (Manner of Nomination and other Terms and Conditions of Service of Chairman) Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.727(E) in Gazette of India dated 25th November, 2024 under sub-section (3) of Section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Govind Ballabh Pant National Institute of Himalayan Environment, Almora, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Govind Ballabh Pant National Institute of Himalayan Environment, Almora, for the year 2023-2024.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION; AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH
EASTERN REGION (SHRI SUKANTA MAJUMDAR): Sir, I beg to lay on the
Table:-

- (1) A copy of the Central University of Jharkhand (Addition) Statutes, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No. CUJ/Statute/II/2010/Part/II in Gazette of India dated 17th May, 2024 under sub-section (2) of Section 43 of the Central Universities Act, 2009
- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 44 of the Pondicherry University Act, 1985:-
 - (i) Notification No. PU/LC/Amendments/2023-24/F.No.39-12/2023-CU-I published in Gazette of India dated 5th December, 2023, making certain amendments, mentioned therein, to Statute 1 of the Pondicherry University Act, 1985.
 - (ii) Notification No. F.39-4/2019-CU I dated 03.02.2021 published in Gazette of India dated 23rd November, 2021, making certain amendments, mentioned therein, to Statutes of the Pondicherry University Act 1985.
 - (iii) The Pondicherry University (Amendment) Statutes 2021 published in Notification No. F.No.F.39-4/2019-CUI/dated 03.02.2021 in Gazette of India dated 9th November, 2021.
 - (iv) The Pondicherry University (Amendment) Statutes 2019 published in Notification No. F.No.39-4/2019-CU-I dated 6.12.2019 in Gazette of India dated 26th November, 2022.
- (3) Three Statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at Item No. (ii to iv) of (2) above.
- (4)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the School of Planning and Architecture, New Delhi, for the year 2023-2024.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the

- Government of the working of the School of Planning and Architecture, New Delhi, for the year 2023-2024.
- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the University of Hyderabad, Hyderabad, for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the University of Hyderabad, Hyderabad, for the year 2023-2024, together with audit report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the University of Hyderabad, Hyderabad, for the year 2023-2024.
- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru University, New Delhi, for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru University, New Delhi, for the year 2023-2024, together with audited accounts.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Nehru University, New Delhi, for the year 2023-2024.
- (7) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Nagaland University, New Delhi, for the year 2022-2023 together with audit report thereon.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.
- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Shastri Indo Canadian Institute, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith audited accounts
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Shastri Indo Canadian Institute, New Delhi, for the year 2020-2021.

- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.
- (11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technical Teachers Training & Research, Bhopal, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technical Teachers Training & Research, Bhopal, for the year 2023-2024.
- (12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technical Teachers Training and Research, Chandigarh, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technical Teachers Training and Research, Chandigarh, for the year 2023-2024.
- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technical Teachers Training and Research, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technical Teachers Training and Research, Kolkata, for the year 2023-2024.
- (14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Board of Apprenticeship Training (BOAT), Northern Region, Kanpur, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the

Government of the working of the Board of Apprenticeship Training (BOAT), Northern Region, Kanpur, for the year 2023-2024.

- (15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management, Raipur, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management, Raipur, for the year 2023-2024.
- (16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management, Bombay, Mumbai, for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Annual Audit Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management, Bombay, Mumbai, for the year 2023-2024, together with audit report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management, Bombay, Mumbai, for the year 2023-2024.

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (2) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यकरण और प्रशासन के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS,
FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
5th and 6th Reports**

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I beg to lay the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution: -

- (1) Fifth Report on Demands for Grants (2024-25) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).
- (2) Sixth Report on Demands for Grants (2024-25) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर, 9 श्री बसवराज बोम्मई – उपस्थित नहीं।
श्री रुद्र नारायण पाणी।

**श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति
पहला से तीसरा प्रतिवेदन**

श्री रुद्र नारायण पाणी (धेन्कानल) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में पहला प्रतिवेदन।
- (2) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।
- (3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS

1st to 5th Reports

SHRI KIRTI AZAD (BARDHAMAN-DURGAPUR): Sir, I beg to lay the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers (2024-25):-

- (1) First Report on Action Taken by the Government on the observations/recommendations of the Committee contained in their Forty Sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Insecticides & Pesticides — promotion and development including safe usage — licensing regime for insecticides' pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers.
- (2) Second Report on Action Taken by the Government on the observations/recommendations of the Committee contained in their Fiftieth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Promotion of Medical Device Industry' pertaining to the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers.
- (3) Third Report on 'Demands for Grants (2024-25)' pertaining to the Department of Fertilizers.
- (4) Fourth Report on 'Demands for Grants (2024-25)' pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals.
- (5) Fifth Report on 'Demands for Grants (2024-25)' pertaining to the Department of Pharmaceuticals.

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS

Action Taken Statements

SHRI KIRTI AZAD (BARDHAMAN-DURGAPUR): Sir, I beg to lay on the Table Six Action Taken Statements (Hindi and English versions) showing Final Action Taken by the Government on the recommendations contained in the following Action Taken Reports of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers (2024-25):-

- (1) Action Taken Statement on Forty-seventh Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Action Taken by the Government on the observations/ recommendations of the Committee contained in their Thirty-ninth Report (17th Lok Sabha) on 'NANO fertilizers for sustainable crop production and maintaining soil health' of the Department of Fertilizers.
- (2) Action Taken Statement on Forty-eighth Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on action taken by the Government on the observations/recommendations of the Committee contained in their Fortieth Report (17th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2023-24) of the Department of Fertilizers'.
- (3) Action Taken Statement on Fifty-first Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on action taken by the Government on the observations/recommendations of the Committee contained in their Forty-first Report (17th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2023-24) of the Department of Chemicals and Petrochemicals'.
- (4) Action Taken Statement on Forty- Fifth Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on action taken by the Government on the observations/ recommendations of the Committee contained in their Forty- Second Report (17th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2023-24)' of the Department of Pharmaceuticals.
- (5) Action Taken Statement on Fifty-second Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on action taken by the Government on the observations/ recommendations of the Committee contained in their Forty-third Report (17th Lok Sabha) on 'Planning for fertilizers production and import policy on fertilizers including GST and import duty thereon' of the Department of Fertilizers.
- (6) Action Taken Statement on Forty-ninth Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on action taken by the Government on the observations/recommendations of the Committee contained in their Forty-fourth Report (17th Lok Sabha) on 'Fertilizers Subsidy Policy and Pricing Matters including need to continue Urea Subsidy Scheme' of the Department of Fertilizers.

STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL
Final Action Taken Statements

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): Sir, I beg to lay the following Final Action Taken Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel:-

- (1) Thirty-second Report (17th Lok Sabha) on action taken by the Government on the observations/recommendations contained in Twenty-eighth Report (17th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2022-23)' relating to the Ministry of Steel.
- (2) Thirty-third Report (17th Lok Sabha) on action taken by the Government on the observations/recommendations contained in Twenty-ninth Report (17th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2022-23)' relating to the Ministry of Mines.
- (3) Thirty-fourth Report (17th Lok Sabha) on action taken by the Government on the observations/recommendations contained in Thirtieth Report (17th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2022-23)' relating to the Ministry of Coal.
- (4) Thirty-fifth Report (17th Lok Sabha) on action taken by the Government on the observations/recommendations contained in Thirty First Report (17th Lok Sabha) on the subject 'Development of Aluminum and Copper Industries in the Country' relating to the Ministry of Mines.
- (5) Forty-first Report (17th Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Thirty-sixth Report (17th Lok Sabha) on the subject 'Skill Development in Steel Sector' relating to the Ministry of Steel.
- (6) Forty-second Report (17th Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Thirty-seventh Report (17th Lok Sabha) on the subject 'Import of Coal –Trends and Issue of Self Reliance' relating to the Ministry of Coal.
- (7) Forty-third Report (17th Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Thirty-eighth Report (17th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2023-24)' relating to the Ministry of Coal.
- (8) Forty-fourth Report (17th Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Thirty-ninth Report (17th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2023-24)' relating to the Ministry of Mines.
- (9) Forty-fifth Report (17th Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Fortieth Report (17th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2023-24)' relating to the Ministry of Steel.

(1205/KN/SAN)

***लोक महत्व के अविलम्बनीय मुद्दे**

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल के दौरान लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय को मैं उठाने की अनुमति दे रहा हूँ। मुझे आशा है कि सदन सहयोग करेगा। हम दो-दो मिनट में अपनी बात कहें। काफी दिनों से शून्य काल नहीं हुआ है और कई माननीय सदस्यों का आग्रह है।

... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : सर, तीन मिनट की व्यवस्था है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : अध्यक्ष जी, संविधान के डिस्कशन की चर्चा में राज्य सभा के एक सांसद का नाम गलत ढंग से लिया गया है।

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट बैठिये। आप दो बजे के बाद अपना विषय उठाना, शून्य काल में नहीं।

मेरा आग्रह है कि आप शून्य काल में दो मिनट में अपनी बात कहें। जो विषय दिए हैं, उस विषय पर अपनी बात रखें। हम शून्य काल व्यवस्थित तरीके से चलाना चाहते हैं।

कई माननीय सदस्य नए हैं, जो अपने संसदीय क्षेत्र के विषयों को उठाना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आप सब चेयर को सहयोग करेंगे।

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल जी।

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलना का समय दिया, इसके लिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में सोलर, विंड और थर्मल प्लांटों के माध्यम से देश में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन 'दीये तले अंधेरा वाली' कहावत सिद्ध हो रही है। लोगों को घरेलू एवं कृषि कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में बिजली नसीब नहीं हो पाती है, जिससे किसानों को रबी की बुवाई करने में देरी हो रही है। नहरी क्षेत्र में भी बिजली की गम्भीर समस्या है। फव्वारा पद्धति से डिगियों के माध्यम से, लाइट नहीं मिलने की वजह से, किसान अपनी बुवाई नहीं कर पा रहे हैं। किसानों को मात्र दो-तीन घंटे बिजली मिलती है और वह भी कम वोल्टेज होने की वजह से, उनकी मोटरें जल जाती हैं, जिससे किसानों का उसकी रिपेयरिंग के लिए बहुत खर्चा आता है। ट्रांसफार्मर जलने के बाद महीनों भर उनको रिप्लेसमेंट नहीं किए जाते हैं और लाइनें फॉल्ट हो जाती हैं तो किसानों को दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। एफआरडी टीमें सही ढंग से काम नहीं करती हैं। पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलने के कारण उपज ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : मेरी आपके माध्यम से मांग है कि किसानों को समय पर पूरी बिजली मिले। आरडीएसएस स्कीम के तहत जो जीएसएस बन रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से बनाया जाए। किसानों को पूरी बिजली मिले, इसके लिए फीडरों को दुरुस्त किया जाए। ट्रांसफार्मर नए लगाये जाए और नए जीएसएस बनाए, ताकि किसानों को घरेलू बिजली और एग्रीकल्चर के लिए बिजली समय पर मिलती रहे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठिये।

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : करीब 75 हजार लोग आज भी अंधेरे के अंदर हैं और उनको नए कनेक्शन दिए जाए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पहली बार चुनकर आए हैं। कई विषय राज्यों के रहते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो केन्द्र के विषय हैं, उनको सामान्य रूप से उठाएं। अगर राज्य-केन्द्र के विषय हों तो आप उठा सकते हैं। आपको यह प्रयास करना चाहिए।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker, Sir, once in a while, my name is coming in the draw of lots. Since only 20 Members are successful, kindly allow some more time to at least those who figure in the list.

Sir, I thank you very much for affording me this opportunity to raise the issue of Employees' Pension Scheme, 1995. I draw the attention of the Labour Minister, through you, to the grave irregularity and injustice shown to the poor workers of this country. I have been fighting this cause since 2014. Several representations, interventions and submissions were made in this House, but unfortunately, nothing positive is coming from the Labour Ministry.

On 04.11.2022, the Supreme Court gave a full-fledged judgement by virtue of which the employees are entitled to receive a higher pension under the Employees' Pension Scheme. Even after the lapse of two years, so far one per cent of the total persons, who have given the applications, has got higher pension in the State of Kerala. As per the media reports, only two per cent people have got higher pension. The total number of applications already submitted till August 7, 2024 is 17,48,775.

(1210/SNT/VB)

The EPFO has given higher pension only to 8,401 people. Kindly see that even after two years of the Supreme Court judgement, the Employees' Provident Fund Organisation is taking a very negative attitude towards the workers, and not giving higher pension. So, my submission is higher pension has to be given at the earliest.

Also, regarding the calculation of pension, a new method of calculation has been taken into account, that is, *pro rata* basis of allocation. It has been divided into two parts, that is, pension before 01.09.2014 and pension after 01.09.2014. It is against the Act; it is against the scheme; and it is against all norms. So, that has to be reconsidered.

The final point is regarding the minimum pension. In the 16th Lok Sabha, I had given a Private Member Resolution. The whole House had unanimously consented to it and a recommendation has already been given. So far, the minimum pension has not been increased. So, I request for the enhancement of the minimum pension. These three issues have to be considered.

श्री उज्ज्वल रमण सिंह (इलाहाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जैन समुदाय के पवित्र पूजा स्थल गिरनार पर्वत की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

जैन समाज अति अल्पसंख्यक है। जैन समाज का हमेशा से ही राष्ट्र-निर्माण में अहम योगदान रहा है। जैन धर्म के अनुयायियों पर किस न किसी रूप से प्रहार किया जाता रहा है। गिरनार पर्वत की पाँचवीं टॉप, जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली है।

वहाँ पर भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक दिवस, 13 जुलाई को जैन समाज के लोगों को निर्वाण लाडू चढ़ाने से रोका गया। भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थ कमेटी के सदस्यों ने बताया कि पूजा-अर्चना की सामग्री- बादाम आदि भी रोकी जा रही है।

मैं आपके माध्यम से, सरकार से पुरजोर अपील करता हूँ कि जैन समुदाय के धर्म तीर्थ और संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए जैन बोर्ड की स्थापना की जाए।

धन्यवाद।

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड राज्य में पाँच जनजातियों की क्षेत्रीय भाषाएं- संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़माली, खोरठा, पचपरगनिया और नागपुरी बोली जाती हैं। इनमें से सिर्फ संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। जबकि आठ अन्य जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है। किन कारणों से इन भाषाओं को छोड़ा गया है? भारतीय भाषा संस्थान द्वारा इन पर क्या शोध हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इन भाषाओं को कैसे बढ़ावा देने की योजना है?

मैं आपके माध्यम से, सरकार से यह जानना चाहता हूँ क्योंकि कुड़माली भाषा झारखण्ड, बंगाल, असम और ओडिशा राज्यों में लगभग 3 करोड़ कुड़मी और अन्य समुदायों द्वारा बोली जाती है। आगामी जनगणना भाषा कॉलम में कुड़माली भाषा के स्थान पर कुड़माली थार को रखा गया जबकि कुड़माली भाषा को अन्य रूप में रखा गया है। कुड़माली भाषा झारखण्ड राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में भी दर्ज है। कुड़माली भाषा का पठन-पाठन झारखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्यों के दो विश्वविद्यालयों द्वारा भी करायी जाती है।

श्री सतपाल ब्रह्मचारी (सोनीपत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय परिवहन मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जींद-पानीपत रोड का निर्माण कार्य लगभग 15 वर्षों से लंबित है। वहाँ डबल इंजन की सरकार है। मैंने पहले भी इसके लिए रिक्वेस्ट किया था, जिसका जवाब मिला था। माननीय गडकरी जी की नज़रों से वह रोड कैसे बच गया, क्योंकि वह रोड भी एन.एच. है। उसका कारण यह बताया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा रोड के किनारे के पेड़ों की कटाई नहीं करायी गयी है।

आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से मेरा पुनः आग्रह है कि जींद-पानीपत रोड, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है, यह हरियाणा के मध्य भाग को जोड़ने वाला रोड है, इसके बारे में आप सब जानते हैं, इसलिए उस रोड के निर्माण कार्य को पूरा कराया जाए।

महोदय, आपके माध्यम से मेरी एक और अपील है।... (व्यवधान)

(1215/PC/AK)

माननीय अध्यक्ष : श्री राम प्रसाद चौधरी जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सतपाल जी, ऐसे नहीं होता है, आप सिर्फ अपना विषय रखा कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राम प्रसाद चौधरी जी – आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री राम प्रसाद चौधरी (बस्ती) : मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों के हित के लिए वर्ष 1978 में दो जिलों के लिए सरयू परियोजना शुरू की गई थी। वर्ष 1982 में इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के दस जिलों में लागू करने का काम किया गया था और 'राष्ट्रीय सरयू परियोजना' के नाम से शुरू किया गया था।

मान्यवर, लगभग दस हजार करोड़ रूपए की लागत से यह सात हजार किलोमीटर की यह नहर बनी हुई है। 11 दिसंबर, 2021 को इस देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने बलरामपुर में पहुंचकर इस नहर को राष्ट्र को समर्पित किया था।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, जैसे बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, ऐसी जगहों पर जब पानी जाता है, तो नहर की कटान होती है। किसानों की हजारों एकड़ जमीन में जलभराव हो जाता है। चाहे रबी की फसल हो, चाहे धान की रोपाई का समय हो, किसान अपनी फसल कर नहीं पाता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से भारत की सरकार के जल शक्ति मंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ कि वे पुनः इसका सर्वे कराकर जो मेन नहर है, उसको पक्का करने का काम करने का कष्ट करें। बहुत से किसानों का अभी मुआवजा बाकी है, उसे देने का काम भी सरकार करे।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
धन्यवाद।

1218 बजे

(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया (साबरकांठा) : आदरणीय सभापति महोदया, धन्यवाद कि आपने मुझे शून्य काल में अपना विषय रखने का मौका दिया।

महोदया, मैं आपके माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारे साबरकांठा और अरवल्ली जिलों से गुजरने वाले शामलाजी-चिरोडा नेशनल हाईवे के कार्य को पूर्ण करने के लिए 454 करोड़ रूपए जैसी भारी धनराशि आवंटित की है।

मैं इसके लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि वर्तमान में यह कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन मुझे जनता और हिम्मत नगर की नगर पालिका की जनता से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि हाईवे नंबर – 48, जो हिम्मत नगर की नगर पालिका से गुजरता है, उसके कारण पीने के पानी की पाइप लाइन, गटर लाइन और गैस लाइन को बार-बार तोड़ना पड़ता है, जिससे सरकार के पैसों का अपव्यय होता है।

अतः वर्तमान में जारी इस कार्य के दौरान इन सभी भूमिगत पाइपलाइनों की उचित व्यवस्था की जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इसके अतिरिक्त जिले से गुजरने वाले हाईवे पर प्रांतिज तालुका के रसूलपुर गांव का अंडरपास स्वीकृत नहीं हुआ है। इसके कारण आसपास के चार-पांच

हजार लोगों एवं किसानों को आवागमन में असुविधा होती है। इसके अलावा हिम्मत नगर तालुका के पिपलोदी और भिलोड़ा तालुका के गडादर कंपा के पास अंडरपास नहीं होने के कारण आम जनता को कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, इन तीनों स्थानों पर अंडरपासेज स्वीकृत किए जाएं।

इसके अलावा हाईवे पर स्थित सभी पुलों के आसपास सर्विस-रोड्स बारिश के कारण बारंबर टूट जाती हैं। इसलिए, इसे आरसीसी तकनीक से बनाया जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है।
धन्यवाद।

(1220/IND/UB)

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : महोदया, आज हमारे लिए बहुत गर्व का दिवस है। आज ही के दिन 16 दिसम्बर, 1971 में हमने पाकिस्तान पर जीत पाई थी और बांग्लादेश का निर्माण किया था। पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यह संभव कर दिखाया था। आज दुर्भाग्य देखिए कि हालात बदल गए हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं। बांग्लादेशी सनातनी समुदाय को डर है कि वहां की कट्टरपंथी सरकार किसी भी स्तर तक गिर सकती है। मंदिरों में मूर्तियां जलाई जा रही हैं। हिंदू परिवारों की सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। यह न केवल मानवाधिकार का उल्लंघन है बल्कि हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर प्रश्न भी उठाता है। भारत सरकार की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की है कि बांग्लादेश हो या विश्व का कोई भी देश हो, वहां हिंदू सुरक्षित रहें और सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकें।

महोदया, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण यादव का मामला हर भारतीय के लिए चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बावजूद पाकिस्तान ने उनके प्रति न्याय का उपहास किया है। यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध भी है। मेरा सवाल है कि क्या सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश सरकार से विशेष वार्ता करने की योजना बना रही है? पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण यादव की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाया है? मैं दो वाक्य बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

“चुप रहो तो पत्थर, बोलो तो बगावत, यह कैसा समय है।

यह कैसी बांग्लादेश और पाकिस्तान की सियासत है

मोदी जी इस चक्रव्यूह को कब तोड़ेंगे।”

*SHRI GURMEET SINGH MEET HAYER (SANGRUR): I thank you, Ma'am Chairperson that you have given me the opportunity to speak on an important matter of Urgent Public Importance. Sports have played a vital role and have a glorious history in Punjab. Many players from Punjab have set records that have not yet been broken.

Ma'am, Balbir Singh Sr. had scored 5 goals in hockey in Olympic games final. Udham Singh ji won 3 gold medals and one silver medal in Olympics. The first individual Olympic Gold medal was won by Abhinav Bindra ji from Punjab.

Ma'am Chairperson, there is a scheme of 'Khelo India' of Central Government. But Punjab is granted a paltry sum under this Scheme. We have given wonderful players to the country in Olympic games and Asian games. Out of over 650 players in Indian contingent, over 50 players belonged to Punjab and over 20 players had won medals for the country. It is 20% of total medals won by the country. In Olympics too, our hockey team won a medal. However, adequate funds have not been granted to Punjab.

We in Punjab have only 2% population of the total population of India. However, we bring 20% medals for the country. More money is allocated to other States. These States do not provide any medal to the country. Gujarat was given over Rs.400 crore. UP was provided over Rs.400 crore.

So, I urge upon the Government that funds should be allocated to States for sports on the basis of their performance so that such States can perform much better in future.

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Madam, I would like to bring to your attention several railway developmental issues in my Parliamentary constituency.

Firstly, establishing a third railway line between Renigunta and Gudur is essential to ease the current congestion in the railway traffic. There is a dire need for early completion of the Pudi-Yerpedu railway line. I would also like to request the hon. Minister to restore the train stoppages at Vendodu, Naidupeta, and Sullurupeta, which were suspended after COVID-19 came.

* Original in Punjabi

(1225/RCP/RV)

Additionally, the widening of the underpass near Ambedkar Nagar in Gudur is very essential to decrease the traffic bottlenecks in Gudur town.

Thirdly, introduction of a Vande Bharat sleeper train between Tirupati and Visakhapatnam is very much needed for pilgrim traffic. Moreover, the new train services connecting Tirupati with Varanasi and Ayodhya will meet the rising demand of pilgrims.

Lastly, regular MEMU services connecting Tirupati, Nellore and Kadapa are much needed. This is because there are seven industrial SEZs. So, it will be very helpful for my Parliamentary constituency.

Thank you, Madam.

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : जय श्री राम!

माननीय सभापति महोदया, जहां मैंने अपने जीवन के 50 साल गुजारे हैं, उसके बारे में, यानी फिल्म एण्ड टीवी इंडस्ट्री के बारे में सदन के सामने कुछ हार्ड फैक्ट्स रखना चाहता हूं।

इस इंडस्ट्री में जो नींव के पत्थर होते हैं, वे छोटे और मंझोले कर्मचारी होते हैं, टेक्नशियन्स और छोटे कलाकार होते हैं। इन कलाकारों और श्रमिकों का बहुत शोषण होता है। वहां जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वे अधिकतर फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के पक्ष में होते हैं। इन पर भारत सरकार और राज्य सरकार के श्रम कानून लागू होने चाहिए। इन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे काम के निर्धारित घंटे, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल मिसहैप से बचने की सुविधा होनी चाहिए। निर्धारित समय के पश्चात् इनके लिए ओवरटाइम की व्यवस्था होना चाहिए। श्रम कानून के अनुसार इनके लिए अवकाश, महिला कामगारों को प्रसूति अवकाश, चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। अपने जीवन के संध्या काल में जब इन कर्मियों की आय का कोई साधन नहीं रहता, उस समय सभी सरकारी कानूनों के अन्तर्गत इन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, श्रमिक अस्पताल की सुविधा इत्यादि। इन लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट तैयार होना चाहिए और निर्माताओं के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना आवश्यक बना दिया जाए।

महोदया, छोटे कलाकार फिल्म निर्माण के बहुत अनिवार्य अंग होते हैं। मेरा माननीय आई. एण्ड बी. मिनिस्टर और श्रम मंत्री जी से आग्रह है कि दोनों मंत्रालयों को मिलकर उनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाए, जो इन वर्कर्स को वे सभी सुविधाएं दिला सके, जो किसी भी दूसरी इंडस्ट्री के वर्कर्स को मिलती हैं।

जय श्री राम!

श्री प्रदीप पुरोहित (बारगढ़) : सभापति महोदया, मैं जिस लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लोगों का यहां प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, वह देश का और ओडिशा का एक सबसे पिछड़ा क्षेत्र बारगढ़, पदमपुर लोक सभा क्षेत्र है।

महोदया, मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को और देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कई सालों से वहां कई सरकारें आईं और कई सरकारें गयीं,

पर वहां के लोगों की बरगढ़-नुआपाड़ा रेल परियोजना की जो मांग थी, वह पूरी नहीं हो पा रही थी। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी एवं अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र में 2,926 करोड़ रुपये की लागत से 138 किलोमीटर की बरगढ़-नुआपाड़ा रेल लाइन को सैंक्शन किया है।

महोदया, यह परियोजना पश्चिमी ओडिशा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके साथ ही यह परियोजना वहां रोजगार-सृजन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ किया जाए। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण कार्य में कोई भी विलम्ब न हो और इसे समय-सीमा में अच्छे तरीके से पूरा किया जाए, ताकि उस क्षेत्र के लोग शीघ्र ही इस परियोजना का लाभ उठा सकें।

(1230/GG/RCP)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : मैडम चेयरमैन, यह सबजेक्ट सभी से ताल्लुक रखता है, वह है एमपीलैड्स फंडा मैडम, यह वर्ष 1993 में शुरू हुआ और पांच लाख रुपये प्रति एमपी, प्रति वर्ष दिया जाता था। उसका लाभ देख कर पांच सालों में इसको चालीस गुना बढ़ा कर दो करोड़ रुपये सालाना, हर एमपी के लिए हर क्षेत्र में कर दिया गया। मैडम, पिछले 14 सालों से पांच करोड़ रुपये से एक नया पैसा नहीं बढ़ाया गया है। पांच करोड़ रुपया जो वर्ष 2011 में बनता था, मंहगाई बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट की दर बढ़ गयी, मटीरियल की कॉस्ट बढ़ गयी, जीएसटी बढ़ गया। मैं एक जानकारी और शेयर करना चाहता हूँ कि राजस्थान में एक एमएलए को 40 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, बिहार, जो सबसे गरीब प्रदेश है, वहां 24 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं, झारखंड में तीस करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं और दिल्ली में तो 105 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। पंजाब में 70 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। यह एमएलए को दिया जा रहा है, मतलब एक एमपी सेगमेंट में है।

इस सरकार से मेरी गुजारिश होगी कि हर एरिया के डेवलपमेंट के लिए कम से कम 40 गुना नहीं तो 10-12 गुना बढ़ा कर 50-60 करोड़ रुपये प्रति एमपी, प्रति वर्ष बढ़ाया जाए और जीएसटी कंपोनेंट को यहीं पर काट कर भेजा जाए, ताकि पूरी रकम से वहां पर काम हो सके। यह मेरी प्रार्थना है। ... (व्यवधान)

एडवोकेट प्रिया सरोज (मछलीशहर) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान नॉर्डन रेलवे के जलालगंज रेलवे स्टेशन, जनपद जौनपुर, उत्तर प्रदेश की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। यह रेलवे स्टेशन अपनी श्रेणी के अन्य रेलवे स्टेशनों की तुलना में रेवन्यू के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस रेलवे स्टेशन से केराकत तहसील, मणियाऊं तहसील, पिंडरा तहसील तथा सिरकोनी जैसी अन्य जगहों से लोग आ कर ट्रेन पकड़ते हैं। पूर्व में इस स्टेशन पर वरुणा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव था, जो कि कोरोना काल में बंद कर दिया गया। वरुणा एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव के समय पर ही शटल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20401 और 20402 का संचालन वाराणसी से लखनऊ तथा लखनऊ से वाराणसी के बीच में किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि दोनों शटल एक्सप्रेस ट्रेनों का जलालगंज रेलवे स्टेशन पर ठहराव न होने से

यहां की आम जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा रेलवे को रेवन्यू का भारी नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि शटल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20401 और 20402 के ठहराव की स्वीकृति जलालगंज रेलवे स्टेशन पर प्रदान की जाए। इससे न केवल क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी, बल्कि रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा और क्षेत्र का समग्र विकास होगा।

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र बिहार के सुपौल जिले के अंतर्गत राघोपुर प्रखंड के सिमराही बाजार के मध्य होते हुए उत्तर से दक्षिण एनएच 106 - बीरपुर से बीहपुर तथा पूरब से पश्चिम 4 लेन एनएच 57 (वर्तमान में एन. एच 27) जाती है। उक्त सड़क के सिमराही चौराहे पर बराबर दुर्घटनाएँ होती रहती हैं एवं आवागमन भी बाधित रहता है तथा जान-माल की भी काफी क्षति होती है।

अतः जनहित में सदन के माध्यम से भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ कि उक्त चौराहे पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाय।

SHRI ARUN NEHRU (PERAMBALUR): Madam Chairperson, thank you for giving me the opportunity to speak.

Madam, I want to draw the attention of the House to an important point, which is the requirement of a railway line through my constituency Perambalur in Tamil Nadu. The advantages have been explained time and again on the need for the railway line which is the only non-railway region in Tamil Nadu. All the other sectors have a railway line within a 40-kilometre radius. But this railway line of approximately 160 kilometres can help the nation to grow in two ways.

(1235/SMN/MY)

It has the largest non-leather footwear factory in the county. 50000 people are going to be employed in that factory.

Second, the largest amount of maize production in the country happens in Perambalur, Madam, which is about five lakh metric tons. Now, a connecting railwayline will help people to go to the factory and also improve agricultural productivity thereby increasing the contribution to the national growth.

I urge, through you Madam, the Railway Minister to please expedite this project for the growth of the nation.

Thank you, Madam.

*SUSHRI PRANITI SUSHILKUMAR SHINDE (SOLAPUR): Hon'ble Madam Chairperson, thank you, I want to raise an important issue related to my city Solapur. A parallel water pipeline work has been pending for the last many years in Solapur. So, the water supply is irregular and only a few days a week, it is being supplied. Hon'ble Nitin Gadkariji and Chief Minister of Maharashtra both are very good friends and they should sit together to resolve this problem. This work has been still pending just because of the issues of compensation for land acquisition. The authority had approved it few years back, but it is still incomplete as the appropriate compensation must be given to the farmers for their lands. Today, Ujani Dam is full, but the people of Solapur are deprived of drinking water. Potable water is being supplied only once or twice a week. So, the NHAI and State Government should sit together and solve this issue with mutual co-operation. They keep-on making tall promises during election campaign but it is still unfulfilled. Water in the adjoining villages like Vibidar, Kolekati, Savaleshwar, Karamba is highly polluted because the adulterated chemical water is being discharged by MIDC, Chincholi. The ground water is highly polluted in this area and people cannot do farming. So, the Central Government should find a solution to this problem immediately. We have demanded for textile park in Solapur city many times. But Hon'ble Prime Minister has not fulfilled his promise. Hence, the Central Government should develop a textile park in Solapur as early as possible. Thank you.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you, Madam.

The Places of Worship Act, 1991 imposes a non-derogable obligation towards enforcing a commitment to secularism under the Constitution. The law is hence a legislative instrument designed to protect the secular feature of the Indian Constitution which is one of the basic features of the Constitution. Non-retrogration is the foundational feature of the fundamental constitutional principles of which secularism is the core component. The Places of Worship Act is thus, a legislative intervention which preserves non-retrogration as an essential feature of our secular values. Historical wrongs cannot be remedied by people taking the law in their own hands. In preserving the character of the Places of Worship Act, Parliament has mandated in certain terms that history in its wrongs shall not be used as an instrument to oppress the present and future.

Madam, this was said in the seven-judge constitutional bench in the Judgement of Babri Masjid Vs. Ram Mandir. I demand the Government to execute the laws made by the Parliament; its non-enforcement is a violation of Parliament's sovereignty.

* Original in Marathi

Madam, 12 egregious cases have been filed against masjids and dargahs to convert or change their character which includes Baba Budangiri dargah in Karnataka; Bija Mandal masjid, Vidhisha, Madhya Pradesh; and Badruddin Shah dargah in Bhagpat. The Modi Government must give a clear answer as to his commitment to implement the defending laws in Parliament. The Modi Government must file a reply in the Supreme Court defending the law in the interest of the country and to uphold Parliament's sovereignty.

Madam, I demand that this Government does not take this country back to the era of 1800 and 1900s which was a very dark period in the history of our country.

मैडम, कहीं ऐसा न हो कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सज़ा पाई। मैं हुकूमत से इस बात की मुतालबा करता हूँ कि ऐसी तंज़ीमों की हरगिज़ सियासी तौर पर सरपरस्ती न करें, जो इस मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री धर्मेन्द्र यादव (आजमगढ़) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंडल आयोग की सिफारिश के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। मंडल आयोग की सिफारिश जिस समय लागू हुई थी, वह सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार बना कर लागू हुई थी। उस समय न केवल मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई, बल्कि उन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत सारी संस्तुतियाँ दीं।

सभापति जी, मंडल आयोग की सिफारिश, इसी सदन के पारित किए हुए कानून और तमाम चीजों की धज्जियाँ उड़ाते हुए, वर्ष 2014 से लेकर अब तक देश के तकरीबन 150 आईएएस अधिकारी जो अपनी मेधा, प्रतिभा और मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा में सफल हुए थे, उस परीक्षा की सफलता के बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है।

सभापति जी, मंडल आयोग की सिफारिश के बाद वर्ष 1993 में डीओपीटी ने कार्यालय ज्ञापन जारी किया। जिस कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि अगर कोई अभ्यर्थी चयनित हो रहा है तो उसके माता-पिता की जो वेतन की आय है, जो कृषि की आय है, वह क्रीमी लेयर की कैटेगरी में काउंट नहीं होगी।

(1240/CP/RP)

वर्ष 1914 से लेकर आज तक शैक्षणिक आय, वेतन की आय, कृषि की आय को जोड़कर डेढ़ सौ से ज्यादा चयनित अभ्यर्थी सड़कों पर घूम रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट के तमाम फैसलों के बाद भी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, कानून मंत्री मेघवाल साहब यहां उपस्थित हैं, आपके मंत्रालय ने भी सिफारिश की है, लेकिन डीओपीटी मंत्रालय उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, स्वीकार न करते हुए ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) तरीके से, सदन के पारित किए कानूनों पर भी ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) कर रहा है।

सभापति जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बसंत कुमार नाम का अभ्यर्थी, जो रक्षा मंत्रालय की ऑडिट सर्विस में सेलेक्ट हुआ, उसी आय प्रमाण पत्र के आधार पर वर्ष 2023 की परीक्षा में 47वीं रैंक पाकर आईएएस की परीक्षा टॉप कर रहा था, ऐसे भी परीक्षार्थी आज सड़कों पर घूम रहे हैं। देश की संसद की सर्वोच्चता है। देश के संविधान पर दो दिन तक लंबे-लंबे बखान भाजपा की ओर से किए गए। उन तमाम चीजों को नजरंदाज करके नौजवानों के साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, कमलजीत सहरावत जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्रीमती कमलजीत सहरावत (पश्चिम दिल्ली) : महोदया, मैं आपका ध्यान दिल्ली की एक गम्भीर समस्या की तरफ दिलाना चाहती हूँ। दिल्ली का वायु प्रदूषण विशेषकर सर्दियों के दौरान एक सतत मुद्दा रहा है। कारकों के संयोजन के कारण दिल्ली का एक्यूआई अक्सर गम्भीर स्तर तक बिगड़ जाता है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में जीवन की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। दिल्ली की वर्तमान सरकार बढ़ते हुए वायु और जल प्रदूषण के स्तर के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और हर साल इस सार्वजनिक चिंता को रोकने में विफल रही है। दिल्ली में बहुत चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के सभी लोग जहरीली हवा के संपर्क में हैं, जिससे सभी को गम्भीर स्वास्थ्य खतरे हो रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन की गुणवत्ता का अधिकार अर्थात् प्रदूषणमुक्त जल और वायु का अधिकार भी सुनिश्चित करता है। इसलिए अपने नागरिकों को यह अधिकार सुनिश्चित करना हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। दिल्ली की वर्तमान सरकार से दिल्ली की इस खतरनाक स्थिति पर काबू पाने की कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली का वायु प्रदूषण एक जटिल मुद्दा है, जिससे विभिन्न स्रोतों जैसे वाहनों के उत्सर्जन को कम करना, औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करना, निर्माण धूल का प्रबंधन, आसपास के राज्यों में पराली जलाने से रोकना, अपशिष्ट प्रबंधन आदि को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

आदरणीय महोदया, दिल्ली की सरकार हर समस्या का समाधान सिर्फ मार्केटिंग करके करना चाहती है। इसकी वजह से आज दिल्ली में स्थिति गम्भीर है। मैं कहना चाहती हूँ कि दिल्ली की हालत यह है:

‘दीवारों पर लगे हैं इतने इश्तेहार
कि नजर ही नहीं आती कोई भी दरार,
झूठे वादों को सुन-सुनकर सोचते हैं हम,
काश सच में आती दिल्ली में यह बहारा’

आज दिल्ली जिस स्थिति में पहुंच गई है, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वह इस चिंताजनक स्थिति का संज्ञान ले और इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकाले, क्योंकि दिल्ली सरकार इसको करने में पूर्णतया विफल है।

माननीय सभापति : मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि केवल एक मिनट में अपने विषय पर चर्चा करें, जिससे अधिक से अधिक सदस्य यहां अपनी बात रख सकें।

श्री के. सी. वेणुगोपाल जी।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, most of the people of Kerala are working in all parts of India, and around the world. They belong to the low-income group. During the festival season only, they are going back to their motherland, Kerala. Now, there are festivals like Christmas, and New Year.

(1245/NKL/NK)

Every Keralite is facing difficulty to travel back to Kerala because of the shortage of trains. Every day, the Media of Kerala is reporting this issue only. Everybody is in a great distress. Earlier, additional special trains used to run during this festival season. But this year, there are no sufficient additional trains also. So, my request to the Government is this. The Government should sanction additional special trains for Kerala for this festival season so that people can travel back to Kerala on the occasion of Christmas and New Year. Otherwise, the passengers who want to travel back to Kerala would be in a great turmoil. I think, the Government should look into it. SHRI RAJABHAU PARAG PRAKASH WAJE (NASHIK): Thank you, hon. Chairperson Madam, for giving me this opportunity.

I rise to draw the attention of this House to an urgent matter concerning the upcoming Kumbh Mela in Nashik. To accommodate millions of pilgrims and tourists, the following priorities must be addressed.

First is comprehensive infrastructure development. It includes construction and upgradation of roads, bridges, and transportation networks, including the Dwarka-Nashik Road Bridge and the Outer Ring Road. It also includes renovation of Nashik Road Railway Station and bus stands, with special trains and buses for visitors.

Secondly, as far as basic amenities for pilgrims are concerned, there should be adequate sanitation facilities, drinking water, and waste management systems. Moreover, there should be focus on establishment of healthcare centres and development of affordable accommodation facilities, including tent cities.

Third is environmental sustainability. It includes protection of the Godavari River and natural resources through eco-friendly practices.

Fourth is security and crowd management. It includes deployment of advanced crowd management systems, CCTV cameras, and sufficient security personnel.

The Kumbh Mela is a platform to position Nashik as a hub of sustainable development and cultural tourism. Immediate allocation of funds and resources is essential to ensure its smooth execution and long-term benefits for the region. Thank you.

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity.

I rise to bring to your kind attention to a significant issue faced by the people of Chalakudy Parliamentary Constituency in Kerala. It is the only parliamentary constituency in the State that does not have a Kendriya Vidyalaya. This constituency holds strategic importance due to the presence of Cochin International Airport, which serves as a hub for numerous Central Government offices, including CISF, Coast

Guard, Immigration, Customs, etc. Despite this, the region has been overlooked in terms of educational infrastructure provided by the Central Government. Furthermore, there is adequate land available in the vicinity to establish a Kendriya Vidyalaya, which would cater to the educational needs of the children of Central Government employees as well as the general public.

I urge the government to consider this genuine request and take immediate steps to allocate a Kendriya Vidyalaya for Chalakudy constituency.

Thank you.

श्री नारायणदास अहिरवार (जालौन) : सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र जालौन, गरौठा, भोगनीपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। यहां बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा न होने के कारण स्थानीय निवासियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनपद जालौन का जिला मुख्यालय उरई है और जनपद कानपुर देहात एवं हमीरपुर के निवासियों के लिए भी दिल्ली तक सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। दिल्ली जाने के लिए लोगों को अधिक समय और धन व्यय करना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के लिए सीधी रेल सेवा और कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव अनिवार्य है जिससे यहां के लोग अपने दैनिक कार्य एवं रोजगार के लिए सीधे दिल्ली जा सकें। सीधी ट्रेन के अभाव में इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी आने-जाने में परेशानी होती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि श्रम शक्ति एक्सप्रेस 12451/12452 जो नई दिल्ली से रात्रि 11.55 पर चलकर सुबह 6.15 पर कानपुर पहुंचती है और रात्रि 11.55 पर पुनः रवाना होती है। लगभग 18 घंटे तक कानपुर में खड़ी रहती है, इस ट्रेन को जिला मुख्यालय उरई तक बढ़ा दिया जाए जिससे जालौन क्षेत्र के निवासियों को दिल्ली तक सीधी रेल सेवा का लाभ मिल सके।

छपरा एक्सप्रेस 11123/11124 वर्तमान में यह गाड़ी ग्वालियर से बरौनी तक चलती है। इस ट्रेन को ग्वालियर से बढ़ाकर नई दिल्ली तक किया जाए। जिससे क्षेत्र के निवासियों को नई दिल्ली तक सीधी ट्रेन की सुविधा मिल सके।

(1250/SK/VR)

डॉ. लता वानखेड़े (सागर) : माननीय सभापति जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र सागर और इससे सटे अन्य संसदीय क्षेत्र के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण विषय पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ।

मध्य प्रदेश हमारे देश के मध्य में स्थित एक ऐसा राज्य है जिसकी भौगोलिक स्थिति न केवल इसे अद्वितीय बनाती है, बल्कि इसे पूरे भारत के लिए एक रणनीति के केंद्र के रूप में स्थापित भी करती है। देश के हर कोने से मध्य प्रदेश तक पहुंच आसान है और यही कारण है कि इसे देश का हृदय स्थल कहा जाता है। अगर हम मध्य प्रदेश में विशेषकर संसदीय क्षेत्र सागर और इसके आसपास अधिक भारी उद्योग जैसे कार निर्माण, इस्पात निर्माण और अन्य निर्माण इकाइयों की स्थापना करेंगे तो यह न केवल इस क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा वरन रोजगार के अवसर सृजित कर प्रतिभा पलायन को रोकने में भी कारगर सिद्ध होगा।

*SHRIMATI BAG MITALI (ARAMBAG): Thank you for providing me the opportunity to speak. I pay my respects to Shri Shri Ramkrishna Thakur & Maa Sarada. Meghnad Saha also suggested the construction of seven barrages. But the central government failed to execute that. Hwang-Ho is known as the sorrow of China. Similarly, DVC is the sorrow of Arambag Constituency. That's why when we explain the abbreviation of DVC- we term it synonymous with drowning, floating and rinsing in water. The floodgates were opened to release lacs of Cusec water overnight, resulting in turmoil for lacs of people from the Arambag Constituency due to the sudden floods. Even their last straw was swept away in front of their eyes. They lost everything- from their agricultural land to their cattle. Why DVC didn't dredge the rivers before releasing water? Why they didn't renovate the river dams before releasing water? Immediately, they should take steps to complete the dredging and embankment process of all the rivers. How long will the people from Khanakul, Purshurah, Harinkhola, Arandi, Salehpur, Arambag, Chandrakona, Goghat remain frightened by the floods? When they need water, there is a scarcity of it. This is the season to cultivate Boro paddy, but DVC isn't releasing the water at this hour. All these Boro Paddy lands have dried up and cracked. Their untimely release of water is flooding the land. How long will their turmoil go on? Please grant me a minute to finish my subject. I am a ICDS worker. Integrated Child Development Services was launched on 2nd October, 1975. The objective was to provide nutritional care, health improvement and education development to the children. It intended to create a strong foundational base for a child's mental, physical and social development. But there is still work to be done to improve the nutrition of the mother and child. The funds for nutrition is also decreasing. The Children of today are the future of tomorrow. This needs immediate consideration and increased allocation for nutrition funds. If this is not done, in future the country will be plagued by malnutrition. I would also request to increase the wages of the workers and helpers so that they can sufficiently provide for their families. No more indifference, no more duplicity, no more deprivation. Thanks again for letting me speak. Joy Bangla!

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : माननीय सभापति जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इतने लंबे समय से बहुत महत्वपूर्ण मांग, जो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की है, को उठाने का मौका दिया।

समस्तीपुर लोकसभा में दो आरओबी मुक्तापुर और भोला टॉकीज़ हैं, जो कई वर्षों से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है और अब इसका काम बहुत तेजी से करने की आवश्यकता है। समस्तीपुर में बहुत व्यापार के कारण जाम की समस्या रहती है। मुक्तापुर आरओबी समस्तीपुर को

दरभंगा मेडिकल कॉलेज से जोड़ता है। जब यहां जाम लगता है तो मेडिकल समस्या वाले लोगों को काफी तकलीफ झेलनी पड़ती है।

मेरी मांग है कि मुक्तापुर और भोला टॉकीज़ आरओबी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यहां के लोगों की वर्षों से मांग ही नहीं, सपना भी है, इसलिए इसे पूरा किया जाए।

(1255/KDS/SAN)

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : महोदया, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान देश के आकांक्षी जिलों में कटिहार को शामिल किया गया है, उस ओर दिलाना चाहता हूँ। भारत सरकार ने वर्ष 2018 में जिन 112 जिलों को आकांक्षी जिलों में शामिल किया था, उनमें हमारा संसदीय क्षेत्र कटिहार भी था। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचों में सुधार करके वर्ष 2022 तक नया भारत बनाने का संकल्प था। इसके तहत आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया था।

महोदय, मुझे यह कहते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि जुलाई, 2023 में कटिहार जिला आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में अंतिम पायदान पर पहुंच गया है और यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि डबल इंजन की सरकार बिहार में है, उसके बावजूद जिले को वह प्राथमिकता नहीं दी गई, जिसकी उसे आवश्यकता थी। ... (व्यवधान) महोदया, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : आकांक्षी जिले वाला विषय था। माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए। मल्लेश बाबू जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं आग्रह कर रही हूँ कि अपनी बात को एक मिनट में कम्प्लीट करें।

SHRI M. MALLESH BABU (KOLAR): Madam, I represent Kolar constituency of Karnataka. The Bengaluru-Chennai Expressway, also known as National Expressway-7, is an ambitious infrastructure project aimed at enhancing connectivity between the two key urban centres in India. As part of the Bharatmala Pariyojana initiated by the NDA Government, this four-lane expressway promises to facilitate smoother transportation and economic growth in the region. However, the project's execution has raised significant concerns among the local communities, particularly related to the adverse effects of heavy truck movements on the surrounding village and district roads.

During the construction phase of this expressway, substantial quantities of mud are being excavated from the nearby tanks and transported to the worksite through trucks. Unfortunately, the roads designated for this purpose -inter-link village roads and major district roads - were not designed to withstand the weight of such heavily laden vehicles. As a result, these roads have suffered considerable damage, severely impacting the daily commutes of villagers and school students who rely on them for their livelihood and education.

Hence, I would request the hon. Minister of Road Transport and Highways to take prompt action to address this pressing issue and ensure the restoration of the disrupted village connectivity roads.

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : धन्यवाद सभापति जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मुझे अवसर दिया गया। आज देश में ग्राम सभा स्तर पर, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, रोजगार सेवक की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जिनको मैं निम्न प्रकार से व्यक्त करता हूँ- आज ग्राम प्रधान, जो मनरेगा के द्वारा जिला स्तर पर कार्य कराता है, धन न होने के कारण ग्राम प्रधान पूर्ण से अपना काम नहीं करा पा रहा है।

महोदया, ग्राम सभा में हर घर जल, हर घर नल योजना, जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसके तहत ग्राम सभा में तमाम गलियां, सड़कें खोदकर तमाम सड़कों को तोड़ दिया गया है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि उन सड़कों की मरम्मत करने का भी काम उन संस्थाओं द्वारा कराया जाए। साथ ही साथ रोजगार सेवक और ग्राम प्रधान मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को भी बढ़ाकर ग्राम प्रधान का कम से कम वेतन 5 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया जाए। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर 237 रुपये से 500 रुपये की जाए और रोजगार सेवक, जिनका वेतन 7788 रुपये है, उसको बढ़ाकर कम से कम 10 हजार रुपये किया जाए। धन्यवाद।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : धन्यवाद सभापति महोदया, आज 16 दिसम्बर है और 16 दिसम्बर को आज के ही दिन बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। भारतीय सेना में भारतीय सेना के नायकों ने और उस वक्त की लीडरशिप ने एक बहुत बड़ा काम किया था। 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने बंदी बनाकर छोड़ा था और पाकिस्तान ने प्रजातंत्र की जो हत्या की थी, लोकतंत्र की हत्या की थी, हमने वहां लोकतंत्र स्थापित किया था। मैं आपके माध्यम से देश को यह बताना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में नजरूल इस्लाम, त्रिपुरा के राजा बर्मन फैमिली, कांग्रेस के पूर्व मुख्य मंत्री मुकुल संगमा, जो टीएमसी में हैं, उनके पिता जी और सबसे बड़ा योगदान बाबू जगजीवन राम जी का था, जो उस वक्त के रक्षा मंत्री थे। जय जवान, जय किसान का नारा वहीं सफल हुआ था।

(1300/MK/SNT)

दलित, वंचित, शोषित समाज से आने वाले बाबू जगजीवन राम जी ने यह भूमिका निभाई थी। उनको इतिहास ने भुला दिया। ... (व्यवधान) इंदिरा जी के योगदान को कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन बाबू जगजीवन राम जी के योगदान को जो आज तक समाज ने नकारा है, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उनके योगदान को भी समाज को बताया जाए... (व्यवधान)

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा (वायनाड) : सभापति महोदया, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया। आज विजय दिवस है। वर्ष 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जांबाजों ने यह लड़ाई लड़ी, सैन्य अधिकारियों को, सैनिकों को और सब शहीदों को मैं सबसे पहले नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई थी, वह उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था। पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई-बहनों की आवाज को कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई और अपने उसूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थीं। मैं उनको भी नमन करना चाहती हूँ। वे इस देश की महान शहीद हैं, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया, जिससे यह देश विजयी हुआ। आज इस संदर्भ में दो मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वह जो लड़ाई थी, वह उसूलों की लड़ाई थी। लोकतंत्र का वसूल ... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप कंप्लीट कीजिए।

... (व्यवधान)

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा (वायनाड) : सभापति महोदया, मैं संक्षेप में बोल देती हूँ। मेरे दो मुद्दे हैं, मैं संक्षेप में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा यह है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, हिन्दू और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए, बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनको पूरा समर्थन देना चाहिए, जिनको पीड़ा हो रही है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप एसोसिएट करेंगे?

... (व्यवधान)

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा (वायनाड) : सभापति महोदया, आज सेना के हेडक्वार्टर से वह तस्वीर उतारी गई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। ... (व्यवधान)

1304 hours

(At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shri A. Raja and some other hon. Members left the House.)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, under the Ministry of Home Affairs, there is an organisation which is called BPR&D. The BPR&D has appointed two private organisations, namely, NACER and SARD. They are

doing survey in West Bengal regarding law and order, perception of public safety, and public opinion ignoring the State of West Bengal. All the time, the Ministry of Home Affairs takes the information from the State Government. But an organisation has been appointed by the MHA. They are appointing and they are engaging private organisations. It really betrays the federal structure of the country.

I will request the Minister of Home Affairs to look into the matter and give us an answer to that.

(1305/SPS/AK)

*SHRI KARTICK CHANDRA PAUL (RAIGANJ): Namaskar Madam. In 2008, when late Cabinet Minister Priya Ranjan Dasmunsi was a member of Parliament from this constituency (Raiganj), an AIIMS hospital was sanctioned in this district. Later the proposal was shifted and the AIIMS hospital was established in Kalyani, Nadia. In 2024, after I was elected as a member of Parliament, I requested the Honourable Health Minister Jagat Prakash Nadda to sanction another AIIMS in Raiganj. In reply, he informed me that there is no such proposal from the side of the West Bengal State government. Later I requested the Honourable Chief Minister of West Bengal to send a proposal to sanction another AIIMS hospital in Raiganj. Through you Madam, I am requesting the concerned authorities. If an AIIMS hospital is established in Raiganj, along with the people of West Bengal, the people from neighbouring states like Bihar, Jharkhand, and Assam will also benefit from better healthcare facilities. These will also create job opportunities and will help in the economic development of the area. Madam, through you, I request the Honourable Prime Minister and the Honourable Health Minister to kindly establish an AIIMS hospital in Raiganj. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Shri Hibi Eden -- not present.

Shri Eatala Rajender.

श्री इटेला राजेंदर (मल्काजगिरि) : महोदय, मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी मल्काजगिरि के अंदर सिकंदराबाद कैंटोनमेंट है। It is under the Defence Ministry. वहां पर कोरोना के समय काम करने वाले बहुत सफाई कर्मचारी मर चुके हैं। उन लोगों ने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए दरखास्त की है तो पांच परसेंट के अंदर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट देने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा। मैं खुद

* Original in Bengali

डिफेंस मिनिस्टर जी से मिला था। वे सफाई कर्मचारी हैं, जो कोरोना के समय मर चुके हैं। वे गंदा काम करने वाले गरीब लोग हैं। मैं आपके माध्यम से मानवता की दृष्टि से उन सौ लोगों को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुंबई उत्तर-पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में एम्स अस्पताल और कैंसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की अत्यावश्यकता पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मुंबई केवल महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी ही नहीं, बल्कि पूरे देश का एक महत्वपूर्ण चिकित्सा केंद्र है, जहां लाखों लोग इलाज के लिए आते हैं। मुंबई के उपनगर भारत के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक हैं। यहां की जनसंख्या में हो रही तेज वृद्धि और चिकित्सा सुविधाओं पर बढ़ते दबाव के कारण, आधुनिक और समर्पित अस्पतालों की स्थापना की अत्यंत आवश्यक हो गई है।

आज, हमारे पास केईएम, जेजे, टाटा मेमोरियल जैसे बेहतरीन अस्पताल हैं, लेकिन वे उपनगरों और महानगर क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। विशेष रूप से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए इलाज की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक है। कैंसर के उपचार के लिए समर्पित अस्पतालों की भारी कमी है। मुंबई और एमएमआर क्षेत्र में कैंसर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इन रोगियों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिसके कारण उन्हें न केवल अपनी बीमारी से जूझना पड़ता है, बल्कि आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। बिहार राज्य में दो एम्स की स्थापना हो चुकी है। महाराष्ट्र में केवल एक एम्स है, जो नागपुर में स्थित है, जबकि मुंबई जैसे महानगर में एम्स अस्पताल का न होना एक गंभीर चिंता का विषय है। एम्स जैसी प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान की स्थापना से यहां लाखों लोगों को उच्च गुणवत्ता वाला, किफायती और सुलभ इलाज मिलेगा।

मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर गम्भीरता से विचार किया जाए और सरकार शीघ्र ही इस दिशा में ठोस निर्णय लेकर उप नगर में एम्स की स्थापना करें।

SHRI AVIMANYU SETHI (BHADRAK): Thank you, Madam Chairperson. मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे से यह जानना चाहता हूँ कि proposed Highway between Dharmapuri and Jamujhadi on NH-16 है, जो माननीय मंत्री जी उस समय प्रॉमिस किया जा, जब वह पुरी में एक सभा में गए थे। What is the status of that Highway? Is it true that the DPR is already completed and it is pending for approval at the Ministry? What are the reasons for the delay? Thank you, Madam Chairperson.

(1310/MM/UB)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ्फरनगर) : धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लाना चाहता हूँ।

मान्यवर, केन्द्रीय गन्ना क्रय अधिनियम के अनुसार गन्ना किसान अपने गन्ने की आपूर्ति चीनी मिलों को करते हैं। गन्ना उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल है और इसके साथ-साथ किसानों की सारी अर्थव्यवस्था- बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्च उस पर टिके हुए हैं। हमारी राज्य सरकार एक सलाह मूल्य घोषित करती है, जिसके आधार पर चीनी मिलें गन्ना किसानों को मूल्य का भुगतान किया करती हैं। दुर्भाग्य यह है कि अक्टूबर में चीनी मिलें चलीं और आज दिसम्बर का अंतिम पड़ाव है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान को यह नहीं पता है कि वह अपना गन्ना किस भाव पर बेच रहा है। अभी राज्य सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया है। आप ही की कैबिनेट के एक साथी ने कहा था कि 400 रुपये के पार गन्ना मूल्य होगा। परंतु उसका भी पता नहीं है कि वह कहां है और कैसे हो रहा है? मेरा सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार से वह अनुरोध करे, आग्रह करे या निर्देशित करे, जैसे भी करे, लेकिन गन्ना मूल्य 400 रुपये के पार घोषित कराने की कृपा करें। इसके अलावा किसानों के साथ जो ज्यादती होती है, जब वह गन्ना मूल्य मांगता है तो उन्हें पकड़कर बंद कर दिया जाता है। ऐसी जेल में डाला जाता है कि मिलाई ही बंद कर देते हैं। इस पर भी अंकुश लगाने का काम करें। धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : महोदया, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ। मैं देश के उन लाखों श्रमिकों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो देश में रेलवे स्टेशंस पर माल गोदाम से गुड्स ट्रेन्स के लिए लोडिंग और अनलोडिंग का काम पीढ़ियों से कर रहे हैं। लेकिन, उनको रेलवे की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ठेकेदार उन मजदूरों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। अपनी पीठ पर पूरे दिन में वे सौ-सौ बोरा लादते हैं, उसके लिए उनको प्रति बोरा दो-तीन रुपये मिलते हैं। जबकि रेलवे का कुली अगर 40 किलो सामान उठाता है तो उसके लिए लिखा रहता है कि उसको 60 रुपये देना है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि कोविड के समय में भी, जब पूरा देश ठहराव की स्थिति में था तो देश के 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाने का काम इन्होंने ही किया था। आज भी देश की सभी गुड्स ट्रेन्स में ये लोग काम कर रहे हैं। उनके लिए प्रति बोरा मानदेय बढ़ाकर पांच रुपये किया जाए ताकि उनको सौ बोरे के लिए कम से कम पांच सौ रुपये मिल सकें। धन्यवाद।

*SHRIMATI PRATIBHA SURESH DHANORKAR (CHANDRAPUR): Hon'ble Chairperson, thank you. The premiums for crop insurance deposited with the insurance companies by the Government are actually paid through the public money.

But, when the farmers file their claims for crop insurance compensation, they are being deprived of the insurance benefits due to various reasons. In my Lok Sabha Constituency, around 87,742 farmers did not get the insurance amount for the last crop cycle. So, a notice is served to the Oriental crop insurance company and the district administration. By misusing the public funds, the Government is helping the insurance companies getting rich and making the farmers poor. These needy and distressed farmers have been waiting for insurance money for the last one year. So, I would like to request the Union Government to look into it urgently so that these farmers would get a relief through the crop insurance benefits.

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Madam, I would like to draw the attention of the House to a matter of great importance. I think the entire House will agree on this issue.

Our young people are the human resource and the greatest asset of our country. In the crisis of corporate life balance, safeguarding the well-being of the young professionals of India, is the need of the hour. The tragic and untimely death of Anna Sebastian Perayil, a 26-year-old chartered accountant, from my constituency in Kerala, has brought to light a critical issue of extreme work pressure and its impact on the health and well-being of the IT professionals. This young girl, who was a bright student, worked in a member firm of Ernst & Young, SRBC, Pune. This is an institutional murder committed by the corporates and the multinationals of this country. This young girl had to work 14 hours and seven days a week and died of a fatal cardiac arrest.

(1315/RCP/YSH)

Mental health is something, which has to be very seriously looked up by this House. No labour laws and direction by courts are being followed by the corporates and multinational companies.

I urge upon the Government of India to take necessary action to inquire into the death of Anna Sebastian and take necessary step to protect the well-being of the young professionals in this country.

Thank you.

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी (नन्दुरबार) : सभापति महोदया, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि केवडिया में, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, उसके बारे में मैं एक गंभीर प्रश्न रखना चाहता हूँ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो चेस्ट लेवल है, जो कि 153 मीटर की हाइट पर है, वहां पर एक छेद किया गया है, ताकि वहां से गैलेरी व्यू मिले। वहां पर एक लेजर शो भी बनाया गया है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि वहां पर एक शौचालय भी बनाया गया है। मैं मानता हूँ कि यह जो शौचालय है, यह अपमान की बात है। क्या देश के पूर्व केन्द्रीय मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता के स्टैच्यू के बीचोंबीच टॉयलेट करना अपमान नहीं है तो क्या है?

मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या यही इनकी देशभक्ति है? मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से विनती करता हूँ कि इस शौचालय को वहां से हटाया जाए।

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे (बीड) : माननीय सभापति महोदया, मैं महाराष्ट्र के बीड जिले से आता हूँ। मेरे जिले में कानून की सुव्यवस्था नहीं रह गई है, जिसकी वजह से वहां पर, जो संतोष देशमुख नाम के सरपंच थे, उनका अपहरण करके मर्डर कर दिया गया। उनके मर्डर के बारे में हमने बहुत बार मांग की है कि उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और जो खूनी है, उसको फांसी की

सजा मिलनी चाहिए। इसलिए मैं सदन से संतोष देशमुख को न्याय दिलाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि लंबे समय से दिल्ली की दो पॉलिसीज़, जो डीडीए को लागू करनी हैं, पहली, लैंड पूलिंग पॉलिसी है और दूसरी जीडीए पॉलिसी है, ये पॉलिसीज़ लंबित पड़ी हुई हैं। इन दोनों पॉलिसीज़ के लागू हो जाने से दिल्ली स्लम बनने से बचेगी। इनसे दिल्ली की आय भी बढ़ेगी और दिल्ली के किसानों की जमीन, जो दिल्ली सरकार के द्वारा कौड़ियों के दाम पर एक्वायर की जाती हैं, उससे दिल्ली के किसानों को अच्छा मुआवजा भी मिलेगा।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि लैंड पूलिंग और जीडीए पॉलिसी को दिल्ली के हित में, दिल्ली के किसानों के हित में तुरंत लागू किया जाए।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, the minorities and Hindus are being tortured in Bangladesh. The Foreign Secretary visited Bangladesh recently. I talked to the External Affairs Minister along with Prof. Sougata Ray in this House, day before yesterday. I am surprised why the Government is keeping mum. The House is running. Let us know what actual development is taking place. A statement from the Government is urgently required. Either the External Affairs Minister or the Prime Minister himself should come before the House to save the Hindus and the minorities facing torture in our neighbouring country, Bangladesh.

Madam, we believe that this matter will be sent to the Government and we will get a reply by tomorrow.

(1320/RAJ/PS)

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) : सभापति महोदया,

क्या वे सब मानव नहीं,
क्या गलती है उनकी सीमा पार रहते हैं?
जिस देश में रहते हैं, वह उसको ही अपना कहते हैं
आज परीक्षा उनकी कि
धर्म बढ़ा हो रहा वहां
हिन्दू, सिख या बौद्ध, जैन होना पाप है वहां।

मैं इस सदन का ध्यान हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह मुद्दा केवल बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि मानवता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

बांग्लादेश में हाल ही में 2,010 घटनाएं दर्ज हो गई हैं, जिनमें हत्या, छेड़छाड़ और अपहरण जैसी अमानवीय घटनाएं शामिल हैं। इन घटनाओं के कारण 1,705 परिवार प्रभावित हुए हैं। विशेष रूप से चिन्मय कृष्ण दास जैसे सम्मानित धार्मिक नेता की गिरफ्तारी ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है।

बांग्लादेश के 64 जिलों में फैले अत्याचारों ने न केवल हिंदू, बल्कि बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यक समुदायों को भी संकट में डाल दिया है। यहां तक कि ढाका,... (व्यवधान)

*SHRI SHREYAS M. PATEL (HASSAN): Hon'ble Chairperson, madam, thank you for permitting me to speak during the zero hour. I wish to present before you and the House a serious problem faced by the people of my Hassan constituency.

Respected Chairperson, Madam, the conflict between the wild elephants and man in Hassan district in Malenadu region of Karnataka, has reached to its peak. In the district, the problem is so severe that during the last one decade more than 80 farmers have lost their lives, more than 55 elephants have been killed, hundreds of people have suffered with physical injuries. In such a situation many farmers of Alur, Belur and Sakaleshpura are finding it difficult to live peacefully. Moreover, there is constant increase in the number of elephants in this region, their number is around 120 now, it will become more complicated issue in future if we don't address the elephant menace now itself.

Respected Chairperson, in these days the wild elephants are entering into plantations of coffee, banana, paddy fields, areca nut gardens in villages like Alur, Belur, Chikkodi, Arehalli and on the roads also they are roaming. In Belur and Chikkodi areas the elephant menace is causing difficulty to school-college going children, who are straggling to commute.

Respected Chairperson, the daily wagers earning Rs 300-400 to meet their both ends, are also badly affected by the elephant menace.

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI SANDHYA RAY): Thank you, hon. Member.

SHRI SHREYAS M. PATEL (HASSAN): Madam, I am concluding. ...
(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, Shri Kodikunnil Suresh ji

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you Madam Chairperson.

Madam Chairperson, I rise to draw the urgent attention of this House to an alarming increase in road accidents and fatalities in Kerala, particularly on the National Highways -- NH-66, NH-966, NH-544, State Highway (SH-8), as well as on other key roads undergoing constructions. This issue demands immediate intervention from the Central Government to ensure safety of the commuters and pedestrians on the roads.

In recent weeks, multiple tragic incidents have occurred. In Alappuzha, Kalarkode (NH 66), six lives of MBBS students were lost due to poorly managed traffic and hazardous road conditions caused by ongoing construction. In Palakkad, Kalladikode (NH-966), a devastating crash claimed the lives of four children, highlighting the lack of safety infrastructure. In Pathanamthitta district (SH-8), four fatalities occurred due to unsafe road conditions and absence of proper traffic management.

HON. CHAIRPERSON: Thank you, hon. Member.

Please conclude.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam, I am concluding.

In Thrissur, Nattika (NH-66), five people lost their lives in a tragic accident, further emphasizing the dire need for immediate corrective measures on this critical highway. In Coimbatore, Madukkarai (NH-544) also, same type of accident happened.

Madam, in the entire State of Kerala, for the last 10-15 days, serious accidents have been happening because of unscientific road constructions by the National Highways Authority of India as well as by the State Governments.

I would like to request the Government, through you, to direct the National Highways Authority of India to take urgent action in this regard.

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन) : सभापति महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

माननीय सभापति जी, पहले पेट्रोलियम मंत्रालय में एससी और एसटी वर्ग के लोगों को जो पेट्रोल पंप्स आवंटित होते थे, कंपनी उसमें जमीन को भी लीज पर देती थी।

(1325/KN/SMN)

उस एससी, एसटी वर्ग के कैंडीडेट को पूरा सेट-अप लगाकर कंपनी देती थी और चालू करके देती थी। लेकिन विगत वर्षों से देखने में आ रहा है कि कंपनी उस वर्ग के व्यक्ति से कहती है कि आप ही जमीन लेकर आयें। आज जमीनों के भाव आसमान छू गए हैं।

माननीय सभापति महोदया, एससी, एसटी वर्ग का जो कैंडीडेट है, वह उसे एफोर्ड नहीं कर सकता है, लीज पर नहीं ले सकता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि पुनः उस व्यवस्था को चालू करें। माननीय प्रधान मंत्री जी का उद्देश्य है कि एससी, एसटी वर्ग के लोगों का उत्थान करना है, इसलिए उनका उत्थान हो सके। धन्यवाद।

*DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB): I thank you, Hon. Chairperson, I hail from Shri Fatehgarh Sahib. This is the place where two younger sons of our Tenth Guru Shri Guru Gobind Singh ji were walled alive by the Mughals. Luckily, Hon. Minister Sir is present here.

I urge upon the Central Government that this place should be included in the international tourist circuit. The Central Government should provide international level facilities here.

Thank you.

#SHRI MALAIYARASAN D. (KALLAKURICHI): Madam Chairperson, Vanakkam. I wish to raise an issue pertaining to the people of Kallakurichi Parliamentary Constituency, particularly of Kallakurichi, Salem, Thiagadurgam and Rishivandhiyam. Kallakurichi district was created as a new district in the year 2019. More than 16 lakh people live in this district. Between Chinnasalem and Kallakurichi, a new rail route was proposed with the help of Union government in the year 2016. But the work relating to this rail project is implemented in a snail pace. I urge that it should be expedited. I also urge that a new railway line should be laid upto Mugaiyur so that the traveling time between Chennai and Salem will be reduced by two hours benefitting the rail passengers. I urge that these railway projects should be implemented keeping in view the interests of the people of our Kallakurichi district. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu has been implementing schemes in the State in a non-partisan manner ensuring everything for all the people. Similarly, I wish that the Union government should also implement all the

* Original in Punjabi

Original in Tamil

schemes in a non-partisan manner benefitting all the States of our country including Tamil Nadu. Thank you.

SHRIMATI ANITA SUBHADARSHINI (ASKA): The healthcare system in my Constituency Aska, Ganjam district of Odisha, is at a devastation stage. We are deprived of the basic healthcare system. We do not have a diagnostic centre for which my people have to go a long way because of the lack of political interest of the previous State Government.

So, Madam, through you, I urge the Central Government for having a diagnostic centre and ultrasound X ray in my local area where we badly need them so that my constituency people will be benefited.

Madam, through you, I would like to request the Central Government to provide for some financial assistance for the ultrasound and x ray machines in my local block level hospitals. Also, we want a big diagnostic centre there so that my people will be benefited.

Thank you so much.

*SHRI BHASKAR MURLIDHAR BHAGARE (DINDORI): In my Lok Sabha Constituency, Dindori, the main and prominent crop is Onion. In the entire Nashik District, the farmers had a bumper production of onions. The States like Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh have a 30-40% more production this year. So, the price of onion is going down day by day. In Dubai and Gulf countries, the onions from Pakistan are available at cheaper rate, so the demand for Indian onion is very less in Gulf market. This is a serious crisis for onion producing farmers.

In my constituency, at Lasalgaon APMC, the average rate for onion on 12/12/2024 was around Rs. 3500 per quintal, but today it is around Rs 1500 per quintal as on 16/12/2024. If the MSP for onion keeps on decreasing day by day, the farmers would not get even the production cost. So, through you madam, I would like to request the Union Government to reduce the Export Duty for onions from 20% to zero. Kindly look into it to do justice to the farmers.

Thank you.

(1330/VB/SMN)

श्री आलोक शर्मा (भोपाल) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की राष्ट्रीय संस्कृति निधि के अंतर्गत भोपाल में राजा भोज के नाम पर शोध संस्थान बनाने का विचार है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो राजा भोज के नाम पर भोपाल में कब तक शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा?

माननीय महोदया, भोपाल का एक हजार साल का गौरवशाली इतिहास है, भोपाल की गौरवशाली संस्कृति है। हमारा भोपाल राजा भोज का भोपाल है, हमारा भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, हमारा भोपाल चन्द्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, हमारा भोपाल प्रतिहार वंशों का भोपाल है, हमारा भोपाल रानी कमलापति गौड़ का भोपाल है। भोपाल की वास्तविक विरासत को विश्व पटल पर लाने हेतु सरकार की क्या कोई कार्य-योजना है? कृपया यह बताने की कृपा करें।

श्री दिनेश चंद्र यादव (मधेपुरा) : माननीय सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सहरसा जिले के सोनवर्षा प्रखण्ड के फतेहपुर-परेरिया गांव के निवासी स्वर्गीय हर्षवर्धन सिंह, आईपीएस अधिकारी की, 3 दिसम्बर, 2024 को कर्नाटक के हासन में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वे वर्ष 2023 के कर्नाटक काडर के आईपीएस ऑफिसर थे। वे अपनी पहली पोस्टिंग के लिए हासन में अपना योगदान करने जा रहे थे। दुर्घटना तब हुई जब पुलिस वाहन का टायर फट गया, चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण वह वाहन एक घर और पेड़ से टकरा गया। गाड़ी के टायर फटने की घटना डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। सरकार ट्रेनिंग पर काफी पैसे खर्च करती है, लेकिन बाद में उसे ऑफिसर की लापरवाही में धकेल दिया जाता है। जूनियर और सीनियर अधिकारियों के बीच उसे राजनीति का शिकार बना दिया जाता है। सरकारी गाड़ी की हालत खराब थी, ऐसी घटना मन को विचलित कर देने वाली है। कर्नाटक सरकार के लापरवाह पदाधिकारी के कारण देश ने एक युवा एवं होनहार अधिकारी को खो दिया।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसकी उच्चस्तरीय जाँच करायी जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, मृत अधिकारी के आश्रितों को न्याय एवं आर्थिक सहायता दी जाए।

***SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BATHINDA):** Hon'ble Ma'am Chairperson, I want to raise the issue of Jagjit Singh Dallewal . He is protesting and fasting at the Shambhu border for the last 21 days so that the genuine demands of farmers should be met. However, the Government does not seem to care about him during the last 21 days. His life is in danger. This is a serious

issue. Only after the Supreme Court order, a junior officer of the Government was sent there.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, आपने जो विषय दिया है, आप उस पर बोलें।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिण्डा) : जी हाँ, मैडम। मैंने यही इश्यू दिया था। यह सबसे जरूरी इश्यू है।

Ma'am, 4 years ago, the Central government had assured the farmers.

माननीय सभापति : आपने जो विषय दिया था, कृपया आप उस पर बोलिए।

*SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BATHINDA): For the last 21 days, the farmer leader is sitting on fast unto death. His health has deteriorated. Over 700 farmers have already attained martyrdom. The Central Government can save the life of one farmer leader. Please accept the demands of farmers and save this precious life. Thank you.

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : माननीय सभापति महोदया, गाज़ियाबाद में अधिवक्ताओं पर जो लाठी चार्ज हुए हैं, यह पहली घटना नहीं है, इसके अलावा भी पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ऐसी घटनाएं घटी हैं कि अधिवक्ताओं के साथ हिंसा हुई है और उनकी जानें भी गई हैं।

(1335/PC/NKL)

सभापति महोदया, यह कष्टपूर्ण है। अधिवक्ता अपना पूरा जीवन लोगों को न्याय दिलाने में लगाता है। अधिवक्ता अमीर-गरीब, सबकी आवाज उठाता है।

मैं आपके माध्यम से कानून मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे जल्द से जल्द पूरे देश में सख्ती से 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' लागू करें, जिससे अधिवक्ताओं के अधिकार सुरक्षित रह पाएं और उनके साथ कोई घटना न घटने पाए, जिससे उनके बच्चों का भी कोई नुकसान न हो।

मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ और पुनः कानून मंत्री जी से अपील करता हूँ कि वे जल्द से जल्द पूरे देश में 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' को सख्ती से लागू करें। धन्यवाद।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : माननीय सभापति महोदया, मैं आज इस सदन में जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के मुसाबनी एवं घाटशिला प्रखंड के 15 पंचायतों की जनता की समस्याओं को उठाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इनकी सबसे बड़ी चिंता प्रधान मंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रह जाना है। यह क्षेत्र लंबे समय से विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गया है और अब, जब हमारे देश में प्रधान मंत्री आवास योजना जैसी ऐतिहासिक योजना लागू की गई है, तो इसके लाभ से क्षेत्र के कई ग्रामीण परिवार वंचित हैं।

माननीय सभापति महोदया, वर्ष 2011 के संसेस में ये 15 पंचायतें प्रधान मंत्री आवास योजना या किसी भी प्रकार की योजना की सूची में शामिल नहीं होने के कारण इनको किसी भी

प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। इनको शहरी क्षेत्र की सूची में डाला गया है, जबकि ये न शहरी क्षेत्र में हैं और न ही ग्रामीण क्षेत्र में हैं। इस तरह, इस योजना के तहत लाभ न मिलने से इन परिवारों के जीवन-यापन की स्थिति बहुत ही दयनीय है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन 15 पंचायतों को शहरी सूची से हटाकर पुनः ग्रामीण क्षेत्र की सूची में सम्मिलित किया जाए, जिससे इस योजना का लाभ इन सभी पंचायतों के सभी परिवारों को प्रदान की जा सके।

धन्यवाद।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूँ कि प्लीज़, वे जिन विषयों को लिखित में देते हैं, उन्हीं विषयों पर चर्चा करें।

... (व्यवधान)

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : सभापति महोदया, धन्यवाद।

महोदया, आपने मुझे शून्य काल में अपने लोक सभा क्षेत्र धौरहरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश की इस समय जो एक प्रमुख मांग है, उसकी तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट कराने का अवसर दिया है।

सभापति महोदया, हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो ग्रामीण इलाके के लोगों की पहली मांग होती है कि उनके ग्राम सभा में बारात घर का निर्माण करा दिया जाए।

महोदया, पहले गांवों में प्राइमरी स्कूल में बारात रुकने की इजाजत होती थी। इधर के दौर में प्राइमरी स्कूलों में बारात रुकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम सभा में, खासकर धौरहरा लोक सभा क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम सभा में बारात घर का निर्माण कराया जाए। जब तक बारात घर का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तब तक प्राइमरी स्कूलों में बारातों को रुकने का अवसर प्रदान किया जाए, जिससे ग्रामीण इलाकों की प्रमुख समस्या का समाधान हो सके।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : चेयरपर्सन मैडम, थैंक-यू।

आज मैं आपके माध्यम से इस सदन को और पूरे हिन्दुस्तान को यह बताना चाहता हूँ कि दलाई लामा इंस्टिट्यूशन को रिकॉगनाइज़ किया जाए। 'हिज़ होलीनेस दि फोर्टीन्थ दलाई लामा' का नाम तेनजिन ग्यात्सो है। आज इस मोड़ पर दलाई लामा इंस्टिट्यूशन पहुंचा है, हिज़ होलीनेस 90 इयर्स के हो गए हैं।

मैडम, वर्ष 1959 से चाइनीज़ सरकार ने फैसला करके रखा है कि पन्द्रहवें दलाई लामा को चाइनीज़ गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। अभी के 'हिज़ होलीनेस दि फोर्टीन्थ दलाई लामा' अगर मर जाते हैं, तो एक रीइन्कार्नेशन बुद्धिस्ट कल्चर में, धर्म होता है। जब वे रीइन्कार्नेट होंगे, तो वे फिफ्थीन्थ दलाई लामा होंगे और चाइना अपॉइंटेड दलाई लामा भी होंगे। 'हिज़ होलीनेस' का कम्पैशन, पीस, लव, इस मिशन में है, इसलिए, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 'हिज़ होलीनेस दि फोर्टीन्थ दलाई लामा' को भारत रत्न से अवॉर्ड किया जाए। अभी से हम तैयार

रहें कि हम फिफ्टीन्थ दलाई लामा के रूप में चाइना वाले दलाई लामा को रिकॉगनाइज़ करेंगे या हिन्दुस्तान में जो जन्म लिया है, उन दलाई लामा को हम रिकॉगनाइज़ करेंगे। यह फैसला बाकी है।

थैंक-यू-वैरी-मचा।

(1340/VR/IND)

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): Thank you, hon. Chairperson. The Government of India is implementing the Centrally-sponsored Pradhan Mantri Poshan Scheme in coordination with the States and Union Territories. The scheme serves around 120 million children in over 1.27 million schools across the country. The share of the Government of India in this scheme is 60 per cent whereas the share of the State Governments is 40 per cent. But the Central Government has not increased their share since 2019 and the payment is very meagre.

Madam, most of these workers belong to below poverty line families. They cannot manage their life with an honorarium of Rs.3,700. These Mid-Day Meal workers and helpers are considered volunteers and not employees, which in turn keeps them out of pension and provident fund facilities. Though their salaries are referred to as honorarium, I would like the Government to increase its Central share. Thank you.

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : महोदया, चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में रेलवे, हाईवे और अन्य क्षेत्रों में केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत कुछ दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है, जो शेड्यूल-5th में ट्राइबल जिला है। यह रेलवे की दृष्टि से आज भी बचा हुआ है। वहां चाहे नई रेल लाइन हो, ब्रॉडगेज हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो या डबलिंग हो, सारे काम चल रहे हैं लेकिन प्रताप गढ़ और बेगू क्षेत्र ऐसे हैं, जहां रेलवे की सेवाएं नहीं हैं। मनसौर से प्रतापगढ़ होते हुए गुजरात एक नई रेल लाइन के लिए फाइनल सर्वे केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। ऐसे ही नीमच से बेगू होते हुए कोटा एक नया फाइनल सर्वे सैंक्शन किया है।

महोदया, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि पीएम गति शक्ति या अन्य योजना के माध्यम से वहां भी रेल लाइन पहुंचे, ताकि वहां के लोगों को फायदा मिल सके।

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमन्द) : महोदया, मैं अपने राजसमन्द परिवार को यहां से बोलना चाहती हूँ कि मैं सदन में हमेशा उनकी आवाज बनूंगी। देश में सड़क हादसों को रोकने और उसमें जान-माल की कम से कम हानि को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार अधिक से अधिक कार्य कर रही है। हमारे यहां राजसमन्द में देसूरी की नाल घाट मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जो चारभुजा से पाली जाती है, उस पर स्थित सड़क घुमावदार है और जंगल के बीच से रास्ता निकलता है। घुमावदार सड़क होने पर भी खतरनाक मोड़ों पर सड़क सुरक्षा के उपाय

नहीं हो सके हैं और पूरे घाट इलाके में एलिवेटेड सड़क बन जाये, यह मांग जनता लम्बे समय से कर रही है, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति नहीं मिल पाई है।

महोदया, अभी कुछ दिन पहले ही इस घाट में बड़ा सड़क हादसा फिर से हो गया, जिसमें 3 स्कूली बच्चों की जान चली गई और अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हो गये हैं। अतः इन सड़क हादसों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाएं:-

पूरे देसूरी की नाल घाट में पर्यावरण मंत्रालय से एन.ओ.सी. प्राप्त करके पूरे घाट में एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जाये।

घाट को राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत लाया जाये और सकरे मोड़ों को चौड़ा किया जाए।

घाट की सड़क के किनारे अपेक्षित स्थानों पर विभिन्न सड़क सुरक्षा उपाय किये जाएँ। घाट की सड़क में ट्रैफिक नियंत्रण के उपाय किए जाएँ।

यह सिर्फ राजसमन्द में ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र में ऐसा होना चाहिए ताकि दुर्घटनाएं न हों।
(1345/SAN/RV)

*SHRI NILESH DNYANDEV LANKE (AHMEDNAGAR): Hon'ble Madam Chairperson, today I rise to discuss an urgent issue. Prime Minister's National Relief Fund provides maximum Rs. 3 lakh for medical treatment, but it needs to be increased. Under PMNRF, an MP can refer only 35 cases per year. This rule is not appropriate and the cap of 35 cases should be removed and maximum cases should be granted a permission. The number of panel hospitals should also be increased immediately. At least one panel hospital should be there in each tehsil.

This PMNRF scheme is being implemented through postal service. It should be implemented through online mode so that a patient should get a financial relief as early as possible.

Madam, one more special provision option should be included in PMNRF. If the diagnosed disease is not in the approved list, it should be treated as special case and financial assistance could be provided.

Thank you very much for this opportunity to speak.

#SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Madam Chairperson, Vanakkam. People belonging to middle class live in their constructed houses in the Vennai Malai and Velayuthampalayam areas of Karur parliamentary Constituency. These

* Original in Marathi

Original in Tamil

houses were issued with the ownership rights called the 'Patta'. They have regularly paid property tax, water tax and electricity bills. These habitations are also considered as land belonging to Vennai Malai Murugan temple and Pugazhi Malai murugan temple. These lands are also listed as "'Inam' land and temple land. Therefore, this land belongs to the families which live there. Transfer of property has also taken place. Many people have sold and bought these properties of land. People started living in this land for the last hundred years even before the Hindu Religious Endowment Board was created. Some of them have sold those properties and purchased a piece of land in the urban areas and had settled there after constructing a house for themselves. Even after the Court's verdict was pronounced on this issue, the Registration Department had continued to register buying and selling of these properties. These people should not be displaced and asked to vacate the land in the name of claiming to be a temple land. Home is a dream for any person every person. Particularly, these people have invested their lifetime earnings in this land and built their houses there. They have been living there for more than 30 years to 50 years. Now making them homeless is unacceptable. 'Inam' land of the temples has become a contentious issue now. I urge that a justifiable and amicable solution should be reached by the Union government on this issue in consultation with the State government of Tamil Nadu. Thank You.

श्री रविन्द्र वसंतराव चव्हाण (नांदेड़) : माननीय सभापति महोदया, मैं नांदेड़, महाराष्ट्र संसदीय क्षेत्र से हूँ नांदेड़ जिले में किसान भाइयों की पीक बीमा राशि लगभग 617 करोड़ रुपये है। इसमें केन्द्र सरकार के 267.3 करोड़ रुपये के हिस्से की राशि का मिलना अभी तक बाकी है। महाराष्ट्र सरकार के हिस्से की 349.7 करोड़ रुपये की राशि मिल चुकी है, लेकिन केन्द्र सरकार के हिस्से वाली राशि अभी तक नहीं मिली है। इसके कारण किसान भाई इस लाभ से वंचित हैं।

महोदया, मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि पीक बीमा के 267.3 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के हिस्से की राशि तुरन्त महाराष्ट्र सरकार को अदा की जाए, जिससे किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके।

DR. T. SUMATHY ALIAS THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Madam Chairperson, I thank you for allowing me to raise this very important issue.

The Cyclone Fengal has destructed the Northern districts of Tamil Nadu, disrupting infrastructure, livelihood and daily lives of people; especially the landslide that happened in Tiruvannamalai is a major havoc.

The situation has been commendably handled by our Chief Minister, *Thiru M.K. Stalin* well. More than 500 employees have been deployed to restore the roads, especially the Chittoor bye-pass road. Many Executive Engineers had been deployed for the work and the situation was kept under control. In addition, more than Rs. 30 crore have been given for the welfare measures and Rs. 37 crore have been deployed through the self-help groups. Despite that, the situation there needs a large amount of money.

Our Chief Minister had represented for an interim relief of more than Rs. 2,000 crore. Our Prime Minister claims that the Government follows the tagline of *Vasudhaiva Kutumbakam*. Is Tamil Nadu not a part of that family, a part of India? ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य पप्पू यादव जी।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिमा) : माननीय सभापति महोदया, नालन्दा, पेपर एग्जामिनेशन और घोटाला, ये बीपीएससी, यूपीएससी, नियोजित शिक्षक परीक्षा के संबंध में पूरक बन गए हैं। पेपर्स लीक के मामले लगातार हो रहे हैं।

महोदया, परम ज्ञान निकेतन, गया से लेकर कई ऐसे स्कूल्स में पेपर्स लीक के मामले आए हैं। कोई भी एग्जामिनेशन बिना पेपर लीक के नहीं हो पा रहा है। अभी सीजीएल परीक्षा का जो मामला आया, उसमें यह आया कि एक बच्चे की रिजल्ट 40 लाख रुपये लेकर दी गयी। यह रिपोर्ट आ गयी है।

मैडम, दूसरा, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा। उसी बीच, सॉफ्टवेयर की गलती के कारण हमारे यहां के 85 हजार बच्चे फॉर्म नहीं भर सके। उसका एक्सटेंशन नहीं हुआ। दो पदाधिकारी – एम. एम. राजू, और परमार - इन दोनों को गलत तरीके से, जबकि उन पर विजिलेंस की जांच हो गयी, एफ.आई.आर. हो गयी और उनकी पोस्टिंग कर दी गयी।

मैडम, मेरा मामला सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार का भी है... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री राजेश वर्मा जी।

(1350/GG/SNT)

श्री राजेश वर्मा (खगड़िया) : सभापति महोदया, मैं सदन को एक बहुत ही गंभीर बीमारी के विषय में अवगत कराना चाहता हूँ। सभापति महोदया, एसएमए – स्पाइनल मसक्यूलर ऑट्रोफी एक गंभीर बीमारी है, जिससे प्रत्येक वर्ष लगभग चार हजार बच्चे देश में, बिहार में लगभग ढाई सौ बच्चे, भागलपुर में लगभग 16 बच्चे और मेरे लोक सभा क्षेत्र खगड़िया में लगभग तीन ऐसे बच्चे हैं, जो इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी में मांसपेशियों का नसों के साथ संपर्क टूट जाता है और छह साल के बाद वह बच्चा बोलना बंद कर देता है। उसके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता है और धीरे-धीरे वह मौत की तरफ बढ़ता जाता है। इस बीमारी के इलाज में लगभग साढ़े

17 करोड़ रुपये का एक इंजेक्शन लगता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इसको लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाए ... (व्यवधान)

श्री देवेश शाक्य (एटा) : सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र एटा-कासगंज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। इन दोनों जनपदों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली, आगरा, लखनऊ और बरेली जाना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि एक केंद्रीय विद्यालय, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और इसके साथ-साथ जनपद कासगंज में मध्यम वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए एक राजकीय विद्यालय कासगंज जनपद में खोलने की कृपा करे। इसके साथ-साथ एटा में जो राजकीय विद्यालय है, उसमें शिक्षकों की कमी है और उसमें विज्ञान संकाय की यदि व्यवस्था हो जाए तो वहां पर मध्यम वर्ग के लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): I would like to draw the attention of the House towards an urgent matter regarding extension of Angamaly-Sabari Railway line from Erumeli to Vizhinjam via Nedumangad. Nedumangad has already been selected under the Government proposal for rail connectivity for towns having above 50,000 population. Railway facility to Nedumangad town could be provided through the expansion of Angamaly Sabari railway from Erumeli to Vizhinjam International seaport via Pathanamthitta, Konni, Pathanapuram, Punalur, Anchal, Kilimanoor, Vattapara, Nedumangad, Kazhakkootam, and Kattakada. The extended line would establish an additional corridor for passenger and freight movement. The expansion of Sabari railway project is important for the overall development of the State.

I request the Government to sanction the expansion of Angamaly-Sabari railway from Erumeli to Vizhinjam.

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी (श्रीनगर) : मैडम चेयरपर्सन, मैं आपके ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री से यह गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर में जो पुलिस सब-इंस्पेक्टर के रिक्लूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है, इनकी नॉलेज में होगा कि वह पिछले चार सालों से डिले हुआ है, जिसकी वजह इर्रेगुलैरिटीज़ थी। जो रिक्लूटमेंट एजेंसी इन्होंने मुंतखब की थी, अपॉइंट की थी, इस रिक्लूटमेंट के लिए, एप्टेक, उनकी इर्रेगुलैरिटीज़ की वजह से यह डिले हुआ और डिले की वजह से जो एस्प्रेट्स हैं, जिनकी ऐज अब अपर लिमिट से बाहर निकल गई है, मेरी गुज़ारिश है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू-कश्मीर ने भी रिक्मेंड किया है, जैसे कि आप जानते हैं कि यह सब्जेक्ट होम मिनिस्ट्री के हाथ में है, हम चाहते हैं कि जेकेपीएसआई में वन टाइम ऐज रिलैक्सेशन दी जाए ताकि ये एस्प्रेट्स अपने लिए रोज़गार हासिल कर सकें। शुक्रिया।

श्री मनोज कुमार (सासाराम) : मैडम, मैं अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। बिहार में ममताकर्मी स्वास्थ्य विभाग में हैं। उनके लिए मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। वर्ष 2008 से इनकी बहाली बिहार सरकार में हुई। तब से अभी तक ममताकर्मीयों को प्रति

प्रसूति एक सौ रुपया दिया जाता था अब तीन सौ रुपया दिया जाता है। लेकिन इनका जो काम है, जैसे डॉक्टर करते हैं, वैसे ही नर्स करती हैं।

(1355/MY/AK)

आज तक वे अस्पताल में आठ-दस घंटे तक मजदूरी करती हैं, लेकिन उनको एक रुपया भी नहीं मिलता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ममताकर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। अस्पतालों में जो सुविधाएं डॉक्टरों एवं नर्सों को मिलती हैं, वही सुविधाएं हमारे ममताकर्मियों को भी मिलनी चाहिए। धन्यवाद।

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Madam, I rise before you to draw the kind attention of the hon. Railway Minister, through you, to a matter of significant importance, namely, shortage of train facilities to northern parts of Kerala.

In just a few days, the world will come together to celebrate Christmas and New Year -- a time filled with happiness and joy. A large number of individuals will travel to their hometowns from their workplaces to celebrate Christmas and New Year with their families. ... (*Interruptions*)

Madam, please allow me to complete. ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, आप केवल एक विषय बोलिए।

... (व्यवधान)

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Madam, however, the residents of Northern Kerala are facing substantial challenges due to inadequate transportation options. ... (*Interruptions*) Madam, I am concluding by mentioning my demand. ... (*Interruptions*) I would urge the Government of India to consider introduction of special train services connecting Northern Kerala with Chennai, Delhi, Bangalore, Trivandrum, and Mumbai.

श्री दिलीप शङ्कीया (दारंग-उदालगुड़ी) : सभापति जी, मैं दो विषय रखना चाहता हूँ। मेरा पहला विषय Bodoland Territorial Region (BTR) के बारे में है। वहाँ मेरे संसदीय क्षेत्र का उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है। यह जनजातीय बहुल क्षेत्र है। जनजातीय बहुल क्षेत्र उदालगुड़ी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का एक केंद्र स्थापित किया जाए।

दूसरा, कार्बी आंगलॉग भौगोलिक दृष्टि से असम का सबसे बड़ा जिला है। वहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जरूर खुले। इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री जी से विशेष रूप से निवेदन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राहुल कर्वा (चुरु) : सभापति महोदया, राजस्थान के अंदर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है। इस योजना के वर्ष 2023-24 की रबी फसल और वर्ष 2023 के खरीफ फसल के प्रीमियम के इश्यू पर मैं बोलना चाहता हूँ।

महोदया, वर्ष 2023-24 के रबी फसल का जो प्रीमियम है, उसे राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक जमा नहीं करवाया। राजस्थान के चुरु जिले में किसानों का 400 करोड़ रुपये का क्लेम बनता है। इस पैसे को जमा नहीं करने के कारण, आज एक साल से ऊपर हो चुका है, किसानों को उनका क्लेम नहीं मिल रहा है।

महोदया, वर्ष 2023 खरीफ फसल के अंदर भी आज तक किसानों की आठ सौ पटवार मंडलों की शिकायत स्टेट गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़ी हुई है। डबल इंजन के नाम पर सरकार ने वोट मांगे, लेकिन आज तक राजस्थान का एक इंजन बंद पड़ा है। किसानों की एक-एक साल तक प्रीमियम की राशि स्टेट गवर्नमेंट जमा नहीं करवा रही है। हमारे किसानों को कैसे क्लेम मिलेगा?

महोदया, मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों को क्लेम दिलाए। सरकार विद ब्याज क्लेम दिलाने का काम करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) : माननीय सभापति महोदया, अभी शून्य काल के दौरान माननीय सदस्य द्वारा विजय दिवस को लेकर यहां पर कुछ वक्तव्य दिये गए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो दो विषय रखे थे, उनमें से एक विषय था कि जो पेंडिंग पहले रक्षा मंत्रालय में लगी थी, उस पेंडिंग को वहां से हटा दिया गया है। मैं मात्र सदन के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि वह पेंडिंग मोस्ट बिफिटिंग प्लेस मानेकशॉ ऑडेटोरियम में पूरे सम्मान के साथ स्थापित की गई है ताकि वहां उसे और अधिक लोग देख कर उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें... (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, I may be allowed to ask one clarification. ... (Interruptions)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: महोदया, मुझे लगता है कि ऐसे विषय जो भारत की सेना और भारत की सेना से सम्मान से जुड़े हुए हैं, भारत की सेना के शौर्य से जुड़े हुए विषय हैं, उनको लेकर इस तरह की राजनीतिक टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए... (व्यवधान) मुझे लगता है कि इस विषय पर हम सब संसद में बैठे हुए सम्माननीय सदस्यों को अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान रखते हुए, उस पर निश्चित रूप से हमें टिप्पणी करने से पहले विचार करना चाहिए... (व्यवधान)

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : सभापति महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र में भीलवाड़ा-छापड़ा-जहाजपुर-देवली रोड है, जिसकी लंबाई कुल 95 किलोमीटर है। इस रोड को टू लेन से फोन लेन किया जाए। यह मार्ग देवली के एनएच 52 से प्रारंभ हो कर जहाजपुर के 148डी से जुड़ता है और छापड़ा तक जाता है। उसके बाद बनेरा होते हुए एनएच 48 से जुड़ता है।

(1400/CP/UB)

इस रोड पर अत्यधिक ट्रैफिक होने के कारण, जाम और दुर्घटनाओं के कारण न केवल आमजन परेशान होते हैं, बल्कि आपातकालीन सेवाएं भी ठप हो जाती हैं।

पिछले लंबे समय से आमजन की यह मांग है कि इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए... (व्यवधान)

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : सभापति महोदया, हमारे संसदीय क्षेत्र के जनपद देवरिया, जनपद बलिया, सलेमपुर लोक सभा क्षेत्र में जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तुरहा, गोंड, खरवार और धनगर जातियों को क्रमशः एससी, एसटी में अधिसूचित किया गया है। इन जातियों को प्रमाण पत्र न मिलने से इनका सम्पूर्ण विकास रुका हुआ है। इनको संवैधानिक हक नहीं मिल रहा है। तुरहा जाति एससी में अधिसूचित है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में इसे तुरहया और तुरहा कहा जाता है, लेकिन अधिकारी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं।... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : महोदया, पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन की एचटी लाइन हरियाणा, दिल्ली के कई इलाकों से गुजर रही है, जिसमें किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा है। राइट ऑफ वे में जो लाइन के आसपास का लगभग एक एकड़ क्षेत्र होता है, उसमें 30 प्रतिशत मार्केट रेट दिए जाने की गाइडलाइन्स हैं, जबकि जमीन की वैल्यू में 90 पर्सेंट की गिरावट होती है। वहां मार्केट रेट की बजाए कलेक्टर रेट दिया जाए। किसानों की मांग है कि उन्हें मार्केट रेट के हिसाब से 90 पर्सेंट दिया जाए। वहां किसान आंदोलनरत हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।

1401 hours

(Shri Dilip Saikia in the Chair)

शंभू बार्डर पर भी किसान बहुत लंबे अरसे से बैठे हैं। एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 21 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। सरकार उनसे बात नहीं कर रही है। उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। केवल 101 किसान दिल्ली आना चाहते हैं, उनको इजाजत दी जानी चाहिए और सरकार उनसे बात करे।

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : सभापति महोदय, आज मैं इस महान सदन में उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर अपना गम्भीर शोक व्यक्त करना चाहूंगा। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने एक महान कलाकार को खोया है। भारतीय संस्कृति के प्रति उस्ताद जाकिर हुसैन के योगदान को याद करते हुए, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार उनको सम्मानित करे। उनकी जो महत्वपूर्ण बातें थीं, जो हमने एडवरटाइजमेंट में देखा था, “वाह उस्ताद वाह”, वह हम कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ।

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति महोदय, मैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सांसद हूँ। इस द्वीप समूह का 700 किलोमीटर लंबा संसदीय क्षेत्र है। पिछले पांच साल में पोदान समिति जिला ने केवल 25 किलोमीटर रास्ता बनाया। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि पीआरआई के पास जो फंक्शन था, फंड था, पॉवर थी, वह खत्म हो चुकी है। उसे कृपया दोबारा दे दीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 700 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, आप इस बात को जानते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप मांग इस पर विचार करें, अंडमान को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, भारत माता की जय।

**LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE
ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Rajabhau Parag Praksash Waje	Shri Arvind Ganpat Sawant Shrimati Supriya Sule
Shri Ujjwal Raman Singh	Shri Vishaldada Prakashbapu Patil
Dr. Prashant Yadaora Padole	Shri Vishaldada Prakashbapu Patil
Shri Dharmendra Yadav	Shri Manickam Tagore
Shri Arun Nehru	Dr. T. Sumathy alias Thamizhachi Thangapandian
Shri N.K. Premachandran	Shri Anto Antony Shri M.K. Raghavan Shri Kodikunnil Suresh Shri Benny Behanan Shri Hibi Eden Adv. Adoor Prakash Shri K.C. Venugopal
Shri Ram Prasad Chaudhary	Shri Arun Nehru
Shri Ummeda Ram Beniwal	Dr. T. Sumathy alias Thamizhachi Thangapandian
Dr. Mohammad Jawed	Shri Vishaldada Prakashbapu Patil Shri Rajesh Ranjan Shri Devesh Shakya Shri Aditya Yadav Adv. Chandra Shekhar Shri Zia Ur Rehman Shri Gurmeet Singh Meet Hayer Shri Rajeev Rai Shri Naresh Chandra Uttam Patel Shri Ramashankar Rajbhar Shri R.K. Chaudhary Dr. T. Sumathy alias Thamizhachi Thangapandian Shri Chhotelal Shri Arun Nehru

	Shri Anto Antony Shri M.K. Raghavan Adv. Adoor Prakash Shrimati Priyanka Gandhi Vadra Shri Hibi Eden Shri Imran Masood Dr. Mallu Ravi Shri Benny Behanan Shri Rajmohan Unnithan Sushri S. Jothimani Dr. Amar Singh Shrimati Jyotsna Charandas Mahant Shri Kuldeep Indora Kumari Sudha R Shri Suresh Kumar Shetkar Shri Shahu Shahaji Chhatrapati Adv. Dean Kuriakose Dr. M.K. Vishnu Prasad Sushri Praniti Sushilkumar Shinde Dr. Prabha Mallikarjun
Shri Nilesh Dnyandev Lanke	Dr. Prashant Yadaorao Padole
Shri Ramvir singh Bidhuri	Shri Jagdambika Pal
Shri Harendra Singh Malik	Shri Jagdambika Pal
Shri Bhaskar Murlidhar Bhagare	Shrimati Supriya Sule
Shrimati Kamaljeet Sehwat	Shri Sudheer Gupta Shri Jagdambika Pal
Dr. Nishikant Dubey	Shri Sudheer Gupta Shri Jagdambika Pal
Shrimati Priyanka Gandhi Vadra	Shri Manickam Tagore Shri Vishaldada Prakashbapu Patil Captain Viriato Fernandes
Shri K.C. Venugopal	Shri Kodikunnil Suresh

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1404 बजे

माननीय सभापति (श्री दिलीप शङ्कीया) : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को तुरन्त व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

Re: Need to take comprehensive measures to ensure security of oil and natural gas pipelines

SHRI PARSHOTTAMBHAI RUPALA (RAJKOT): Security of the fuel pipelines has become a serious issue. This is important not only from the economic point of view, but also from the view point of national security. Recent developments have made it even more evident that lapses in the security of these pipelines can have serious consequences. Moreover, the warning of targeting oil pipelines by terrorists trained in Pakistan has made situation even more serious. It is a clear that along with external threats, internal security challenges also exist in the region. The recovery of a power IED near ONGC pipelines in Assam has further increased the concern of security agencies. This incident shows that the terrorist organisations and other anti-social elements are active in targeting these critical infrastructures. The HPCL pipelines in Pune have suffered damage due to fuel theft, which is an indication of lack of security measures. This incident not only caused economic losses, but also increased the sense of insecurity among the local communities. I request the Ministry of Home Affairs to take concrete steps in collaboration with the Ministry of Petroleum and Natural Gas to make these security measures more effective. (ends)

Re: Condition of washrooms in Railway Coaches

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारडोली) : मैं इस सदन के माध्यम से रेलवे मंत्रालय और माननीय रेल मंत्री जी द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की प्रशंसा करना चाहता हूँ। वंदे भारत ट्रेनों का संचालन और रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कदम देश के विकास को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। विशेष रूप से गुजरात के सूरत को बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत एक प्रमुख स्टेशन के रूप में शामिल करना अत्यंत सराहनीय है। यह सुविधा सूरत जैसे औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देगी और यात्रियों को तेज और आधुनिक परिवहन का विकल्प प्रदान करेगी। इसके साथ, मैं रेलवे डिब्बों में वॉशरूम सुविधाओं की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्तमान में, प्रत्येक डिब्बे में चार वॉशरूम हैं, जिनमें तीन भारतीय शैली के और एक वेस्टर्न शैली का होता है। बढ़ती मांग को देखते हुए, मेरा सुझाव है कि तीन भारतीय शैली के वॉशरूम में से दो को वेस्टर्न शैली में बदला जाए, ताकि प्रत्येक डिब्बे में तीन वेस्टर्न और एक भारतीय शैली का वॉशरूम उपलब्ध हो। यह बदलाव यात्रियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगजनों की सुविधा को बढ़ाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से इस पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध करता हूँ।

(इति)

**Re: Need to set up a Research Institute of Indian Ocean Cultural Studies in
Jajpur district, Odisha**

DR. RABINDRA NARAYAN BEHERA (JAJPUR): Indian Ocean played a major role in disseminating Indian Culture across the shore since the dawn of civilization. India's trade through the Bay of Bengal was controlled by the ports of Kalinga i.e., Tamralipti, Dhamra, Radhanagar, Langudi, Ratnagiri etc. The socio-cultural impact and interaction are witnessed in several islands of South Asia like Sri Lanka, Java, Sumatra etc . Buddhism played key role for diffusion of Indian Culture in the cultural spectrum of South Asia. The cultural interaction with ASEAN Countris are faintly studied . Puspagiri Vishwabidyalaya which existed during Samrat Ashok period near Languli Hills and Udaygiri of Jajpur District in the bank of river Kelua was supposed to be a learning centre of Buddhism. Hence, a Research Institute of Indian Ocean Cultural Studies may be set up in this locality to undertake multi-disciplinary research(Ph.D.), M.Phil and Diploma Courses and also revival of the glorious Puspagiri Univerity. This may be functioned as an Autonomous Organisation/ University. It may have Maritime Heritage, South Asian Culture, Language, Literature & Ethnic studies, Buddhism & Peace Studies, International Cooperation etc. The Centre would be a pioneer research organisation like IISER, NISER in Humanities field which would attract international scholars from across the Indian Ocean Countries.

(ends)

**Re: Four-laning of Jherda-Mander- Revdar-Sirohi NH and construction
of by-pass roads**

श्री लुम्बा राम (जालौर) : राष्ट्रीय राजमार्ग 168 सिरोही से मण्डार तक नेशनल हाइवे स्वीकृत हुआ था, मगर यह रोड़ टोल रोड़ होने से आज दिन तक फोरलेन नही बन सका । वर्तमान में यह सड़क अक्टूबर 2024 में टोल मुक्त हो गई है । इस रोड़ को राजस्थान सरकार ने हाल ही मे (अक्टूबर 2024) भारत सरकार को सौंप दिया है। यह सड़क कांडला पोर्ट से दिल्ली से सीधे जुड़ी हुई है। इस मार्ग से टोल समाप्त होने के कारण ट्रैफिक लोड काफी बढ़ गया है। जिससे इस सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस मार्ग पर मंडार, रेवदर और सिरोही तीन घनी आबादी वाले शहर है। इन शहरों में दिन में ट्रैफिक जाम हो जाता है। अतः आपसे आग्रह है कि झेरडा -मंडार-रेवदर -सिरोही का राष्ट्रीय राजमार्ग को फोर लेन तथा मंडार रेवदर और सिरोही के पास बाइपास का निर्माण जल्द से जल्द करवाने का श्रम करावो।

(इति)

Re: Need to provide air connectivity to Bareilly with various cities of the country

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार (बरेली) : मैं आपके माध्यम से माननीय, नागरिक उड्डयन मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि मेरा लोकसभा क्षेत्र बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत का प्रमुख जनपद है तथा यह जनपद पर्यटन, धार्मिक, व्यापारिक व सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है, फिर भी वर्तमान में एक दिन में केवल एक (1) उड़ान है जो क्षेत्र की अधिकतम क्षमता को उचित नहीं ठहराती है। इस प्रकार समग्र मूल्यांकन पर बरेली को AIR BUS-320/321 के संचालन के द्वारा प्रमुख शहर जैसे चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा, कोलकाता, हैदराबाद, जम्मू / श्रीनगर आदि लंबी दूरी के प्रमुख शहरों, एवं ATR विमान से आसपास के शहर जैसे दिल्ली, जयपुर, अमृतसर, पटना, लखनऊ और देहरादून को हवाई मार्ग से जोड़ने की काफी संभावनाएं हैं। बरेली हवाई अड्डे के अन्य शहरों से हवाई मार्ग से जुड़ने से बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों को वास्तविक लाभ मिलेगा तथा बरेली, भारत के सग्रम विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सकेगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि बरेली शहर को विमान सेवा द्वारा उपरोक्त शहरों से जोड़ा जाए, इसके लिए मैं और बरेली क्षेत्र की जनता सदैव मंत्री जी की आभारी रहेगी। (इति)

Re: Need to ensure timely passage of the 125th Amendment to the Constitution regarding empowerment of Autonomous District Councils in the Sixth Schedule Areas

SHRIMATI KRITI DEVI DEBBARMAN (TRIPURA EAST): I would like to draw the attention of the House and Hon'ble Minister of Home Affairs to a grave concern regarding the severe delay in the passage of the 125th Amendment to the Indian Constitution. The Amendment seeks to empower the Autonomous District Councils (ADCs) in the Sixth Schedule areas, including the state of Tripura, to ensure better governance, safeguard indigenous rights, and improve socio-economic conditions. Despite the significant importance of this amendment for the socio-economic and political empowerment of our indigenous people, it has been over five years since the bill was introduced in the Lok Sabha in 2019. The report of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs was submitted on 5th March 2020, but there has been no further progress. Several meetings have been held with the Ministry of Home Affairs, involving representatives from all concerned ADCs, yet the bill remains pending. In this regard, I would like to request the Government to ensure timely passage of the 125th Amendment to the Constitution and address the current challenges faced by the indigenous communities in the Sixth Schedule areas due to the delay in the passage of this Amendment.

(ends)

**Re: Conservation of National Parks and Wildlife Sanctuaries
in the country**

डॉ. फगुन सिंह कुलस्ते (मंडला) : प्राकृतिक आवास में वन्य जीवन की दुर्दशा खतरे में है। पूरे देश में सरकार द्वारा कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनाए गए हैं और उनका रखरखाव किया जा रहा है। सरकार द्वारा निर्धारित और लगाया गया बहुत सारा धन भी वांछित परिणाम नहीं दे रहा है जिसके लिए इन प्राकृतिक आवासों का निर्माण किया गया था। उनकी स्थिति में सुधार और पुनर्वास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इन प्राकृतिक आवासों को बचाने के लिए अधिक धन आवंटित करने की तत्काल आवश्यकता है। वांछित परिणाम लाने के लिए मौजूदा प्रणाली/मशीनरी और योजनाओं में सुधार करने की भी आवश्यकता है। देश में वन्य प्राणी अभयारण्यों, पार्कों का निर्माण देश में अनेक स्थानों पर किया गया है। परन्तु देखा यह जा रहा है कि पार्कों के निर्माण के आस-पास रहने वाले गावों के व्यक्तियों को शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड जो है, जिसका भुगतान प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के रूप में सरकार ने देने का प्रावधान किया है क्या यह राशि उन परिवारों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त है। (इति)

Re: Four laning of Mirzapur – Gopiganj road

डॉ. विनोद कुमार बिंद (भदोही) : मेरे लोकसभा क्षेत्र भदोही (उत्तर प्रदेश) के गोपीगंज से होते हुए हजारों की संख्या में दर्शनार्थी रोजाना मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल धाम दर्शन करने के लिए जाते हैं और इसी मार्ग से बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों की तरफ होता है। ऐसे में मिर्जापुर-गोपीगंज मार्ग को फोर लेन किया जाए या किया जाना अति आवश्यक है। इस मार्ग के फोरलेन होने से आवागमन में काफी आसानी होगी और यह मार्ग नेशनल हाईवे 19 से भी कनेक्ट हो जाएगा। इस मार्ग के फोरलेन होने से जहां तक एक तरफ दर्शनार्थियों और आमजन को आवागमन में आसानी होगी वहीं भदोही-मिर्जापुर परिक्षेत्र के कालीन कारोबार को भी इससे बड़ा लाभ मिलेगा। (इति)

Re: Facilities for Senior Citizens

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : बचपन और जवानी के बाद जब एक व्यक्ति वृद्धावस्था में प्रवेश करता है तो उसके जीवन में काफी परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले सेहत संबंधी समस्याएं इसके पश्चात अकेलापन परेशान करता है। पहला प्रमुख कारण है संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन, नई व पुरानी पीढ़ी के बीच का फासला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं तथा उसके आनुषंगिक संगठन जैसे संस्कार भारती सेवा भारती इत्यादि वरिष्ठ नागरिकों को उपयोगी कार्यों में लगाकर उन्हें महत्वपूर्ण होने का निरंतर एहसास कराते हैं। सरकार को भी चाहिए कि वरिष्ठ नागरिकों को कम से कम ₹10000 महीना पेंशन दें, ताकि वह अपने भोजन और वस्त्र इत्यादि का प्रबंध बिना किसी परेशानी के कर सकें। सरकार को चाहिए केवल बुजुर्ग नागरिकों के लिए सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में सप्ताह में एक दिन ऐसा निर्धारित करें जब केवल वरिष्ठ नागरिकों की ही देखभाल हो। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से मिलने वाली सस्ती दवाइयों से बुजुर्ग लोगों को अपना स्वास्थ्य ठीक रखने में बहुत सहायता मिली है। वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा, भ्रमण, तीर्थाटन व देशाटन इत्यादि में सुविधा पहुंचाने के लिए रेल, बस, इत्यादि में किराए में छूट दी जानी चाहिए।

(इति)

Re: Need to establish a Tribal University in Karbi Anglong district of Assam and also set up a Campus of

Indira Gandhi National Tribal University at Udalguri in the State

श्री दिलीप शङ्कीया (दारंग-उदालगुड़ी) : कार्बी आंगलोंग जिला असम राज्य में एक प्रशासनिक इकाई है। भारत के संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) द्वारा प्रशासित एक स्वायत्त जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार कार्बी आंगलोंग जिले की जनसंख्या 956313 है। कार्बी आंगलोंग की साक्षरता दर 69.25 प्रतिशत है। इसका कुल क्षेत्रफल 10 हजार 404 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कार्बी जनजाति का वर्चस्व है। कार्बी के अलावा, लालुंग (तिवा), दिमासा कछारी, रेंगमा नागा, कुकी, गारो, खासी और श्याम लोग जिले के विभिन्न इलाकों में रहते हैं और अपनी जातीय पहचान बनाए रखते हैं। असम के जिलों में इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, लेकिन इस जिले में शैक्षिक संस्थानों की संख्या बहुत ही कम है और उच्च शिक्षा के लिए तो कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। अतः आपके माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि पूर्वोत्तर राज्य असम में जनजातीय समुदायों को उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कार्बी आंगलोंग जिले में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र उदालगुड़ी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश) का एक कैंपस स्थापित किया जाए।

(इति)

Re: Need to establish a 150-bedded ESIC hospital in Dhanbad, Jharkhand

श्री दुलू महतो (धनबाद) : सदन के मध्यम से माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि मेरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र - धनबाद, जिसे 'कोल कैपिटल ऑफ इंडिया' के नाम से जाना जाता है, झारखंड राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ के श्रमिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण से न केवल क्षेत्रीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक विकास हो रहा है। धनबाद में कार्यरत हमारे मेहनती श्रमिकों को खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें श्वसन रोग, चोटें और दीर्घकालिक व्यावसायिक बीमारियाँ होती हैं। इस स्थिति में, स्वास्थ्य देखभाल की वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त हो चुकी है, और श्रमिकों को तत्काल और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता है। इसलिए, हम आपके माध्यम से माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री से निवेदन करते हैं कि धनबाद में एक अत्याधुनिक ESIC 150-बेडेड अस्पताल की स्थापना करवाई जाए जिससे यह अस्पताल श्रमिकों के स्वास्थ्य की तुरंत चिकित्सा जरूरतों को तो पूरा करेगा ही साथ ही दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल में मदद करेगा।

(इति)

Re: Need to provide ownership rights of houses under PM UDAY Scheme to people living in unauthorized colonies in Delhi

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली की 69 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को एफ्लूएंट (समृद्ध) कॉलोनी कहकर पीएम उदय योजना के अंतर्गत मालिकाना अधिकार नहीं दिए जा रहे, उन्हें भी अन्य अनधिकृत कॉलोनियों के समकक्ष मानकर मालिकाना अधिकार दिया जाए। हाईकोर्ट की भी यही भावना है।

इन कॉलोनियों में लगभग 4 लाख लोग रह रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा इन कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। इन कॉलोनियों के निवासी नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं, लिहाजा इन कॉलोनियों को भी मालिकाना अधिकार दिया जाए, वैसे भी ये कॉलोनियां प्राइवेट लैंड पर ही बसी हुई हैं।

(इति)

Re: Need to retain Akashvani Kendra at Darbhanga, Bihar and declare it as a broadcast centre for Maithili language programmes

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा) : मेरी माँग सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी से है कि दरभंगा में अवस्थित आकाशवाणी केन्द्र को यथावत रखने एवं मैथिली भाषा का केन्द्र घोषित कर इसके अस्तित्व को बनाए रखा जाय। यह केन्द्र वर्ष 1976 से अब तक मैथिली भाषा के विकास, मिथिला संस्कृति का संरक्षण, मैथिली गीत-संगीत का संवर्धन करती आ रही है। कुछ दिन पूर्व आकाशवाणी केन्द्र दरभंगा की प्रशासनिक व्यवस्था आकाशवाणी केंद्र पटना के अधीन कर दी गई और अब प्रसार भारती आगामी माह से आकाशवाणी दरभंगा केंद्र को मात्र रिले केन्द्र बनाने जा रही है और यह निर्णय साढ़े आठ करोड़ मैथिली भाषियों के भावना को आहत करेगी। इस केंद्र के प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सीतामढ़ी, शिवहर और बेगूसराय जिला समाहित है। मैथिली भाषा भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित एक संवैधानिक भाषा है। भारत सरकार ने भारतीय संविधान को मैथिली भाषा में अनुवादित कर इसका विमोचन किया है। मन की बात" आकाशवाणी केन्द्र दरभंगा से ही मैथिली भाषा में प्रसारित की जाती है। साढ़े आठ करोड़ मैथिली भाषियों की भावना का सम्मान करते हुए आकाशवाणी केन्द्र दरभंगा को मैथिली भाषा का केन्द्र घोषित करते हुए इसके अस्तित्व को बनाए रखा जाए। (इति)

Re: Need to ensure strict compliance with the guidelines for treatment and rehabilitation of Persons with Mental Illness (PWMI)

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): I rise to address a critical issue regarding the rights of persons with mental illnesses (PwMIs). The Mental Healthcare Act of 2017 guarantees the right to community living, but many individuals who are deemed "fit for discharge" continue to be confined in mental health establishments due to a lack of community-based facilities like halfway homes. The intention behind halfway homes was to facilitate the seamless reintegration of PwMIs into society after prolonged institutionalization. The inaccurate data on the Manoashraya dashboard tracking rehabilitation and halfway homes, published by the Ministry of Social Justice and Empowerment, is particularly concerning. The data is riddled with discrepancies, including duplicate entries, inconsistent information, and missing reports from crucial states. This failure to maintain accurate records only perpetuates the delay in providing adequate care and rehabilitation to PwMIs. I urge the Union Government to clean up the data, publish accurate records of the halfway homes in the country, and ensure strict compliance with the various Guidelines for the rehabilitation of PwMIs that have been issued. It is crucial that the treatment and rehabilitation of PwMIs is enshrined in a rights-based approach that is centered around their autonomy and dignity. (ends)

Re: Need to increase Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) subsidy

DR. NAMDEO KIRSAN (GADCHIROLI-CHIMUR): In the past year, the average construction costs have increased by approximately 11%. This surge can primarily be attributed to a substantial rise in labor expenses, alongside a moderate escalation in the prices of construction materials. These factors have contributed to heightened operational costs for developers, compelling them to reevaluate their strategies. While rise in prices of key construction materials was relatively modest over the last year, labour costs have been driving the overall cost of construction upward. With labour accounting for more than one-fourth of overall construction cost, a 25% annual rise in labour costs has stretched construction budgets and impacted operational expenses. Moreover, the need for skilled labour and the associated costs for training, safety and regulatory compliance further adds to spiraling labour costs. The report indicates that the aggregate impact of price rise in four critical construction materials—cement, steel, copper, and aluminium—has been relatively subdued. Additionally, average cement prices have experienced a significant reduction of 15%, while average steel prices have decreased marginally by 1% over the past year. I, therefore request that the PM-Awas Yojana Subsidy may kindly be increased accordingly. (ends)

Re: Need to fix salary and allowances of Krishi Vigyan Kendra employees at par with those of ICAR and Central Agricultural University employees

SHRI S. SUPONGMEREN JAMIR (NAGALAND): The salaries and allowances of employees of Krish Vigyan Kendra (KVKs) may be fixed at par with those of employees of ICAR and Central Agricultural Universities.

(ends)

Re: Need to revise Standard Input Output Norms (SION) for regulating duty free import of natural rubber

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): I wish to bring to the attention of this Winter House the urgent need to revise the outdated SION Norms (standard Input Output Norms) governing the duty-free import of natural rubber. These norms, established in the 1970s, allow 44 kg of natural rubber per 100 kg of tyre production. However, the natural rubber content in tyres has drastically reduced to 18-20% today. Despite significant technological advancement, the norms have not been revised. As a result, more than double the necessary quantity of natural rubber is permitted for duty-free import, with only 50% of the imported rubber required to be exported. The remaining 50% is diverted to the domestic market, suppressing domestic rubber prices and causing severe financial distress to our rubber growers. Additionally, companies are making huge profits due to these outdated norms, further exacerbating the issue. The Rubber Board of India is mandated to conduct periodic reviews and update these norms, but no action has been taken in this regard. I urge the Government to direct the Rubber Board to immediately revise the SION Norms to reflect the current technological realities and protect the livelihood of natural rubber growers in the country.

(ends)

Re: Need to construct a rail over-bridge at Itki in Ranchi, Jharkhand

श्री सुखदेव भगत (लोहरदगा) : राँची के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इटकी रेल फाटक पर आवागमन में आम जनमानस को असुविधा हो रही है। ज्ञात हो कि यह सड़क भारत की सबसे पुरानी यक्ष्मा अस्पतालों में से एक अस्पताल को जोड़ती है। यह रेलवे फाटक झारखंड की राजधानी राँची की लाइफलाइन को सुचारू रखने की गति को अवरूद्ध / मंद करता आ रहा है।

आम जनमानस की सुविधा हेतु आवश्यक है कि इटकी रेल फाटक पर ओवरब्रिज के निर्माण की प्रकिया प्रारंभ की जाए।

(इति)

**Re: Stoppage of trains in Pratapgarh and Kaushambi districts of
Uttar Pradesh**

श्री पुष्पेंद्र सरोज (कौशाम्बी) : जनपद प्रतापगढ़ के परियावाँ व्यापारिक कस्बे में लखनऊ-प्रयागराज इंटरसिटी ट्रेन संख्या 14209/14210 तथा कानपुर प्रयागराज इंटरसिटी ट्रेन संख्या 14101/14102 का ठहराव तथा ग्राम बिसहिया में रेलवे ट्रैक के पास भूमिगत पार्किंग तथा लेवल क्रॉसिंग का निर्माण करना है। जनपद कौशांबी के सिराथू रेलवे स्टेशन पर कानपुर वाया प्रयागराज-मुंबई (लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट ट्रेन संख्या 04151/04152) का ठहराव करना है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य अत्यंत आवश्यक है कृपया पूर्ण करने के आदेश देने की कृपा करें।

(इति)

**Re: Need to review inclusion of Muzaffarnagar and Shamli districts in
National Capital Region**

सुश्री इकरा चौधरी (कैराना) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) क्षेत्रीय योजना 2021 को एनसीआर क्षेत्रों की आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। हाल के वर्षों में, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई जिलों को एनसीआर क्षेत्र में शामिल किया गया है। किसान और छोटे व्यवसाय मालिक इस समावेशन से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। वाहन स्क्रेपेज नीति जैसी नीतियां, जो दिल्ली जैसे शहरी केंद्रों में प्रदूषण को कम करने के लिए बनाई गई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में असमान रूप से प्रभाव डालती हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के शामली और मुजफ्फरनगर जिले में किसान और ईंट भट्टा संचालक पुराने वाहनों और उपकरणों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें अब अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है। ऐसे उपकरणों को बदलना एक बड़ा आर्थिक बोझ है, जहां आय कम होती है और विकल्प सीमित होते हैं। इसके अतिरिक्त, इन नव-शामिल जिलों के विकास के लिए आवंटित धनराशि में पारदर्शिता का अभाव है, और यह स्पष्ट नहीं है कि इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जा रहा है। सरकार को शामली और मुजफ्फरनगर जिलों के समावेशन पर पुनर्विचार करना चाहिए। विकास नीतियों को इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि वे ग्रामीण क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करें।

(इति)

Re: Need for a separate religion code to 'Saridharam' and 'Sarna Dharam' followed by Santhals and other tribals in various parts of the country

SHRI KALIPADA SAREN KHERWAL (JHARGRAM): As we know the Santhals are the largest homogeneous tribe of India and they are mostly inhabited in the States of West Bengal, Jharkhand, Odisha, Bihar, Assam and Tripura. The Santhals and other Adivasi communities profess and practice their own religion the "SARIDHARAM" and 'SARNA DHARAM" since time immemorial. Although the right to practice, profess and propagate our own religion is our Fundamental Right as per the Article 25 and 26 of the Constitution of India, yet the SANTHALS and other Adivasis have not been allotted separate religion code for 'SARIDHARAM" and SARNA DHARAM. I would like to mention here that the West Bengal Assembly has already introduced and approved a Bill as per 'Motion Under Parliamentary Rule 185' for allotment of Separate Religion Code for SARIDHARAM for Santhals and SARNA DHARAM for other Adivasis on 17th February, 2023. Therefore, in order to honour the religious sentiments of the Santhals and other Adivasi communities, I, strongly demand for allotment of a separate religion Code for the SARIDHARAM, and the SARNA DHARAM, and also demand for a separate Column for 'SARIDHARAM' and SARNA DHARAM in the Data Collection Form to be used in the forthcoming Census of India. (ends)

Re: Need to ensure protection of sensitive data of beneficiaries availing treatment under Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (ABPMJAY)

SHRI KIRTI AZAD (BARDHAMAN-DURGAPUR): I wish to raise the issue of patient privacy violations under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PM JAY). The National Health Authority (NHA) has been publishing personally identifiable information of beneficiaries on its websites, including full names, discharge dates, and treatment costs, accessible through basic searches. This practice violates the constitutional right to privacy under Article 21, as upheld by the Supreme Court in Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India. The publication of personal health data lacks legal backing under the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) or Health Data Management Policy (HDMP), which explicitly prohibits such disclosure without anonymisation. The success of the scheme can be achieved through anonymised and aggregated data, making such public disclosures unnecessary. Additionally, no informed consent is sought from beneficiaries, further contravening HDMP guidelines. Publishing this data not only fails constitutional tests of legality, necessity, and proportionality but also increases risks of data misuse and breaches. I urge the Government to immediately address this grave violation of privacy, ensure compliance with established legal and constitutional safeguards, and take necessary corrective measures to protect the sensitive data of millions of Indian citizens availing treatment under AB-PM JAY.

(ends)

Re: Need for synchronization of portals operated by Central Government and various State Governments to address the threat of cyber crime in the Country

SHRI ARUN NEHRU (PERAMBALUR): Cyber crime is real threat to the growth of the nation due to its scale and reach along with anonymity of the criminals. currently, the crime reporting structure for the citizens are in silos. The Union Government is operating a portal which doesn't synchronize with the State Government portal for filing of complaint and consequent follow-up. Law and order is a State Government subject and it's imperative that the Central Government educates and redirects the complaints to its correct jurisdiction quickly and take effective steps for solving this serious issue.

(ends)

Re: Need to curb pollution caused by transportation of coal and iron ore at Visakhapatnam Port, Andhra Pradesh

SHRI SRIBHARAT MATHUKUMILLI (VISAKHAPATNAM): Despite the pollution-control measures implemented by ports in Visakhapatnam, residents continue to wake up to find their homes coated with black dust. A major source is the handling, stacking, and transportation of coal and iron ore. The average concentration of PM2.5 in Vizag exceeds the national average and is 10 times higher than WHO standards. This poses a serious threat to the respiratory health of the city's residents. I request an immediate action plan to conduct a long-term comprehensive study, including comparative analyses with other port cities, engaging local stakeholders and experts to identify causes and effects of dust pollution on the local community and public health in Visakhapatnam. Additionally, it is essential to ensure that ports adhere to the regulations set by APPCB and NGT including implementing a semi-automatic tarpaulin coverage system for cargo transportation, exploring the use of tube conveyor systems, stringent monitoring and evaluating feasibility of chemical spray among others. Further, Government can consider funding ports to construct covered cargo storages and explore redesigning rolling stock to facilitate covered transportation of coal instead of relying on open wagons, with complete transition towards container cargo handling as a long-term goal. Ultimately, public health must be prioritised at all costs.

(ends)

**Re: Need to establish a Handicraft Training Institute at Harnatand in
Valmikinagar Parliamentary Constituency**

श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर) : मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वाल्मीकिनगर के हरनाटांड में हस्तशिल्पकार केंद्र की स्थापना के सम्बन्ध में आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र थारू तथा उराव जन जाती के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं, ये लोग अधिकांश जंगल से घिरे भू-भाग में रहते हैं, तथा अपनी आजीविका के लिए तरह-तरह के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। थारू तथा उराँव समाज की महिलाएँ हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में अधिक अनुभवी हैं तथा इस क्षेत्र में अपना अहम् योगदान कर सकती हैं। इस समाज की बेटिया तथा महिलाएँ अपने पूर्वजो द्वारा सिखाई गई कला पर ही आधारित हैं। यदि इनकी कला को दिखाने हेतु जरूरी कदम उठाए जाये तो ये बेटिया तथा महिलाएँ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर सकती हैं तथा इस जनजातीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूँ कि वाल्मीकिनगर लोकसभा अंतर्गत थरुहट की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध हरनाटांड में एक हस्तशिल्प प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना यथा शीघ्र की जाय।

(इति)

**Re: Need for CBI inquiry into the increasing criminal activities in Beed
district, Maharashtra**

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे (बीड) : 9 दिसंबर को दोपहर 3 बजे, संतोष देशमुख, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र बीड के मस्साजोग ता.केज गांव सरपंच पति थे, का अपहरण कर लिया गया। देशमुखजी की लाश शाम 6 बजे मिली। इस बात के स्पष्ट संकेत मिले हैं कि उन्हें बेरहमी से टॉर्चर और प्रताड़ित किया गया था। देशमुखजी गांव के विकास के लिए किए गए अपने काम के लिए सम्मानित थे और उनका निधन बहुत दुख का कारण है। दूसरी घटना पुलिस थाना परली (वै), जि. बीड के एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन अमोल डुबे जिनका अपहरण करके 2 करोड़ रुपये फिरोती की मांग की गयी। 90-95 लाख फिरोती वसूलकर उसे बीच रास्ते छोड़कर भाग गये। यह बढ़ती घटनायें बीड जिले की कानून व्यवस्था की तेजी से बिगड़ती हुई स्थिति का संकेत हैं और यह आवश्यक है कि इन सभी दुर्घटनाओं की जल्द से जल्द CBI जांच की जाए।

(इति)

Re: Need to take steps for timely completion of Inland Passenger Water Transport System in Maharashtra

श्री नरेश गणपत म्हरके (ठाणे) : महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड(एमएमबी) ने मुंबई महानगर क्षेत्र(एमएमआर) के दूरदराज के नागरिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए अंतर्देशीय यात्री जल परिवहन प्रणाली के कार्यान्वयन की योजना बनाई है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना भायंदर, कोलशेत, कल्हेर और डोंबिवली में चार जेटी के निर्माण के माध्यम से मीरा-भायंदर, ठाणे, भिवंडी और डोंबिवली को जोड़ेगी। वसई क्रीक-उल्हास नदी पर संचालित यह प्रणाली पूर्व-पश्चिम संपर्क को सुदृढ़ करेगी, जिससे एमएमआर में बढ़ती आबादी और यात्रा पैटर्न को पूरा किया जा सकेगा। चार जेटी का निर्माण डेढ़ साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है, जिसकी अनुमानित लागत 96.12 करोड़ रुपये है। यह राशि सागरमाला योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी। यह परियोजना क्षेत्र के यातायात दबाव को कम करने, समय की बचत करने और पर्यावरण अनुकूल आवागमन प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि, वित्तीय चुनौतियों के कारण इस प्रणाली के कार्यान्वयन की गति धीमी रही है। मेरा माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री जी से आग्रह है कि वे इस अति महत्वपूर्ण परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करें। यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति प्रदान करेगी।

(इति)

Re: Need to set up a bench of Allahabad High Court at Meerut, Uttar Pradesh

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : आज मैं आपके समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के न्याय पाने के अधिकार से सीधे जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट, प्रयागराज की एक खंडपीठ मेरठ में भी होनी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रयागराज से बहुत अधिक दूरी पर स्थित होना एक बड़ी समस्या है। न्याय पाने के लिए लोगों को सैंकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी होती है। वकीलों और स्थानीय लोगों द्वारा लगातार इस मांग को उठाया जा रहा है। वे कहते हैं कि मेरठ में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित होने से न्यायपालिका अधिक सुलभ होगी और लोगों को त्वरित न्याय मिल सकेगा। मेरठ में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने में निम्नलिखित लाभ होंगे:

- न्याय का त्वरित निपटारा: लोगों को न्याय पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
- आर्थिक बोझ में कमी: लोगों को न्याय पाने के लिए दूर-दराज के इलाकों में जाने के लिख खर्च नहीं करना पड़ेगा।
- विकास को बढ़ावा: मेरठ में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित होने से क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार के अवसर बहेंगे।

अंत में, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह मेरठ में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाए। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक लंबे समय से चली आ रही मांग है और इसे पूरा करना सरकार का नैतिक दायित्व है।

(इति)

**Re: Need to provide compensation for land acquisition for
Greenfield National Highway No. 744 as per the terms and
conditions applied to N.H. 66**

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The development of NH 744 Greenfield Highway is standstill due to delay in completion of land acquisition process. This is due to the delay in decision regarding the share of State Government and GST, loyalty exemption. The compensation is not yet disbursed till date. The undertaking for apply the same terms and condition of land acquisition of NH 66 to NH 744 also not materialized. Now orders were issued to calculate the compensation of building on the basis of its age. It is not in tally with the term applicable to NH 66. There is difference in calculation of salvage value also. The land acquisition with regard to two villages are kept idle due to change in alignment. Hence I urge upon the Government to apply the same terms and conditions applied for fixing the compensation for land acquisition of NH 66 to the Green Field National Highway 744.

(ends)

अनुपूरक अनुदानों की मांगें

1404 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, अब सभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगें - पहला बैच 2024-25 को चर्चा तथा मतदान के लिए लिया जाएगा।

अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर श्री सुधाकर सिंह एवं श्री हनुमान बेनीवाल के कई कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं। यदि माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्ची भेज दें, जिसमें उस कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्या लिखी हो, जिसे वे प्रस्तुत करना चाहते हैं।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात् नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि माननीय सदस्य उस सूची में कोई विसंगति पाते हैं तो वे कृपया इसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर मौजूद अधिकारी को दे दें।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 8, 10, 11, 13 से 21, 23 से 38, 43 से 54, 56, 57, 60 से 62, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 74, 76 से 79, 81, 83, 85 से 87, 89 से 95 और 97 से 102 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।”

श्री के. सी. वेणुगोपाल जी।

(1405/RCP/NK)

1405 hours

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you Chairperson, Sir for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Supplementary Demands for Grants and the Appropriation Bill. Reality has a way of asserting itself. Despite all the propaganda in the world, what is the reality of our economy? Whenever Supplementary Demands for Grants are taken up, I think, the hon. Finance Minister's presence is very much required because we are going to pass the Supplementary Demands. The hon. Finance Minister is not present here. Then, what is the point in discussing?

HON. CHAIRPERSON (SHRI DILIP SAIKIA): The State Finance Minister is present here.

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I am talking about the Cabinet Minister. When SDGs happen, according to my priorities, the FM will be there.

What is the reality of our economy? Our economy is deeply in trouble and it warrants an urgent action and attention. The data and the trends emerging from recent months highlight serious challenges affecting the Indian economy. There are challenges affecting workers, business persons and more particularly our common people. The challenges are created by policy missteps and a lack of strategic action from the Government to address the current crisis.

Let us see the GDP growth rate. Everybody knows that now the GDP growth has fallen down to 5.4 per cent. This Government every time is telling us about the tall promises of GDP that they will increase the GDP. This serious slowdown underlines the fragility of our economic recovery. This also puts serious doubts on the Government's unrealistic claim of double-digit growth and inflation control.

Decline in wages is one of the most alarming situations in this country now. A study conducted by FICCI and Quesada Corp Ltd., reveals a grim reality. Wages in key sectors like IT, retail, logistics, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), banking and engineering have not risen significantly over the past few years. Basically, the wages are same or similar to the wages that we had 10 years before. When adjusted for inflation, the real wages have either stagnated or declined. This is leaving the people with a reduced purchasing power and in turn it is reducing the domestic demand. In rural India, the situation is worse.

Over the past five years, the real wages have fallen by 0.4 per cent. Agricultural wages have grown by a meagre 0.2 per cent. For the first five months of this year, the whole wage growth was a meagre 0.5 per cent and in agriculture it was just 0.7 per cent. These figures are alarming. Nearly half of our work force is engaged in agriculture. A majority of non-farm employment is informal and low-paying in our country. Even the corporate sector reflects this grim trend. Between 2019 and 2023, the wage growth across major industries ranged from a meagre 0.8 per cent in engineering and manufacturing to 5.4 per cent in FMCG.

In contrast, the corporate profits have multiplied. Wages have come down but the corporate profits have multiplied. This is what is happening in this country nowadays. Rich people have become richer, but poor people have become poorer. The toxic work culture in many of the corporate companies is not the concern of the Government at all. Earlier, Shri Hibi Eden raised this matter in the Zero Hour. I do not want to repeat it. The Government is not taking any action on these things.

The Prime Minister talked about two crore jobs per year. He has been telling us about this since 2014 onwards. Now, 10 years are already over. Sir, 20 crore jobs could have been created. How many jobs have been created?
(1410/PS/SK)

Not only the creation, but also the ability to generate quality jobs is the heart of this crisis. The inability to provide quality jobs is the major issue in this sector. The workforce participation has risen from 49.8 per cent to 60.1 per cent. The workforce participation has increased very much. People are available and they are searching for jobs. But the jobs that are being created, are neither well-paying nor productive at all. According to the Government's quarterly Periodic Labour Force Survey (PLFS) released last month, during July-September, the unemployment rate in the urban areas is 6.4 per cent.

Sir, the hon. LoP has rightly pointed out in his speech that instead of creating jobs, you are cutting the thumbs of the small businesses and MSMEs, and you are even crushing the dreams of millions of youths in the country. Therefore, the share of export of MSME specified products in all India exports in February, 2024 was 45.7 per cent. That sector is completely disturbed. A decline in consumer confidence is also a serious issue which has to be looked into.

The rural India is crying nowadays. MGNREGA is affected very badly. I myself raised a question during the Question Hour about the deletion of employees in MGNREGA, which has not been properly replied at all. MGNREGA is one of the best tools for encouraging the economic sector at the lower level, which has not happened so far.

Sir, inflation is skyrocketing. Vegetable prices have increased by a staggering 42.2 per cent in October, reaching a 57-month high. The prices of edible oil spiked by 9.5 per cent. The increase in cost of daily essential commodities continues to erode the savings and purchasing power of the common man, which is very detrimental.

Day before yesterday, the hon. Prime Minister talked about 'Viksit Bharat' and everything. What is the poverty rate of this country nowadays? Where are we standing in the global scenario? I will tell you about the latest update of the Global Multidimensional Poverty Index (MPI) which was released last month by the United Nations Development Programme and the Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). We have 234 million people living in poverty in India, which is medium Human Development Index, placing our country among five globally, with a largest number of people living in poverty. They are telling us about Viksit India.

Sir, now, I come to attack on federalism. Every State has a right to have an equal share from the Union Budget. Now, what is happening? Every time, the State of Kerala is crying. Now, they are asking for VGF for the Vizhinjam port also. The State of Karnataka has written letters to the Government of India several times. The State of Karnataka has faced a significant financial setback losing Rs. 1,87,867 crore since 2017-18 due to the step-motherly treatment by the Central Government. The State of Karnataka's share of Central taxes has been reduced from 4.71 per cent in the 14th Finance Commission to 3.64 per cent. This is the same case with the States of Kerala, Himachal Pradesh, Telangana, and other States. Wherever the Opposition is ruling, the Government is having a step-motherly attitude towards those States. This is a very serious concern.

Now, I come to natural calamities. This morning and day before yesterday also, an hon. Member from Wayanad and other hon. Members from the State of Kerala, have raised the issue of natural calamity. Five months have passed.

Significant measures have been taken to create a sense of security and support to people who have lost their entire families. The hon. Member from Wayanad narrated about that incident very emotionally.

(1415/SMN/KDS)

After a period of five months, the Union Government is not releasing the special assistance to that State. We, all the MPs, met Amit Shah Ji who is looking after disaster management. After that, the State Government of Kerala got a letter from the Home Minister. In that letter, it is stated that they have sent Navy during disaster; and we have sent other forces. These are the common things which the Central Government has to do.

Now, the Central Government did not give any special package for Wayanad. But the Union Government asked the State Government to settle the airlifting charges which is Rs. 130,61,98,003. On the one side, hon. Home Minister is telling them that we have sent Navy and everything and on the other side, now, the Government of India is asking those expenses from the State Government of Kerala. This is very unfortunate. ... (*Interruptions*)

Yesterday, you spoke for one hour and ten minutes. You have not even allowed us to yield for one second, brother.

Now, I am coming to an important issue. In our financial system, the regulatory bodies are having a crucial role. In our country, 11 crore people are depending on stock markets. Most of them are from middleincome group of this country.

Sir, the Security and Exchange Board of India (SEBI) is entrusted with the task of safeguarding the hard earned money of the Indian middle-class. Basically, the SEBI comes under the Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance. It operates under the responsibility of the Ministry to ensure the regulators' integrity.

Under the Seventh Schedule of the Constitution, it is very clear. As per the Seventh Schedule of Constitution, the Government of India holds exclusive powers to regulate the Indian stock markets. Any lapse or misconduct within SEBI is a direct reflection on the Finance Minister's part or the Central Government's part.

Who is selecting the SEBI Chairperson? The Secretary, Department of Economic Affairs which functions under the Ministry of Finance, is a part of the

financial sector regulatory appointment committee who selects the SEBI, Chairperson. This Committee is tasked with selecting the SEBI Chairperson and its wholtime Members. It means the Finance Ministry is directly responsible for ensuring that an individual with unimpeachable integrity and ethical standards to be appointed to this crucial regulatory body.

Sir, what happened with the SEBI Chairperson? Several serious allegations have surfaced against the SEBI Chairperson indicating a severe breach of ethical and regulatory standards.

Through you, Sir, I am informing the House. Between 2017-2024, Ms. Buch allegedly received over Rs. 16 crore from ICICI bank while serving as Chairperson of SEBI, responsible for regulating that banking. This amount was five times more than her salary from SEBI, presenting a blatant conflict of interest.

Number two, she received Rs. 2.16 crore rental income from entities linked to a company under SEBI's investigation. What does it mean? The SEBI is investigating a company. The Chairperson has rented an office to that company.

The Chairperson allegedly traded in listed securities worth Rs. 36.9 crore while holding access to unpublished price sensitive information, a direct violation of SEBI's code of ethics.

(1420/RP/MK)

For she failed to disclose assets in Singapore and the USA between 2017 and 2021 despite being obligated to do so. Payment from six listed entities, including Rs. 2.59 crore from the Mahindra group were funnelled through Agora Advisory Private Limited, a company she claimed was dormant but in which she retained a 99 per cent stake.

Sir, despite these revelations, the Finance Minister neither initiated an independent inquiry nor taken any disciplinary action. We all know why it is not done. This inaction undermines the Government's claim of transparency and commitment to investor confidence. The Finance Minister is not here. But, I want to ask her a direct question. You know, you are an experienced Member. Whenever the Supplementary Demands for Grants is taken up, the hon. Finance Minister is supposed to be here. The Finance Minister's speech is over in the

other House. ... (*Interruptions*) The leader of the other House is already there, Nadda ji.

HON. CHAIRPERSON (SHRI DILIP SAIKIA): Two State Ministers are sitting here.

... (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, through you, I want to specifically ask six questions to the Finance Minister.

The first question is, why has the Finance Ministry not initiated any disciplinary or legal proceedings against the SEBI Chairperson despite clear evidence of a conflict of interest that undermines the integrity of the regulatory body? The second question is, what criteria or assessment has been applied to justify allowing the current SEBI Chairperson to continue in her role despite allegations that may erode public and investors' trust in India's financial regulatory framework? The third question is, does the Finance Ministry acknowledge and take responsibility for the damage caused to investor confidence, both domestic and foreign, due to the lack of timely action against the SEBI Chairperson in light of the serious allegations? The fourth one is, can the Finance Minister clarify whether the Government is willing to accept responsibility for the uncertainty and volatility in the stock markets stemming from the alleged conflict of interest involving the SEBI Chairperson? The fifth one is, what step does the Finance Ministry intend to take to ensure transparency and accountability in SEBI's leadership, particularly, in light of recent allegations that may harm India's financial ecosystem? The sixth one is, does the Ministry believe that retaining a Chairperson under such circumstances sends the wrong signal about India's commitment to corporate governance and regulatory transparency?

Sir, the Finance Minister's failure to act decisively not only tarnishes the credibility of the Government, but also jeopardises the national financial governance framework. What is the conflict of interest of the Government and the SEBI Chairperson? Why is the Government not taking any action? I also went thoroughly, and thought about it. Everybody in this country has the same thinking. Why are such allegations coming against the Chairperson? Why is the Government not taking any action? For whom? Are they not taking any action? This question is in the public domain. Everybody knows that only one answer is

there. There is no action at all because of one person. Sir, you can see that. That is the whole story. There is already a report in the public domain. Sir, the name of one biggest business group, Adani Group is figured for the stock manipulation and accounting fraud. Shockingly, SEBI Chairperson had personal stakes in offshore entities used in the Adani money scandal. How can she investigate a scandal which she is a part of? This is the greatest irony, Sir. What is this Government doing? I want to talk about the poverty rate of this country. That is increasing day by day. People are becoming poorer and poorer.

(1425/NKL/SPS)

But one man is getting everything in this country.

Sir, according to a latest report, there is an Adani Port or a terminal every 500 kilometres along the country's coastline. This country has 7,516 kilometres long coastline, and at every 500 kilometres, either there is an Adani Port or a terminal. ... (*Interruptions*) Their company runs seven airports. ... (*Interruptions*)

Sir, if we talk about our economic policies, assets, foreign policies – everything is rooted for one man. ... (*Interruptions*) Now, it is high time. ... (*Interruptions*) Now, it is high time that we call this dubious crony capitalist Government.

Sir, I am sorry to say in this Parliament that this Government has basically become of Adani, by Adani, for Adani. ... (*Interruptions*) This Government has become that. Otherwise, why are you worried to take action? You need credibility for the stock market. You need to protect the interests of the people who are investing in stock markets. You are not taking any action. ... (*Interruptions*) You are not taking any action. Why are you scared to take action? I think, this is the biggest question arising in the public domain nowadays.

Sir, we would like to ask the hon. Finance Minister whether the hon. Finance Minister is going to conduct an inquiry, or ask the Parliament to have a JPC to inquire into all these things. We asked for the JPC inquiry several times. The JPC is going to be headed by you people only. Now, you have majority. At least, the Members of the JPC have to understand as to what is going on in this stock market system; what is going on through the SEBI activities. I am not questioning any Member's integrity. Every individual has his own integrity on that side also. But this case, for the last several months, has been clearly creating doubts in the minds of the common people that why this person, even though he

is having a lot of allegations resulting to stock market crash, is being allowed to continue. I think, you cannot answer this question now. But this country needs an answer. ... (*Interruptions*) It is because there are crores and crores of people who are investing in this system. ... (*Interruptions*) At least, there should be a JPC inquiry. ... (*Interruptions*) I want this House and the public to know whether the Government is going to conduct a JPC inquiry. At least, give a reply. ... (*Interruptions*)

Sir, I do not want to take much of your time. That is why I told you that the atmosphere is spreading that this country's entire monopoly is being given to one individual. If somebody is bringing that issue into the public domain, you try to abuse him. You try to abuse him as you want. At the most, you defame him. In your social media group, that work has been going on for the last so many years. We are not worried about that. Whenever we question the person who is creating problems for our country, you people do not allow us to raise questions. In this Parliament also, several times, we talk about that but the name itself is removed. Why are you scared? What is your relation to that person? The country needs to know, Mr. Kiren Rijju ji. Why are you giving this much of importance to a particular person? ... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION; AND MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PRALHAD JOSHI): What about Shri Revanth Reddy?

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Shri Revanth Reddy refused to accept Rs. 100 crore. You do not know about that. ... (*Interruptions*) Shri Revanth Reddy also comes under the ambit of the Centre. If any such thing is there against him, you investigate, brother. Who has stopped you to investigate? ... (*Interruptions*) If any such thing is there against Shri Revanth Reddy, Yediyurappa or anybody else, please investigate. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI DILIP SAIKIA): Venugopal ji, please address the Chair.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Venugopal ji, please address the Chair.

... (*Interruptions*)

(1430/VR/MM)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I am concluding my speech in a minute.(*Interruptions*)

Sir, this is a discussion for Supplementary Demands for Grants.(*Interruptions*) The Government is asking money from us.(*Interruptions*) The Government is asking money from the Parliament.(*Interruptions*) The Government is before the Parliament for getting the Supplementary Demands for Grants passed.(*Interruptions*)

Sir, the country should know what action the Ministry of Finance and the Economic Affairs Department have taken against that person.(*Interruptions*) Why are you not taking any action?(*Interruptions*) For whom are you not taking action?(*Interruptions*) This is a great concern of this country.(*Interruptions*) Lack of accountability weakens democracy and creates fertile ground for corruption.(*Interruptions*) So, this should be stopped by this Government.(*Interruptions*) With these words, I am concluding my speech. Thank you, Sir.

(ends)

TEXT OF CUT MOTIONS

SHRI SUDHAKAR SINGH (BUXAR): I beg to move:

(TOKEN)

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY (PAGE 28) BE REDUCED BY RS. 100. **25**

1. Need to provide permanent building for the Kendriya Vidyalaya at Buxar in Bihar.
2. Need to open a Kendriya Vidyalaya at Kaimur in Bihar.

(TOKEN)

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE (PAGE 31) BE REDUCED BY RS. 100. **28**

3. Need to clean and develop Gokul Jalashay (Wetland) to provide clean drinking water to people of Buxar in Bihar.
4. Need to protect Kaimur Hills to maintain the ecological balance of the area and also to benefit tribal population.

(TOKEN)

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (PAGE 66) BE REDUCED BY RS. 100. **60**

5. Need to decongest traffic by providing new and smooth access roads around New Ashok Nagar Rapid Rail Transit (RRTS) station in Delhi.

(TOKEN)

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD MINISTRY OF RAILWAYS (PAGE 90) BE REDUCED BY RS. 100. **85**

6. Need to provide stoppage of Ranchi Rajdhani Express (12439), Nandan Kanan Express (12815), Agra Kolkata Express (13167), Jaisalmer Howrah Express (12371), GKP Shalimar Express (15021) and Kolkata Amritsar Express (12357) trains at Bhabhua Road and Mohaniya railway stations.
7. Need to tackle congestion and ensure regulation of vehicular traffic movement around Delhi Cantonment railway station.
8. Need to ensure proper sanitation and civic amenities in and around Delhi Cantonment railway station.

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरें रिजिजू) : फाइनेंस मिनिस्टर राज्य सभा में हैं, क्योंकि वहां एलओपी बोल रहे हैं और यह कनवेंशन है कि अगर एलओपी बोलते हैं तो उनको सुनना पड़ेगा, इसलिए वे वहां बैठी हैं। एमओस, फाइनेंस सभी बातों को नोट कर रहे हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग भी सुन रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप जिस आदमी की बार-बार बात कर रहे हैं, मोदी जी ने या हमने, किसी ने उनको करोड़पति नहीं बनाया है।... (व्यवधान) हम लोगों ने यूनिर्कोर्न बनाए हैं। हम लोगों ने स्टार्टअप्स बनाए हैं, स्टैंड अप को लेकर आए हैं। ... (व्यवधान) यूनिर्कोर्न्स हम लोगों के समय में ही पैदा हुआ है। ... (व्यवधान) आप जिनका नाम ले रहे हैं, सारा पोर्ट और एयरपोर्ट का बिजनेस आप लोगों ने ही उनको दिया है। ... (व्यवधान) ख्वामख्वाह हम लोगों को आप बदनाम मत कीजिए। ... (व्यवधान) इस देश में बहुत सारे उद्योगपति हैं जो आप लोगों के समय में पैदा हुए हैं। ... (व्यवधान) यहां इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. संजय जायसवाल जी।

1432 बजे

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : सभापति महोदय, वित्त मंत्रालय द्वारा रखे गए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, के.सी. वेणुगोपाल जी का भाषण मैं बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। मुझे पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र जीवन इनके भाषण से याद आ गया। मेरे यहां सर्जरी के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रो. मोतीलाल सिंह जी। इसी तरह से जब कोई बात करता था तो वह यह जरूर कहते थे – बाबू! तुम अंग्रेजी तो बहुत बोले, लेकिन थोड़ा सर्जरी भी बोल लेते तो बहुत अच्छा होता। इन्होंने एक शब्द सप्लीमेंटरी डिमांड फोर ग्रांट्स के बारे में नहीं बोला कि 44000 करोड़ रुपये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। In his whole speech there is not even one word on Supplementary Demands for Grants.(Interruptions) I am not yielding.(Interruptions) You have not said even one word whether the demand for Rs. 44,000 crore is genuine or not.(Interruptions) आपने बहुत अच्छी अंग्रेजी बोली, बहुत सारी बातें बोलीं, लेकिन एक शब्द सप्लीमेंटरी डिमांड फोर ग्रांट्स के बारे में बोल देते तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता। यह कोई नई बात नहीं है, उधर से सभी को ऐसे ही बोलने की आदत है। अभी हम संविधान पर भी चर्चा सुन रहे थे तो एक सांसद महोदय ने अपनी मैडन स्पीच में बोला कि छोड़िए नेहरू जी को कि उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया मुझे यह बताइए। मुझे कम से कम इतनी खुशी है कि कांग्रेस की तरफ से यह स्वीकारोक्ति आ रही है कि नेहरू जी ने बहुत सारी गलतियां कांग्रेस के राज में की थीं। मोदी जी ने क्या किया, इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि हम लोग वर्ष 2024-25 में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में गरीबों और देश के किसानों को दे रहे हैं। वर्ष 2021-22 में हम लोगों ने 7 लाख 57 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी और इतना ही नहीं, यह जो कह रहे हैं कि राज्यों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, हमने पांच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राज्यों को सेंटर स्पोसर्ड स्कीम में दिया है। इनके सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट प्रधान मंत्री के जमाने में इनका बजट जितना होता था, उतनी तो हम सब्सिडी भी दे रहे हैं और राज्यों को भी दे रहे हैं। लेकिन अंतर एक ही है कि उस समय के जो माननीय प्रधान मंत्री थे, उस समय यूपीए था अब वह इंडी गठबंधन हो गया है, उस समय के प्रधान मंत्री से जब भ्रष्टाचार के बारे में पूछा जाता था, क्योंकि बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए जाते थे, तो वह कहते थे कि गठबंधन धर्म की मजबूरियां होती हैं, जबकि हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रहेगा। यह अंतर एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं में है।

(1435/YSH/SAN)

सभापति महोदय, हमें आज 10 साल हो गए हैं, लेकिन ये लोग किसी भी केन्द्रीय मंत्री पर एक रुपये का भी भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं लगा सकते हैं। यह हमारी सच्चाई है। ... (व्यवधान) ये किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। इनकी हालत यह थी कि इन्होंने अपने गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर 'इंडी' रख लिया। उसका एकमात्र कारण यह है कि पूरा देश जानता था कि यूपीए और भ्रष्टाचार पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं। इसलिए इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अपने गठबंधन का नाम बदल दिया। हमारे यहां पर भोजपुरी में एक कहावत है : 'सियरा उहे बा, रंग बदलले बा' अर्थात्, The fox is same; it has only changed its colour.

आज इनके गठबंधन का नाम इंडी गठबंधन हो गया हो, लेकिन हालत वही है। आज भी अगर भ्रष्टाचार का किस्सा आता है तो या तो पश्चिम बंगाल से आता है या कर्नाटक से आता है। अभी हमें 10-11

साल सत्ता में हो गए हैं, लेकिन फिर भी जहां से भी भ्रष्टाचार उभरता है, किसी न किसी इंडी गठबंधन के ही प्रदेश से उभरता है। यह इस देश की एक विडंबना है।

आज हम लोगों के खिलाफ एक और नेरेटिव हर जगह चलाया जाता है। वह नेरेटिव है कि आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अगर हमारे माननीय नेता सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पढ़ लिए होते कि उसमें क्या लिखा हुआ है तो उनको यह पता रहता कि उनके जमाने में जितना कृषि मंत्रालय का बजट होता था, उतना हम अभी किसानों के लिए इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में एक्स्ट्रा मनी मांग रहे हैं। हम अभी लगभग 25 हजार करोड़ रुपये मांग रहे हैं। हम लोगों ने इस देश के किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से 3 लाख 46 हजार करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से कैश दिए हैं और यह 3 लाख 46 हजार करोड़ रुपये की पूरी राशि किसानों को दी गई है। यह वह राज नहीं है कि मैं एक रुपये भेजता हूँ तो लोगों के पास 15 पैसे जाते हैं।

अगर मोदी जी ने 3 लाख 46 हजार करोड़ रुपये भेजे हैं तो एक-एक किसान को वह पैसा मिला है। उसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यह हमारी सरकार का काम है। इसी तरह से हम लोगों ने इस सरकार में, मोदी 3.0 में 14 हजार 235 करोड़ रुपये की सात योजनाएं किसानों के कल्याण के लिए स्वीकृत की है। यह हमारी पहचान है। एमएसपी में 10 वर्षों में हमने रिकॉर्ड वृद्धि की है, यह हमारी पहचान है। लेकिन दिक्कत एक ही है कि ये लोग इस पर क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि इनके किसी भी नेता को सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट, जो कि 203 पेज का है, उसे पढ़ने के लिए इतनी ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी कि उसकी गर्मी से शरीर को आग लग जाने का भी खतरा हो सकता है। इसलिए ये लोग सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट नहीं पढ़ते हैं। हम यहां पर वर्ष 2009 से देख रहे हैं कि पहले नेताजी कुर्ता-पायजामा पहनते थे, लेकिन फिर जब मोदी जी की पहली सरकार आई, दूसरी सरकार आई, तीसरी सरकार आई तो तपस्या से इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ी कि अब दिसम्बर में भी टी-शर्ट पहनते हैं और मोदी जी की चौथी और पांचवीं सरकार आना निश्चित है तो उस समय क्या होगा, उसके लिए मैं अभी न बोलूँ तो ज्यादा बेहतर होगा।

सभापति महोदय, आज इनकी यह हालत है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वित्तीय घाटे को काबू करने के लिए बजट के समय 5.1 परसेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट की बात की थी, उसे अब 4.9 परसेंट कर दिया गया है। यह बताता है कि यह सरकार कितने अच्छे ढंग से वित्तीय प्रबंधन कर रही है।

सभापति महोदय, मैं इस सप्लीमेंट्री डिमांड में जो रेयर हेल्थ डिजीजेस के लिए 317 करोड़ रुपये अलग से दिए हैं, उसके लिए रेयर हेल्थ डिजीजेस से सफर करने वाले सभी मरीजों की तरफ से इस सरकार को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि दुनिया की एक तिहाई रेयर हेल्थ डिजीजेस हमारे देश में होती हैं। वैसे ही हेल्थ रिसर्च के लिए जो 89 करोड़ रुपये की राशि सप्लीमेंट्री डिमांड में दी गई है, यह भी बहुत अच्छा फैसला है।

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए 128 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई है, वह भी यह बताती है कि यह सरकार कितनी संवेदनशील है।

सभापति महोदय, वर्ष 2020-21 में जब पूरा विश्व आर्थिक व्यवस्था से लड़खड़ा रहा था, उसके बाद हम उठकर दुनिया के बड़े राष्ट्रों में सबसे तेज इकनॉमी से बढ़ने वाले राष्ट्र बने। यह इसी जनता के अटूट विश्वास से खरा उतरने का मोदी मैजिक है। इसी कारण हम लगातार तीन बार पूर्ण बहुमत के साथ

सरकार बना रहे हैं। यही एक कारण है कि हमारे साथी कांग्रेस के जो सांसद हैं, वे भी लगातार तीन बार डबल डिजिट में आ रहे हैं। तीन बार से ये आज तक थ्री डिजिट में नहीं आ सके।

(1440/RAJ/SNT)

मैं इस बार एक परिवर्तन जरूर देख रहा हूँ कि माननीय सांसदों की डबल डिजिट में संख्या होने के बावजूद भी ये लोग इतने खुश और जोश-जज्बे से भरे हुए हैं कि मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये हमेशा डबल डिजिट में रहें, जिससे इनका जोश और जज्बा हमेशा बरकरार रहे, एकदम बिल्कुल बरकरार रहे।

एक डर है कि जिस तरह से आज कल इंडी गठबंधन में चल रहा है और इनके लीडरशिप पर क्वेश्चन हो रहा है, कहीं ऐसा न हो कि गठबंधन के लोग... (व्यवधान), सुप्रिया जी बोल ही चुकी हैं कि टीएमसी के ममता जी पर विचार किया जाए। आरजेडी भी बोल रही है कि ममता जी पर विचार किया जाए... (व्यवधान) धर्मेन्द्र जी भी बोलते रहते हैं। अगर सभी लोग भाग गए तो यह कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट में आ जाएगी। अभी यह रीजनल पार्टिज की कृपा से किसी तरह डबल डिजिट हो पाए हैं।

सभापति महोदय, मुझे बस इतना ही कहना है कि कभी भी काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। यही नतीजा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में लोक सभा चुनाव के नतीजे इनके लिए कुछ अच्छे हुए, लेकिन तीन महीने में ही जनता ने इनकी हकीकत को समझ लिया और हरियाणा और महाराष्ट्र से रिकॉर्ड मतों से इनको बाहर करने का काम उसी जनता ने किया है, जो लोक सभा चुनाव के समय उन राज्यों में दूसरा परिणाम लिखा था।

सभापति महोदय, जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, तो यह भी जरूर लिखा जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भारत कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बन रहा था, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट प्रधान मंत्री जी ने आकर, अपने कार्यकाल समाप्त होते-होते तक उसको सबसे निचले पायदान पर पुनः खड़ा कर दिया। यह भी लिखा जाएगा कि कैसे एक गरीब चाय वाले ने अपने तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत को बनाने के लिए लगातार मेहनत करके सफलता के उस मुकाम को हासिल किया।

सभापति महोदय, इस वर्ष हम 48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इसके लिए चाहे वह जीएसटी हो, मुद्रा योजना, जन-धन खाता, डीबीटी और सबसे ऊपर माननीय प्रधान मंत्री जी का यह विश्वास कि अगर हम अपने युवाओं, महिलाओं को समुचित अवसर देंगे, तो 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी सेल्फ हेल्प बहनें हैं। आज एक करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन चुकी हैं। प्रधान मंत्री जी ने तीन करोड़ का वादा किया था, हम उसे भी अचीव करने जा रहे हैं।

बिहार जैसे पिछड़े राज्य में भी जीविका की बहनों ने एक ऐतिहासिक काम किया है। बिहार के एक माननीय सांसद के रूप में मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि यूपीए ने 10 वर्षों में जहां बिहार को केवल 75 हजार करोड़ रुपए ग्रांट के रूप में दिए थे, वहीं माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बिहार को 2 लाख, 81 हजार करोड़ रुपए ग्रांट के रूप में मिले हैं। यह बताता है कि प्रधान मंत्री जी न केवल अंतिम व्यक्ति के लिए संवेदनशील हैं, बल्कि जो इंडी गठबंधन का एक घटक आरजेडी है, जिसके वर्ष 1990 से वर्ष 2005 के राज में बिहार की स्थिति वर्ष 1947 के बिहार जैसी हो गई थी।

उसके लिए वे कितने संवेदनशील हैं, उसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ एवं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

आज से सवा सौ साल पहले एक नरेन्द्र ने अमेरिका में यह भविष्यवाणी किया थी कि अगली सदी भारत की होगी और दूसरा नरेन्द्र इस देश का प्रधान मंत्री बन कर उस सपने को हकीकत में बदलने का काम कर रहा है। उस सपने के साथ इस देश की प्रत्येक जनता चल रही है।

हम लोगों ने देखा है कि जब हम बच्चे थे, तो खिलौने मेड इन इंडिया में होते थे, पर जब हमारे बच्चे हुए, तो खिलौने विदेशों से आकर बनने लगे, लेकिन प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व के साथ हम लोगों ने न केवल मेक इन इंडिया और पीएलआई का निर्णय लिया बल्कि मेगा टॉय पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क, मेगा फार्मा पार्क, डिफेंस कॉरिडोर, ये सभी स्थापित करके, जो देश खिलौनों के लिए विदेशों पर निर्भर हो गया था, वहीं आज हम ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स और हाइटेक उपकरण दुनिया में बेच रहे हैं। यह मोदी जी की उपलब्धि है।

आज हम सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाने जो रहे हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज को दुनिया में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। हम एक तरफ हर गरीब को बिजली, गैस, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज, घर, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति कर रहे हैं। हम बिना गारंटी के रेहड़ी-पट्टी से लेकर देश के युवाओं, विश्वकर्माओं को सब्सिडाइज्ड लोन दे रहे हैं, जिससे हमारा प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक तरक्की कर सके। लेकिन इन लोगों के इतने सारे इल्जाम के बावजूद भी मुझे याद है। आज मैं स्वर्गीय अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि भी देना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि *yes, we are industry-friendly government.*

(1445/KN/AK)

यह बिल्कुल साफ है कि जो ईमानदारी से टैक्स भरेगा, सरकार उस इंडस्ट्री का साथ देगी, लेकिन जो बेईमानी और भ्रष्टाचार करेगा, यह सरकार उसे किसी भी स्तर पर छोड़ने वाली नहीं है। यही इनकी तकलीफ का सबसे बड़ा कारण है। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम ले रहे थे। मैं भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लेना चाहूंगा, जिसका नाम ये हमेशा लेते हैं। उस इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम नीरव मोदी है। यह जानने की चीज है कि कौन इम्पीरियल होटल में गया था। इम्पीरियल होटल में रात को मॉडलिंग शो देख कर अगले दिन नीरव मोदी को बैंकों से कैसे उधार पैसे मिल गए? यह भी बताने का काम हमारे यूपीए गवर्नमेंट के समय के हमारे मित्रों को जरूर करना चाहिए।

आज हम लोग हर चीज के लिए कृत संकल्प है। अगर हम इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भारत के प्रत्येक उद्यमी को सामने खड़ा होना होगा और उसकी मदद करनी होगी। इसलिए मैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लाए गए इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स फोर ग्रांट्स का पूर्ण समर्थन करता हूँ। अपने प्रधान मंत्री जी का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि लोक कल्याणकारी योजनाओं में उन्होंने जो कुछ किया है, उसके लिए भारत के नागरिक भी सदा आभारी हैं। आप कितने भी रोड़े अटका लीजिए, वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनकर ही रहेगा।

जय हिंद, जय भारता।

(इति)

1446 बजे

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे वर्ष 2024-25 के अनुदानों की अनुपूरक मांगें – प्रथम बैच पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।

मान्यवर, ये अनुपूरक मांगें, जो माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, यह 87,762 करोड़ रुपये के लगभग हैं। अभी हमने जुलाई में ही बजट पास किया है। हमारी प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं थी कि एक महीने में ही हमें अनुपूरक मांगें लानी पड़ीं। जिन मदों पर हम अनुपूरक मांगें लाये हैं, अभी माननीय डॉ. जायसवाल साहब किसान सम्मान निधि की चर्चा कर रहे थे। यह पहले से अनुमानित था, पूरे वर्ष का बजट अनुमानित था और अगर खर्च अनुमानित था तो इसको मुख्य बजट में ही लाना चाहिए था। उसको फिर से अनुपूरक मांगों के रूप में लाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके साथ-साथ जब हम अनुपूरक मांगें लाते हैं तो हमें यह भी विचार करने की आवश्यकता है कि हमने जो मूल बजट में पैसा लिया है, उसका कितना प्रतिशत खर्च करने में हम सफल हो पाए हैं। मैंने तमाम ऐसे विभागों में देखा है, जनकल्याण से जुड़े तमाम विभागों में देखा है कि 50 प्रतिशत भी मुख्य बजट का हम खर्च नहीं कर पाते हैं। इस तरह से हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो प्लानिंग है, जो हमारा अनुमान है, वह लचर है, जिसके कारण हम उसमें खर्च नहीं कर पाते हैं।

अगर हम वर्ष 2023-24 के केन्द्रीय बजट का उदाहरण लें तो फरवरी, 2023 में बजट पेश करने के आठ महीने के बाद जब लेखा-जोखा निकाला गया तो एक तिहाई भी खर्च नहीं हुआ। निश्चित रूप से जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको बजट समय पर खर्च करके और उसके आधार पर विभिन्न योजनाओं को बनाना चाहिए, उसका जिक्र नहीं किया गया।

मान्यवर, हमारा अच्छा बजट न होने के कारण ही इस देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। इस देश में जो आर्थिक असमानता है, उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। देश के लगभग एक फीसदी लोगों के पास 41 परसेंट सम्पत्ति का हिस्सा है और दूसरी तरफ जो कमजोर आबादी है, जो गरीब लोग हैं, 50 प्रतिशत आबादी के पास देश की जीडीपी का केवल 13 परसेंट और संपत्ति का 4.1 परसेंट हिस्सा है।

(1450/VB/UB)

बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में अपने एक भाषण में कहा था कि इस देश में जितनी भक्ति, वीर पूजा और अंध विश्वास है, उतना अन्य किसी देश में नहीं है। धर्म एवं भक्ति तथा वीर पूजा मुक्ति के साधन भले ही हो सकते हैं, परंतु राजनीति में भक्ति और वीर पूजा अधोगति में ले जाने वाला अधिनायकवाद हो जाता है।

स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव के आधार पर व्यतीत सामाजिक जीवन ही लोकतंत्र कहलाता है। स्वतंत्रता तो हमें मिली किन्तु भारत में समता का अभाव है। यहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता का बोलबाला है। विषमता का बोलबाला के कारण ही, देश में अरबपतियों की संख्या अमेरिका और चीन से ज्यादा है या लगभग उनके बराबर है। लेकिन हमारे यहाँ गरीब ज्यादा हैं। इसका कारण है कि हम जो बजट बना रहे हैं, जिस तरह से हमें छोटे और मध्यम उद्योगों को

बढ़ावा देना चाहिए, रोजगारपरक उद्योगों को हमें बढ़ावा देकर हर व्यक्ति को रोजगार देने की आवश्यकता है। उसे करने में हम विफल हुए हैं।

इस देश में 70 फीसदी लोग कृषि पर आधारित हैं, उनका जीवन कृषि पर निर्भर करता है। किसान हमारे देश का मूल आधार है। हमारे तमाम महापुरुषों ने इस बात को कहा था कि इस देश का विकास खेत-खलिहानों से होकर गुजरता है। लेकिन हमने उस दिशा में ध्यान देने का काम नहीं किया। आज किसान परेशान है। जहाँ किसान की आवश्यकता डीएपी खाद की है, उस पर सब्सिडी देने की, लेकिन उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, हम उचित मूल्य पर उसे देने में विफल हो रहे हैं। इस बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आप अनुपूरक बजट लाये भी, तो उसमें किसानों के लिए उस तरह की कोई व्यवस्था लाने का काम नहीं किया गया।

इसी तरह से, बैंकों द्वारा बड़े-बड़े उद्योगपतियों के कर्ज के एक बहुत बड़े हिस्से को राइट-ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन किसानों का कर्जा माफ करने के लिए हमारी सरकार के पास संसाधन नहीं हैं। तमाम किसानों द्वारा मांग करने के बावजूद उनका आज तक कर्जा माफ नहीं किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

मान्यवर, आज किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई लड़ रहा है। उद्योगपति लोग अपने दाम तय कर लेते हैं और धंधा करने वाले दूसरे लोग भी अपने दाम तय कर लेते हैं, लेकिन किसान ही एक ऐसा वर्ग है, जो पूरे देश को खिलाने का काम करता है। अगर आज हम लोग 82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे पा रहे हैं, तो वह किसान की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है, लेकिन आज उस किसान को भी यह सरकार उसके उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का काम नहीं कर रही है, जिसके कारण किसानों की हालत अच्छी नहीं है। अगर किसानों की हालत अच्छी नहीं होगी, तो देश की हालत भी अच्छी नहीं होगी। हमें किसानों की आमदनी बढ़ाने की आवश्यकता है, उसकी उत्पादन लागत कम करने की आवश्यकता है। लेकिन उत्पादन लागत कम नहीं हो रही है, वह लगातार दिन दुगुना और रात चौगुना गति से बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ, उसकी आमदनी घटती जा रही है। अगर अभी एक किसान को ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना हो, केवल 5 केवीए का कनेक्शन लेना हो, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद से उस किसान को डेढ़ लाख रुपए से ज्यादा जमा करना पड़ता है। लेकिन किसान को विद्युत का कनेक्शन आसानी से मिल जाए, उसके लिए इस बजट में व्यवस्था करने का काम नहीं किया गया।

इसी तरह से, मेरा यह मानना है, माननीय डॉ. संजय जायसवाल जी कह रहे थे कि स्वास्थ्य के लिए 391 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मैंने जो अनुपूरक बजट देखा है, कुल 90 करोड़ रुपए के इस अनुपूरक बजट में, स्वास्थ्य विभाग के रिसर्च के काम को मिलाकर यह राशि रखी गई है, तो यह 391 करोड़ रुपए कैसे हो गया?

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : सर, इन्होंने मेरा नाम कोट किया है, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा।

माननीय सभापति (श्री दिलीप शङ्कीया) : आप इनके बोलने के बाद बोलिएगा।

(1455/PC/RCP)

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : माननीय सभापति महोदय, मेरे पास बजट की अनुपूरक मांगों की यह 203 पेज का दस्तावेज़ मेरे पास है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की फिगर केवल 89.51 करोड़ रुपए की है। ... (व्यवधान) इसलिए, मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि इस तरह की स्थिति है।

मान्यवर, मेरा यह मानना है कि हमारे देश में जितनी भी सामाजिक संरचना है, हमारे देश में एससी भी हैं, एसटी भी हैं, ओबीसी भी हैं और कमजोर वर्गों के लोग भी हैं। उनको शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा पर हो रहा है। उनके लिए भी इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति या अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की व्यवस्था हो सकती। अगर हम इस दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे, तो निश्चित रूप से देश का भला नहीं कर पाएंगे।

मान्यवर, मैं फसल बीमा के बारे में कहना चाहूंगा। फसल बीमा होता है, सरकार राशि जमा करती है, किसान से भी पैसा लिया जाता है। हमारी फसल नष्ट हो जाती है, उसके लिए ऐसा तरीका बनाया गया है, जिससे कंपनी को पैसा न देना पड़े, वह केवल मुनाफा ही कमाती रहे। इस तरह से किसान के बारे में भी सोचकर उसको लाभ देने का काम नहीं किया गया।

मान्यवर, मैं अब बेरोजगार नौजवानों के विषय पर आता हूँ। कैसे उनकी गरीबी दूर होगी, इस बारे में भी इस बजट में जिक्र करने का कोई काम नहीं किया गया।

मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि अगर हम निश्चित रूप से देश का भला चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो वह केवल नारे से नहीं होगा। केवल 'विकसित भारत' कह देने से देश का विकास नहीं होगा। उसके लिए हमें योजनाएं बनानी पड़ेंगी।

जो देश की आर्थिक स्थिति है, वह भयावह स्थिति है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम पूंजीपतियों को, चाहे वे एक हों, दो हों या तीन हों, उनके तो 18 लाख करोड़ रुपए राइट-ऑफ हो जाएंगे, लेकिन किसान के लाख-करोड़ रुपए भी राइट-ऑफ नहीं होंगे।

इसलिए, मैं आज इस सदन के माध्यम से यह अपेक्षा करता हूँ। निश्चित रूप से केवल हवा-हवाई बातें कर देने से, केवल 500 रुपए प्रति महीने किसान को देने भर से उसकी स्थिति नहीं सुधरेगी। जो किसान सम्मान निधि है, एक किसान को मात्र 500 रुपए एक महीने में मिल रहे हैं। उससे उसकी अमदनी बढ़ने वाली नहीं है। अगर आप उसको लाभ देना चाहते हैं, तो आप किसान को खाद पर छूट दीजिए, कीटनाशक दवाओं पर छूट दीजिए, बीज पर छूट दीजिए और विद्युत कनेक्शन पर छूट दीजिए। तब ही किसानों का भला होने वाला है। इसी के साथ अनुसूचित जाति के लोगों की छात्रवृत्ति का भी इसमें प्रोविजन नहीं किया गया है।

मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस दिशा में आप पहल करने का काम करें, जिससे उन लोगों की दिक्कतें दूर हों। आप रिज़र्वेशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन लोगों का हक मारने का काम कर रहे हैं। वह भी पूरा करने का काम करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कहना चाहूँता कि आपने मुझे बालने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शङ्कीया) : ऑनरेबल मेंबर, प्रो. सौगत राय जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रोफेसर साहब, आप एक मिनट रुकिए।

... (व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : सभापति जी, मेरा अनुरोध रहेगा कि श्री लालजी वर्मा जी बहुत ही सीनियर सांसद हैं। वे कह रहे हैं कि हैल्थ के लिए सप्लिमेंट्री बजट केवल 89 करोड़ रुपए का है। यह राशि केवल आईसीएमआर को दी हुई है। ... (व्यवधान) हम 320 करोड़ रुपए की ग्रांट-इन-एड रेयर हैल्थ डिजीजेज़ के लिए दे रहे हैं। ... (व्यवधान) एम्स के लिए 222 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ... (व्यवधान) इसके अलावा आरएमसीएच के लिए 150 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ... (व्यवधान) अतः मेरा कहना है कि माननीय सदस्य अपना डेटा सुधार लें। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: He has named Sanjay ji. Do not talk like this.

... (Interruptions)

माननीय सभापति : डेटा को गलत तरीके से यहां पेश नहीं होना चाहिए। यह सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर किसी माननीय सदस्य के डेटा को सुधार दिया गया है, तो आप इसमें क्यों आपत्ति कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी – आप बोलिए।

... (व्यवधान)

1459 hours

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Supplementary Demands for Grants. It is unfortunate that the Finance Minister is not there. But still, I have some points to make. I shall be brief. Ms. Sayani Ghosh will speak on the other points.

The Supplementary Demands have been brought under Articles 114(1), 115 and 217 of the Constitution. There is nothing to oppose the Supplementary Demands for Grants because the money has already been spent.

(1500/PS/IND)

The Government is asking for an Appropriation of the extra amount spent. What is the extra amount? It is Rs. 87,000 crore roughly. Out of this Rs. 87,000 crore, Rs. 44,000 crore is the outgo, and the rest will be met by savings from the Government's expenditure. So, where is this Rs. 44,000 crore going? Out of it, Rs. 9,692 crore will go towards PM-KISAN; Rs. 9,500 crore for rural telecom connectivity; Rs. 6,500 crore for fertilizer subsidy; and Rs. 4000 crore for Defence services.

Now, the problem with the Supplementary Demands for Grants is that if you spend more money, then you push up the Government's financial deficit target. The Government has set a target of 4.9 per cent. Now, these Supplementary Demands will push up the financial deficit. The only way for the Government will be to reduce its spending on infrastructure. This Government is caught in a pincer movement. What is the reason? The reason is that they are not being able to decide whether to go for growth or to go for controlling the inflation.

There was a dispute between the Finance Minister and the Governor of Reserve Bank, Shri Shaktikanta Das. The Reserve Bank wanted to keep the repo rate stable, whereas the Finance Minister was pressing for reducing the repo rate so that more money could go to the economy. Ultimately, the Governor of the Reserve Bank had to leave.

Now, there is a typical crisis in the whole economy. The crisis is that our growth projections for the last quarter have slipped to 5.4 per cent. This is very damaging to the economy. How does the Government make up for this slip in the economy? Unless the economic growth rate comes up, the country cannot progress. And this is a sharp slowdown. The main slowdown has been in the

manufacturing sector, which has expanded to only 2.2 per cent this year. Now, to sustain higher growth, you need more private investments. To have more private investments, you have to spend more on infrastructure. If you spend more on infrastructure, inflation will go up. So, this is a double whammy that the Government is caught in. Prime Minister Mr. Modi made a two-hour speech. It was like a speech to a school collection but he did not touch upon these basic problems of growth.

And now, we will have more problems because one of our strong points was exports. With Donald Trump as American President, exports will be curtailed because he will impose more tariffs. So, where do we go from here? I have no objection to allowing the Finance Minister to have Supplementary Demands. But what is her answer to this basic question facing the Indian economy -- growth or control of inflation? Inflation has also showed an upward trend. It has gone up to 6.2 per cent. So, if inflation increases, then who is put to difficulty? The middle-class people will be put to difficulties. That is what is happening.

This Government has patronised the big industry. Now, I saw a figure that the profits of the big industries -- as seen in the names of Tata, Reliance and Adani -- have gone up.

(1505/SMN/GG)

How? Post-Covid, the tax profits of companies listed in stock exchange has risen to 5.2 per cent of GDP. It is only profit. Compared to this, the share of employee compensation has been coming down.

So, the profits of industrialists and capitalist are increasing and the salaries of the middle-classes and working classes are coming down. So, one newspaper has headline – profits move but pay is far from fair. So, this is the situation in the Indian economy. Everybody is saying that this is good for growth. The Finance Minister is here. Maybe she will reply. Earlier, I had commented on her of not having a foreign degree. I am withdrawing that comment. But it would have been good if the Finance Minister was an economist from an Indian University. She will be able to tackle the problem in which the Indian economy is caught - growth or control of inflation. At this rate of growth of 5.2 per cent in the last quarter, Indian economy cannot make progress. I say all this because I have many other demands to make before the Finance Minister. We come from

the State of West Bengal which has been deprived of Rs. 22,000 crore in the NREGA funds. We have been deprived of Rs. 2,500 crore on account of PM-AWAS Yojana. But I am not here to speak on West Bengal demands only. I am speaking on the economy as a whole. The economy is not in a fair shape. So, why will you allow the Finance Minister to go away with these supplementary demands in her kitty? If you see the Supplementary Demands for Grants, out of Rs. 87,000 crore, only Rs. 19,000 crore is the capital expenditure. The rest is the revenue expenditure. So, on the one hand, unless you invest in capital expenditure and infrastructure, private investments will not come. Adani's and Ambani's depend on the Government to provide the infrastructure so that they can make more profits. So, all these problems in the Indian economy need to be considered. I do not see anybody in the Ministry or in the Government, who can really tackle such a problem. It would have needed Manmohan Singh to tackle this problem.

More advantages to the poorer sections have to be given. Sir, I do not want to prolong my speech further. The economy is hamstrung by lack of policy; by lack of clarity and the economy cannot go on with the Prime Minister's speeches only.

Lastly, Mr. Venugopal has spoken about asking for a JPC Inquiry against the working of SEBI and its complicity in manipulating the shares of the Adani group. While not emphasising on that, I, in general support, his demand. ...
(Interruptions)

Let him come. But let him not manipulate the share market. If he manipulates the share market, then he shall be driven out of India ultimately as he is being driven out of US.

Thank you, Sir.

(ends)

1509 hours

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Vannakkam Chairman, Sir, as a representative of the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), I stand to address the first batch of Supplementary Demands for Grants for the fiscal year 2024-25.

Sir, the Government seeks an approval for the additional expenditure to the tune of Rs. 87,762.56 crore. Out of this, the Government is seeking the approval for Rs. 44,142 crore and Rs. 43,618 crore, the Government is trying to manage by itself.

(1510/RP/MY)

Sir, if you see the Demands for Grants or whatever they ask for, nearly Rs. 13,191 crore is asked for agriculture and farmers welfare; Rs. 6,000 crore for fertilizers; Rs. 12,000 crore for telecommunications; Rs. 12,000 crore for defence; Rs. 3,000 for external affairs; and Rs. 6,000 crore for police, and other departments falling under Home Ministry, etc.

Sir, I would not like to go into all the subjects, but I want to concentrate on my area, that is, agriculture. Sir, the Ministry of Agriculture has two departments, one is Farmer's Welfare and another one is Agriculture Research and Education. Sir, if you look at the Demands, the Department of Agriculture and Farmers Welfare is responsible for implementing various schemes run by the Government of India. This includes some major schemes like PM-KISAN, MISS, Crop Insurance, RKVY, and Kishori Shakti Yojana, etc.

Out of these, the PM-Kisan Samman Nidhi Yojana is more interesting. The BJP Government once promised in 2016 to double the farmers' income by 2022, and that is the reason the PM-Kisan Samman Nidhi Yojana was launched in 2019 to enable the farmers to meet their agriculture and household needs. Now, the Government is giving Rs. 6,000 in three equal instalments every year. But, is it happening rightly? As per the findings of the C&AG Report, the PM-Kisan Samman Nidhi Yojana has been launched in many areas. They say that approximately 35 per cent of the applications were found to be ineligible for the Scheme. In certain areas, the funds have been dispersed and the recovery is happening. Around 0.24 per cent of the total funds has been collected. These discrepancies are major flaws in the Scheme. The PM-Kisan Samman Nidhi Yojana cash benefits given in three separate instalments are not for all the

farmers. Since they cover those with the land, that means that the Scheme excludes a significant chunk, that is, nearly 5.37 crores of landless families as estimated in 2011 or 2.4 crores of people with the leased-land as estimated in 2019, these people have been left out.

The Standing Committee on Agriculture 2020 pointed out very clearly that the PM-KISAN Scheme cannot be effectively implemented because there are a lot of lacunae like non-availability of land records, non-transference of land to the heirs of deceased landholders, community-owned lands in Northeast, incorrect bank details, and malfunctioning of Aadhaar connections. The Committee also observed that benefits under such schemes are not available to tenant farmers because all the agriculturists are not landowners.

As per the information provided to Unstarred Question in July 2024, no specific census or survey has been conducted to ascertain the number of landless farmers in the country. So, how do you come to know that the PM-Kisan Samman Nidhi Yojana is a successful one? Why are you demanding more money? The agriculture census recorded that these kinds of landless farmers are nearly around 5,31,000. They are waiting for these funds.

Sir, the other scheme is the MISS Scheme. The Budget says that under the Interest Subvention Scheme, the fund allocation in the revised estimates has increased from Rs. 18,000 crore in 2023-24 to Rs. 22,600 crore in 2024-25, reflecting a 22 per cent increase.

Sir, another major flaw is the Crop Insurance Scheme. The budget for the crop insurance scheme has seen a three per cent decrease from Rs. 15,000 crore to Rs. 14,600 crore in the revised estimates of 2024-25. This allocation is being made to meet the frequency of climate-related disasters, and it has to be increased. The Standing Committee on Agriculture in 2023 raised concerns and asked how the ministry plans to implement the schemes related to extreme weather conditions.

(1515/NKL/CP)

Sir, agriculture is the backbone of India. If we talk about agriculture, there are very important things that have to be discussed. The State of Tamil is supposed to be a major agricultural State in Southern India. If you see the history, many States have given Budgets but I would like to proudly say that Tamil Nadu is the first State in India where in the year 1989, our hon. Chief

Minister, Dr. M. Karunanidhi, our DMK Leader, first implemented the free electricity scheme in India. That was the first scheme for farmers in the agriculture sector. After that, many States followed it. But till today, there have been many Governments which are coming in and trying to follow that scheme. Now, our Chief Minister is following the footsteps of Dr. M. Karunanidhi. How is he doing it? Now, he is extending the scheme in such a way that nearly three to three and a half lakhs of agriculturists have been benefited because of this kind of scheme. The Government should propose a Budget like that.

Also, we are discussing about agriculture which is an important issue in this country. But the Tamil Nadu Government is setting an example. Before the Budget, the Tamil Nadu Government has set the norms in such a way that the Agriculture Budget is submitted first for discussion. First, a separate Budget is included and then, the General Budget comes in. This is how a Government should run.

Sir, for the State of Tamil Nadu, we have got a lot of requirements. The subsidy for the production and distribution of seeds should be extended for all the varieties. Under the F&S scheme, the paddy seed subsidy should be increased for more than 10 years. Talking about cereals, the seed subsidy on Jowar and Kambu should be increased to 15,000 per quintal.

The Tamil Nadu Government has asked for relief. But, the Government of India is not at all caring about it. We are focusing on agriculture. We are facing a lot of difficulties. But, the Government of India does not even have time to look at that.

The GST is levied on rice. There is five per cent GST on rice, which has to be reduced. About 32 metric tonnes of wheat was allocated for Tamil Nadu, but now it is reduced. It has to be increased. There is a request for increase in the wheat allotment.

Kerosene distribution, which is a major issue in Tamil Nadu, has been reduced. The people living in hilly areas have to be benefited.

HON. CHAIRPERSON (SHRI DILIP SAIKIA): Please conclude.

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, I am concluding.

Another important thing is this. Whenever any Government comes to power, the major thing that they talk about is employment. But, after this Government came to power, I do not think there is any improvement in the

employment generation. ... (*Interruptions*) I want to quote one example. Please give me a minute.

Sir, I was in this august House in the last term and I have been re-elected again. But I have been fighting from the day one for the opening of the Vellore Airport. I fought in this House for this issue. The Government gave money, and the Airport was opened. During the last elections, our hon. Prime Minister visited Vellore. He landed at the same Vellore Airport, went to Vellore district, and campaigned. But, till today, the Airport has not seen an opening ceremony at all. We are waiting for that.

HON. CHAIRPERSON: Thank you, hon. Member.

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, I am concluding.

Also, money has been asked for Defence. Madam Finance Minister, you are allocating a lot of money for the Defence. We are happy about it. But I want to bring one issue to your notice. There are a lot of ex-servicemen in the country, who go for treatment to medical hospitals. But in many areas, the private hospitals are not giving proper treatment at all. The families, which have suffered in war, and the people who have lost their organs like hands, legs, and are handicapped, are still facing a big difficulty.

(1520/VR/NK)

Even in Vellore a lot of private hospitals are ignoring the ex-military personnels for medical assistance.(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI DILIP SAIKIA): Please conclude.

Now, Shri Magunta Sreenivasulu Reddy ji.

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, I am concluding in one minute.

....(*Interruptions*) Sir, I have to make just last point.

HON. CHAIRPERSON: Okay, complete your speech in 30 seconds.

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, we are the citizens of India. We want to work with India. When we want to work with India, we want to work with the Government also. But the Government has to make sure that they do not see Tamil Nadu as an enemy State. They have to see it as a State of India.(*Interruptions*) Thank you very much, Sir, for allowing me to speak.

(ends)

1521 hours

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Respected Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants 2024 and 2025. I, on behalf of my party, Telugu Desam Party, under the leadership of our hon. Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, welcome the Supplementary Demands for Grants for 2024-25 and the Appropriation Bill.

We are all aware that the confidence level in the world itself has gone up because our hon. Prime Minister has brought many schemes in this country to take care of the poor people. At present, there are now 210 notified countries in the world. Out of that, more than 50 per cent of the countries are approaching our hon. Prime Minister for resolving their problems. So, he is looking like a big brother in the entire world.

Sir, in this year's General Budget passed during the Monsoon Session, the NDA Government under the leadership of Shri Narendra Modi recognized the dire situation that my State of Andhra Pradesh was in, and announced a fund of Rs.25,000 crore for our Capital and other infrastructure projects. So, I am very much thankful to the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister because this would not only bring life back in our State, but also inspire the people of Andhra Pradesh to move forward. The previous Government was just looking after the welfare and not the developmental works. But, now, under the leadership of our hon. Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu Garu, we will be able to see the development in the entire State of Andhra Pradesh.

Sir, inspired by our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi's vision of Atmanirbhar and Viksit Bharat, our hon. Chief Minister of Andhra Pradesh has launched a scheme called Swarana Andhra -2047. Through this vision, he is aiming for 2.4 trillion-dollar economy with an annual growth rate of about 15 per cent for our State.

Sir, we still have a lot of pending issues in our State, which need to be resolved. Many Centrally-sponsored schemes have been launched for the development of our State. But due to paucity of funds, we are unable to complete those projects. Our visionary hon. Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu, who has got 46 years of experience in governance, has found many ways to fulfil the dream of developing the State. One of those is P4, that is, Public, Private,

People's Participation. The other one is HAM model, that is, Hybrid Annuity Model. If the Government of India permits, the Central Government funds will be there, the State Government funds will be there, other funding agencies will be there and the developers will also be there. If it is done, all the programmes meant for development in Andhra Pradesh will be implemented.

Sir, I would like to give a humble suggestion to the hon. Finance Minister. For a prosperous India, the States should also be healthy. The Government of India does a huge collection in terms of GST. We get about Rs.16 lakh crore from the entire country. The Government of India will have to create some brackets for the development of the States. Through this, you should allow 75 per cent of the GST collected from a particular State to go in that State itself. Then only the States will be healthy.

(1525/SAN/SK)

Sir, now I would like to speak about the Supplementary Demands for Grants. Last year, the Housing and Urban Development Ministry was allocated Rs. 85,000 crore. I would request the hon. Minister, in the presence of other Members, to increase its allocation to Rs. 1,50,000 crore.

We have got some issues in Andhra Pradesh. There is a NIMZ, National Industrial Manufacturing Zone in Kanigiri Assembly Constituency. It was announced long back by the Central Government, but it is not moving forward. I request, through you Sir, the hon. Finance Minister to speed it up.

The next is the issue of modernisation of the Buckingham Canal in Andhra Pradesh. It is a big canal starting which starts from Kakinada and goes to Chennai. It is the oldest canal which was constructed by the Britishers. The canal and its modernisation is very much required for the State of Andhra Pradesh.

Sir, about 16 medical colleges were announced by the previous Government, out of which only three are being sponsored by the Central Government. Rest of the medical colleges have to be sponsored by the Central Government so that the State will be able to complete them.

Sir, the inter-linking of rivers is also a pet project of our hon. Chief Minister. Earlier, the inter-linking of rivers from the Ganga to the Cauvery was the dream project of our former Prime Minister, late Vajpayee ji. Now, our visionary leader and Chief Minister of Andhra Pradesh, Mr. Chandrababu Naidu *garu* has taken up inter-linking of the Godavari-Pennar. It is an inter-linking of river project

costing about Rs. 72,000 crore so that all the people of Andhra Pradesh will have irrigation facility and drinking facility. I request, through you, the hon. Finance Minister to help the State of Andhra Pradesh in this regard. The intervention by the Centre is required, and if it is declared as a national project, we will be happy to be associated with that project.

Sir, the Renigunta project needs about Rs. 3,500 crore. That project has to be completed with the help of the Central Government. That is also hanging on.

Sir, we have got the Standing Committees in the Parliament. They can undertake study tours but they are limited to domestic destinations. All the States are sending their MLAs abroad for study and all that. I request, through you, the Government, on behalf of all the hon. Members, that our Standing Committees should also be allowed to undertake tours to foreign countries so that we all feel happy about it.

Sir, I come to my last point, which is a favourite of all the Members. The MPLAD Fund has to be increased. It has been pending for a long time. It was hiked to five crores of rupees about ten years back. It is through the hon. MPs only that all the Central Government schemes are also being implemented. I request the hon. Minister to increase it to Rs. 25 crore. If it is done, all the Members will be happy.

Sir, so many issues are highlighted here in the Supplementary Demands for Grants also. I thank Modi 3.0 Government. It is going to be successful in the 18th Lok Sabha also. I am sure that we will have many more developmental schemes in our country.

Thank you very much.

(ends)

1528 hours

SHRI ANIL YESHWANT DESAI (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Hon. Chairperson, Sir, after discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants, the Appropriation (No. 3) Bill will be considered for passing. I think, the hon. Finance Minister will take the consent of the House.

Sir, if we go by the last quarter, as per the data released by the National Statistics Office, the GDP growth stood at 5.4 per cent, much lower than the projections made by the Reserve Bank of India, which stood at more than seven per cent. During this period, it has come down on an average, and the manufacturing sector has taken a heavy beating in respect of which the growth stood at only 2.2 per cent. Along with that, even the construction sector and the mining sector also showed growth on the lower side compared to the seven per cent it was in the last quarter or first quarter.

(1530/SNT/KDS)

It is expected that the low growth rate is going to create complications in the remaining half of the financial year. This is going to impact the economic performance in the second half. Fiscal management will also be an issue and it will be a challenge for the Government to contain it at a lower level. If the target of 4.9 per cent is to be achieved, it will have to cut down majorly on its Government expenditure. When the Government expenditure comes down or it is reducing, the result is that there is growth in unemployment, as we have seen. The question is this. How will we mop up for the rest or how will we be able to contain? The only answer that we see is that private investment needs to come into play. I would like to know whether the conditions prevailing in the country will induce private investment and really boost the economy. It is a big question in front of not only the Government but also for the people of India as the society is suffering.

Today, India's youth is restless as unemployment is growing by the day. He is in search of a job. The Central Government tries its best by declaring schemes like Startup India, giving some concessions, declaring that skill will be taken into account, and skill centres are being opened by the day. But this remains on the paper. However, the reality on the field is something different. We have been seeing that a very few of these startup programmes emerge successful and a majority of them flop. They are not able to do the things they had in mind.

The ever-growing inflation is not going to come down and this has broken through the budget of the families, the middle class, and the poor. By the day, essentials or vegetable prices are going up, though it comes in the paper for a day or a fortnight that the Consumer Price Index has come down, and some kind of a joyous situation prevails only in the Treasury Benches. In reality, the society is still suffering and their woes are to be heard by the Government and put into practice. I think this Appropriation Bill will take care of all this.

Sir, coming to agriculture sector, basically agriculture sector is the only sector where we could see the growth in the last quarter. It has to maintain this and should give some motivation to the farmers. The reality is that the Government should think of giving MSP the way it is being calculated by the farmers. It was mentioned that there will be doubling of income of the farmers in so-and-so period, which could never take place. It should not be an everlasting phase. It should really mean that farmers get MSP. Like in Maharashtra, soybean or cotton or maize cultivating farmers are suffering because whatever MSP is being declared, it is not coming up to their expectations. I think that needs to be taken into consideration.

Finally, Sir, I would put it this way. Now, there is a provision made in the Department of Public Enterprises for meeting additional expenditure towards salaries and allowances. My humble request to the hon. Finance Minister would be that the Insurance Act, which is in the offing, is going for the amendment. This Insurance Act will provide for 100 per cent FDI, and composite license is being contemplated. That composite license will be issued to the private players.

1534 hours

(Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

All the Government companies, all the public sector units in the general insurance and life insurance sectors will be kept aside. This will deprive them of making the business who had the monopoly in the sector and they did well. Over the years, all these companies, may it be LIC or New India Assurance, have been paying handsome dividends to the coffers of the Central Government. But the irony of the fact is that these very companies will be deprived in the Bill which is being contemplated to be brought in.

Hon. Finance Minister, I am addressing a very important issue. You are aware of it. You are aware of the issue I am making a mention about.

(1535/AK/MK)

The banks have got their upward pay revision, LIC has followed it, and only General Insurance Companies like New India Insurance, United India, National Insurance, etc. are awaiting their turn to get upward pay revision. I think that enough of provision has been made. Shrimati Nirmala Sitharaman ji has shown keen interest to see that these people also get their due, and if so, I will be extremely happy.

My last request is regarding GST rationalisation in the rates of Mediclaim. The entire country is awaiting your decision. I think that in the month of December the GST Council was to take a decision on it, which is yet to come. If it comes, then it would be a good relief for the people of India. Thank you very much.

(ends)

1536 hours

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, I stand on behalf of the NCP (SP) in support of the List of Supplementary Demands for Grants.

Madam, obviously after every Budget, clearly it is evident that all Departments / States have their own issues and challenges in implementing the Budget. So, clearly this List of Supplementary Demands is something that we all support because we do understand that it is the need of the hour. I must say that compared to the last time, this time it clearly comes out far more organised because the amount is much lesser than last time. So, I would compliment the entire Department for being either more organised or more structured or working better -- whatever it is, but we are much more satisfied than we were the last time regarding the Demands for Grants.

Right now, I do understand that India is no more an insulated economy because of the global scenario. So, we do understand that every economy that is not insulated has its own challenges. I think that we really need to put all our minds together, and this entire House needs to be together in what awaits India's economy in the world scenario.

Clearly, a few points that everybody over here has said including about the growth having come down to 5.4 per cent, which is clearly alarming. I am sure that the hon. Finance Minister is also as alarmed as we are. But clearly, decrease in consumption growth, persistent inflation, necessity of sticking to a monetary policy, the alarming lower private investments and sluggish FDIs really are worrying all of us.

I just would like to ask pointed questions to the hon. Finance Minister because we are elected representatives and there are a few questions in our minds, and she can reassure the nation in her reply what steps is this Government is taking for job creation given the scenario and the way the economy is going. How are you going to increase consumption or purchasing power right now considering growth has slowed down? How are you going to reduce the food and retail inflation? What steps are you going to take for it?

India was always a savings economy, but with the changing global scenario, people are clearly becoming a more spending economy. There was a time when the interest rates used to be 11-13 per cent and it used to be in double digits, but now it has come down to 6-7 per cent. So, people are not saving as much as they did, which is eventually going to hurt our economy in the long run. How are incomes going to increase given the scenario of slow down? What specific steps is this Government going to take to increase domestic investment?

Earlier, when she brought in the Banking Bill, which we all supported, I even brought out an issue of the NBFCs. I would like to ask just out of concern that NBFCs are encouraging and they are growing, but they have a lot of deposits that people put. Is there a regulator that she has in mind for all these NBFCs? I am asking this because these NBFCs reach the last person. So, it has to be regulated. What are the checks and balances or mechanism that this Government has in mind so that we all feel very safe and secure like normal banks do?

The other question that I would like to ask the hon. Finance Minister is this. We have a huge unorganised sector in this country. Even in a reply given by the Government in the morning it was mentioned that they are trying to consolidate the entire unorganised sector and bring them under some protection scheme so that all the schemes that are done by the Government of India are supported. It is called the '21-point Programme', which this Government has started. If there is a huge unorganised sector even today in India, how are you going to consolidate it? Is there a timeline for it? Today, you have said that you have got about 30 crore people under that scheme, which is clearly not covering all the unorganised sector.

(1540/UB/SPS)

So, what steps are you taking? There has to be a timeline. I am taking away from the intention of the Government that they really want to take in everybody including the gig workers, domestic help and unorganised workers. Do you have a plan to bring every Indian who is in the unorganised

sector to come into the organised sector which will eventually help our economy?

Regarding fiscal deficit, which a lot of hon. Members have spoken about, the Government keeps talking about the five trillion-dollar economy and that the size of our economy will reach trillion-dollar easily. I do not think whether it is in terms of power or we would need to reach five trillion-dollar economy just because of the size of our country. But if you look at the fiscal deficit, one way is to print more notes. If you print more notes, clearly inflation will go up. Tax is increasing; you are saying that more people are paying taxes. What specific steps are you taking as the numbers are showing that the foreign borrowing has substantially gone up in this country? So, how is this Government going to manage this fiscal deficit given the global scenario and India's economy slowing down? How are you going to push the growth?

The current account deficit is another very important question because exports have gone down and imports have gone up. If, on the one hand, you have exports going down, imports are increasing, how is this current account deficit going to be managed given the global scenario? I am not blaming you for the imports going down. I am not an economist, but I do understand that much that given the global scenario, exports have gone down. So, what steps is the Government going to take? I think the entire reply of the hon. Finance Minister will give the confidence to this country which it lacks right now because of the war going on and how President Trump's administration will be going about tariffs. These things come into newspapers and it clearly affects the markets.

I would like to highlight one very important point which has alarmed me personally. Yesterday, the hon. Prime Minister in his reply talked about an 11-Point Programme. I welcome that 11-Point Programme. He made one very important point in it where he said that we want zero corruption in this country. I support him wholeheartedly if he really walks the talk.

Now, I am coming to my question. In 2014, he had mentioned that we will work with Switzerland and bring every penny of black money, which is

in Switzerland, back to India. I do not want to get into that issue about Rs. 15 lakh. I am not saying something about Rs. 15 lakh. I want to make a more serious point. I am not going to make a political point here at all. My point is, in the newspapers in the last few weeks, there was an issue about taxation with regard to Nestle. I do not care whether it is Nestle. For me, it is an X factor as we can call it. It is not about the company. We and Switzerland had a very good relationship for decades. We have worked with them, you have talked about economic issues with them, bringing black money from there and all that. You had committed to the nation that we will work closer with Switzerland and get all that information and bring that money back to this country.

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI SANDHYA RAY): Please conclude.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Yes, Madam. The Nestle issue is not about the company alone. The hon. Health Minister has confirmed that the Nestle report does not show anything bad about the Nestle product. They have given them a clean chit in a simple language. Now, we are at loggerheads with Switzerland, they have removed India from the 'most favoured nation category'. We are looking to be a global player, improving our relationships with all the countries, then why are we not working on this double taxation issue? How are we going to get more foreign investments? How is India going to build confidence? Nestle is a global brand, whether we like it or not. I am not praising a single brand. It is not about Nestle. It is about every foreign company which is looking to invest in India and it is a win-win situation for both of us and for Nestle also because there are a lot of companies like Nestle and most foreign companies, when we are talking about FDI, invest in India, create jobs, and create wealth for Indians which help the Indian economy. So, what is the logic of this Government and could you kindly clarify the stand on this?

Talking about agriculture, Sanjay ji is unfortunately not here but he extensively talked about agriculture. I appreciate that they have started many schemes but they have committed to a complete loan waiver especially from the State I come from, be it soybean, be it cotton, be it milk.

(1545/MM/RCP)

इनकी सरकार ने कहा था कि हम महाराष्ट्र के हर किसान का पूरा कर्जा माफ करेंगे। So, will this Government commit because eventually the economy is not doing well in Maharashtra? So, they have to completely waive off their loan.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : प्लीज, कम्प्लीट कीजिए।

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): So, I would like to ask the hon. Finance Minister regarding this. In the intervention she has made, she has promised and committed that they are going to give us a lot of money for agriculture, which I welcome. But will there be a complete loan waiver? आज ही सुबह हमारे सांसद भगरे जी ने कहा है, एग्रीकल्चर मंत्रालय, कॉमर्स मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्टर को इस पर निर्णय लेना होगा। महाराष्ट्र में चाहे प्याज हो, सोयाबीन हो, दूध हो या कपास हो, लेकिन सबसे अधिक क्राइसिस प्याज का चल रहा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 40 से 20 टके का एक्सपोर्ट लगाया है, उसके बाद पिछले हफ्ते चार हजार रुपये क्विंटल पर प्याज जा रहा था। लेकिन आज वह 1500 रुपये पर आ गया है। आज महाराष्ट्र का किसान रो रहा है। मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री से विनती है कि आप कॉमर्स और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से बात करें।

माननीय सभापति : धन्यवाद माननीय सदस्या।

श्री नरेश गणपत म्हस्के।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : आप हमेशा प्राइस स्टेब्लाइजेशन फण्ड के बारे में कहती हैं। If you can intervene, then it will be of great help to us.

I have two last points. You have even asked for money for census and surveys regarding this. In this Budget, now the Government talks about delimitation as well as महिला आरक्षण बिल। हम सभी ने इस बिल को पास किया था। प्रधान मंत्री जी ने कल इसके बारे में बोला है कि यह बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। अगर यह वर्ष 2029 में इम्प्लीमेंट होना है when will this Government have the census for delimitation? Our constituents are 23 lakhs.

माननीय सभापति : श्री नरेश गणपत म्हस्के।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : उसके बारे में आज रेड्डी जी भी बोल रहे थे कि आज हमें पांच करोड़ रुपये मिलता है ... (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति : धन्यवाद माननीय सदस्या।

माननीय सदस्य, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

1547 बजे

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) : महोदया, आपने मुझे सप्लीमेंटरी डिमांड फोर ग्रांट्स में मेरी पार्टी शिवसेना की तरफ से बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, मैं सबसे पहले महाराष्ट्र की जनता को नमन करता हूँ कि उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत का आशीर्वाद हमारी महायुति को दिया और संविधान बचाने का ढोंग रचने वालों को करारा जवाब दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी महायुति सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की विचारधारा के साथ अगले पांच साल काम करेगी और हम जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।

महोदया, आज जब हम अमृतकाल की बात करते हैं तो हम पिछड़े वर्ग के विकास की बात करते हैं, महिलाओं के विकास की बात करते हैं, युवाओं के विकास की बात करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण इस देश के विकास की बात करते हैं। हमारे लिए हमारे पंत प्रधान जी और वित्त मंत्री जी पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र हो, रिकॉर्ड एफडीआई हो, डिजिटल इंडिया हो, स्वच्छ भारत हो या आवास योजना हो, इन सभी के कारण आज देश एक नई दिशा में जा रहा है, विकसित भारत की तरफ जा रहा है।

यूपीए के समय हमारी अर्थव्यवस्था अनर्थ व्यवस्था बन गयी थी और रोज अखबारों में सिर्फ भ्रष्टाचार, आतंकवादी हमले और बर्बाद होती अर्थव्यवस्था की खबरें आती थीं, लेकिन आज हम भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं। भारत में निवेश को देखते हैं और रोजगार देखते हैं। आज भारत ध्रुव तारे की तरह विश्व के पटल पर चमक रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कैसे कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया।

(1550/YSH/PS)

सभापति महोदया, यूपीए की सरकार की तरफ से जारी 1.31 लाख करोड़ रुपये के ऑयल बांड्स का भुगतान मौजूदा व आगामी केंद्र सरकार को इस वर्ष अक्टूबर से लेकर मार्च, 2026 के बीच करना होगा। एक दशक पहले केंद्र सरकार की तरफ से जारी इस मूल्य के दो बांड्स के लिए अब मूल व ब्याज के तौर पर 20,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। इसके बाद वर्ष 2023 में सरकार को 22,000 करोड़ रुपये के बांड्स और वर्ष 2024 में 40,000 करोड़ रुपये के बांड्स का भुगतान करना होगा।

वर्ष 2026 में भी 37,000 करोड़ रुपये के बांड्स के लोन का बोझ उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारी सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र में सब्सिडी को 85 परसेंट तक घटाने का साहसिक कार्य किया है। वर्ष 2013 में यह सब्सिडी 25 बिलियन डॉलर थी, जो अब 3.5 बिलियन डॉलर तक सिमट गई है। इसके अलावा, पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेलों के निर्यात मूल्यों में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में यह 60.84 बिलियन डॉलर था, जो अब 84.96 डॉलर बिलियन तक पहुंच गया है, जो वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 12.59 परसेंट है।

यह फर्क सिर्फ आंकड़ों का नहीं, विचारधारा का भी है। आप ने कर्ज निर्भर भारत बनाया और हमने आत्मनिर्भर भारत बनाया।

*Madam chairperson, I had cleared it during the last session that the 'Rahu Kaal' has started after the entry of Shri Rahul Gandhi. With the blessing of Rahulji, now this Rahu-Kaal has affected the Mahavikas Aghadi in Maharashtra.

सभापति महोदया, कांग्रेस के लिए मैं सनी देओल का एक डायलॉग बोलना चाहूंगा - यह कांग्रेस का हाथ है, जिस पार्टी पर पड़ता है ना, वो उठता नहीं उठ जाता है। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी की भी महाराष्ट्र में इसी तरह की हालत हो गई है। उनकी मशाल अब बुझने लगी है। बालासाहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व वाला विचार भी राहुल जी के साथ जाने से उन्होंने जला दिया है और उसका नतीजा यह है कि आज उनको कांग्रेस के वोट बैंक पर निर्भर होना पड़ रहा है।

दूसरी तरफ हमारे पक्ष के प्रमुख नेता और उप मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे जी का धनुषबाण और मजबूत हो गया है, इसलिए महाराष्ट्र में 80 लाख लोगो ने शिव सेना को वोट दिया है। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व पर विश्वास रखा है, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व को बचाने का काम किया है। संविधान में जो दायित्व हमें दिया गया है, उसको लाड़की बहिण योजना, लाडका भाऊ योजना, आपला दवाखाना, समृद्धि महामार्ग और कोस्टल रोड जैसी योजनाओं के माध्यम से पूरा करने का काम किया है।

आज इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में मैं पंथ प्रधान जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आज 83 ग्रांट्स और 3 एप्रोप्रिएशन्स के माध्यम से कुल 87,762.56 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इसमें से 44,142.87 करोड़ रुपये का व्यय नेट कैश आउटगो के रूप में है और 43,618.43 करोड़ रुपये की धनराशि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की बचत और बढ़ी हुई प्राप्तियों के माध्यम से पूरी की जाएगी।

कृषि क्षेत्र के लिए 7,691.81 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया है।

सभापति महोदया, ये सभी प्रावधान विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र के सपने को साकार करेंगे और विपक्ष के साथी कह रहे थे कि सिर्फ 87000 करोड़ रुपये से क्या होगा? मैं समझ सकता हूँ कि उनको यह राशि क्यों कम लग रही है, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ डबल पैसे का भ्रष्टाचार किया है, चाहे 2जी हो, सीडब्ल्यूजी हो और अब एक नया स्कैम आया है। राहुल जी इंडी अलायन्स के नेतृत्व के नाम पर क्षेत्रीय पार्टियों को बरबाद करने का स्कैम कर रहे हैं।

(1555/RAJ/SMN)

जो विपक्ष के साथी कह रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था बुरी है, मैं उनके लिए कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। 2014 से 2024 के बीच, बैंकों की शाखाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मार्च 2014 में कुल 1,17,990 शाखाएं थीं, जो अब बढ़कर 1,65,501 हो गई हैं। ग्रामीण शाखाओं की संख्या 41,855 से बढ़कर 55,372 हो गई है। इसी तरह, सेमी अर्बन शाखाएं 32,504 से बढ़कर 45,314 और अर्बन शाखाएं 21,007 से बढ़कर 29,276 हो गई हैं। यह विस्तार ग्रामीण और शहरी भारत के बीच वित्तीय समावेशन को मजबूत करता है।

इस नई ऊर्जा और दृष्टि के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। यह केवल सुधार नहीं है, बल्कि एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण की यात्रा है। मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करता हूँ।

अंत में, मैं विपक्ष को एक शेर के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ :

इस मोड़ पर घबरा कर न थम जाइए आप
जो बात नई है, उसे अपनाइए आप
डरते हैं क्यों, नई राह पर चलने से
हम आगे-आगे चलते हैं,
पीछे-पीछे आइए आप।

धन्यवाद।

(इति)

1557 बजे

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : सभापति महोदया, सप्लिमेंट्री डिमांड्स फोर ग्रांट्स भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर दोबारा व्यापक चर्चा करने का एक उपयुक्त समय है। यह चर्चा उस समय हो रही है, जब दूसरे तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि रेट 5.4 प्रतिशत पर आ गया है। आरबीआई आई का अनुमान था कि अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत से बढ़ेगी। उपभोक्ता की खपत कमजोर हुई है। निगमित आय कर में वर्ष 2019-2020 में कटौती करने के बावजूद निजी निवेश नहीं बढ़ा है। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के सहारे यह अर्थव्यवस्था चल रही है। इस वर्ष 151890 लाख करोड़ रुपए सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। पर जैसे ही सरकार ने इसके क्रम में थोड़ी-सी कमी की, अर्थव्यवस्था के ऊपर सीधा-सीधा असर दिखना शुरू हो गया है। भारत का जो निर्यात है, वह कम हुआ है। गुड्स के क्षेत्र में भारत का शेयर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का सिर्फ 1.8 प्रतिशत है और सर्विसेज में वह शेयर 4.3 प्रतिशत है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार सदन के समक्ष 87762.56 करोड़ रुपए की मांग लेकर आई है, जिससे सरकार का खर्चा 3908276.56 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा।

सभापति महोदया, कोई भी अर्थव्यवस्था पांच बिन्दुओं पर खड़ी है। सबसे पहला, सेविंग्स बचत, दूसरा कंजम्पशन खपत, तीसरा इनवेस्टमेंट निवेश, चौथा प्रोडक्शन उत्पादन, पांचवा इम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ रहा है कि इन पांचों मापदंड के ऊपर भारत की अर्थव्यवस्था के परखच्चे उड़े हुए हैं। फरवरी, 2024 में जब वित्त मंत्री तथाकथित एक श्वेत पत्र लेकर आई थीं, मैंने उस समय भी कुछ आंकड़े दिए थे। आज मैं वे आंकड़े इस सदन के समक्ष दोहराना चाहता हूँ।

(1600/KN/RP)

इस मुल्क का वर्ष 2013-14 में जो सेविंग टू जीडीपी रेशियो था, वह 34 प्रतिशत था, वर्ष 2023-24 में वह घटकर 31 प्रतिशत रह गया है। जो प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जिस उपभोक्ता खपत की बात मैंने पहले की थी, वह वर्ष 2013-14 में 60 प्रतिशत था, वर्ष 2023-24 आते-आते वह 55 प्रतिशत पर गिर गया है। इनवेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो – जो निवेश अर्थव्यवस्था में होता है, वर्ष 2013-14 में इनवेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 33.8 प्रतिशत था, वर्ष 2023-24 में वह 29.6 प्रतिशत पर गिर गया है। जो ग्रॉस फिक्स्ट कैपिटल फॉर्मेशन है, वह वर्ष 2013-14 में 31.3 प्रतिशत थी, वर्ष 2023-24 में वह गिर कर महज 30.8 प्रतिशत रह गई है। जो बेरोजगारी दर है, वह वर्ष 2013-14 में 5.42 प्रतिशत थी, वर्ष 2023-24 में बढ़कर 8 प्रतिशत हो गई है। नवंबर, 2024 में जो बेरोजगारी दर थी, वह 8 प्रतिशत थी।

सरकार यह कहती है कि हमने वर्ष 2015 और 2023 के बीच 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। लेकिन मैं सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2004 से 2014 तक 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया था। सरकार यह कहती है कि हम 81.35 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दे रहे हैं। जब हम सरकार में थे तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए थे। हम चाहेंगे कि आप 140 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दीजिए, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि रोजगार कहां है? आपकी अर्थव्यवस्था में रोजगार नहीं पैदा हो रहा है, इसलिए आपको निःशुल्क राशन लोगों को देना पड़ रहा है। सरकार यह कहती है कि पिछले 5 साल में जो कृषि की वृद्धि दर है, वह 4.18 प्रतिशत थी। इस वर्ष वह गिरकर 4 प्रतिशत रह गई है। अगर पांच वर्ष में कृषि की वृद्धि दर 4.18 प्रतिशत से बढ़ी थी तो पिछले दस वर्ष में मनरेगा का बजट इतना क्यों बढ़ा है? वर्ष 2013-14 में, जिसे यह सरकार गड्ढे खोदने की स्कीम कहती थी, उस पर लागत 32,992.83 करोड़ रुपये आती थी, वर्ष 2024-25 में वह बढ़कर 86 हजार करोड़ रुपये हो गई है। मनरेगा के तहत जो पर्सन डेज थे, वर्ष 2014-15 में सिर्फ 165.64 करोड़ पर्सन डेज थे, वर्ष 2023-24 में 309.1 करोड़ पर्सन डेज हो गए हैं।

मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि पिछले इतने वर्षों से, हमारे जो किसान हैं, वे सड़क पर बैठे हुए हैं। हमारे जो किसान हैं, सरकार से बात करने के लिए वे दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, उन मांगों के ऊपर जिन मांगों को सरकार ने स्वीकार किया था, जब वे तीन काले कानून उन्होंने पास लिए थे। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि ये किसानों से बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? आप एक तरफ तो किसानों को अन्नदाता कहते हैं और दूसरी तरफ आप उनकी तौहीन करते हैं। उनके ऊपर टियर गैस छोड़ते हैं, उनके ऊपर रबड़ बुलैट्स चलाते हैं। आप लोग भारत के किसानों की रोज बेइज्जती करते हैं। मैं सरकार को यह भी बताना चाहता हूँ कि जो महंगाई दर थी, वह वर्ष 2013-14 में 5.3 प्रतिशत थी, वर्ष 2023-24 में वह बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई है। सरकार का जो कर्ज है, 31 मार्च, 2012 को वह 55,87,150 लाख करोड़ रुपये था। 31 मार्च, 2025 को सरकार का कर्जा बढ़कर 181,68,456.91 करोड़ रुपये हो जाएगा। दस साल में आपने भारत की आने वाली पीढ़ियों के ऊपर 112,85,394.83 लाख करोड़ रुपये का कर्जा बढ़ाया है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने, यह जो पैसा है, यह किस चीज पर खर्च किया है। आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही है। मैं जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करता हूँ।

(1605/VB/NKL)

वर्ष 2005 से 2014 तक जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8 प्रतिशत था। वर्ष 2015 से 2024 तक यह गिरकर 5.9 प्रतिशत रह गया है। सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट था, वह वर्ष 2013-14 में महज 5,02,858 करोड़ रुपए था। वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 16,53,070 करोड़ रुपए हो गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, वित्त मंत्री जी यहाँ से उठकर चली गई हैं, अगर सरकार लगभग 17 लाख करोड़ रुपए अपने खर्च चलाने के लिए मार्केट से उठाएगी, तो जो निजी क्षेत्र हैं, उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? आप निजी क्षेत्र को बढ़ाने की बात करते हैं, जब निजी क्षेत्र को क्रेडिट का एक्सेस नहीं होगा, अपने खर्च चलाने के लिए सरकार ही सारे पैसे इकट्ठे करेगी, तो भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से बढ़ेगी?

महोदया, मैं सिर्फ दो आंकड़े और देना चाहता हूँ। 26 मई, 2014 को रुपये के मुकाबले डॉलर का रेट 58 रुपए 58 पैसे था। उस समय यह कहा गया था कि डॉलर का रेट प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। आज डॉलर का रेट क्या है? आज यह 84 रुपए और 87 पैसे है। लेकिन हम ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, जो उस समय हुआ करती थी। आखरी में, मैं महंगाई की बात करना चाहूँगा। भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए जो अर्थव्यवस्था है, उनके रोजमर्रा का जो बजट है, जो घर का बजट है, वह उस पर निर्भर है। वर्ष 2014 में एलपीजी सिलेंडर 410 रुपए का हुआ करता था, वर्ष 2024 में वह 803 रुपए का है। पेट्रोल 71 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था, जो आज 94 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर है। डीजल जिसकी सबसे ज्यादा खपत हमारे किसान लोग करते हैं, वह 55 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था, आज वह 87 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर है। वर्ष 2014 में सरसों का तेल 90 रुपए लीटर था, आज यह 165 रुपए लीटर है। वर्ष 2014 में आटा 22 रुपए किलो था, आज यह 55 रुपए किलो है। दूध 35 रुपए लीटर था, आज यह 60 रुपए लीटर है।

सभापति महोदया, इस देश की गृहिणियाँ त्राहि-त्राहि कर रही हैं। आज आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। आप 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं, हम भी चाहते हैं कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो। लेकिन अर्थव्यवस्था में जो असमानता है, आज 10 प्रतिशत भारत के लोगों के पास भारत की 77 प्रतिशत पूंजी है। नीचे के जो 62 करोड़ लोग हैं, उनके पास महज 1 प्रतिशत भारत की पूंजी है। ऐसी असमानता से यह अर्थव्यवस्था किस तरह से चल सकती है? मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था को आप आम आदमी के लिए चलाइए। इस देश में सिर्फ एक शिबॉय मॉडल बनाकर वन नेशन, वन कम्पनी का जो प्रयोग है, वह भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से कुचल देगा।

(इति)

1608 बजे

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : माननीय सभापति महोदया, सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, 2024-25 पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं इसके सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

अगर देखा जाए, तो जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, पिछले 10 वर्षों में हमारी इकोनॉमी किस तरह की थी और 10 वर्षों के दौरान इकोनॉमी का जो परिप्रेक्ष्य है, 10 वर्षों के पहले हमारी इकोनॉमी एक वुन्डेड इकोनॉमी मानी जाती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत इकोनॉमी के मामले में एक ग्लोबल पावर हुआ है। पहले हम फ्रेजाइल-5 इकोनॉमी में थे। 10 वर्ष पहले, हमारी गिनती विश्व में पाँच सबसे कमजोर देशों में मानी जाती थी। आज हम विश्व में पाँचवीं लार्जस्ट इकोनॉमी हैं। आने वाले समय में, अमेरिका और चीन के बाद भारत का नाम होगा। मोदी जी के नेतृत्व में, पिछले 10 वर्षों में यह काम हुआ है।

(1610/PC/VR)

अगर हम यूपीए का टाइम देखें, हमारे कांग्रेस के मित्र अभी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि यह होना चाहिए, वह होना चाहिए। चलो, आपको मोदी जी पर विश्वास है, इसीलिए, आप कहते हैं कि यह होना चाहिए। लेकिन मैं यह बता दूँ कि दस साल पहले, वर्ष 2014 तक आपकी जो जीडीपी ग्रोथ थी, वह मात्र 4.7 परसेंट थी। आपके समय में जो इनफ्लेशन था, जिस महंगाई की आप हमेशा बात करते हैं, वह इनफ्लेशन आपके समय में डबल डिजिट्स में थे। 10.92 परसेंट की महंगाई आपके समय में थी और आपका फिसकल डेफिसिट, जो कि इतना कभी नहीं रहता है, वह यूपीए के टाइम में 5.8 परसेंट था। जब कैट ब्लीडिंग कर रही थी, वह 4.8 परसेंट था। करीब 6,80,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे।

दस साल पहले इकोनॉमी का यह हाल था। आपने पूरे देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान नहीं रखा। आप भ्रष्टाचार में डूबे रहे। चाहे 2जी स्कैम हो, उसमें 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटला था। चाहे कोल स्कैम हो, उसमें 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। चाहे कॉमन वेलथ गेम्स से लगाकर आदर्श स्कैम का करप्शन हो, हर तरह के करप्शन में आप डूबे थे, इसलिए अर्थव्यवस्था का आपने ध्यान नहीं रखा। अगर हम देखें तो आपने ग्रोथ स्टोरी को पूरी तरह से स्कैम स्टोरी में ट्रांसफॉर्म कर दिया था।

सभापति महोदया, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नेंस की बात करें, economic resonance की बात करें, तो जीडीपी ग्रोथ 8.2 परसेंट पर पहुंचकर भारत दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। उनके समय में इनफ्लेशन ग्यारह पॉइंट कुछ परसेंट के पास था, यह इनफ्लेशन हमने 5.4 परसेंट पर हमने रोक रखा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि फॉरेक्स रिजर्व ऑल-टाइम-हाई है, जो की करीब 658.2 मिलियन डॉलर का है। हम देखें कि ये सिर्फ नंबरर्स नहीं हैं, ये नेशन बिल्डिंग के नंबरर्स हैं।

अगर हम फाइनेंशियल इनक्लूजन की बात करें, तो बैंक्स भले ही नेशनलाइज्ड हो गए थे, लेकिन वे गरीबों के लिए नहीं थे। आज की तारीख में बैंक्स गरीबों के लिए भी हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से खाते खोलकर, करीब 34 करोड़ लोगों के खाते हैं, जिनके खातों में सीधे पैसा जाता है। यह माना जाता था, श्री राजीव गांधी जी खुद दुखी थी। वे मानते थे कि मैं एक रुपया भेजता हूँ और पंद्रह पैसे ही पहुंचते हैं। यह उनके खुद का एडमिशन है। लेकिन आज मोदी जी जब एक रुपया भी भेजते हैं, तो लोगों के खातों में वह एक रुपया पहुंचता है, किसी तरह का लीकेज नहीं होता है।

सभापति महोदय, अगर हम टैक्स रिटर्न की बात करें, तो पहले एक टैरर था। आज लोग विलिंगली टैक्स रिजीम में आना चाहते हैं। पहले 3.8 करोड़ टैक्स फाइल होता था, अब जो कि अब 6.86 करोड़ हो गया है। 48 करोड़ जन धन अकाउंट्स अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहले इनके सिर्फ स्लोगन थे, सिर्फ नारे थे। हम नारों से हटकर सॉल्युशन में विश्वास करते हैं। मोदी जी ने नारों से दूर होकर इस पर ध्यान केंद्रित किया कि निराकरण कैसे हो, सॉल्युशन कैसे हो?

जहां तक इनफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात है, अगर हम फिजिकल इनफ्रास्ट्रक्चर को की तरफ देखें तो जहां पहले 74 एयरपोर्ट्स थे, अब 149 हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7,63,000 किलोमीटर, अगर मैं अपने लोक सभा क्षेत्र की बात करूँ, तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि करीब 550 करोड़ रुपए की ग्राम सड़क योजना बनी, एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है।

जहां तक रेलवेज की बात है, 95 परसेंट ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यूपीए के टाइम में, वर्ष 2014 से पहले, सात से आठ लाख रूरल हाउस प्रतिवर्ष बनते थे। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 45 लाख, कहां सात लाख थे, अब 45 लाख रूरल हाउस प्रतिवर्ष बनते हैं।

अगर हम सोशल इनफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो दस साल पहले, यूपीए के टाइम में रूरल सैनिटेशन 39 परसेंट था। अब यह 97 परसेंट है।

(1615/IND/SAN)

महोदया, अपने आप में यह बहुत बड़ा काम हुआ है। जब हम गांव में जाते हैं तो वे लोग मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। खास कर महिलाएं मोदी जी को धन्यवाद देती हैं और हमसे कहती हैं कि उन्हें राम-राम कहना, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत आराम कर दिया है। जब ये बातें हम सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं के बराबर था लेकिन अब 100 प्रतिशत गांवों में बिजली है। उज्ज्वला योजना से मिट्टी के चूल्हे और धुएँ से महिलाओं को निजात मिल गई है। उज्ज्वला योजना के नौ हजार कनेक्शन हो गए हैं। इनका काम सिर्फ वोट बैंक बनाने का था, लेकिन हम स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखकर काम करते हैं।

हेल्थ केयर में आयुष्मान भारत योजना की अचीवमेंट देखें तो 33 करोड़ कार्ड्स इश्यू हो चुके हैं। सरकार ने हेल्थ सेक्टर में जितना खर्चा किया है, उसके बारे में ये सोच ही नहीं सकते हैं। पिछले दस सालों में 79 हजार करोड़ रुपये इलाज के लिए खर्च किए गए हैं। हम कह सकते हैं कि यह विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है। यूपीए सरकार ने दस साल पहले देश को गुमराह किया और कहा कि एनपीए सिर्फ दो लाख पचास हजार करोड़ रुपये का है जबकि वास्तविक आठ लाख पचास हजार करोड़ रुपये एनपीए था। पहले फोन बैंकिंग का कल्चर था। अब प्रोफेशनल बैंकिंग का कल्चर है और एनपीए को आईसीबी लाकर रेजोलूशन करके बैंकों की हालत अच्छी की है। एक बात दस साल पहले छिपाने वाली थी और पिछले दस सालों के दौरान ट्रांसपेरेंसी का जमाना आया है। फ्यूचर विजन और प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूँ तो पीएम गतिशक्ति और तीन मेजर रेलवे कोरिडोर और इंडस्ट्रीयल कोरिडोर हैं। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पाली संसदीय क्षेत्र में 7500 करोड़ रुपये इंडस्ट्रीयल कोरिडोर के लिए दिए हैं। डिजिटल रेवोल्यूशन भी आया है। गांव का छोटे से छोटा वेंडर भी डिजिटल पेमेंट लेता है। 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांजेक्शन यूपीआई से हुए। पीएम स्वनिधि योजना का अचीवमेंट अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर देखने वाला है। अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में करीब 78 लाख करोड़ रुपये स्ट्रीट वेंडर्स को देकर आर्गेनाइज्ड सेक्टर में लाने का प्रयास किया गया है। दो लाख तीस हजार लोग थर्ड टाइम क्रेडिट ले चुके हैं। 11 हजार करोड़ रुपये के कोलेट्रल फ्री लोन दिए गए हैं। पावर्टी एलिवेशन में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड दिया गया है। मनीष जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासियों को फ्री में क्यों नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि वे भी फ्री में अनाज लेना नहीं चाहेंगे। 34 लाख करोड़ रुपये डीबीटी से ट्रांसफर किए गए हैं। अगर राजीव गांधी जी की बात मानें कि 15 परसेंट पैसा पहुंचता था और 85 परसेंट लीकेज होता था तो इसका मतलब 34 लाख करोड़ रुपये में से 25 लाख करोड़ रुपये का लीकेज हो जाता और गरीबों तक पैसा नहीं पहुंचता। पीएम किसान योजना के लिए जो एलोकेशन एनहांस किया है, वह करीब 3132 करोड़ रुपये का है। शेड्यूल्ड कास्ट सब-प्लान के लिए 196 करोड़ रुपये, ट्राइबल्स के लिए 127 करोड़ रुपये का एलोकेशन पहली बार हो रहा है। टोटल एडिशनल कमिटमेंट 3500 करोड़ रुपये की है।

(1620/RV/SNT)

सभापति महोदया, अभी कांग्रेस पार्टी के हमारे एक साथी कह रहे थे कि बजट में किसानों को क्या मिला है? मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यूपीए सरकार के समय में किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपये का बजट हुआ करता था और मोदी जी के समय में अभी जो वर्ष 2024-2025 का बजट है, उसमें किसानों के लिए 1,50,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह डिफरेंस है। ये लोग आंकड़ों पर बात नहीं करेंगे। इतना बड़ा डिफरेंस है।

महोदया, इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ है कि 'इन्क्लूसिव फार्मर वेलफेयर' हुआ है। हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर एस.सी. और एस.टी. को लक्ष्य करते

हुए काम किया है। भारत के संविधान में 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' सोशल जस्टिस लाने हेतु सरकार के लिए एक तरह से नीति निर्देशक हैं। उसके लिए अगर देश में पहली बार काम हुआ है, तो यह मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। रबी सीजन में टाइमली सपोर्ट करने के लिए काम किया जा रहा है और एग्रीकल्चर को प्रायोरिटाइज्ड करने के लिए काम किया जा रहा है। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए 4,000 करोड़ रुपये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के प्रोजेक्ट्स के लिए दिए गए हैं। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सब्सिडी के लिए 106 करोड़ रुपये दिए गए हैं। एफपीओज़ के प्रमोशन एण्ड पब्लिसिटी के लिए 2 करोड़ 52 लाख रुपये दिए गए हैं। ये सारी सप्लीमेंटरी डिमांड्स एग्रीकल्चर के लिए मांगी गयी हैं, जो कि बहुत वाजिब है।

इन सारे प्रयासों का कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट यह होगा - building long-term agricultural assets; strengthening farmer collectives; modernising agriculture marketing; and creating sustainable farm infrastructure.

जहां तक रिसर्च की बात है तो हम एग्रीकल्चरल रिसर्च में काफी पीछे थे। दस साल पहले एग्रीकल्चरल रिसर्च न के बराबर होती थी। पर, अब एग्रीकल्चरल रिसर्च को मजबूत करने के लिए 192 करोड़ रुपये रखे गए हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए भी प्रावधान रखे गए हैं। आईसीएआर हेडक्वार्टर्स के लिए भी प्रावधान रखे गए हैं, जिससे हमारी रिसर्च मजबूत हो और इसका लाभ किसानों को मिले।

इससे चार बड़े फायदे होंगे - building agricultural research capacity; strengthening grassroot level extension; enhancing agricultural education; and promoting innovation in farming.

कांग्रेस और बीजेपी सरकार के बीच हम कुछ कॉन्ट्रैस्ट प्वायंट्स देखते हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे और एनसीपी की सुप्रिया जी भी किसानों के लोन्स माफ करने की बात कह रही थीं। कांग्रेस पार्टी का काम लोन वेवर का है और हमारी पार्टी का काम किसानों को स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट देने का है। The Congress always focussed on middlemen; we focus on direct benefits. They neglected infrastructure; we are building future for the country. What will be its impact? Its impact will be, comprehensive support from seeds to market; infrastructure creation by building farmers' future; and research integration by knowledge to field connection.

If we look at the era of Nehru, they neglected agriculture leading to food crisis. जो फूड क्राइसिस हुआ, यह नेहरू युग में ही हुआ। बाद में कभी फूड क्राइसिस नहीं हुआ। आज हमारे पास सरप्लस फूड है। We are ensuring food security. They focussed on heavy industry at farmers' cost; we are prioritising agricultural infrastructure. They have created dependency; we are creating sustainability.

इसमें रोड मेनटेनेंस फंड के लिए पैसे दिए गए हैं, सेन्ट्रल रोड्स के लिए दिए गए हैं और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए पैसे दिए गए हैं। इससे ये प्रभाव पड़ेंगे - ensuring quality maintenance of existing infrastructure; continuous modernisation of road network; investment in research and development; and enhancement of road quality standards and road safety initiative. यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मोदी सरकार द्वारा ह्यूमैनेटेरिएन्स ग्राउण्ड पर यह एक बड़ा स्टेप लिया गया - cashless treatment for accident victims and supervision of National Highway works.

(1625/RV/AK)

उसका ह्यूमैनेटेरिएन्स इफेक्ट यह पड़ेगा – immediate medical care for accident victims, reduction in accident-related fatalities, financial protection for family of victims, and enhanced road safety measures. इसको पी.एम. गतिशक्ति योजना से लिंक किया जा रहा है। इसको प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कनेक्ट किया जाए।

यूपीए और हमारी सरकार के बीच के कुछ कॉन्ट्रैस्ट प्वायंट्स हैं। The UPA built roads, we built complete transport ecosystem; the UPA focussed on construction, we focus on quality and maintenance; the UPA neglected safety, we prioritised human life. इससे अर्थव्यवस्था के लिए लॉजिस्टिक्स व्यवस्था बेहतर होगी। It will reduce transportation cost. It will enhance access to healthcare and education, reduce accidents for safety, better energy response, industrial corridor for development, etc.

Finally, I can say that the approach to road infrastructure is not just about connecting places, but it is about connecting possibilities. When we allocated Rs. 2,160 crore for maintenance, we are not just maintaining roads, but we are maintaining arteries of our economic growth and the provision of Rs. 127 crore for cashless treatment of accident victims. It shows that our infrastructure vision is not just about cement and concrete, but it is about care and compassion.

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1626 hours

DR. GUMMA THANUJA RANI (ARAKU): Madam, at the outset, I would like to thank you for allowing me to put forth the YSR Congress Party's views on the Appropriation Bill.

Before coming to the Appropriations, I would like to raise two important issues concerning my State of Andhra Pradesh in this House. The first point is that through you, I would urge the Union Finance Minister to take steps to halt the disinvestment of the Vizag Steel Plant. I would like to bring to your kind attention that the Visakhapatnam Steel Plant was set up after a decade-long public agitation in which 32 people had laid down their lives. The decade-long public agitation "Vishakha Ukku-Andhrulla Hakku" had resulted in the 17th April 1970 declaration of the then Prime Minister of India to establish a Steel Plant at Visakhapatnam.

The Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), the corporate entity of Visakhapatnam Steel Plant is a Navratna Company under the Ministry of Steel, Government of India. It is the largest public sector industrial unit in the State creating employment opportunities for close to around 20,000 people directly and many other indirect employment opportunities in the city of Vishakhapatnam. It is India's first shore-based integrated steel plant and a producer of a lot of steel products catering to the requirements of construction, infrastructure, manufacturing and automobile sectors.

I would like to draw the attention of the House to the fact that the plant had a good performance between 2002 and 2015 earning profits with positive net worth. The plant has pragmatically turned-around in 2002 after being reported to BIFR as a sick company. The company has around 19,700 acres of land currently and the valuation of these lands alone could exceed Rs. 1 lakh crore due to the location of the plant in the urban area.

The RINL currently has a capacity of 7.3 million tonnes and has taken up plant modernisation and capacity expansion recently, which made the plant to borrow loans from banks to take up the expansion work. Owing to the unfavourable steel cycle globally, the company was making losses since 2014-2015 and was finding it difficult to service the debt. One of the major structural issues that also lead to high cost of production is the absence of captive mine thereby affecting the profitability.

(1630/UB/GG)

Madam, we can surely say that the plant can again become profitable if we receive some support from the Government of India. Therefore, I would urge the hon. Finance Minister that instead of taking the disinvestment route, kindly do handholding with Andhra Pradesh and support some measures like allotting captive iron ore mines to bring down input cost and swapping high-cost debt with low-cost debt and converting debt into equity through equity conversion. The measures could ease the burden of debt servicing and improve financial sustainability of the plant.

The second major issue, especially in my constituency of Araku, is the relief and rehabilitation of people in the four mandals of Rampachodavaram because of the damage caused by the Polavaram Irrigation Project. In Chinturu and Yetapaka, for R&R, as on date, a total of Rs. 255.85 crore were spent. During the period of 2014-19, no amount was spent towards R&R. During the period of 2019-23, Rs. 252.84 crore were spent. In the last four years, 252 times more expenditure was made towards R&R. During the period of 2014-19, no PDFs were shifted. The displaced people have not received their compensation. I urge the Central Government as well as the State Government of Andhra Pradesh to ensure timely disbursement of the compensation package as well as providing secure alternative areas for rehabilitation, especially for the Tribal Community. The tribal people have already sacrificed a lot. I once again urge both the Central Government as well as the State Government to take immediate steps for clearing the pending compensation to be given to the project-affected families.

Madam, the Pradhan Mantri Kisan MaanDhan Yojana offers a contributory security policy. However, the assured pension of Rs. 3000 has been the same for the past five years. Given the average annual inflation, I would like to urge the Central Government to increase this amount to, at least, Rs. 7000. I hope the hon. Finance Minister will take into account these suggestions and incorporate them.

Thank you!

(ends)

1633 बजे

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : सभापति महोदया, मैं वर्ष 2024-25 की पूरक अनुदान मांगों के कटौती मांगों के प्रस्तावों के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदया, सारी पूरक अनुदान मांगों को मैंने अध्ययन किया है। देश में अभी सामाजिक, आर्थिक जनगणना नहीं हुई है। जो संवैधानिक प्रावधान है, उसमें आज देरी क्यों हो रही है, यह सरकार अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है, जहां सामाजिक आर्थिक जनगणना पूरी हो चुकी है। और जो आंकड़े ऊभर कर आए हैं, उनसे बिहार की भयावह तस्वीर दिखाई देती है। आप देखेंगे कि बिहार की 70 फीसदी आबादी प्रति दिन 70 रुपये से भी कम पर गुजारा कर रही है। उसके आर्थिक सुधार के लिए विशेष राज्य का दर्जा का प्रस्ताव, जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, आदरणीय राबड़ी देवी जी के नतृत्व में भारत सरकार को भेजा था। लंबे समय से यह मांग बिहार सरकार कर रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए, क्योंकि जो राष्ट्रीय औसत है, मानव विकास सूचकांक, उस स्तर पर बिहार को जाने के लिए यह आवश्यक मांग है। दो आंकड़े बहुत भयावह हैं। एक, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या बिहार के भीतर है। दूसरा, हम शिक्षा के क्षेत्र में हम सबसे पीछे हैं। बिहार में केवल मात्र सात प्रतिशत ग्रेजुएट हैं। हमारी उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो निवेश की आवश्यकता है, उस निवेश को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की अगर मदद नहीं मिलेगी तो बिहार राष्ट्रीय औसत से पीछे ही रहेगा और हमारी गरीबी उन्मूलन पर स्पष्ट प्रभाव आगे भी दिखाई देता रहेगा।

(1635/MY/RCP)

इसके लिए, अभी बजट में शिक्षा के लिए जो पैसे मांगे जा रहे हैं, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के जरिए, हमारे जो केंद्रीय प्रिमियम इंस्टीट्यूशंस थे, उसके लिए एक 'एक देश एक एडमिशन प्रणाली' का विकास किया गया। इसको हम सीयूईटी बोलते हैं। आज देश में बच्चों के एडमिशन के लिए जिस संस्था को यह काम दिया गया है, वह संस्था एनटीए है। यह संस्था पहले से ही एक विवादास्पद संस्था है। हम लोग दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय से पढ़ कर निकले हैं। इस विश्वविद्यालय का सत्र पहले जुलाई महीने में शुरू हो जाता था। आज एक निकम्मी संस्था के चलते एडमिशन का काम तीन महीने पीछे चल रहा है। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो अच्छे छात्र हैं, वे निजी क्षेत्र में चले जा रहे हैं। जो कमजोर छात्र हैं, वे सरकार की व्यवस्था के शिकार बनते जा रहे हैं।

महोदया, मैं किसानों के ऊपर इसलिए बात करना चाहता हूँ, मैंने देखा है कि आपने किसानों के लिए पैसे मांगे हैं। मैं कृषि संबंधी संसदीय समिति में सदस्य हूँ। फर्टिलाइजर के लिए पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। खासतौर से उत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब से लेकर कहीं भी फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं है। हमारे पास जो आंकड़े थे, हमारी जो उपलब्धता थी, वह हमारी जरूरत से ज्यादा है। जरूरत से ज्यादा उपलब्धता के बाद भी अगर किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, खासतौर से डीएपी जो गेहूं की बुआई के लिए अति आवश्यक है तो हमारे किसान गेहूं की कैसे बुआई कर सकते हैं? यह एक चिंतनीय विषय है। हम फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी का सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। फर्टिलाइजर जैसी महत्वपूर्ण चीज अभी तक

किसानों को क्यों नहीं उपलब्ध हो रही है? लंबे समय से हमारे किसानों की मांग रही है कि फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है, वह किसानों के खातों में सीधे जानी चाहिए, न कि कंपनियों के खाते में जानी चाहिए। ये कंपनियाँ भारत सरकार से सब्सिडी लेने के बाद भी किसानों तक फर्टिलाइजर नहीं पहुंचा पा रही हैं। इससे हमारे किसानों का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा, यह बात सोचने की है।

महोदया, भारत सरकार के मंत्री कई अवसरों पर कहते हैं कि हम एमएसपी की गारंटी देते हैं, हमेशा किसानों का पैसा बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन यूपीए ने कभी भी एमएसपी की गारंटी नहीं दी। एक आंकड़े बहुत साफ है, जब यूपीए की सरकार चल रही थी, तब देश में खाद्यान्नों पर खासतौर से गेहूं और चावल पर, हमने एमएसपी के ऊपर 140 परसेंट दाम बढ़ाने का काम किया। वहीं जो भाजपा और एनडीए की सरकार है, उसने पिछले दस सालों में मात्र 70 परसेंट ही दाम बढ़ाने का काम किया है। आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन आंकड़ों से खेल रहा है, उन आंकड़ों के अध्ययन से आप समझ सकते हैं।

महोदया, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर हमारे देश के किसान आंदोलित हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली आ कर अपनी बात रखना चाहते हैं। पिछले एक साल से वे दिल्ली के बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। जब भी वे दिल्ली आने के लिए प्रयास करते हैं तो उन पर आँसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। पुलिसिया उत्पीड़न का जो तरीका नहीं है, वह भी उनके साथ अपनाया जाता है। किसानों के नेता आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी स्वास्थ्य की जो चिंता पार्लियामेंट के जरिए होनी चाहिए, वह हमें देखने को नहीं मिल रही है।

महोदया, मैं अपनी बात को एक मिनट में समाप्त करना चाहता हूँ। हम आर्थिक संघवाद की बात कर रहे हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने उम्मीद की थी कि राजनैतिक संघवाद के साथ आर्थिक संघवाद के बिना हम कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर को खड़ा नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में 42 परसेंट राज्यों के पास जाने के बाद, बचे हुए 58 परसेंट के जो बंटवारे हैं, वह न्यायपूर्वक नहीं हैं। उस पैसे का इस्तेमाल जिस सार्वजनिक हित के लिए होना चाहिए, यह गरीबी उन्मूलन के लिए होना चाहिए। राष्ट्रीय औसत से नीचे जो पिछड़े हुए राज्य हैं, उनके पास उस फंड से पैसा जाना चाहिए। लेकिन, वह पैसा वहां न जाकर ताकतवर लोगों के हाथ में जा रहा है। वह पैसा उन राज्यों के पास जा रहा है, जो पहले से ही विकसित हैं। इस विषय पर कहीं भी चर्चा देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए, मैं इस अनुदान विधेयक का विरोध करता हूँ।

(इति)

1639 hours

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (PONNANI): Madam Chairperson, thank you for permitting me to take part in this very important discussion. I would like to use this opportunity to express my deep concerns with regard to the serious challenges faced by our national system in general and our economy in particular. As we all know, our nation is a modern nation. We are living in a modern country and various stages of history and dimensions of culture have led us to this modern condition, this modern state of affairs.

(1640/PS/CP)

Madam, it is a march of history; it is a cultural march; and it is a civilisational march. The most significant aspect, dimension, feature and factor of this historical march is our pluralism. When we deal with any field of our national life, including economy, we have to keep this very important pluralistic aspect of India's national system in our mind. But I am very sorry to note here that nowadays what is going on in the country is the crippling and toppling of our great traditions of our country. बुनियादी सवाल वही है। When we come to economy, there is poverty, unemployment and inflation. But we have to take the backward communities, backward sections of the society, sidelined society, and marginalised society if you really want our economy to grow and progress.

Madam Chairperson, our country has imbibed and observed every cultural aspect of vividity and plurality of the civilisational scenario of the world. We remember the song of Raj Kapoor, whose birth centenary India celebrated recently. People throughout the world are remembering him. Now, I say one line from his song, '*Phir Bhi Dil Hai Hindustani*'. When welcoming everything from various cultural spheres of human lives, we were keeping that heart of India alive, and that *Hindustani Dil*, that heart of India, is always pluralistic. When we were listening to the speeches of the hon. Members on the other side of the House, they were all referring to *Pichda, Dalit, and Alpsankhyak*. What is the condition of minorities in the country? Along with secularism, socialism also belongs to the cardinal mottos of our system. But being allergic to these terms, it has become a kind of ailment nowadays. And I would like to emphasise that justice is denied to the backward communities and backward sections of the society including the minorities. The rights of the minorities are

eroded. Where will we reach? Instead of taking the nation to progress, nowadays, there are engineering and encouraging actions to search places of worship under the other religion's places of worship. That is going on in the country especially concerning certain sections of the society. Instead of making attempts to solve the basic problems faced by the sidelined society and marginalised sections of the society, what is going on is that policies are being adopted for the subversion of the basic ethos of our nationhood and fundamental principles of the society. It is equal to ridiculing, abusing, and defaming the system. It destroys and disturbs the social peace and peaceful coexistence in the country.

Madam, I would like to emphasise here that when we specifically focus on the economy, the real power today is technological power. Technological advancement is highly essential. India has reached that race. We admit it. But along with this digital revolution, we have to take into consideration the conditions of our farmers. That is very, very important. World is leading. The world is going, reaching and marching towards a quantum technology. But the conditions of our farmers are still the same in the country. Even now, they are on strike. It is very unfortunate.

Madam Chairperson, I would like to conclude my remarks by quoting the words of a king of India, who ruled the country centuries back. He said, and I quote:

“The cultivators are the source of prosperity. I have encouraged them and shall always watch over their condition that no man may oppress and injure them, for if a ruler cannot protect the humble peasantry from the lawless, it is a tyranny to extract revenue from them.”

I am quoting it from Bharat Bhushan Gupta's book – *India Through The Ages*. A king of India, Sher Shah, made this remark centuries back. And even now, it is unfortunate to see that the farmers are on strike for their basic rights.
(1645/NK/SMN)

So, first of all, that has to be corrected and undone before taking the economy of the country into progress.

Thank you, Madam.

(ends)

1645 hours

*SHRI GURMEET SINGH MEET HAYER (SANGRUR): I thank you, hon. Chairperson ma'am for giving me the opportunity to speak on Supplementary Demands for Grants.

Ma'am, all hon. Members from the treasury benches have emphasized that India has become the fifth largest economy in the world. But, the ground reality is dismal. We are representatives from all parts of India. We also know about data and statistics.

As far as per capita income is concerned, we are at 141 number. Only 10 per cent people out of 140 crores have an income of over Rs. 25,000/-. So, 90 per cent people earn less than Rs. 25,000/- per month. In 2014, the hon. P.M. had assured the farmers that their income will be doubled. In 2011, a Central Committee had been constituted. The present P.M. was C.M. of Gujarat at that time. At that time, he said that MSP guarantee should be provided by the Government.

However, Sir, 11 Budgets have been presented after this Government came to power. But, no budget ever mentioned about these promises. Our farmers from Punjab ushered in the Green Revolution. They made us self-dependant in foodgrains. These farmers had to launch an agitation for getting withdrawn black laws. Over 700 farmers were martyred. A written agreement was signed by the Central Government and protesting farmers that MSP guarantee will be given to the farmers.

Over 300 days have passed. The Haryana-Punjab border has been sealed as if it is Pakistan border. The Government asked the farmers not to bring tractor-trolleys. The farmers abided by it. Only

* Original in Punjabi

100 farmers wanted to come to Delhi on foot. However, even they are not being allowed to come to Delhi to protest.

Our aged farmer leader Shri Jagjit Singh Dellewal is sitting on fast unto death. Sir, he has children and grand-children. His condition is deteriorating. He is not protesting for his personal gains. He is sitting on fast unto death for welfare of farmers of the country.

So, I urge upon the Government to look into this matter seriously. The Central Government has waived off Rs. ten lakh crores worth of loans of industrialists. But the loans of farmers worth only 18.5 thousand crores are not being waived off.

A few days ago, we celebrated the 75th anniversary of our constitution. But, farmers of Punjab are not being given right to speech and right to free movement. Shri Jagjit Singh Dallewal, the farmer leader is not being allowed to come to Delhi. Sir, 80 per cent Punjabis fought for the independence of the country. Our Punjabi soldiers regularly attain martyrdom for protecting the country. But, our farmers are suffering. They ushered in the Green Revolution and made the country self-reliant in production of foodgrains. We used to import foodgrains. Our soil was degraded. Our waters were polluted. What have these farmers got in return?

So, I urge upon the Government to fulfill the promises made to the farmers. MSP guarantee should be given to them. No more farmers should attain martyrdom.

Thank you.

(ends)

(1650/SK/RP)

1650 hours

*SHRI SUBBARAYAN K. (TIRUPPUR): Madam Chairperson, Vanakkam. I want to take part in the discussion on the Supplementary Demands for Grants and express my views. When we look into the state of affairs in the country, it clearly shows what the policy of this Government is. This Government wants to show that nation has progressed. But actually growth has seen a decline. Inflation has increased. Unemployment has also increased in an unprecedented manner. Micro Small and Medium Enterprises are in the verge of destruction. Corporate giants have flourished. Foreign Direct Investments has captured our domestic market. These factors explain that where the nation is heading to. There is a defect in the thought process of this Union Government. The vision of the ruling party is as it says that Corporate Giants like Adani and Ambani are creating social wealth in the country. Is it true? Farmers and Labourers create this social wealth. This ruling dispensation is not even aware of this fact. They think with a different and wrong economic perspective. Ten years ago, while presenting the first Budget of this NDA Government, the then hon. Finance Minister made a statement and it clearly enunciates this Government's stand. They announced that the Union Government will create a conducive environment ensuring free flow of Foreign Direct Investment in India. Farmers and Labourers are not in their vision. Rather Corporate giants, businessmen and Multi-national companies are occupying their minds. Therefore, their rule is in favour of the multi-national foreign companies. Their regime is of Foreign Direct Investments. Corporate Giants rule the country on their behalf. That is why I will say this Government has morally failed to rule this country. They have lost the faith of the people. They have betrayed the

* Original in Tamil

people. In a short span of time, I cannot say everything. Still I will be saying important points. What this Government has given as assurance to WTO. This Government has accepted the instruction of WTO not to fix remunerative price for the farm produce grown by farmers. That is why this Government is acting against the farmers of this country. Devil is teaching lessons from Vedas. I have seen a devil teaching lesson for the last few days. The way they show that this Government is protecting the Constitution and the Nation. But it is a mere eyewash. This is unacceptable. Finally, I want to say one thing. They claim to eradicate corruption from this country. Let them, in the first instance, prove their honesty by asking apology for the electoral bond irregularities. They should also be punished. Those in power termed it as legal although the Hon Supreme Court categorically stated the electoral bonds as illegal. Should they rule us? Will they run this country in a legitimate manner? Only they have to answer this question. If you say you are opposing corruption, please clarify who are all with you in Maharashtra How did they get powerful posts in the Government? What is the reason behind that? If they unite with you, they can engage in corrupt practices. If they oppose you, they will be termed as corrupt persons. What a double standard this Government practises. Finally, I want to say that this Government is running on the belief of superstitions. They want to continue to be in power by misguiding the people through superstitions and misconceptions. Cycle of History is on the move and it is for sure that the Modi led Government will definitely fall very soon. Thank you. Vanakkam.

(ends)

(1655/KDS/NKL)

1655 बजे

श्री राजाराम (काराकाट): धन्यवाद सभापति महोदया, पांच ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यह बयान लगातार सत्तापक्ष की तरफ से इतराते हुए आता है, लेकिन वे इस बात की चर्चा नहीं करते कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कहां है? डेमोक्रेसी का इंडेक्स क्या है? लोन कितना हो गया है? हेल्थ और एजुकेशन के मामले में ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट पर हम कहां टिके हुए हैं? इस पर वे चर्चा नहीं करते हैं। अडानी की प्रॉपर्टी पर वे इतराते रहते हैं कि उनकी संपत्ति बढ़ेगी तो देश की संपत्ति बढ़ेगी। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। 7 हजार 795 करोड़ रुपये का एचडीआईएल प्रोजेक्ट, जिसको अडानी प्रॉपर्टीज ने 285 करोड़ रुपये में लिया। 1700 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी रेडियस एस्टेट्स एंड डेवलपर्स को अडानी गुड होम्स ने 76 करोड़ रुपये में लिया। 1175 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी नेशनल रेयॉन कॉरपोरेशन को अडानी ने 160 करोड़ रुपये में लिया। 12 हजार करोड़ रुपये की एस्सार पावर एमपी लिमिटेड को अडानी पावर लिमिटेड ने ढाई हजार करोड़ रुपये में लिया। 3 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी दिग्घी पोर्ट लिमिटेड कंपनी को अडानी पोर्ट ने 705 करोड़ रुपये में लिया। कुल मिलाकर 61 हजार 832 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को 15 हजार 977 करोड़ रुपये में खरीदा गया। यह एस्टिमेंट बैंक ने लगाया है, हमने नहीं।

महोदया, मोदी जी यह कहते हैं कि ये वेल्थ क्रिएटर्स हैं। ये वेल्थ क्रिएटर्स हैं या ... (*Expunged as ordered by the Chair*) हैं? ये ... (*Expunged as ordered by the Chair*) हैं, वेल्थ क्रिएटर्स नहीं हैं। अगर इसी ट्रिकिल डाउन थ्योरी के तहत चूंचू करके विकास हो जाता, तो जब ट्रंप अहमदाबाद आए थे, तो झुग्गी झोंपड़ियों के सामने दीवार क्यों खड़ी कर दी गई थी। गुजरात मॉडल की बात होती है कि यही तरीका देश का है। अमीरों के बढ़ने से आम आदमी की गरीबी कहां दूर हो गई? कहां आम आदमी के जीवन में खुशहाली आ गई? हम देख रहे हैं कि विषमता बढ़ रही है और इसी को हिन्दुस्तान का विकास कहा जा रहा है।

महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन के साथ जो समझौते हुए, उनको लागू करते हुए एमएसपी सी टू + 50 परसेंट दीजिए। किसानों को आत्महत्या से रोकिए। जमीन अधिग्रहण के मामले में बहुत संघर्ष के बाद वर्ष 2013 को जो कानून बना, उसे लागू करके किसानों को मुआवजा दीजिए, इससे भागिए नहीं। स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैं कुछ क्षेत्रीय मांगों को उठाकर अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे यहां दो-दो एनटीपीसी हैं। देश को हम बिजली देते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो समझौते बिजली, रोजगार देने के मामले में हुए हैं, उनमें ग्रामीणों की लगातार उपेक्षा हो रही है और भारी विक्षोभ बढ़ रहा है। इस पर ध्यान दिया जाए। इंद्रपुरी जलाशय बिहार में बहुत जरूरी हो गया है। बारुन-बिहटा रेलवे लाइन, डिहरी-डुमरांव बलिया रेलवे लाइन, डिहरी में रेल कारखाने की प्रधान मंत्री जी ने भी घोषणा की थी और डेहरी में स्वरा हवाई अड्डे के बारे में भी घोषणा की थी। आप जब बिहार जाते हैं, तो केवल ऐसे ही ब्लैंक घोषणा मत कीजिए, बल्कि उसको लागू भी करिए।

महोदया, सुधाकर जी ने भी एक बात उठाई कि जो गरीब राज्य हैं, उनको सहायता दीजिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। जातीय जनगणना कराकर देश में जो उपेक्षित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको बाकायदा सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। इन मांगों को दोहराते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो एक खाका खींच रहे हैं कि हम अमीर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, अगली पीढ़ी पर हम कितना कर्ज छोड़कर जा रहे हैं? इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि कितना कर्ज बढ़ता जा रहा है? इन आंकड़ों को भी आप सदन में ले आइए। अगर हिम्मत है, तो ले आइए, नहीं तो ऐसे ही अपनी पीठ मत थपथपाते रहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

(इति)

(1700/VR/MK)

1700 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Madam, Chairperson. Before commencing my speech with regard to various Supplementary Demands for Grants submitted to this House, I would like to raise a serious technical matter of grave concern regarding the parliamentary procedure in reappropriation of grants for which I am seeking a specific clarification from the hon. Minister. I am also seeking a ruling from the hon. Speaker also.

Madam, in the introductory note of Supplementary Demands for Grants itself, it is clearly stated that, "Besides stock and provision of Rs.126 lakh is being sought, Rs.1 lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases of involving new service or new instrument of service". This is the introductory note.

Madam Chairperson, as far as new instrument of service is concerned, we all know that it is a relatively large expenditure, that is, the result of a significant expansion of an existing policy or activity. The reporting limits for a new instrument of service are up to 20 per cent of the original appropriation or up to Rs.100 crore whichever is higher. Amount exceeding 20 per cent of the original appropriation or above Rs.100 crore requires mandatory approval from the Parliament.

Madam, you may be pleased to see that to incur the expenditure on a new instrument of service, prior approval from the Parliament is required through Supplementary Demands for Grants. In an emergency, the Contingency Fund of India can be used to meet the expenditure until Parliament authorises it. This arrangement should only be used when the Parliament is not in Session. There are two methods of re-appropriation. We all know, I need not explain it. You are having savings in a particular Head. If you are having a saving, it can be brought into another Head.

There is another way to do it. You can take money from the Contingency Fund of India and later re-appropriate through the Supplementary Demands for Grants. If you are taking advance from the Contingency Fund of India, you have to get the prior approval of the Parliament or immediately after taking the

advance, you have to lay a statement in the Parliament that you have taken an advance.

I would like to refer to para 5 of the Delegation of Financial Powers Rules 2024. It very clearly stipulates that in such cases, the following procedure recommended in the 4th Report of the Sixth Lok Sabha Committee on Papers Laid should be observed. I quote:

“As far as possible, before such withdrawal is made, the concerned Minister may make a Statement on the floor of the Lok Sabha for information giving details of the amount and the scheme for which the money is needed. In emergent cases, however, where it is not possible to inform the Members of the Parliament in advance, the withdrawal may be made from the Contingency Fund of India and soon thereafter, a Statement may be laid on the Table of the Lok Sabha for the information of the Members.”

Madam, I would like to seek a clarification from the hon. Finance Minister. Since there is a paucity of time, I would request you to refer to Grant no.71, which pertains to the Ministry of New and Renewable Energy, in which Rs.100 crore advance is being withdrawn from the Contingency Fund of India for meeting expenditure under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana and Rs.35 crore towards grants for creation of capital assets. That means, an amount of Rs.100 crore has already been taken as advance for Demand No.71. So, there are many re-appropriations, but I am not going into all the examples.

I would like to know from the hon. Minister whether a Statement, as stipulated by the Rules, is being laid on the Table of the House. If it is not made, kindly state the reason. I would like to seek a specific clarification from the Minister, and if such a Statement is not laid on the Table of the House, I would also seek a ruling from the hon. Speaker regarding this matter. This is a technical objection which I would like to make.

Madam, now I would like to come to the Demands for Grants. This is the 2024-25 First Batch of Supplementary Demands for Grants consisting of 83 Grants and 3 Appropriations. The gross additional expenditure is Rs.87,762 crore. Out of this, the net cash outflow is Rs.44,142.87 crore. Technical Supplementary is Rs.43,618 crore. Token Supplementary Demand for Grants is Rs.1.26 crore, totalling to Rs.87,762 crore.

(1705/SAN/SPS)

Out of this amount, Rs. 13,000 crore are for agriculture and allied activities, Rs. 12,000 crore for the Department of Telecommunications and more than Rs. 12,000 crore for the Ministry of Defence.

Madam, now it has become a usual practice of Parliament to bring a series of Supplementary Demands for Grants in every financial year. The Public Accounts Committee has observed, rather reiterated, that the Ministers and the Departments have been coming with Supplementary Demands for Grants without conducting a proper scrutiny of the expenditure incurred and likely to be incurred by them during the financial year. This is happening due to the lack of foresight of various Ministries and Departments.

For example, I would like to take Demand No. 50 regarding the Cabinet. There is actually an adjustment as there are savings also. The Demand seeks Rs. 4,787.44 crore for the Cabinet expenditure. For what is it being used? Out of this amount, Rs. 4,666 crore are being used for capital expenditure on account of cyber security research and development. My question to the Ministry is: Is it an unforeseen emergent expenditure? This indicates a bad budget planning process. So, I urge upon the Ministry to adhere to the strict compliance of Financial Rules and the directions of the Public Accounts Committee to avoid Supplementary Demands for Grants because the Cabinet expenditure of Rs. 4,666 crore for cyber security research and development has to be incurred. It is coming as a Supplementary Demand for Grant. What is the emergent situation? Why was it not anticipated? It only means that a totally bad budget planning process is being followed and that has to be corrected. That is the first submission that I would like to make.

Madam, now I come to the state of economy. The GDP growth rate for the second quarter of the current year is just 5.4 per cent, the lowest in the last seven quarters, but what is projected in the Budget document is seven per cent real GDP growth and 10.5 per cent nominal GDP growth.

This was stated by the hon. Finance Minister, Nirmala Sitharaman ji, in her Budget Speech. When we are proudly claiming that India is the fastest growing economy in the world, targeting to be the third largest economy in the world and a developed country by 2047, the basic genuine issues of the common people are still there. There has been exponential growth of unemployment in the country, which was never experienced in the country during the post-Independence period. There are also so many other issues like price rise and poverty which are remaining as such. They need to be addressed. I would like to know from the hon. Minister how she is going to address all these things.

My next point is regarding the expenditure. When the Government and the Minister is coming with Supplementary Demands for Grants, the Government has to submit to the House the data regarding expenditure. The expenditure of the Government during the current financial year has also to be analysed. The monthly review of the accounts of the Government of India up to October 2024 reveals a total Government expenditure of Rs. 24,73,898 crore. It means that 51.3 per cent of the total Budget allocation has already been spent. That is very good.

I would like to seek a clarification from the hon. Minister on one point. When I examined the expenditure on MSME sector – Micro, Small and Medium Enterprises – which is a labour-intensive sector and plays an important role in the growth of the economy, I found that it is less than 50 per cent. I have gone through the Performance Smartboard of the Department of Economic Affairs and it is being seen that the total Budget allocation is Rs. 22,137.95 crore for the MSME sector during 2024-25 and the revised outlay is Rs. 16,468.42 crore. I do not know how the revised outlay has come now because the revision will come only after the financial year ends. In this case, the advance revision of outlay has come. I cannot understand this. I request the hon. Minister to clarify this. The revised outlay is of Rs. 16,468.42 crore and the expenditure incurred so far is Rs. 3,992.73 crore. It means that less than 50 per cent of the total

budget outlay has been spent during these six months on MSME. I would like to seek a clarification from the hon. Minister as to why it is so low.

Madam, a major component of the allocation in the Supplementary Demands for Grants is Rs. 13,000 crore for the agriculture sector. You know very well that the farmers across the country are on the street to protest against the shortage of the DAP, di-ammonium phosphate. The RSS-affiliated Bharatiya Kisan Sangh is also on the streets and participating in the strike.

(1710/SNT/MM)

The doubling of farmers' income by 2022, was one of the promises made by the Prime Minister during 2014. What happened to the doubling of the income of the poor farmers? I would like to urge upon the hon. Minister regarding three more issues. I will only mention bullet points.

There is GST of 18 per cent on renting of commercial property. A registered person, who takes a rented building from an unregistered person, shall have to remit 18 per cent of GST through reverse charge mechanism. That has to be reviewed. The second point is regarding the LIC. The first-year commission of the LIC agents have been reduced from 35 per cent to 28 per cent, thereby seven per cent of the commission has come down. Fourteen lakh LIC agents are being suffered. That has to be corrected. It is because of the IRDAI's direction. As regards cashew industry, 2.5 per cent of custom duty is to be reviewed. Also, regarding the PF pension, this morning in the 'Zero Hour', I have already stated about it. All these issues have to be considered and I am seeking very specific clarification regarding all these points.

With these points, I would like to oppose the Supplementary Demands for Grants put forward to the House by the Government. Thank you very much.

(ends)

1711 बजे

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आज सदन में सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक भारत की संचित निधि से 87762.56 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी और वितरण का प्रस्ताव करता है। लेकिन इसका स्वरूप और आवंटन हमारे देश की असल जरूरतों और जनता की भलाई से कोसों दूर लगता है।

सभापति महोदया, कुछ समय पहले भी हमने इस सदन में बजट देखा था और आज अनुपूरक अनुदान मांगों पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज से एक महीने से कुछ ज्यादा समय के बाद फिर हम एक आम बजट देखेंगे। लेकिन मुझे यह आंकड़ों की बाजीगरी से ज्यादा कुछ नहीं लगता है। सत्ता पक्ष के लोग बड़ी जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे कि लाखों-करोड़ रुपये का प्रावधान किसानों के लिए किया गया है। महोदया, अगर किसानों के लिए इतना ही प्रावधान किया गया था तो मैंने वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव में माननीय प्रधान मंत्री जी को मंच से वायदा करते हुए सुना था कि मार्च के बाद आवारा और निराश्रित पशुओं की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन क्या उन आवारा पशुओं के लिए कोई कार्य योजना सरकार ने बनायी है? अगर बनायी है तो यह सदन, यह देश और जनता उस बारे में जानना चाहती है। अगर लाखों-करोड़ रुपये किसानों के लिए आवंटित हुए हैं तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के कोने-कोने तक आज किसान डीएपी के लिए लंबी-लंबी लाइन लगाकर के पुलिस की लाठियां खाने पर मजबूर क्यों हैं? मैंने इस देश के उद्योगपतियों का लाखों-करोड़ रुपया माफ होते देखा है, लेकिन क्या सरकार गांव के गरीब किसान का कर्ज माफ नहीं कर सकती है? हम सरकार से मांग करेंगे कि गांव के गरीब किसान का कर्ज भी माफ किया जाए।

मान्यवर सभापति जी, जब किसान अपना हक मांगने के लिए निकलता है तो उसे पुलिस की लाठी खानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश ने देश को कई प्रधान मंत्री दिए हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए सरकार ने क्या कोई योजना बनायी है? क्या सरकार कोई उद्योगधंधा लगाने जा रही है, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।

सभापति जी, शिक्षा और स्वास्थ्य इनकी प्राथमिकता में नहीं है। शिक्षा मंत्रालय के लिए 8500 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 7300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो देश की बढ़ती जनसंख्या और स्वास्थ्य संस्थानों की जरूरत

के हिसाब से अपर्याप्त है। अगर हम मेडिकल कॉलेज को देखें तो उत्तर प्रदेश में कागजों पर तो बहुत मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में न भर्ती हो रही है और न ही इक्विपमेंट है। अगर हम जिला अस्पतालों की हालत देखें तो इतनी दुर्दशा है कि हॉस्पिटल में कुत्ते विचरण करते हुए पाए जाते हैं। बेड पर कुत्ते सो रहे हैं, दवाई नहीं है और हर एक बीमारी के लिए केवल एक दवाई दी जाती है-पेरासीटामोला

(1715/YSH/AK)

सभापति महोदया, पिछड़े और गरीब वर्गों की इन अनुपूरक मांगों में अनदेखी की गई है। इसमें दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है। इसमें सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय को 4200 करोड़ रुपये, जनजाति मंत्रालय को मात्र 3100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह सब सरकार की सामाजिक जिम्मेदारियों से विमुखता को दर्शाता है।

यह सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स सरकार की जनविरोधी नीतियों और वित्तीय अनुत्तरदायित्व का प्रतीक है। यह जनता की समस्याओं की अनदेखी है। इसमें गरीबी और महंगाई से निपटने का कोई ठोस प्रावधान नहीं दिखता है।

जल जीवन मिशन के तहत, हर घर जल योजना का हर जगह बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर, जो सड़कें विगत सालों में बनी थीं, आज एक-एक सड़क खोद दी गई है, पाइप लाइन्स डाल दी गई हैं। सरकार उसकी जांच करवाए। सरकार सड़कों को रिपयेर करवाने का काम करे। मैं यह बात दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि सरकार बदलेगी और जब कभी जांच होगी तो आजादी के बाद जल जीवन मिशन सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा।

माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं दो लाइन्स कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

“सच बात मान लीजिए चेहरे पर धूल है,
इल्जाम आइनों पर लगाना फिजूल है।”

(इति)

1717 बजे

सुश्री सयानी घोष (जादवपुर) : सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, साथ ही इस अपॉर्च्युनिटी के लिए मैं अपनी पार्टी की भी आभारी हूँ।

Madam, demanding for Supplementary Demands for Grants is a Constitutional pre-arrangement and I agree that it should definitely not be objected. But it also raises another question. Why does the Government need further allocation when it has not been able to spend what it already has?

In the Financial Year 2024, the Government's final consumption expenditure was 14 per cent, but it decreased to 4.4 per cent in the second quarter of Financial Year 2025. This means that the Government has spent much less this year as compared to last year. In the first quarter of 2024-2025, the Government's spending was Rs. 4.15 lakh crore and many cited the Model Code of Conduct as a reason for spending less. But in the second quarter, it further decreased to Rs. 4.1 lakh crore.

Madam, to my simple understanding, this grant is being demanded from the exchequer, but this is the money which is collected from the people and it is meant to be spent for the people. Since Prof. Saugata Ray has already spoken about the technical aspects, today I choose to speak on what this Government has delivered to the people of this country, namely the utilisation of resources in Departments it is seeking additional grants for and also its complex relationship with the State of West Bengal.

सभापति महोदया, इनके बुलडोजर के चलते भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। भारत में एक मिडिल क्लास, जो एक साल पहले वेजिटेरियन थाली 100 रुपये में खाता था, आज वही वेजिटेरियन थाली 152 रुपये की हो गई है। टमाटर की कीमत 247 प्रतिशत बढ़ गई। आलू की कीमत 180 प्रतिशत बढ़ गई। लहसुन की कीमत 128 प्रतिशत बढ़ गई और तेल, नमक, आटा, मैदा की कीमतें 18 प्रतिशत बढ़ गई हैं। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसे लेकर बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन आज अमृतकाल में थैली भरकर पैसे लेकर जाता है और पॉकेट में आलू, टमाटर, प्याज लेकर घर वापस आता है।

सभापति महोदया, पहले माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार और आज उनके विचार में महंगाई एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। विश्वगुरु, विश्व बंधु इस अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं।

Madam, 74 per cent of the Indians are unable to afford a healthy diet. The household savings have plunged to a 50-year low. Around 48 per cent of the households in this country are facing a financial crisis. उनका खर्चा उनकी कमाई से ज्यादा है।

The economic inequality in India is at a 100-year high. The country's GDP growth rate for the second quarter of 2024-2025 decreased to 5.4 per cent, which is the lowest in two years. The Government's total debt has reached a staggering Rs. 176 lakh crore and the total debt is expected to soar up to Rs. 185 lakh crore by the end of the financial year.

आज आपके उधार की वजह से हर हिन्दुस्तानी पर सवा लाख रुपये का बोझ चढ़ गया है और आप उनकी मजबूरी को अपनी ताकत समझते हैं। पश्चिम बंगाल में आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वे मुझे पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल दो करोड़ नौकरी देने का वायदा किया था, अर्थात् साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ? उन वादों का क्या हुआ?

(1720/RAJ/UB)

मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि

पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई-कोई
वादे तो सभी करते हैं, निभाता है कोई-कोई

Madam, as per the latest report by CMIE, the unemployment rate has risen to 9.2 per cent in June 2024 as compared to 4.9 per cent in 2013-14. Female unemployment rate is much higher at 18.5 per cent in June 2024 as compared to 7.7 per cent in 2013-14. Around 37 per cent of working women are unpaid. In rural areas, this figure is at a horrific 43 per cent. प्रधान मंत्री जी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' बोलते हैं, अगर ऐसा ही है तो आज भारत के लोग देश छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2023 के बीच 6,70,000 भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी। सिर्फ वर्ष 2022 में यह संख्या लगभग 2,25,000 थी। In 2022 alone, 7,500 high net-worth individuals with the net worth of more than Rs. 8.3 crore or more left India. नवम्बर, 2022 से सेप्टेम्बर, 2023 सिर्फ दस महीनों में 96,917 Indians were arrested attempting to cross into the United States illegally. मोदी जी कहते हैं, वे सब के साथ हैं, मगर ये आंकड़े बोलते हैं कि जो सबका होता है, वह किसी का नहीं होता है। इनका बंगाल के साथ कुछ अलग ही रिश्ता है। The relationship is that of *quid pro quo*: "तुकरा कर मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब वोट है, तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं"।

As per the available reports, as on 19th July, 2024, Rs. 1.23 lakh crore is already due to the Government of West Bengal against the flagship programmes like MGNREGA, PM Awas Yojana, PM Gram Sadak Yojana, National Health Mission, and Central Food Subsidy. Further, the amount of Rs. 40,806 crore is the projected dues against these schemes bringing the total amount to a staggering Rs 1.71 lakh crore. मैडम, हमें हेल्थ केयर स्कीम के लिए फंड नहीं दिया जाता है, क्योंकि कलर कोडिंग मैच नहीं करता। आप 'सबका साथ – सबका विकास' की बात करते हैं। Is it hinging on colour coding? आपको रंग पसंद नहीं है, तो आप बंगाल के लोगों को पैसा नहीं देंगे। फिर, आप आकर कहते हैं कि हम बंगाल में क्यों नहीं जीत पाते? Madam, this stepmotherly attitude is the reason, जिसके कारण बंगाल के लोग हर बार इनको बड़ा-बड़ा रसगुल्ला खिला कर वापस दिल्ली भेज देते हैं।

Even after making several attempts to crush our aspirations and our economy, the West Bengal Government stands tall and true towards its commitment towards its people. बंगाल में सिर्फ दीदी है, तो मुमकिन है। The West Bengal Government started transferring money to the bank accounts of 21 lakh people who worked for the 100 days' scheme without receiving any payments from the Central Government under MNREGA. Even before Ayushman Bharat, in West Bengal, *Swasthya Sathi*, a cashless scheme, was launched providing treatment costing up to Rs. 5,00,000 for people belonging to any strata of the society. आज कोलकाता के किसी आलीशान प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पर एक अमीर आदमी की चिकित्सा होती है, वहीं बगल वाले बेड पर एक गरीब मजदूर, गरीब किसान की भी ट्रीटमेंट होती है। यही ममता बनर्जी का विकास है। आपके अमृत काल में, the cost of medical treatment has been doubled in the last five years.... (व्यवधान) आप आरजी कर घटना के बारे में न बोलें। अभी तक आपकी सीबीआई भी कुछ बोल नहीं पाई है। हमारी पुलिस ने जो कहा था, they are still sticking to that. आप उसके बारे में बात न करें।... (व्यवधान) सर, आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें।... (व्यवधान)

Medical inflation is at 14 per cent. रेग्युलरली ली जाने वाली दवाइयों की कीमत 50 प्रतिशत बढ़ गई है। आप सिविल एविएशन के लिए ग्रांट्स मांग रहे हैं। एक-एक डोमेस्टिक फ्लाइट की राउंड ट्रिप की टिकट 20-30 हजार रुपए में बिक रही है। आज आम आदमी हवाई चप्पल पहन कर हवाई जहाज नहीं चढ़ रहा है, आम आदमी हवाई चप्पल बेच कर हवाई जहाज चढ़ रहा है।

You are demanding funds for education but conveniently ignoring the fact that 11 lakh children have dropped out of school according to your own

data. आज भारत में 47.51 प्रतिशत स्कूल्स के पास कंप्यूटर्स की फैसिलिटी है और उसमें से 33.9 प्रतिशत के पास इंटरनेट कनेक्शंस हैं। With regard to legal aid to the poor, you have not been able to provide legal aid to more than one per cent of the eligible population. In public enterprises, 5.1 lakh public sector jobs have disappeared in the last 10 years. रेलवे में लगभग 2.5 लाख पोस्ट्स खाली हैं। उनमें से क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरीज में भी वैकेंसीज हैं। आज कल नए भारत की ट्रेन्स पटरी के ऊपर कम और पटरी के बाहर ज्यादा चलती हैं।

मैडम, इस सदन में मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि मैं अपने जादवपुर, लोक सभा क्षेत्र के लिए एक बारुईपुर - कवि सुभाष मेट्रो एक्सटेंशन की मांग की थी।

(1725/KN/RCP)

मुझे डिपार्टमेंट से यह चिट्ठी मिली, जिसमें उन्होंने लिखा है कि this project is not economically viable and this project is unremunerative.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्या, आप अपनी बात कम्पलीट कीजिए।

सुश्री सयानी घोष (जादवपुर) : अगर आपको सब जगह से पैसा चाहिए तो मुझे यह बात समझ में नहीं आता कि लोग खुद के लिए आपको वोट देते हैं या आपके फायदे के लिए वोट देते हैं। मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ। This was the reason that अपने प्रॉफिट के लिए आज इन्होंने सीनियर सिटिजन का कंसेशन भी बंद दिया और सीना ठोककर ये बोलते हैं कि वर्ष 2022-23 में हमने 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों से 2242 करोड़ रुपये कमाये।

माननीय सभापति : माननीय सदस्या, आपका धन्यवाद।

सुश्री सयानी घोष (जादवपुर) : मैडम, मैं दो बातें और बोल कर अपनी बात खत्म कर दूंगी। लोक सभा पर खर्च करके क्या फायदा, जब यहां पर विपक्ष को बोलने का अधिकार ही न हो? लोक सभा के लिए भी तो ग्रांट्स मांग रहे हैं। ... (व्यवधान) अभी सर बोल रहे थे कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'। मोदी जी ने दस साल पहले इसे लॉन्च किया था। लेकिन उसके 80 प्रतिशत पैसे सिर्फ पब्लिसिटी, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में न बेटी को पढ़ा पा रहे हैं और न बेटी को बचा पा रहे हैं। ... (व्यवधान) आप बंगाल आएंगे और देखिये कि ममता बनर्जी जी ने विधान सभा में एंटी रेप अपराजिता बिल पास किया है। कन्याश्री योजना शुरू की है। ... (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति : डॉ. के. सुधाकर।

1727 hours

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): Thank you, Madam. I would like to put forth my views supporting the first batch of Supplementary Demands for Grants 2024-25 and the Appropriation Bill. ... (*Interruptions*) The first batch of Supplementary Demands and the Bill includes supplementary proposals pertaining to 83 demands and three appropriations.

I would like to say that “Viksit Bharat 2047” is not merely a slogan for us. It is not just a play of words. It is hon. Prime Minister’s commitment towards Viksit Bharat. The budget in the last 10 years has more sanctity and credibility which has maximised the value and the impact of hard-earned taxpayers’ money. I can suffice with the facts and figures. The GPD, which between 2014 and 2024 used to be two trillion dollars, has gone up by 3.7 trillion dollars today. When we show good figures, the Opposition says that the growth is normal and the growth is organic. But when some parameters go down, then they show the finger at the Government saying that it is the fault of the Government.

Today, a senior leader of the Congress Party specially spoke on fiscal federalism. Our hon. Prime Minister Narendra Modi ji on several occasions spoke about cooperative federalism. Even if you see the budget, since 2017-18, the budget presentation has been shifted to February 1, instead of the last working day of February. This really helps to advance the expenditure cycle by two months. It also helps the States. The States are now able to plan their own budgets better as they are now aware of the details of the Centre’s fiscal plan of the upcoming year. This reform has helped the State Governments plan their project financing, counterpart funding, implementation of Central projects and borrowing requirements well in advance.

There is a continuous false narrative on tax devolution by the Opposition. The Congress and its alliance partners’ allegation about injustice to South India in particular overlooks the transformative fiscal

reforms introduced by the NDA Government under the leadership of hon. Prime Minister Narendra Modi ji.

(1730/PS/VB)

I would like to set the record straight. Madam, who can understand better the needs of the States? The then Chief Minister of Gujarat, our hon. Prime Minister Narendra Modi ji, the first Prime Minister, increased the devolution of funds to the States. From 30 per cent to 32 per cent, the UPA Government, during their ten years of regime, increased only two per cent. From 32 per cent, he increased it to almost 42 per cent. That means to say that during the UPA regime, it was only Rs. 81,795 crore but during 2014 to 2024, our tax devolution was Rs. 2,77,468 crore for Karnataka alone. Time and again, the Congress leaders from the Karnataka Government make an allegation that the Government is showing stepmotherly treatment towards them. The Grant-in-Aid from the Government of India between 2004 and 2014 was only Rs. 60,779 crore; as against this, during our regime, it is Rs. 2,08,832 crore, which is an increase of 243 per cent, or it is 3.4 times more.

So, I would like to ask one thing to the Opposition. You talk about cooperative federalism only when it comes to the devolution of funds or Grants-in-Aid, but when it comes to programmes, they do not care about it. The State of Karnataka was the first State, when Shri Basavaraj Bommai was the Chief Minister, which implemented the National Education Policy way back in 2020. But soon, when the Congress Government came into power in Karnataka, the first thing that they did is that they abolished the New Education Policy and they reversed it. They said that they will come out with a New Education Policy, a State Education Policy. Today, Madam, there is neither a New Education Policy nor a State Education Policy in Karnataka. The school education and higher education are in limbo. The students of higher education are facing hardships. I would like to ask one thing to the Leader of the

Opposition. Is this the *nyaya* that you are talking to cater to your youth? For Yuva, is this the Nyaya that you want to give?

Madam Chairperson, regarding farmers' welfare, the NDA Government has done remarkably. If you see the kind of allocation, no UPA Government has ever done it. Up to 2013 and 2014, they had allocated a very minimal amount. But our Government has spent over Rs. 3.24 lakh crore only under the Kisan Samman Yojana. For the entire agricultural sector, the money allocated was only Rs. 22,000 crore but in 2023-24 alone, our Government has allocated Rs. 1,53,000 crore. This is our firm commitment towards agriculture and farming community.

In 2013-14, a loan of Rs. 7 lakh crore were extended to the farmers; whereas, under this Government, under the leadership of Narendra Modi ji, the loan is increased to Rs. 19 lakh crore to the farmers.

(1735/SMN/PC)

Especially after the Covid Pandemic, when the prices of fertilizers increased in the world market, Prime Minister Shri Narendra Modi Ji did not pass any burden on to the farmers. Whatever the prices were of urea or DAP in 2018, it still exists even today, Madam, in spite of the geopolitical situation and post-covid situation. When you come to MSP, I will give 2-3 examples. What was the support price during Congress regime? It was only Rs. 1310 per quintal. But today, it is about Rs. 3600 per quintal.

Similarly, jowar, pulses, oilseeds, in every food commodity, there is a substantial increase. Today, one of our learned senior Member of the Opposition Benches remarked and opined that our Finance Minister should have done Ph.D from economics. I beg to differ from his views because Madam, Niramala Sitharaman Ji from the time she has taken over, with so much of global challenges, she has proved that she is one of the most prudent, efficient, honest and successful Finance Ministers that India ever had. She will go down in the history for being so.

Madam, Kamaraj the great was not educated academically. But he had the heart and he had the mind. He was the first person in the country to give food grains free of cost to the poor *antyodaya*. So, you need the good heart and the good mind. *Dil aur dimaag chahiye*.

Regarding agriculture, a lot of people debated by lip sympathy. The sector of agriculture or the farming community cannot become rich overnight. By implementing right programmes only, we can achieve this. If you see this, the agriculture growth rate is 3.4 per cent in NDA's regime. It was minus in Congress regime. We have established 9000 PACS multipurpose communities. This is revolutionizing economics in the rural part of India. It can empower the communities by fostering the economic growth. That is why, the establishment of FPOs is the gamechanger in revolution.

Lastly, I would like to make some strong points about how UPA dealt with during their regime. For sixty years, the Opposition did only two things – doles and deals. They rolled out doles for the poor and deals for the rich and cronies. India has transformed in the last ten years breaking the convention of traditional politics. From mega scams, we have reached mega-projects. From 2G, coal scam to expressways and tunnels, Vande Bharat trains; from entitlement to empowerment, from the very Congress guarantees to skill development, from symbolism to substance, from one AIIMS to today we have established 26 AIIMS, from tokenism to totality and from nationalisation of banks to opening of 60 crore bank accounts in this country. This is our firm commitment. This is our firm dedication to ensure that we have built a robust nation under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi Ji.

So, I strongly believe this is not even less than one per cent of the total budget outlay. So, I support this Bill.

Thank you very much for the opportunity.

(ends)

(1740/RP/IND)

1740 hours

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY (BHONGIR): Madam Chairperson, thank you very much for giving me this opportunity. I am a first-time elected representative of this House. For the last three sessions, I have been listening to the hon. President, hon. Prime Minister, Ministers from here on a number of occasions. But, whatever I listened is not at all practical. Out of these 75 years of the Constitution, the Ruling side members were talking only about the last 10 years as if in the remaining 65 years nothing had happened in this country. They talk as if they have built everything. They talk as if this country was started in 2014. In fact, according to them, the civilization was started in 2014. Frankly speaking, whatever they have spoken is not at all practical. Our Prime Minister Narendra Modiji, in the last 10 years, just thought about Gujarat from where he came as the Chief Minister. The development that Gujarat has got, no other State in this country has got. This is a federal structure, and the Prime Minister is meant for all the States across the country, not just for Gujarat.

1742 hours

(Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

Sir, I rise today to participate in the discussion on the Supplementary Demands for Grants. I would like to draw the attention of this House to the pressing developmental needs of Telangana. Our State is just 10 years old. It was initially ruled by BRS Party. It was mismanaged and taken to the doldrums of Rs. 7 lakh crore as loans. Today, every month we are paying Rs. 6,000 crore or more, just as an interest amount. There is no capital involved.... (*Interruptions*) I know my friends want to talk to me but I have to address the Chair.

Today, people of Telangana have elected eight Members of Parliament from Congress, and eight Members of Parliament from BJP. It is our responsibility to get this State back on to its normal stage because the elections are now over. We have to only work for development rather than arguing with each other in this House.

I want to bring a few issues to your notice with regard to agriculture and irrigation. Our Telangana State is primarily an agrarian State with over 55 per cent of the population depending on agriculture. There are a number of significant issues with regard to the Minimum Support Price system in India. While the Government notifies MSP for more than 20 crops, the procurement process is severely limited and primarily focused on rice, wheat and coarse grains, and to a limited extent, pulses.

In 2024, these issues sparked large scale farmers' agitation where farmers demanded that the Government should procure all the crops covered under MSP, and make a legal guarantee. Now, they are talking as if they have done everything in the last 10 years; people of this country are very happy under their rule; and there is nothing happened in the last 70 years. It is only these 10 years, when everything has happened. In the last 10 years, there were more than 1,12,000 farmers who committed suicide due to the wrong policies of this Government which are not catering the needs of the farmers. Farmers have been used by this Government just as a vote bank. During the last two to three years, there are a lot of protests against this Government. But, still this Government is not listening to their demands. Instead, they are doing lathi charge on them. The same they did two days back outside Delhi also. India's agriculture exports have declined to 8.2 per cent in the fiscal year 2023-2024, totalling to 48.82 billion which is falling short of the target of 60 billion set under the Agriculture Export Policy of 2018.

(1745-1750/NKL/RV)

Sir, I want to say that there is minimal investment in agricultural research which was really successful. Investment in agricultural research has decelerated since 2011 but each rupee invested yields a return of nearly Rs. 13.85, which is 13 times on this investment, the highest among farming-related activities, according to a working paper by the National Institute of Agriculture Economics and Policy Research.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Please conclude.

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY (BHONGIR): Sir, please give me one minute. I have got two other issues.

First is regarding the Palamuru-Ranga Reddy Lift Irrigation Scheme for which a promise was made by the then Government when the bifurcation happened that it would get the 'National Project' status. But till now, it has not got the 'National Project' status.

In regard to the cotton and paddy farmers, the other day, I met the hon. Minister also. As regards the procurement by the Cotton Corporation of India, they are creating a lot of nuisance which has to be sorted out.

Now, I come to the health sector. The Domestic General Government Health Expenditure in the developed countries of the OECD is around 8.7 per cent of GDP.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY (BHONGIR): Sir, please let me speak. I am a first-time MP. At least, I am putting some facts. It is a very useful information. Please let me put some facts. Not even two minutes are over.

Sir, I will tell you some figures. In contrast, India's public health spending is abysmally low. According to the WHO and the World Bank, India's General Government Health Expenditure has been just 0.9 to 1.2 per cent of the GDP in recent years.

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Eswarasamy K.

... (*Interruptions*)

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY (BHONGIR): Sir, I would like to say something with regard to my State. ... (*Interruptions*) I would like to say with regard to urban development. ... (*Interruptions*) Sir, I am just concluding. ... (*Interruptions*)

(ends)

HON. CHAIRPERSON: Shri Eswarasamy K., please start your speech.

1747 hours

*SHRI ESWARASAMY K. (POLLACHI): Hon. Chairperson, Vanakkam. I thank you for allowing me to take part in the discussion on the Supplementary Demands for Grants for the year 2024-25. Our Prime Minister in February 2016 announced that by 2022 he would be doubling the income of farmers. But agriculture remains worst hit sector during the last 10 years. Agricultural sector is continuously facing a sharp decline in growth besides the situation of farmers getting worse day by day. The Government had set a target of providing a monthly income of Rs 22610/- to farmers by 2022. But actually, in the year 2021, as per the survey on the status of farmers' families, they only have a monthly income of Rs 10218/-. Besides the loan amount on each farmer was Rs 47000/- in the year 2013 and which has grown up to Rs 74121/- during the year 2024. This Government had introduced the Crop Insurance Scheme with lots of fanfare in the year 2016. But this Government has failed to implement it properly. This has affected crores of farmers. The demands of farmers are ignored and the Insurance companies are making profit. As per the data of the Union Government, 4 to 6 crore farmers have registered under the Prime Minister Crop Insurance Scheme. But during the year 2022-23, 7.8 lakh farmers have been given Rs 3,878 crore. But the Insurance companies have earned a profit of Rs 57,620 crore from 2016-17 to 2021-22. I represent Pollachi parliamentary constituency in Lok Sabha. Pollachi is called the coconut town. Since there is a record production of coconut in Pollachi area, it contributes much to the production and export of coir in the country. Out of the total coir production of the country, 60 per cent is manufactured by Tamil Nadu. Thorough this, there is a market for coconut products for Rs. 3000 crore annually. But coconut production has been affected during the last some years due to water shortage issues, inadequate rainfall, wilt diseases and other issues. Almost 40 per cent of the coconut trees were affected due to these reasons and which has resulted in reduced exports. Moreover the Prime Minister's Crop Insurance Scheme has further increased the worries of farmers manifold. Instead of solving the issues concerning the Crop Insurance Scheme, the Union Government has started reducing its allocation. During 2023-24, the allocation for Crop Insurance Scheme was Rs 15000 crore and which has been reduced to Rs 14600 crore during the current year. We expected that some additional amount will be allocated for Crop Insurance through the Supplementary Demands for Grants but it ended in vain

* Original in Tamil

as no increase in allocation is made. Although the Union Government is not paying heed to the sufferings of poor farmers, Hon Chief Minister of Tamil Nadu Thiru M.K. Stalin and the Government led by him have been providing interest-free loans to farmers through cooperative banks and from May 2021 to December 2023, as much as an amount of Rs 35.85 crore has been given as loan to farmers. This is the achievement our Dravidian Model of Government. For School Education, during the year 2024-25, Rs 73008 crore has been allocated. This is 0.73 per cent more than the Revised Estimate for the year 2023-24. For Higher Education the budget allocation during 2023-24 was Rs 44,095 crore. In the Revised Estimates, this was increased to Rs 57,244 crore. But this year the Budget Estimate stands at Rs 47,620 crore which is Rs 9624 crore less than the revised estimate of the year 2023-24. Further the Budget allocation for Research has been reduced to Rs.350 crore during the current year from a budget of Rs 400 crore of the year 2023-24. Union Government has stopped the release of Rs 2100 crore under the Sarva Shiksha Abhyan. This is highly condemnable. Tamil Nadu did not accept the New Educational Policy as some provisions of that policy are against the Dual Language policy of the State Government of Tamil Nadu. In this scenario, stopping the release of funds to the State is dictatorial attitude. That is why the people of Tamil Nadu gave you a defeat in the parliamentary elections held in Tamil Nadu. The Union Government has been continuously ignoring the interests of Tamil Nadu. Instead of rectifying their mistakes, the Union Government continues to create financial crisis to the States ruled by Opposition parties other than BJP and its Allies. I will conclude my speech with a couplet from Tirukkural.

“VelanRu VenRi Tharuvathu Mannavan Kolathoovung KoDaa Thenin”.

Muthamizh Arignar Dr. Kalaignar has written the meaning for this Kural couplet. It is not the javelin that gives victory to the King but the Sceptre swayed with Unity. Good Governance is termed as Sengol, the Sceptre here in this couplet. It is not the symbols that are considered important. I therefore urge that the Union Government, instead of fighting with the State Governments of the Opposition ruled States, should concentrate in allocation of adequate funds for the implementation of Schemes in major sectors, particularly for Tamil Nadu. Thank you. Vanakkam.

(ends)

1752 बजे

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : सभापति जी, पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है।

महोदय, 87,762 करोड़ रुपये की राशि की मांग की गई है। मैं इन अनुदान की अनुपूरक मांगों के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ, समर्थन करता हूँ। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था आज भारत बना हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा। आज विश्व की बड़ी-बड़ी शक्तियां ऐसा कह रही हैं। महोदय, कृषि और किसान को राहत देने के लिए प्रावधान इसमें रखा गया है। विशेष तौर पर प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए यहां पर 3132 करोड़ रुपये की मांग की गई है। जो काम चल रहे हैं और जिन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, उसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि नौजवनों को स्वरोजगार के अवसर दे कर मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम आज उठाया है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आशा बंधी है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। यह विश्वास आज देश के गरीब को नरेंद्र भाई मोदी जी पर है। विशेष तौर पर अगर मैं जन-धन योजना का जिक्र करूँ तो हम सब जानते हैं कि जन-धन योजना के खाता धारकों के खाते में आज 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार रुपये गरीब से गरीब परिवार में हैं और उनका मनोबल इससे बढ़ता है तथा उनको लगता है कि हम भी इस समाज का हिस्सा हैं।

(1755/MY/SAN)

यह अवसर भी आज देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने देश के गरीबों को दिया है। हमारे कांग्रेस पार्टी के भाई कभी-कभी इसका मजाक उड़ाते थे। आज उनको भी समझ आ गई कि इस जनधन खाते का लाभ हमारे गरीब भाई को मिल रहा है।

महोदय, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो योगदान मोदी सरकार का रहा है, शायद ही इससे पहले किसी सरकार का रहा होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है, वह बहुत ही सराहनीय है। मैं यहां पर आयुष्मान योजना का जिक्र कर रहा हूँ। विशेष तौर पर, अब सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति का इलाज भी फ्री में होगा, कैशलेस होगा। इसके लिए 127 करोड़ रुपये की राशि इस मांग में रखी गई है। यह गरीब को एक बहुत बड़ी राहत देने वाली बात होगी। पहले वे अपना इलाज नहीं करवा पाते थे।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता की वैश्विक सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है, जो कि पहले नहीं दिया जाता था। पहले लोक-लुभावने नारे दिये जाते थे, लेकिन किसी पर भी अमल नहीं होता था। आज चाहे एयरपोर्ट्स हों, रेलवे स्टेशंस हों, हाइवेज हों, एक्सप्रेस हाइवेज हों, हमारे बिजली क्षेत्र में क्रांति आई है। जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी की उपलब्धता बढ़ी है। इसके अलावा भी कई सारी बड़ी-बड़ी योजनाएं देश के लिए समर्पित की गई हैं।

महोदय, यूपीए और विशेष तौर पर कांग्रेस के समय बजट में रखा गया पैसा भी प्रदेशों तक नहीं पहुंचता था। इसके प्रमाण हैं। वह पैसा वहां लगता भी नहीं था। लेकिन, आज जो कहा जाता है, वही दिया जाता है और वह पैसा ग्राउण्ड पर लगता भी है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रिय योजना का ही परिणाम है कि आज हर गरीब के खाते में 10 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये हैं। यह उस गरीब का मनोबल बढ़ाने का काम करता है। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। विशेष तौर पर अगर मैं अपनी बहनों की बात करूँ तो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से देश की बहनों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सहयोग किया है। इससे हमारी बहनों का मनोबल बढ़ा है। अब वह आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ी हैं। हम सब जानते हैं कि पहले बहनों को घर चलाने के लिए अपने मर्दों की तरफ देखना पड़ता था, बड़ों की ओर देखना पड़ता था, लेकिन आज देश की बहनें किसी पर भी निर्भर नहीं हैं। अब वह घर का खर्च स्वयं भी चला सकती हैं। वह अपने आप में गर्व भी महसूस करती हैं। वह उस देश की नागरिक हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी हैं, जो देश के गरीब और गांव की चिंता करते हैं।

महोदय, बैंकिंग क्षेत्र में भी काफी सुधार हुए हैं। अब बैंकों के स्वभाव भी बदले हैं और काम करने का तरीका भी बदला है। आज हमारे बैंक आदर और मान-सम्मान के साथ गरीब को कुर्सी देकर बैठाते हैं। बैंक उनकी जरूरत को भी पूरा करते हैं। उन्हें मालूम है कि इस गरीब के पीछे आज देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं।

महोदय, आज सड़क पर रेहड़ी और फहड़ी लगाने वाला व्यक्ति भी अपने आप में गर्व महसूस करता है। वे कहते हैं कि मोदी जी ने हमें इस लायक समझा है कि हम अपने काम को बढ़ाने के लिए बैंक का सहयोग ले सकते हैं... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : माननीय सदस्य, आप एक सेकेंड के लिए रुकिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सभासदों, अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही आठ बजे तक बढ़ा दी जाए, क्योंकि मेरे पास इस विषय पर बोलने वाले वक्ताओं की लंबी सूची है। क्या आप सब की सहमति है?

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ।

माननीय सभापति: ओके।

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : सभापति जी, मैं कह रहा था कि आज सड़क पर रेहड़ी और फहड़ी लगाने वाला भी अपने आप में गर्व महसूस करता है। वह कहता है कि मोदी जी ने हमें इस लायक समझा कि हम अपने काम को बढ़ाने के लिए बैंक का सहयोग ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं।

(1800/CP/SNT)

उन्हें एक के बाद एक लोन देने की व्यवस्था देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने की है।

महोदय, जम्मू-कश्मीर में बहुत सारी योजनाएं तेज गति के साथ आगे बढ़ रही हैं। वित्त मंत्री जी ने हमें भरोसा भी दिलाया है कि ये प्रोजेक्ट, ये योजनाएं जिस तेज गति के साथ आगे बढ़ रही हैं, इनमें कोई रुकावट नहीं आएगी। यह जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए एक राहत की बात है।

महोदय, मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि भारत-पाक सीमा पर बनी डिच, नहर और बांध सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं। कई वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्र में चाहे वह सम्ब विधान सभा हो या मढ़ विधान सभा हो या आर. एस. पुरा विधान सभा या बिशनह विधान सभा हो, वहां के किसानों को किन्हीं कारणों से उनका मुआवजा वर्ष 2012 से नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि इन अनुपूरक मांगों में उनका भी ध्यान रखा जाए, ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके।

महोदय, हर क्षेत्र के विकास के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का मैं समर्थन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1801 hours

SHRI SRIBHARAT MATHUKUMILLI (VISAKHAPATNAM): Thank you, Chairperson, Sir. I am here to speak on the Supplementary Demands for Grants – First Batch for 2024-25 on behalf of the TDP.

Although the budget sought is Rs. 87,762 crore, the actual cash outflow of Rs. 44,000 crore is less than one per cent of the overall budget. By any count, I would say that that is good planning. Leading an organization myself, I have often found that in the middle of the year, we deviate more than one per cent. So, I would like to acknowledge and appreciate that. In regard to some points spoken by the Opposition in terms of the growth, on inflation and on the manufacturing sector, I think there seems to be a rhetoric, a lot more than a call for action. It is because on one count, we say that inflation should not grow, but on the other count, we are saying that the repo rate also should not be cut down. I would request the Government to cut down the repo rate to kick-start the manufacturing sector and increase its growth, which would overall lead to the growth of the Indian economy. It is much needed, and I would definitely ask for that.

In this Batch of Supplementary Demands for Grants, I would like to speak about some specific points, in particular for the Ministry of Steel. I would like to acknowledge and thank the Finance Minister and the Prime Minister for allocating Rs. 1,650 crore of funds to revive the RINL Steel Plant. I am very happy to state that from the verge of almost being shut down with only one furnace running, now there are two furnaces running at more than 100 per cent rated capacity over the last month-and-a-half or two. With the continued support of the Government, I am sure that all three furnaces will be running, and we will be able to take care of the salaries of all the staff members. I would like to acknowledge this.

The second thing that I would like to bring up is the footwear industry. I have a peculiar problem, Chairperson Sir. I have a foot condition which requires a certain kind of footwear. I was searching for it in India, but I could not find it. I had to go to Germany, and a friend of mine got a cast made for me, and I got that footwear. That is what I am wearing right now. But then when I went to the Standing Committee on Commerce, I realized that there is a Footwear Design and Development Institute under the Commerce Ministry. With the support of hon. Minister, Piyush Goyal ji, I went and visited the institute, and I was very happy to see the kind of research that is happening over there. Alas, most of India does not even know about the research that is happening. So, I request the Finance Minister to consider this footwear

industry and the Footwear Design Institute to really proliferate its activities to the wider nation because the footwear industry is not very concentrated today. It is quite disorganized. The other thing I would request is to separate it from the leather industry because not all footwear is leather now. All different kinds of materials are coming into it.

The next point is about urban planning. When we think of big cities in India, say Bangalore, a lot of people remember traffic. When we say Delhi, people think of pollution. When we say Mumbai, people worry about cost of living. So, the money that happens to be transferred to urban local bodies is a mere 0.5 per cent of the GDP, but the contribution of cities to our GDP is almost 60 per cent.

(1805/AK/NK)

I would also request that if there are good cities that are planning for the future and if they can be incentivised through grants for major infrastructure development, then that would help us abate these problems pre-emptively instead of being reactive. I think that it would be a great thing for the nation.

Coming to the State of Andhra, I would like to request that over the last five years because of the potential mal-intent and delay of many critical projects like Amaravati or Polavaram, the cost of these projects has increased from 25 per cent to 55 per cent. We request the support of the Central Government in line with what has already been announced in this Budget to develop our capital city of Amaravati and to complete the Polavaram project by 2028.

Finally, I would like to end with a point on the State that if we want unemployment to come down and if we want the GDP to grow really quickly to achieve our goal of Viksit Bharat by 2047, I would also request some money to be considered for the skill census -- as the money dedicated for the census -- to be done nation-wide similar to what we are speaking in the State of Andhra. If we can bridge the gap between what the industry needs and what is the available workforce and start bridging the gap through skill development and education, then I think that this demographic dividend that exists will become a huge dividend for the nation and help not just the State of Andhra Pradesh prosper, but all the States of India prosper.

With these few points, I would like to thank the Chairperson for the time given to me to speak. I would like to thank the Finance Minister again for the support extended to the State of Andhra Pradesh and to the steel plant in my Parliamentary Constituency of Visakhapatnam. Thank you.

(ends)

1806 बजे

श्री राजेश रंजन (पूर्णिमा) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय जी से ब्लैक मनी के बारे में जानना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी का नोट बंदी एक स्वर्णिम निर्णय था। उस नोटबंदी के बाद आपने कालाधन के बारे में भी जानकारी नहीं दी, कितना पैसा आया, उसकी भी जानकारी नहीं दी। दस लाख करोड़ रुपये से ऊपर के कितने जाली नोट हैं, बैंक से गैपिंग है, उसकी भी जानकारी नहीं दी। कितना पैसा आपने अकाउंट में दिया, पन्द्रह लाख रुपये की भी जानकारी नहीं दी।

जीएसटी के बारे में सिर्फ इतना कहेंगे कि जीएसटी बड़े व्यापारियों का चोरी का सबसे बड़ा रास्ता है। मिडिल क्लास व्यापारियों के लिए हिन्दुस्तान में एक कपड़े की कीमत दो सौ रुपये है और हम जीएसटी भी दो सौ रुपये देंगे। मिडिल क्लास को कितना मुनाफा होता होगा, यह भारत सरकार का दिल ही जानता है, हम इस पर कुछ और नहीं कहेंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप कुछ पैसा अलॉट कीजिए।

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Kindly address the Chair.

... (Interruptions)

श्री राजेश रंजन (पूर्णिमा) : सभापति महोदय, इस बार बिहार का पांच प्रतिशत जीएसटी आपने कम क्यों किया? इस बार पांच प्रतिशत बजट बिहार का कम किया है, वह किस आधार पर किया है? झारखंड का लगभग 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये जीएसटी का आपने रोक रखे हैं, आपको इस बारे में भी बताना चाहिए। आप चार सौ रुपये पेंशन कब तक देते रहेंगे, आप जितना पेंशन दे रहे हैं, क्या कभी आम आदमी का वृद्धा पेंशन या दूसरे पेंशन को हजार रुपये या दो हजार बढ़ाने बढ़ाने की कोई योजना है?

प्रधानमंत्री आवास योजना आपका सपना है, यह अच्छी बात है, इस राशि को कब बढ़ाएंगे? यह राशि बहुत कम है, इससे किसी का भी सपना पूरा नहीं हो सकता है। यह राशि गबन हो जाती है। आपने ओडीएफ के लिए शौचालय की व्यवस्था है, इसके लिए भी राशि बिल्कुल कम है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। आंगनबाड़ी, ममता, आशा, रसोइया के लिए सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि आंगनबाड़ी सेविका 25 हजार रुपये, सहायक सेविका को 18 हजार रुपये किया जाए। आपने आशा और रसोइया को इस बार बजट में भी कुछ नहीं दिया है। 'आयुष्मान भारत' प्राइवेट अस्पताल वाला बीस लाख, चालीस लाख रुपये का बिल बना देता है।

(1810/SK/UB)

सात-आठ लाख रुपये बिल बना देते हैं, आप सोचें कि गरीबी रेखा और मिडल क्लास के लोग क्या करेंगे? आप ऐसा करें, एमआरआई, सीटी स्कैन, अन्य जांचें और दवाइयां फ्री कर दीजिए, आयुष्मान मत दीजिए।

महोदय, दो लाख करोड़ रुपये बिहार पर कर्ज है। बिहार सरकार आज नहीं, चाहे जिसकी भी सरकार हो, वर्तमान हो या कोई भी रही हो, प्रधान मंत्री जी ने गांधी मैदान में विशेष राज्य की दर्जा की बात की थी। माननीय अटल जी के समय नीतीश जी के नेतृत्व में हम सब साथी मिले थे और

हमने विशेष पैकेज का बड़ा रूल दिया था। उसमें हमने कहा था कि बिहार की जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं, सासाराम, जूट मिल कटिहार से लेकर जितनी चीन मिल्स हैं, आप सारी फैक्ट्रियों के रिहेबिलिटेशन के लिए विशेष पैकेज दीजिए। हमारी लगभग सारी फैक्ट्रियां बंद हो गईं। झारखंड में लगभग 43 परसेंट फैक्ट्रियां बंद हो गईं। मेरा कहना है 'विशेष राज्य और विशेष पैकेज'। जब आप कोई भी बात करते हैं तो जरूर इस बात का ख्याल रखें और बताएं कि विशेष राज्य के बारे में आपके क्या विचार हैं?

महोदय, सबसे बड़ी बात प्रधान मंत्री सड़क योजना की है। बिहार दुनिया का सबसे गरीब प्रदेश है। जाति जनगणना में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में बिहार दुनिया में सबसे निचले पायदान पर है। मैं आपसे बेरोजगारी भत्ता की बात कहना चाहता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा पलायन और बेरोजगारी बिहार में है। हम एजुकेशन ग्रोथ में सबसे नीचे हैं। हम चाहते हैं कि पेंशन और छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। इसके साथ ही युवा बेरोजगारों को कम से पांच से छः हजार रुपये देने का काम करें।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मैं मक्का, मखान, मछली और चायपत्ती के बारे में आग्रह करना चाहता हूं। आप कम से इस योजना पर पांच फैक्ट्रियां मक्का, मखान और चायपत्ती के लिए दें। हमारा सपना है हाई डैमा। आप नए भीम नगर बैराज के रिहेबिलिटेशन के लिए मदद करें।

महोदय, बिहार के निर्माण में पर्यटन की सबसे बड़ी भूमिका है। बिहार के निर्माण में दो बाधक हैं, बाढ़ और सुखाड़। हमारे प्रदेश के तीन हिस्से बाढ़ से प्रभावित हैं। यहां के लिए रेल योजना पर बजट दें ... (व्यवधान)

महोदय, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि बिहार में एक हाई कोर्ट बेंच, पूर्णिया में आईआईएम और आईआईटी देने की कृपा करें।

(इति)

1814 hours

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Sir, while we discuss the Supplementary Demands for Grants, many of our colleagues have pointed out a lot of things but I will only cite one or two very pertinent issues.

The Agriculture Ministry and the other allied Departments are seeking a large amount under the Supplementary Demands. The point is, what is this amount going to be used for?

(1815/PS/KDS)

Sir, you know the difficulties that are being faced by the farmers. They are still out there. They are on a strike. But the point is whether the debt-ridden farmers will be helped out of these Supplementary Demands. Let us take a look at the bank loans. The irrecoverable loans are to the tune of Rs. 4,50,670 crore. In the case of the public sector banks itself, it is Rs. 3,16,331 crore; and in the case of scheduled commercial banks, it is Rs. 1,34,339 crore.

But what we see is that in 2018-19, the Government of India, the Finance Ministry, wrote off Rs. 11.45 lakh crore. It is not the debts of farmers. I would like to know whether there will be some provisions. I would also like to know whether the Finance Minister will take some action to help the debt-ridden farmers. That is the one question that I would like to ask.

Sir, in 2018-19, Rs. 58,905 crore was written off by the State Bank of India. Will there be some action on the part of these debt-ridden farmers? I would like an answer from the hon. Finance Minister.

Some of our colleagues especially from the State of West Bengal said that the State of West Bengal is being treated by the Government of India in a stepmotherly manner. I would like to say that in the case of Kerala, it is a stepped-up stepmotherly treatment. I would cite one case of Vizhinjam International Seaport, a container terminal port. This is not a project of Kerala. This is a project which is to the benefit of the whole country.

The hon. Finance Minister is here. She knows very well about the Viability Gap Funding (VGF). So, what is meant by Viability Gap Funding? It is a financial support mechanism to encourage public-private partnerships in infrastructure projects that are economically justified but not financially viable without additional financial support. What is the aim of Viability Gap Funding (VGF)? It

is to bring in private sector participation in infra projects to promote infrastructure development and to reduce burden on the Government's resources. Normally, it is provided as a grant and not as a loan. But in the case of Kerala alone, out of all the States in this country, it has been given as a loan. I would like an answer from the hon. Finance Minister in this particular case.

Sir, very recently, the Economic Affairs Department under the Finance Ministry gave in-principle approval to the Outer Harbour Project of VOC Tuticorin Port. We do not grudge it. We welcome it. This is a project made on the similar lines with Vizhinjam International Seaport. But why is the State of Kerala being treated like this?

The Government of India is the number one beneficiary out of this particular project because by way of customs duty alone, the Government is going to get at least Rs. 10,000 crore annually. What will the State of Kerala get? The State of Kerala will get just three paise out of the divisible pool. And also, an additional revenue to the tune of Rs. 6,000 crore will come to the Government of India, saving a foreign exchange, and it is an direct and indirect benefit to the nation. But then, we are being treated like this.

Sir, there are other issues also. In the case of Global City, which falls under the National Industrial Corridor Development Programme, the Global City, Kochi project, spanning 358 acres, aims to create 28.32 million square feet of infrastructure under the Kochi-Bengaluru Industrial Corridor. Kerala has already approved Rs. 840 crore for land acquisition, and a Market Demand Assessment Report confirms the project's viability.

But the delay in final approval risks stalling this transformative initiative, which promises economic growth and next generation industrial hubs. Accelerated approval of the preliminary master plan and targeted infrastructure support are essential to realize this project's potential.

These are very vital issues concerning Kerala and also the whole of the nation. But the Government of India is treating Kerala in a stepmotherly, or as I have said earlier, in a stepped-up stepmotherly, fashion.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Please conclude.

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Kerala is seeking to face the severe financial challenges due to retrospective borrowing ceiling cuts; and also due to the reduced Central transfers, we are losing about Rs. 4,710 crore annually. (1820/SMN/MK)

To address this, Kerala seeks Rs. 24,000 crore as special package and also Rs. 25,000 crore for Vizhinjam and Rs. 5,000 crore for related infrastructure projects. Also the fund that Kerala has invested in national highway projects to the tune of Rs. 5,580 crore has been reduced from our borrowing limit and expedite the release of Rs. 2,586.95 crore pending funds under the 15th Finance Commission as health sector grants.

These are all being denied to the State like Kerala, which is a financially stressed State. So, as large sums are being appropriated under these Demands for Grants, the case of States like Kerala be considered in a beneficial and in a sympathetic manner. That is all.

Thank you, Sir.

(ends)

1821 बजे

श्री शशांक मणि (देवरिया) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

मैं आज इस सदन में वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत अतिरिक्त अनुदान की मांग का समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। इस सदन में पिछले सप्ताह करीब 87,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुदान की प्रस्तावना रखी गई थी। उसमें शुद्ध नकद आउटफ्लो करीब 44,000 करोड़ रुपये था, जिसमें बकाया मंत्रालय द्वारा बचत या बढ़ी हुई वसूली से पूरा किया जाएगा। यह केंद्रीय बजट का करीब 1.8 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष के 1.3 लाख करोड़ रुपये से कम है। यह सरकार को 2.4 लाख करोड़ रुपये डेफिसिट से कम ही रखेगा। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, निर्मला जी और पंकज जी को साधुवाद देना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, आज से लगभग 48 घंटे पहले संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा हुई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया। उस उद्बोधन के अंत में उन्होंने 'सबके प्रयास' का उल्लेख किया। उन्होंने उल्लेख किया कि हमें हमारे राष्ट्र की हनुमत शक्ति को जगाना चाहिए, तभी जाकर हमारा राष्ट्र 'विकसित भारत' बनेगा। इस समय मुझे वह प्रेरणादायक श्लोक याद आता है, जो हनुमान जी का है। जामवंत जी कहते हैं -

“कहइ रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहेहु बलवाना,
पवन तनय बल पवन समाना, बुधि बिबेक बिग्यान निधाना।”

हमारी जनता में इतनी हनुमत शक्ति है, जिसको जगाने की प्रेरणा उन्होंने हम लोगों को दी है। मैं समझता हूँ कि इसी से हमारा बजट और अनुदान भी प्रेरित है।

सभापति महोदय, यह अनुदान आदरणीय दीन दयाल जी के एकात्म मानववाद से भी प्रेरित है। विपक्ष हर समय काटो-बांटो की भावना से आगे बढ़ता है। हमारा संविधान और हमारी पार्टी एकात्म मानववाद की भावना से एकजुट होकर अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ती है और यह अनुदान की मांग उसको सिद्ध करती है। इसके विपरीत औपनिवेशिक और संभ्रातवादी सोच वाली पार्टी कांग्रेस ने हर समय डिपेंडेंसी लाई है। हर समय लोगों को आर्थिक रिहाई नहीं, आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ाया है। इसके लिए मैं उनकी निंदा करता हूँ। बहुत सालों तक यह हुआ है। मैं चार प्रमुख विषयों से, चार प्रमुख अनुदानों की मांगों से अपनी बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। इसको अपने संसदीय क्षेत्र देवरिया से जोड़कर रखना चाहता हूँ।

पहला कृषि और किसान कल्याण के लिए 9,900 करोड़ रुपये का अनुदान है। यह हमारी सरकार का किसानों पर ध्यान केंद्रित करने का जो लक्ष्य है, उसको दर्शाता है। लेकिन, इसमें रोचक बात यह है कि कृषि संरचना और विकास कोष के लिए महालोनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र के लिए कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान के सृजन के लिए अनुदान दिया गया है।

सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तमकुहीराज एक विधान सभा क्षेत्र है। वहां हम लोग कृषि विद्यालय, कृषि केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय बना रहे हैं। योगी जी की सरकार के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि यह अनुदान उस विद्यालय को सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ाएगा, ताकि वहां का किसान आगे बढ़ पाए।

दूसरा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए 231 करोड़ रुपये का अनुदान है। हालांकि, यह छोटा है, लेकिन यह टीयर-3 और टीयर-2 जिलों पर केंद्रित है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारे देश की जो अधिकांश आबादी है, वह टीयर-3 जिलों में रहती है, जैसे देवरिया क्षेत्र में। इस अनुदान की मांग में उड़ान योजना, कस्टम और कार्गो के लिए सहायता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बहुत सुंदर कुशीनगर एयरपोर्ट है। उसमें हम लोग उड़ान की व्यवस्था कर रहे हैं। यदि उसमें सबका प्रयास होगा तो हम लोग वहां पर कार्गो का भी टर्मिनल लगाएंगे। सबका प्रयास होगा तो वहां से लीची, आलू और अन्य चीजों को भी भेजेंगे। इस प्रकार से सबके प्रयास की आवश्यकता है। इसके लिए मैं फिर से निर्मला जी को साधुवाद देना चाहता हूँ।

पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के लिए 217 करोड़ रुपये का अनुदान है। यह जलमार्ग विकास के लिए बहुत आवश्यक है, केवल तटीय इलाकों में ही नहीं बल्कि हमारी नदियों में भी जलमार्ग बन रहा है। उसका एक उदाहरण हल्दिया पोर्ट है, जिस पर 150 करोड़ रुपये की लागत से उसकी ड्रेजिंग होगी, ताकि वहां पर पूरे देश की सामग्री पहुंच सके।

सभापति महादेय, मेरे लोकसभा क्षेत्र के बगल में नारायणी नदी बहती है और पोर्ट का इंतजाम हो रहा है। वहां पर भी हम लोग सबके प्रयास से काम करेंगे। वहां के दस जिलों की आबादी से हम लोग कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा और तभी पूर्वांचल उठेगा।

(1825/SPS/RP)

महोदय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए 2,165 करोड़ रुपये का कुल अतिरिक्त अनुदान है, मैं उसके लिए साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वह जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे पिछड़े इलाकों के लिए है, जिसे 500 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूँ कि पिछड़े इलाके, खासकर पूर्वांचल जैसे इलाके, जहां पर वर्ष 1857 में मंगल पांडे उड़े, लक्ष्मी बाई उठीं, लेकिन उसके बाद भी 90 साल तक इन्हीं क्षेत्रों को प्रताड़ित किया गया। मैं आपके द्वारा इस सदन को बताना चाहता हूँ कि ऐसे पिछड़े इलाकों में आगे चलकर और अनुदान दिया जाए।

महोदय, मैं सरकार की इन अतिरिक्त अनुदानों की सराहना करता हूँ, क्योंकि यह गरीब, किसान और विशेष रूप से दलितों तथा पिछड़ों के लिए होगा, लेकिन इसी के साथ-साथ यह अनुदान युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए सक्षम बनाएगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि 50 साल से ज्यादा इस देश में निर्भरता की मानसिकता बनाई गई और अक्सर संविधान को एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया। इसके विपरीत माननीय प्रधान मंत्री जी ने सबके प्रयास का जो मंत्र दिया है, उससे विकसित भारत का सूरज अवश्य उठेगा। इसके लिए हम लोग समर्पित हैं। हम लोग चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए 140 करोड़ नागरिक जागें, सिर्फ हम और आप ही नहीं, पूरा देश जागे, तब जाकर विकसित भारत का सूरज उगेगा।

मेरे लोक सभा क्षेत्र में 19 लाख मतदाता हैं और 26 लाख नागरिक हैं। प्रधान मंत्री जी के आह्वान से हम लोग उत्साहित हैं कि विकसित भारत के आंदोलन में सबके प्रयास के तहत हम सब लोग शामिल हैं। केवल सरकार ही नहीं, बल्कि नागरिक, समाज और निजी क्षेत्र भी विकसित देवरिया लोक सभा क्षेत्र की दिशा में काम करेगा, तभी विकसित भारत आगे बढ़ेगा। यह अनुदान मुझे और मेरे लोक सभा क्षेत्र के 26 लाख नागरिकों को विशाल आत्मविश्वास प्रदान करता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारता।

(इति)

1827 बजे

श्री राहुल कस्वां (चुरु) : आपने मुझे वर्ष 2024-25 के बजट पर सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत से सांसद साथियों द्वारा बहुत सी बातें कही गई हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। मैं कृषि क्षेत्र से आता हूँ। मैं राजस्थान के चुरु लोक सभा क्षेत्र से एक सांसद के रूप में अया हूँ। मेरा 85 प्रतिशत क्षेत्र किसानों केन्द्रित है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जो करीब 25 स्कीम हैं। उनमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं और 8 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। एग्रीकल्चर के अंदर पीएम किसान सम्मान निधि 16 रुपये 44 पैसे प्रतिदिन देने की बात की है, उसके ऊपर 3,500 करोड़ रुपये का बजट बनाने का प्रोग्राम किया गया है। अगर आप स्कीम्स को देखें तो इन पिछले 10 सालों के अंदर बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, लेकिन उन स्कीम्स की वैल्यू क्या है और आज वे कहां स्टैंड करती हैं, उस पर बहुत मंथन करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि मंत्रालयों को भी इनके बारे में बहुत वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। *Where are we standing after ten years of launching of these schemes at some particular point in time?*

सर, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम के बारे में आज भी मैंने बात कही थी। यह एक अच्छी स्कीम थी, लेकिन आज हालत कैसी है? राजस्थान स्टेट, जहां से हम आते हैं, वहां एक-एक साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन सरकार अपने हिस्से की प्रीमियम राशि नहीं भरती है। दो परसेंट की राशि किसानों ने भर दी है और अपना प्रीमियम भर दिया है, लेकिन आज राज्य सरकार वर्ष 2023-24 की रबी की राशि को भरने में सक्षम नहीं है। वह एक-एक साल से पेंडिंग पड़ी है। गाइडलाइंस यह कहती है कि अगर आपको टाइम पर बीमे का क्लेम डिस्बर्स नहीं होगा तो बीमा कंपनियां या राज्य सरकार इंटरैस्ट के साथ पेमेंट देंगी, लेकिन इंटरैस्ट तो छोड़िए, आज तक मूल रकम भी नहीं मिल रही है।

वहां पर किसानों को वर्ष 2023 की खरीदी की पेमेंट नहीं मिल रही है। वहां किसान धरने पर बैठने को मजबूर हैं और उसी तरीके से आज किसान दिल्ली के पास बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। राजस्थान में टेंपरेचर 3 से 4 डिग्री पहुंचने वाला है, लेकिन मजबूरी में वहां पर किसानों के बैठने की बात हो रही है। एमएसपी को बाजरे में शामिल किया गया, मिलेट ईयर के नाम पर केवल बातें चलीं, लेकिन आज तक राजस्थान की सरकार ने एक दाना भी बाजरे का परचेज नहीं किया है। ओने-पौने भाव तथा 400-400 रुपये क्विंटल गैप पर मार्केट में बाजारा किसान को बेचना पड़ा। मूंग और मूंगफली की खरीद की बात चल रही है, लेकिन कोई क्लेरिटी ही नहीं है।

आप कहते हैं कि हम एमएसपी की 22 क्रॉप्स को परचेज कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमें नेफेड ने कहा है कि 25 परसेंट ही खरीदना है, लेकिन मूंग की 5 परसेंट भी परचेजिंग भी नहीं हुई है। वहां पर पोर्टल भी खुला था। मूंगफली और तिलहन में हम डिपेंड करते हैं और विदेशों से मंगाते हैं, लेकिन आज की तारीख में बीकानेर, डूंगरगढ़, चुरु, सरदार शहर में किसान सर्दी के

अंदर तीन-तीन रात इंतजार करता है, तब जाकर नंबर आता है। इस समय कोई करप्शन को रोकने वाला नजर नहीं आता है।

मेरा आपसे कहना है कि सरकार की अनेकों स्कीम्स लांच हुई हैं। दस हजार एफपीओज़ बनाने की बात की थी, लेकिन एफपीओज़ के अंदर क्या एक्टिविटी है? आप किसान के खरीद केंद्र तक नहीं खोल पा रहे हैं, एफपीओज़ केवल फर्टिलाइजर्स को बेचने का काम कर रहे हैं, जो चुरू जिले के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर कर रहे हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना में चुरू जिले में केवल एक दीदी है। पूरे पांच साल के अंदर एक ड्रोन मिला है। एक ड्रोन दीदी है। हम किसके पास जाएं और किससे बात करें।

(1830/MM/NKL)

किसानों के धरने के इश्यू से पता चलता है कि स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में इतनी फ्लॉज हैं कि उनको इम्प्लीमेंट करने की तरफ ध्यान नहीं जाता है। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि किसान की हालत बहुत खराब है। इस ठंड में हम बिजली की बात करते हैं। आपने आरडीएसएस की स्कीम लॉन्च की। राजस्थान को 11 हजार करोड़ रुपये मिले, लेकिन दो-दो साल तक भी कनेक्शन नहीं मिल रहा है। भारत सरकार के द्वारा एक गाइडलाइंस दी गयी कि 50 हजार रुपये तक एक्सपेंडिचर होगा तो ढाणियों में लाइट देंगे। 11 साल के बाद भी चुरू जिले की 48 हजार ढाणियों को आज भी रोशनी की जरूरत है। यह जो 50 हजार रुपये का क्लॉज है, मैं राजस्थान से आता हूं और हमारा एरिया बहुत बड़ा है। इस 50 हजार रुपये के क्लॉज के कारण हम ढाणियों में कभी भी कनेक्शन देने में कामयाब नहीं हो पाएंगे।

मैं मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लॉज को हटाकर एक लाख रुपये प्रति व्यक्ति की क्लॉज को डालें ताकि लोगों को कनेक्शन दिया जा सके। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के बारे में बात करना चाहूंगा। 19 हजार करोड़ रुपये ग्रामीण सड़क योजना के लिए दिए जाएंगे। सेकेंड और थर्ड फेज में हम रोड को वाइडन और स्ट्रेंथन कर रहे थे और अचानक से फोर्थ फेज आता है कि ढाई सौ की आबादी के गांवों को जोड़ने का काम करेंगे। हमारे चुरू में सौ प्रतिशत गांव जुड़े हुए हैं और हमें एक्स्ट्रा रोड्स की जरूरत है। वह रोड्स कहां से लेकर आएंगे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है।

मेरा आपसे निवेदन है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की गाइडलाइंस को चेंज करके इसे ढाई सौ की आबादी से घटाकर डेढ़ सौ किया जाए और मल्टीपल कनेक्टिविटी का प्रावधान किया जाए। वर्ष 1998 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी यह योजना लेकर आए थे और आज भी गांव में कनेक्टिविटी का दूसरा कोई प्रावधान नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास न पैसा है, न स्ट्रीम है, न काम करने के लिए सिस्टम है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस योजना में अलग-अलग गांवों को जोड़ने का प्रावधान किया जाए। कम से कम पंचायत हेडक्वार्टर तक तो गांव जुड़ें, ऐसा प्रावधान करने का आप काम करें।

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : कृपया, आप कनक्लूड कीजिए।

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सर, सीआरआईएफ के लिए 2150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सीआरआईएफ की सेतु बंधन स्कीम पिछले साल लॉन्च की गयी थी। सेतु बंधन स्कीम के टेंडर मार्च, 2023 में हुए और अब वर्ष 2025 आने वाला है, लेकिन आज तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। गतिशक्ति का वह पोर्टल क्या काम कर रहा है, जहां रेलवे और रोड डिपार्टमेंट आपस में बात ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट एनओसी नहीं दे रहा है।

मेरा अंत में इतना ही कहना है कि अनेकों स्कीम्स लॉन्च हुईं लेकिन किसान और किसानों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। आज ग्रामीण विकास मंत्रालय की सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए जब हम लोगों ने बीडीपी बनायी तो उसके लिए 22 से 25 करोड़ रुपये तक की इनवेस्टमेंट की आवश्यकता थी। इसके लिए फंड कहां से लेकर आएंगे? एमपीलेड के लिए पांच करोड़ रुपये मिलते हैं। 15 साल पहले भी पांच करोड़ रुपये एमपीलेड में होते थे और आज भी पांच करोड़ रुपये ही हैं। इससे आप एक गांव में एक कमरा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक लाख रुपये एक पंचायत के हिस्से में आता है। इस एमपीलेड को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक अलग से फंडिंग का पैटर्न दिया जाए जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस हो, जिसकी किश्त भरने का काम भारत सरकार करे ताकि गांव और किसान को मजबूत किया जा सके।

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस सबजेक्ट पर बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1833 बजे

श्री धर्मेन्द्र यादव (आजमगढ़) : धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की अनुपूरक मांगों का अपनी पार्टी की ओर से मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। विरोध केवल इस बजट की स्वीकृति और विरोध का नहीं है। सरकार की एक प्रक्रिया है, आप बजट लेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन मुद्दों पर, जिन बातों और वायदों के साथ यह सरकार दिल्ली में बैठी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि हर साल दो करोड़ रोजगार देने का वायदा आपने किया था, लेकिन आजाद भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर कभी हुई है तो वह आज की तारीख में है। लेकिन वित्त मंत्री जी इस मुद्दे पर आप कभी बात नहीं करती हैं। पप्पू भाई कालेधन की चर्चा कर रहे थे और मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। स्विस् बैंक से सौ दिन में काला धन लाने का वायदा करने वाले लोग 11 साल में भी काला धन नहीं ला पाए हैं।

माननीय सभापति : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री धर्मेन्द्र यादव (आजमगढ़) : सभापति जी, हमारे किसान भाइयों को स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप उनकी फसलों की लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का कानूनी वायदा करने के बावजूद केन्द्र की सरकार ने आज तक उस कानून को लागू करना तो बहुत दूर की बात है, अगर उस मांग को लागू करने के लिए किसान हरियाणा से चलते हैं तो उन्हें सिंधु बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है।

(1835/YSH/VR)

वे नहीं मानते हैं तो जेलों में डाल दिए जाते हैं। उन पर फायरिंग की जाती है। ढोंग करने के लिए उन पर फूल भी बरसाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद फायरिंग भी की जाती है। यहां संसद में बैठे हुए सांसदगण अगर उन किसान भाइयों से जेल में जाकर मिलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। किसानों के ऊपर ऐसा तांडव या तो अंग्रेजों के शासन में हुआ होगा या आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है।

सभापति जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि आपने एमएसपी जारी नहीं की। आपने लगभग सभी विभागों के लिए बजट में अनुपूरक मांगों की है। लगभग 102 मदों में मांग की गई है और 102 मदों में जितनी भी मांगें हैं, उन सब पर तो मैं प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि मुझे सभापति जी इतना समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैंने जिन-जिन पर भी नजर दौड़ाई, वहां पर आपने कहीं भी काम नहीं किया है।

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI) Hon. Member, please address the Chair.

श्री धर्मेन्द्र यादव (आजमगढ़) : जी, मैं आपको ही एड्रेस कर रहा हूँ। अगर मैं किसानों की बात करूँ तो आप उनको डीएपी खाद नहीं दे रहे हैं। आप उन्हें एमएसपी नहीं दे रहे हैं। कर्ज माफी का वादा आपने किया था, लेकिन आज तक कर्ज माफ नहीं हुआ। अगर कोई बड़े उद्योगपति हैं तो उनके लाखों-करोड़ों रुपये का कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन किसानों के ऊपर अगर 10-20 हजार रुपये भी छूटते हैं तो उनके ऊपर आपकी सरकार के माध्यम से पुलिस से वसूली करवाई जाती है। मैं इस मौके पर अपने किसान भाइयों के लिए मांग करता हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने कभी ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि उन्होंने किसानों को पेंशन देने का काम किया था, हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार हमारे किसानों को भी पेंशन दे और हमारे मजदूरों को भी पेंशन दे।

सभापति जी, जहां किसानों की ये समस्याएं हैं, वहीं नौजवनों के साथ हम समाजवादियों का यह नारा रहा है कि 'बेकारों को काम दो या बेकारी का दाम दो, दवा-पढ़ाई मुफ्त हो और कपड़ा-रोटी सस्ती हो।'

मैं अपने नौजवानों के लिए केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि प्राइमरी, नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तथा रिसर्च तक की पढ़ाई हमारे नौजवानों को मुफ्त में करवाई जाए। हमारे नौजवान पढ़ने के बाद जिस तरह से भटक रहे हैं, रोजगार के नाम पर लाठी खा रहे हैं। इलाहाबाद में अलग लाठी चल रही है। लखनऊ में 69 हजार शिक्षक अलग लाठी खा रहे हैं। देश के अलग-अलग इलाकों में नौजवान लाठी खा रहे हैं। उन नौजवानों को लाठी न मिले, बल्कि सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र मिले, यह हमारी आपसे प्रार्थना है। आज अगर हम अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो दो लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। केन्द्र सरकार के लोग जवाब दें कि आखिर उन पदों को कब तक भरने का काम किया जाएगा। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। यह सही है कि प्रधान मंत्री जी की बात का विश्वास देश की जनता ने किया। उनकी बातों और उनके भाषणों पर लोगों ने भरोसा किया। हमें विपक्ष का होने के बावजूद भी इसे स्वीकार करने में संकोच नहीं है, लेकिन वित्त मंत्री जी, जब इतना भरोसा किया है तो आखिर उस भरोसे को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि जो पेट्रोल के दामों का सवाल है, जब यूपीए की सरकार थी तो बहुत लंबी-लंबी बातें की गईं। उस समय वर्ष 2014 में पेट्रोल का दाम केवल 70 रुपये था और आज बढ़कर 100 रुपये हो गया है।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

Now, Shri Vishaldada Prakashbapu Patil ji.

श्री धर्मेन्द्र यादव (आजमगढ़) : सभापति जी, मैंने अभी अपना भाषण शुरू किया है। डीजल का दाम उस समय केवल 57 रुपये था, आज 90 रुपये है। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will decide whether it is a warning or not. I will decide it.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I have given him a lot of opportunities. I allow you 30 seconds to finish your speech.

....(Interruptions)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आजमगढ़) : गैस का दाम 400 रुपये था, आज 1200 रुपये हो गया है। इसी तरह से पेट्रोल से लेकर तमाम चीजें हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रधान मंत्री राहत कोष के लिए प्रार्थना करूंगा। हम लोग चिट्ठी लिखते हैं, वहां 30-30, 40-40 लाख लोगों की आबादी है और केवल 35 लोगों के लिए कंसीडरेशन होता है, हालांकि उसका पैसा बजट से नहीं जाता है, अगर आप बजट से देना चाहते हैं तो प्रधान मंत्री राहत कोष में दे दीजिए, लेकिन मेरा सभी सांसदों की ओर से अनुरोध यह है कि गरीबों के इलाज के लिए 35 की सीमा बढ़ाकर इसको अनलिमिटेड कर दीजिए। यह कोई मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। आप मनरेगा के मजदूरों को रोजगार दीजिए। अग्निवीर की स्कीम को वापस लीजिए। इसी तरह से रोजगार सेवा, आंगनवाड़ी, आशा बहुएं, पंचायत सहायक, शिक्षामित्र, अनुदेशक तथा रसोइए से लेकर जितने भी संविदाकर्मी हैं, उनका मानदेय बढ़ाइए। उनको स्थायी कीजिए और एक आजमगढ़ का विषय है, जो मेरा अपना संसदीय क्षेत्र है, उसके लिए मैं लगातार सदन के माध्यम से वित्त मंत्री जी को कह रहा हूँ। जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी, मैं लगातार इस मांग को दोहराता रहूंगा। ... (व्यवधान)

(इति)

(1840/RAJ/SAN)

1840 बजे

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : सभापति महोदय जी, इस अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ...(व्यवधान) सर, मैं सबसे पहले सरकार को बधाई देना चाहता हूँ...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आजमगढ़) : सभापति जी, आप मुझे बोलने के लिए एक मिनट का समय दे दीजिए...(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : विशाल पाटील जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : धर्मेन्द्र जी, आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : धर्मेन्द्र जी की बातें रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : धर्मेन्द्र जी ने आखिर में जो बोला है, वह रिकॉर्ड में नहीं आएगा।

... (व्यवधान) ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : सभापति महोदय जी, इस अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ...(व्यवधान) मैं सबसे पहले सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने महाराष्ट्र में अच्छी जीत हासिल की है। यह स्वभाविक है कि उन्हें ऐसा लगेगा कि इस जीत के पीछे उनके इलेक्शन के नारे थे, ये उनकी वजह से जीते हैं। जैसे कि उन्होंने नारा दिया कि एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। हकीकत यह है कि महाराष्ट्र में जीत का कारण यह है कि महिलाओं तक ये अच्छा पैसा पहुंचा सकें। लोगों को यह बताया गया कि डबल इंजन की सरकार बनेगी और इनको पैसा दिया जाएगा।

सर, चुनाव जीतने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि अब ये जीत गए हैं, तो महाराष्ट्र को बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। हम बचपन में एक मराठी कविता गाते थे

ये रे ये रे पावसा
तुला देतो पैसा
पैसा झाला खोटा
पाउस आला मोठा

इन लोगों ने पैसा दिखा कर वोटों की बारिश करवा दी, लेकिन जैसे इनको वोट मिले हैं, वैसे इन्होंने सारा पैसा निकाल दिया। इस बार महाराष्ट्र को कुछ अपेक्षा थी, जो पूरी नहीं हो सकी।

सर, मैं पहले से कहता था कि इन्होंने फर्टिलाइजर में कम सब्सिडी का प्रोविजन किया है। अभी 6,593 करोड़ रुपए ज्यादा की डिमांड की गई है। Is it enough? फर्टिलाइजर पर जीएसटी इतनी बढ़ी है कि किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। फर्टिलाइजर की कीमतों में 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। आज इसके कारण किसान मर रहे हैं। इन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना 7000 करोड़ रुपए की मांग की है, लेकिन इनको भूमिहीन किसानों के लिए भी कुछ करना चाहिए था, जो ये कर नहीं पाए। आज किसान इसलिए नाराज हैं कि उनको जितना फायदा चाहिए, उतना फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए आज किसान बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं।

सर, इन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए कुछ पैसे मांगे हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ, लेकिन 213 करोड़ रुपए सफिशिएंट नहीं हैं। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड में ज्यादा निधि देने की जरूरत थी।

सर, सांगली के किसानों को भी एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ज्यादा मिलेगी तो उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। NITI Aayog's Strategy for New India कहती है कि आज 92500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत में जितनी कोल्ड चैन मैनेजमेंट होनी चाहिए, उतनी नहीं बन पाई है। That is why, I was saying that they should have at least doubled the budgetary allocation for agriculture research.

Sir, I also want to say that they spoke about the RCS-UDAN Scheme. आरसीएस-उडान स्कीम के लिए पैसे मांगें गए हैं, लेकिन सांगली जैसे शहरों में नया हवाई अड्डा बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सर, क्वार्टर टू में जीडीपी 5.4 प्रतिशत नीचे आ चुकी है। जब मोदी जी पंतप्रधान नहीं थे, तो सात प्रतिशत जीडीपी होने के बावजूद उन्होंने कहा था कि ध्यान देना चाहिए, रुपया तेजी से कमजोर नहीं होना चाहिए, विकास दर नहीं गिरना चाहिए, इंप्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए। आज ये तीनों चीजें हो रही हैं, लेकिन यह सरकार ध्यान देने को तैयार नहीं है। इकोनॉमी की पुअर परफॉर्मेंस रही है, यह मैनुफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान नहीं देने की वजह से हुई है।

सर, 2.8 प्रतिशत का डीग्रोथ एक्सपोर्ट में हुआ है। मिडल क्लास की पूरी कमर, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने भी लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि 100 देशों में मिडल इनकम ट्रैप में आने वाली है, उसमें इंडिया का नाम लिया गया है। We have to increase the economic growth rate to at least eight per cent, if we have to come out of this.

I urge the Government to please concentrate on the economy. It is directly related to election performance. Therefore, something needs to be done, and especially for the State of Maharashtra which contributes to the economy in a big way.

Thank you.

(ends)

1844 hours

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Hon. Chairperson, Sir, I stand here to know the amount of money granted to the State of Tamil Nadu and particularly to my constituency, Tiruvannamalai, in the aftermath of the Cyclone Fengal and a severe landslide that shattered the socio-economic life in the State, in general.

In the first batch of the Supplementary Demands for Grants (2024-25), the Government seeks parliamentary approval for an amount of Rs. 87,762.56 crore.

(1845/SNT/KN)

The net cash outgo aggregates to Rs. 44,142.87 crore and gross additional expenditure to the tune of Rs. 43,618.43 crore, besides Rs. 6,593.73 crore towards the Fertilizer Subsidy Scheme. I hope that the farmers of Tamil Nadu, particularly in Tiruvannamalai will get the benefit of Fertilizer Subsidy Scheme as sought in the Supplementary Demand for Grants.

I strongly believe that Tamil Nadu will get all pending compensation share out of GST compensation fund. The farmers of Tamil Nadu, being severely affected by Cyclone Fengal and landslide which have broken the backbone of the farmers economically.

Therefore, they urgently need rehabilitation and compensation for reshaping their economy. Our Chief Minister of Tamil Nadu sought interim relief to the tune of Rs. 2,000 crore and to the tune of Rs. 6,675 crore towards relief and restoration in the affected 14 districts.

However, the Ministry of Home Affairs has approved the release of Rs. 944.80 crore to Tamil Nadu from the State Disaster Response Fund, which is squarely inadequate.

I, therefore, strongly demand from the Union Government to make a provision for adequate amount of compensation, relief and restoration in the interest of the people of Tamil Nadu.

I hope that the Supplementary Demands for Grants to the tune of Rs. 7,692 crore under PM-Kisan and related programmes would be adequately devolved amongst various States including Tamil Nadu for the benefit of farmers.

I strongly believe that Tiruvannamalai parliamentary constituency will be immensely benefited by optimum utilization of funds earmarked as Universal Services Obligation Fund by the Department of Communication. I further hope that the amount to the tune of Rs. 2,000 crore on agriculture infrastructure and development fund would be optimally utilized among various States including Tamil Nadu.

As a conclusion remark, I impress upon the Ministry of Finance for adequate allocation of relief and restoration fund as sought by the Government of Tamil Nadu for speedy and timely relief and restoration besides suggesting the Ministries and Departments for optimum utilization of Supplementary Demands for Grants.

Thank you, Sir.

(ends)

1849 hours

SHRI DURAI VAIKO (TIRUCHIRAPPALLI): Thank you, Sir.

This is pertaining to the Life Insurance Corporation of India. For the 140-crore Indian population, insurance, be it life, medical, property or vehicle, is a critical and important service. Against life's unforeseen events such as accidents, health issues or death, insurance is a lifesaver for the population, especially the underprivileged. As such, the IRDAI had announced the goal of India Insured by 2047 and the Union Government has initiated several measures. Life insurance, especially has been very critical to the survival of families which have lost their sole breadwinner. Though it is commendable that the policies issued by LIC had increased from 56 lakhs in the year 1956 to more than 40 crore policies today, considering an individual holding multiple policies, it can be assumed that only 20 crore people have LIC policies. That leaves nearly 120 crore people without a LIC policy.

(1850/AK/VB)

It is to be noted that 96 per cent of these 40 crore LIC policies have been secured by the untiring efforts of the 14 lakh LIC agents who have played a vital role in taking up insurance to the masses, especially the underprivileged and the uneducated.

The recent announcements made by the LIC management have caused serious setbacks to the objective of increasing life insurance among the masses and has been detrimental to the 14 lakh LIC agents and their 70 lakh family members.

Though, there was a 3.5 per cent year-on-year growth of profit after tax by LIC from Rs. 17,469 crore to Rs. 18,082 crore as reported by its CEO, the following measures which are against good public policies have been adopted by the LIC. The first-year's commission of LIC agents has been reduced, though the overall commission is the same. I would like to mention that the agent's commission has remained the same since the launch of the LIC in 1956, though the IRDA had recommended for increasing the agent's commission multiple times. I would request that there should be no reduction in the first-year's commission and the overall commission is also increased as per the request of the 14 lakh LIC agents.

I would also urge to remove the clawback rule, which calls for repayment of agent's commission if the policy is surrendered within the first-year. The move to reduce the entry-age to all popular insurance policies from 55 to 50 years despite the increase in life expectancy would prevent lakhs of people in getting themselves insured. I would recommend the entry-age to be increased to 60 years.

Despite the good financial performance of LIC, the bonus and sum assured on policies has been reduced and the premiums have also been increased. I would urge the Finance Minister that LIC decreases the premiums and increases the bonuses and sum assured. The minimum sum assured has also been increased from Rs. 1 lakh to Rs. 2 lakh, making it difficult for the underprivileged to avail of the insurance policies since the premiums are also increased. The minimum sum assured is to be retained at Rs. 1 lakh.

I would request the Finance Minister to advice the LIC management to implement the above recommendations so as to achieve the goal of 'India Insured by 2047' and keeping the interest of the common man in mind.

Lastly, with regard to the Trichy Metro Rail Project, the Chennai Metro Rail Limited had constituted a Committee, including representatives of the Union Government, to do a feasibility report. The Committee had, in principle, approved the project. On behalf of the public of my Trichy Constituency, I sincerely request the Union Government to approve the project and the hon. Finance Minister to sanction the necessary funds for speedy implementation of the Trichy Metro Rail Project. Thank you, Sir.

(ends)

1853 बजे

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : माननीय सभापति महोदय, इधर कांग्रेस पार्टी के मित्र नहीं हैं। काइंडली, मैं उनको सुनने के लिए बोलता हूँ... (व्यवधान) जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो ... (Not recorded) की एक नयी कमेटी बनी- नैशनल एडवाइज़री काउंसिल। दिल्ली में अलग से पीएमओ मंत्रालय बनाया गया। वह कौन थीं, तो ... (Not recorded) थीं। अंडमान और निकोबार के लिए क्या किया? नैशनल एडवाइज़री कमेटी बनी, ... (व्यवधान)

श्री बी. मणिकम टैगोर (विरुधुनगर) : सर, दूसरे हाउस के मेम्बर का नाम नहीं लेना चाहिए... (व्यवधान)

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : सर, मैं बोलता नहीं था, लेकिन ये लोग बहुत कुछ बोलते हैं... (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लो... (व्यवधान)

सर, अंडमान और निकोबार द्वीप में बफ़र ज़ोन बनाया गया। बफ़र ज़ोन के नाम पर, जो लोग आज़ादी की क्रांति में अंडमान की धरती पर आए थे, उनकी जमीनों को बफ़र ज़ोन में दे दिया। जो रिफ्यूजी लोग थे, उनकी जगह को बफ़र ज़ोन बना दिया। अंडमान और निकोबार के जो देशभक्त लोग सेल्युलर जेल में आए थे, उनको बफ़र ज़ोन बना दिया। कोई संविधान नहीं था, कुछ नहीं था। केवल नैशनल एडवाइज़री काउंसिल था, जिसे ... (Not recorded) ने बनाया था... (व्यवधान) Please do not disturb me. ... (Interruptions) मैं ज्यादा बोलूँगा... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Please address the Chair only.

... (Interruptions)

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : उस समय ... (Not recorded) थे।... (व्यवधान) बफ़र ज़ोन के नाम पर अंडमान के लोगों की जमीनों को बफ़र ज़ोन बना दिया... (व्यवधान) वहाँ होटल बंद हो गए, लॉज़ बंद हो गए, सब बंद हो गए... (व्यवधान) और क्या बनाया? ... (व्यवधान) ईस्ट-कोस्ट में जरावा रिज़र्व बनाया... (व्यवधान) ईस्ट-कोस्ट में कौन बैठे थे? ... (व्यवधान) वहाँ अंडमानी की धरती के लोग थे... (व्यवधान) ईस्ट-कोस्ट में अंडमान की धरती के लोग क्रांतिकारी थे, जिनके लिए सेटलमेंट हुआ था... (व्यवधान) उनको मछली मारने के लिए फिश कैच करना पड़ेगा... (व्यवधान)

(1855/PC/UB)

फिर बनी ... (Not recorded) नेशनल ... (व्यवधान) पहले समुद्र में पांच किलोमीटर मछली मारने जाते थे ... (व्यवधान) मछुआरों को अंदर कर दिया, जेल में डाल दिया, केस बना दिया ... (व्यवधान) फिर, बाद में वाजपेयी जी ने हम लोगों को बचा लिया ... (व्यवधान)

अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ ... (व्यवधान) आप सुनिए कि ... (Not recorded) ने सुनामी में क्या किया? ... (व्यवधान)

श्री बी. मणिकम तैगोर (विरुधुनगर) : सर, ये नाम कैसे ले सकते हैं? ये नाम क्यों ले रहे हैं? ... (व्यवधान)

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अरे, आप सुनिए कि ... (Not recorded) के नाम पर ... (Not recorded) ने क्या किया? ... (व्यवधान) सुनामी आया, खेत डूब गया, सब कुछ हो गया, रुपए दिए सिर्फ नौ लाख, लैंड हैक्टेयर्स में ले लिया। ... (व्यवधान) खेती डूबी पड़ी है, लेकिन ट्रैक्टर दिया, हल दिया, सब दिया। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : माननीय सदस्य, आप किसी का नाम मत लीजिए। ... (व्यवधान)

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : चेयरमैन सर, श्री मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के समय काल में देश के ... (Not recorded) थे, उन्होंने सुनामी घोटाला किया था। ... (व्यवधान) सुनामी में ... (Not recorded) लिया। ... (व्यवधान) लोगों के खेत डूब गए, घर डूब गए, सब डूब गया, नौ लाख रुपए दिए। ... (व्यवधान) रुपयों का क्या किया? खेता इतना डूबा पड़ा है, ट्रैक्टर दिया, बुल्डोजर दिया। ... (व्यवधान) पूरी सरकार ने रुपए ... (Not recorded) लिए। ... (व्यवधान) मैं खासकर नाम नहीं लूंगा। ... (व्यवधान)

आप सब एक और कहानी सुनो। ... (व्यवधान) आप सब सुनो। ... (व्यवधान) अंडमान की धरती पर आपने वाइपर द्वीप का नाम सुना होगा? ... (व्यवधान) वाइपर द्वीप में कौन लोग आए थे? ... (व्यवधान) वाइपर द्वीप पर वे लोग आए थे, जो लोग अंडमान की धरती पर वर्ष 1864 में आए थे। ... (व्यवधान) वाइपर द्वीप पर जो क्रांतिकारी लोग आए थे, जो भारत से और बाकी जगहों से आए थे, वाइपर द्वीप में पहली ओपन जेल, वाइपर चैन गैंग जेल है। ... (व्यवधान) उस जेल में कौन लोग आए थे? हमीरपुरिया आया था। ... (व्यवधान)

श्री बी. मणिकम तैगोर (विरुधुनगर) : सर, सप्लिमेंट्री डिमांड्स पर बात करनी चाहिए। दादा क्या बात कर रहे हैं? ... (व्यवधान)

SHRI BISHNU PADA RAY (ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS): Sir, please ask the hon. Member not to disturb me. ... (Interruptions) कांग्रेस मेरी बात सुन लो। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज़, आप चेयर को एड्रेस करें। ... (व्यवधान)

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : वाइपर द्वीप में फर्स्ट चैन गैंग जेल बनी। ... (व्यवधान) उस जेल में क्या था? हमारे देशभक्त लोगों को कमर और पांव में चैन बांधकर काम

कराया जाता था। ... (व्यवधान) उस द्वीप को कसीनो के नाम पर बेच दिया, जुए का अड्डा बनेगा, नंगा नाच चलेगा। ... (व्यवधान) अर्नब गोस्वामी एक व्यक्ति था, मेरे द्वीप को उसने बचा दिया।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बात कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अर्नब गोस्वामी एक व्यक्ति था, मेरे द्वीप को उसने बचा दिया। ... (व्यवधान) ... (Not recorded) ने बाद में माफी मांगी थी। इससे वाइपर द्वीप बच गया था। ... (व्यवधान)

अब इनकी कहानी को छोड़ता हूँ। ... (व्यवधान) इनकी कितनी कहानी कहूँ? ... (व्यवधान) अंडमान और निकोबार का सारा रुपया इनकी सरकार के पूर्वज मंत्री लोगों ने ... (Not recorded) लिया। ... (व्यवधान) सीबीआई की जांच कराइए। ... (व्यवधान) सबके घर के अंदर से सोना-चांदी निकलेगा। ... (व्यवधान) मैं श्री अमित शाह जी से कहूँगा कि आप इसको देखो। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, अब आप कृपया कंक्लूड कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : नेक्स्ट पॉइंट हैं ... (Not recorded) ... (व्यवधान) ... (Not recorded) ने अंडमान और निकोबार के साथ क्या किया, यह आप सुनिए। ... (व्यवधान) बंगाल से आलू आता है, प्याज आता है, लहसुन आता है, सब्जी, फूल गोभी, पत्ता गोभी। ... (व्यवधान) खजूर का गुड़ भी आता है। ... (व्यवधान) ... (Not recorded) ने बोला कि बंगाल से अंडमान और निकोबार के लिए आलू नहीं जाएगा। ... (व्यवधान) बंद कर दिया। ... (व्यवधान) आलू बंद, प्याज बंद। ... (व्यवधान)

अंडमान में आलू की कीमत 150 रुपए किलो है, लहसुन 500 रुपए किलो है, फूल गोभी 100 रुपए प्रति किलो। ... (व्यवधान) क्यों? क्योंकि ... (Not recorded) ने कहा कि अंडमान में बीजेपी एमपी क्यों बना? ... (व्यवधान) इसलिए, बंद कर दो। ... (व्यवधान) ... (Not recorded) में ममता नहीं है। ... (व्यवधान) ... (Not recorded) का नाम कुछ और करो। ... (व्यवधान) मैंने पत्र लिखकर मांग की। ... (व्यवधान) पत्र ... (Not recorded) को दे दिया, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। ... (व्यवधान) मैंने कहा मुख्य मंत्री जी, आपको पत्र दिया है। ... (व्यवधान) ऐसे होती है आलू की ब्लैक मार्केटिंग। ... (व्यवधान) कहां होता है? बंगाल में होता है। ... (व्यवधान)

अंडमान को आप आलू नहीं देंगे, प्याज नहीं देंगे, लहसुन नहीं देंगे, सब्जी नहीं देंगे? ... (व्यवधान) खजूर की गुड़ नहीं देंगे? ... (व्यवधान) दादा, आप प्याज खाओगे? मैं क्यों नहीं खाऊंगा? ... (व्यवधान) बंगाल के लोग ही प्याज और खजूर का गुड़ खाएंगे? ... (व्यवधान) मैं बताता हूँ कि

अंडमान की धरती के लिए हमारी सरकार ने क्या काम किया है? लास्ट पांच सालों में अंडमान जिला परिषद के लिए 16 लाख रुपए दिए। ... (व्यवधान) दादा, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं। ... (व्यवधान)

(1900/IND/PS)

सभापति जी, जिला परिषद में 16 लाख रुपया दिया गया। क्या इतने रुपयों में सड़क बनेगी। समिति को चार लाख रुपया दिया, क्या इतने रुपये में रास्ता बन सकता है? ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपये दिए, क्या इतने में रास्ता बन सकेगा?

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : बिष्णु पद जी, धन्यवाद। आप बात समाप्त कीजिए।

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति जी, मैं सिर्फ आखिरी बात बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2018 में वायदा किया था और 30 दिसम्बर को मीटिंग हुई थी। 12 फरवरी, 2019 में मीटिंग हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि 279 किलोमीटर सड़क बनाएंगे।

माननीय सभापति : आप बात समाप्त कीजिए।

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंडमान निकोबार के लिए 279 किलोमीटर सड़क के लिए 344 करोड़ रुपये दिए और अंडमान को आगे बढ़ाया। कांग्रेस से कहा कि संभलकर रहना, वरना पोल खुल जाएगी। अंडमान का जो काम हुआ, वह मोदी जी ने किया।

(इति)

1902 बजे

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति जी, मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आज 87762 करोड़ रुपये की सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स लाई गई हैं। ओरीजिनल बजट 48 लाख करोड़ रुपये का था और सप्लीमेंट्री डिमांड इसका 1.8 परसेंट है। मुझे कहना है कि इस डिमांड में 203 पेजेज हैं और इन्हें पढ़ने के बाद लगता है कि यह सब खोखला है। परसों देश के पंत प्रधान, प्रधान मंत्री जी का भाषण हुआ और भाषण देते समय कहा कि 'मुंह को खून लगा है' मैं कहना चाहती हूँ कि एक और जुमला आया है कि खून मुंह को नहीं लगा है बल्कि हमारा खून देश की मिट्टी में शामिल होने का काम हुआ है। देश की मिट्टी में हमारा खून है। इस देश की एकता, अखंडता के लिए और लोगों के लिए न्याय देने का काम कांग्रेस ने किया है और हमारा खून इस देश की मिट्टी में है। मुझे यहां से कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर चाहे झांसी की रानी हो, चन्द्र शेखर आजाद हो, टीपू सुल्तान हो, मंगल पांडे हो, सभी ने देश के लिए खून बहाने का काम किया है। मुझे इस बात का गर्व होता है कि जब किसी ने कहा था कि हम लाल आंखे दिखाएंगे, छप्पन इंच की छाती दिखाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि इंदिरा जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके भी दिखाई थी और पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया।

सभापति जी, मुझे कहना है कि लाल आंख दिखानी है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, छप्पन इंच की छाती है तो बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है, उसकी आप जिम्मेदारी लो और उसे कैसे बंद कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा। मुझे एक और बात कहनी है कि अहिंसा के पुजारी और सत्य के पुजारी महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की? उनका खून इस धरती में मिला है। जिन्होंने गांधी जी का खून किया, कुछ लोग उनका पुतला बनाते हैं। उनकी जयंती को मनाने का काम करते हैं। यह सबसे ज्यादा गलत काम है। फोटो में भी आया था कि कौन लोग उनकी सपोर्ट में खड़े थे। वह किसकी-किसकी फोटो थी, उसे भी देश ने देखा है। देश सब जानता है। हमने देखा है कि देश में शांति रहनी चाहिए, तमिलनाडु में शांति रहनी चाहिए, श्रीलंका में शांति रहनी चाहिए इसलिए टूप भेजने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया। देश में अमन रहना चाहिए, इसमें उनकी भूमिका थी। वे स्वयं वहां शांति का संदेश लेकर गए थे। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि पिछले एक साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन देश के प्रधान मंत्री जी को वक्त नहीं है कि वे मणिपुर जाएं, क्योंकि मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा है। आज वहां के लोग यहां आकर बात करते हैं, यहां आकर गुहार लगाते हैं लेकिन देश के प्रधान मंत्री के पास वहां जाने का समय नहीं है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि लोक सभा के इलेक्शन के समय प्रधान मंत्री जी मुम्बई में प्रचार करने के लिए आए। जिस रास्ते से गए, उस रास्ते में घाटकोपर में एक घटना हुई थी और कुछ लोग घायल हुए थे। पास में ही राजवाड़ी अस्पताल था लेकिन देश के प्रधान मंत्री घायल लोगों को देखने नहीं गए, मृतकों की फैमली को मिलने नहीं गए। यदि इस तरह की संवेदना प्रधान मंत्री जी में देश के लोगों के लिए है तो क्या संदेश जाएगा?

(1905/RV/SMN)

सम्माननीय सभापति जी, परम पूजनीय महामानव 'भारत रत्न' डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वर्ष 1938 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेम्बली के बजट भाषण में जो कहा था, उसे मैं यहां पर कहना चाहती हूँ - 'एक अमीर आदमी सरकार के स्वाधीन या आत्मनिर्भर होने की जोखिम उठा सकता है।' यह मैं जान-बूझ कर कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था - '... यह गरीब ही है, जो चाहता है कि सरकार उसकी सहायता करे। यह गरीब ही है, जिसे अधिक सेवा की जरूरत है।' यह बाबा साहेब ने भारत के बारे में सत्य स्थिति कहने का काम किया।

लेकिन, दुर्भाग्यवश, मैं देख रही हूँ कि आज उलटी परिस्थितियाँ हैं। गरीब आदमी संघर्ष कर रहा है और अमीर मित्रों को देश में फायदा देने का काम चल रहा है। गरीब आदमी रोजी-रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट के लिए दिन-ब-दिन तकलीफ सहता है और अमीरों के लिए, दोस्तों के लिए मुनाफे के फायदे बनाए जाते हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं। यह हम आजकल देख रहे हैं।

सम्माननीय सभापति महोदय, मैं यहां पर सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के नम्बर-42 पर बात करना चाहती हूँ। मैं 'ट्रांसफर टू स्टेट्स' के मुद्दे से शुरुआत करना चाहूँगी। मैं प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए बात करना चाहूँगी। पिछले हफ्ते में मैंने महाराष्ट्र में एक घटना देखी, जो दिल दहला देने वाली थी। वह घटना हिंगोली के एक सरकारी अस्पताल की थी। वहां परिवार-नियोजन की शल्य-क्रिया के लिए कुछ महिलाएं गयीं थीं। शल्य-क्रिया होने के बाद उनके लिए वहां पर पर्याप्त बेड्स की व्यवस्था नहीं थी। 43 महिलाएं ठंड में जमीन पर सोयीं थीं। क्या यही हमारे राज्य की 'लाडली बहन' योजना है, यह मैं यहां से पूछना चाहती हूँ।

सम्माननीय सभापति महोदय, नीति आयोग के अनुसार जो वर्ष 2021 की रिपोर्ट आयी है, उसके मुताबिक 72 प्रतिशत अस्पतालों के बेड्स शहरी इलाकों में हैं और ग्रामीण भागों की अवस्था बहुत खराब है। आज मैं यह कहना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन के लिए जो बजट दिया जाता है, उसका मात्र 40 प्रतिशत बजट ही आवंटित किया जाता है।

सम्माननीय सभापति महोदय, मेरे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कृपया मुझे बोलने दीजिए... (व्यवधान)

सम्माननीय सभापति महोदय, इस साल का हमारे राज्य का स्वास्थ्य का जो बजट है, वह कुल खर्च का 4.6 प्रतिशत है जबकि हमारे राज्य में अभी 'डबल इंजन की सरकार' है, बहुत विकसित राज्य है और हमारे राज्य में ये परिस्थितियाँ हैं कि महिलाओं को इसके लिए डेढ़-दो मील चल कर जाना पड़ता है। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक आई.सी.यू. में बच्चे झुलस कर मर गए।

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : मैडम, आप कृपया एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सम्माननीय सभापति महोदय, मुझे दो मिनट बोलने का समय दीजिए क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे 'एविएशन' पर बात करनी है।

सम्माननीय सभापति महोदय, मैं 'उड़ान' योजना के बारे में बात करना चाहूँगी। जो सात नए एयरपोर्ट्स दिए गए हैं, उनमें लैंडिंग और पार्किंग में कितने पैसे ज्यादा बढ़ाए गए हैं, मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में कभी तो इस सभागृह को जानकारी दी जाए। मैं बताना चाहती हूँ कि यह 350 प्रतिशत बढ़ा है। वे जो चार्ज करते हैं, वे एयरलाइन्स कंपनी को चार्ज करते हैं। एयरलाइन्स कंपनियाँ कोई चैरिटी करने के लिए नहीं बैठी हैं। वे ग्राहक को चार्ज करती हैं। आज आप दिल्ली तक के टिकट की कीमत देख लीजिए, आप लखनऊ-मुम्बई के टिकट की कीमत देख लीजिए। उसे बढ़ाकर 44,000 रुपये तक क्यों किया गया है, क्योंकि ये एयरपोर्ट्स किसी बड़े आदमी को दिए गए हैं, जिन्होंने वहां पर लैंडिंग और पार्किंग के पैसे बढ़ाने का काम किया है... (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति : धन्यवाद।

माननीय श्री रविन्द्र वायकर।

... (व्यवधान)

(1910/GG/RP)

1910 बजे

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : माननीय सभापति महोदय, आज मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स वर्ष 2024-25 के विषय में अपनी बात रखने का अवसर मिला है। यह देश की वित्तीय प्राथमिकताओं को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके तहत 83 ग्रांट्स और 3 एप्रोप्रिएशन्स के माध्यम से कुल 87,762.56 करोड़ रुपये के व्यय की मंजूरी मांगी गई है। इसमें से 44,142.87 करोड़ रुपये का व्यय नेट कैश आउटगो के रूप में है और 43,618.43 करोड़ रुपये की धनराशि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की बचत और बढ़ी हुई प्राप्तियों के माध्यम से पूरी की जाएगी। कृषि और किसानों के कल्याण के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए 7,691.81 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 3,132 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति और जनजाति उप-योजना के लिए प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 4,000 करोड़ रुपये और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के लिए 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नागरी विमानन के लिए, क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS-UDAN) के तहत 231.05 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। शहरी विकास और परिवहन के लिए, मेट्रो परियोजनाओं के लिए 2,201.92 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसके अलावा, सॉवरेन ग्रीन फंड में 2,201.92 करोड़ रुपये और नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) के लिए 108 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

स्वास्थ्य के लिए, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (ICMR) के लिए 89.91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय सेवाओं के लिए, स्पेशल कोर्ट, मुंबई के लिए 1.78 करोड़ रुपये और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRTs) के लिए 2.37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

महोदय, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था आज विश्व में सबसे तेजी से विकास रहा है। दस-12 साल पहले, भारत में बहुत कम स्टार्टअप थे। वस्तुतः पिछले समय में, 2015 से 2022 तक, स्टार्टअप्स में निवेश 15 गुना बढ़ गया है। निवेश में इस उछाल ने एक गतिशील उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया है।

पंत प्रधान आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत, बजट में 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। उसके तहत 1.18 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 87.25 लाख से अधिक का निर्माण और वितरण हो चुका है।

महोदय, देश की जीडीपी वित्त वर्ष 2024-25 में 7 पर्सेंट की मजबूत दर से बढ़ने का अनुमान है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति को

रेखांकित करता है। विकास की यह गति निरंतर रही है, जीडीपी वित्त वर्ष 2022-23 में 7.0% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 8.2% हो गई है।

महोदय, मैं सरकार और मंत्री जी को बधाई देता हूँ और इस supplementary demands for grants का समर्थन करता हूँ।

महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र और मुंबई से सम्बंधित कुछ मांगे आपके सामने रखना चाहूंगा।

मुंबई एयरपोर्ट के विस्तार और नए रनवे के लिए विशेष निधि प्रदान की जाए। क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही रनवे है, जहां से उड़ान भरी जाती है और विमानों की लैंडिंग होती है। जिसकी वजह से देरी होती है। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर दो रनवे की मांग करता हूँ, उसके लिए प्रबंधत किया जाए। महाराष्ट्र के दूरदराज क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए फंड दिया जाए। मुंबई पुलिस के लिए उन्नत हथियार और उपकरणों की व्यवस्था की जाए। कोकण के बंदरगाहों के विकास और मुंबई-गोवा हाइवे के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। मुंबई और कोकण क्षेत्र में मछुआरों के लिए विशेष अनुदान दिया जाए। कोकण रेलवे के स्टेशनों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए निधि का आवंटन किया जाए।

महोदय, यह सरकार के विकासवादी दृष्टिकोण और "सबका साथ, सबका विकास" के वादे को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रस्ताव सभी क्षेत्रों और समुदायों को लाभान्वित करेंगे।

महोदय, पंत प्रधान आवास योजना-2 के माध्यम से दस लाख करोड़ रुपये की निधि की उपलब्धता की गई है। मेरी मांग है कि मुंबई के अंदर जो अनधिकृत झुग्गी-झोपड़ियां बनती हैं, उनको कम करना है तो सस्ते दामों में घर, पंत प्रधान आवास योजना-2 के माध्यम से किया जाए। उसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख 11 हजार करोड़ रुपये के लिए वित्त मंत्री के माध्यम से बजट में कहा गया है तो मुंबई की कनेक्टिविटी के लिए, यानि मेट्रो और रेलवे की कनेक्टिविटी के लिए मैं एक लाख करोड़ रुपये की मांग इस सप्लिमेंट्री बजट के माध्यम से करता हूँ।

धन्यवाद।

(इति)

(1915/MY/NKL)

1915 बजे

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : धन्यवाद, सभापति महोदय। आपने मुझे वर्ष 2024-2025 की पूरक अनुदान मार्गों के प्रथम बैच पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ रहा है, मुख्य रूप से ठेकों के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। बड़े लाभ ठेकेदारों को दिये जाते हैं, जबकि सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए बजट, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से पारित किया जाता है, वह घट रहा है। क्या सरकार पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ आनुपातिक रूप से सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए बजट बढ़ाने की योजना बना रही है? अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए आवंटन पर विवरण यह दर्शाता है कि बजट अनुमान 2023-24 का 1,58,161 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान 2023-24 का 146861.08 करोड़ रुपये हैं। जबकि वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान 165597.70 करोड़ रुपये है। बजट परिव्यय 47,65,768 करोड़ रुपये हैं, जो कुल बजट परिव्यय का लगभग 3% है। यदि नहीं, तो अद्यतन आंकड़े क्या हैं?

महोदय, AWSC/SCSP योजनाएं मुख्य रूप से आय सृजन योजनाओं, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर सकारात्मक कार्रवाई को लक्षित करती हैं, ताकि लक्षित आबादी के बीच गरीबी को कम किया जा सके और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके।

सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों की आबादी के अनुपात में समावेशी विकास के लिए बजट आवंटित करने के लिए जाति गणना के साथ रुकी हुई जनसंख्या जनगणना कब शुरू करेगी?

क्या सरकार बताएगी कि वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अनुसार SCSP और TSP के तहत बजट की व्यय स्थिति क्या है? वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक SCSP और TSP बजट का लंबित बैकलॉग क्या है? बैकलॉग को कम करने के लिए क्या योजना है?

क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम पर मद 1 से पता चलता है कि वर्ष 2022-23 का वास्तविक व्यय 90806 करोड़ रुपये था और वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान केवल 86000 करोड़ रुपये था, जिसमें ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देने के लिए मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत 100 दिनों के काम को देखते हुए भारी कमी की गई है, क्यों?.

13.07 करोड़ सक्रिय श्रमिकों को दर्शाता है, जबकि बजट आवंटन 92.56 करोड़ है।

च

वर्ष 2024-25 में व्यक्ति दिवस सृजित किए गए, यानी अब तक 7 दिन का रोजगार सृजित किया गया। शायद, जी-20 शिखर सम्मेलन दिनांक 7 फरवरी, 2024 के वक्तव्य में संशोधित अनुमान में 74524.29 करोड़ रुपये की खर्च का संकेत दिया गया है, जो बदल सकता है।

बजट अनुमान वर्ष 2024-25 के तहत सक्रिय जॉब कार्ड धारक श्रमिकों को कितने दिनों की गारंटीकृत नौकरी की योजना बनाई गई है? राष्ट्रीय स्तर पर औसत दैनिक मजदूरी भुगतान क्या है? यदि सभी सक्रिय कार्ड धारक श्रमिक 100 दिन काम करते हैं तो कितने बजट की आवश्यकता होगी? क्या मुफ्त अनाज देने के साथ-साथ अतिरिक्त नौकरियां देना उचित नहीं है?

क्या यह वांछनीय नहीं है कि सक्रिय कार्डधारक श्रमिकों को कम से कम 6 महीने या 180 दिन की आजीविका रोजगार सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा निधि में वृद्धि की जाए, ताकि उनमें अपनी रोटी कमाने पर गर्व की भावना पैदा हो और सम्मान के साथ जीने के अधिकार को बढ़ावा मिले?

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग पर समग्र शिक्षा का बजट अनुमान लगभग 10.5% की कमी दर्शाता है। क्या समग्र शिक्षा बजट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुरूप है? सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण आंगनवाड़ी सेवाएँ पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजनाओं के लिए प्रावधान पिछले वर्ष की तुलना में कम है? जबकि एनईपी ने प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के पाठ्यक्रम की सिफारिश की है, जिसके कारण अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके बजट की आवश्यकता है।

क्या अधिकांश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एससी और एसटी समुदाय से हैं? कृपया सामान्य कर्मचारियों के साथ-साथ राज्यवार तैनात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का विवरण साझा करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की राज्यवार प्रभावी उपस्थिति का प्रतिशत क्या है? क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जिसके लिए बजट अनुमान में लगभग 50% की कमी दर्शाता है। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि और अवसंरचना के कारण पूंजीगत व्यय में वृद्धि के बावजूद बजट अनुमान वर्ष 2024-25 में भी कमी की गई है। आप स्वास्थ्य पर व्यय को किस प्रकार बढ़ाएंगे? क्या इसे जीडीपी के 6% के स्वीकार्य स्तर पर लाने का प्रस्ताव रखते हैं?

अनुसूचित जातियों की लगभग 80% आबादी सीमांत किसानों और दिहाड़ी मजदूरों से बनी है जो गांवों में रहते हैं, जबकि शेष आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, इसलिए क्या बड़े पैमाने पर कृषि भूमि पर काम करने वाले दिहाड़ी/प्रवासी मजदूरों के लिए किसान सम्मान निधि स्वीकार्य है? यदि हाँ, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जाति मजदूर और सीमांत किसानों को राज्यवार कितनी किसान सम्मान निधि दी गई, क्योंकि योजना का नाम किसान सम्मान निधि है?

क्या प्रस्तावित यूरिया सब्सिडी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों की प्रतिशत जनसंख्या के अनुरूप है? क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों की राज्यवार लाभार्थी जनसंख्या के बारे में जानकारी देंगे? क्या किसानों को लीगल एमएसपी देने की कोई योजना है?

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसानों के पास कितनी भूमि है?

(1920/CP/VR)

माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध है कि वे सामान्य समुदाय की भूमि के सापेक्ष अनुसूचित जाति और जनजाति की भूमि का राज्यवार विवरण दें। उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन पीएम-यूएसपी लगभग 23 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। क्या पीएम-यूएसपी योजना के तहत एससी, एसटी की आबादी और ड्रॉप आउट योजना के अनुरूप है? यदि हां, तो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रत्येक स्तर पर एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों की ड्रॉप आउट दर क्या है? इसे कैसे कम किया जाएगा? उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन में राज्यवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का प्रतिशत कितना है? प्रधान मंत्री आवास योजना, ग्रामीण बजट में कटौती के बावजूद उच्च आबंटन के कारण एससी और एसटी के क्या अधिक घर बनाए गए हैं? संशोधित बजट 2023-24 में कटौती का क्या प्रभाव पड़ा? वर्ष 2022-23 और 2023-24 में राज्यवार एससी, एसटी समुदायों के साथ-साथ सामान्य समुदाय को कितने घर दिए गए? सरकार द्वारा एससी, एसटी और सामान्य समुदायों को राज्यवार कितने घर आबंटित है? क्या सरकार एससी और एसटी उम्मीदवारों को आबंटित घरों की सूची पते के साथ राज्यवार दे सकती है?

महोदय, सबसे ज्यादा जरूरी है, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के जान की सुरक्षा। एनसीआरबी का डेटा यह कहता है कि एससी, एसटी की महिलाओं का रेप और हत्याएं होती हैं, आज भी उन पर जुल्म होता है और कहीं कोई सुनवाई नहीं है। उनकी बात राज्य नहीं सुनता है। हम लोग केंद्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम केंद्र में कहते हैं तो वे राज्य के ऊपर छोड़ देते हैं। क्या दलित, आदिवासी और पिछड़ों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या उनके जीवन का कोई मोल नहीं है? क्या उनकी बेटियों का सम्मान नहीं है? क्या उनकी बेटियां देश की बेटियां नहीं हैं? क्या उनकी मांओं को अपने बच्चों की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलनी चाहिए?

बजट का तो तब कुछ करेंगे, जब वे जिंदा रहेंगे। मैं लगातार इस पर आवाज उठा रहा हूं मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई ज्यादा उम्मीद बची है। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन वर्गों की सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जब जिएंगे, तभी तो कुछ आगे बढ़ेंगे। अभी 75 साल बाद कहां खड़े हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1722 बजे

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने के लिए आज यहां खड़ा हुआ हूँ। मैं होशंगाबाद, नरसिंहपुर लोक सभा की जनता को धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे यहां पहुंचाया और मैं इस पर गर्व महसूस करता हूँ।

मेरे विपक्षी मित्र जो इस बजट का विरोध कर रहे थे, मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि उनकी बहुत सी व्यक्तिगत डिमांड्स आ रही हैं, एक तरफ वे डिमांड कर रहे हैं और दूसरी तरफ वे बजट का विरोध कर रहे हैं। दोनों में, हंसना और गाल फुलाना एक साथ संभव नहीं हो सकता है। इस बजट में जो अनुपूरक मांगों की गई हैं, वे 87,762 हजार करोड़ रुपये की हैं। उसमें भी 44,142 करोड़ रुपये की नेट कैश आउट गो की मांग की गई है। मैं इसका पुरजोर तरीके से समर्थन इसलिए करता हूँ कि 102 विभागों की प्रत्यक्ष मांग इसमें रखी गई है। जिससे हमारी योजनाएं कमतर न होने पाएं, उनका काम लगातार चलता रहे और काम अतिशीघ्रता से पूरा हो सके।

जब हम इस बजट को देखते हैं तो बजट में हर वर्ग के लिए प्रावधान है। किसानों की बात हमारे मित्रगण बार-बार कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ, 'जाके पांव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई।' किसानों की केवल बात करने से किसानों की समस्या का हल नहीं होगा। यह वही भारत है, जिस भारत में कोई किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा था, लेकिन आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज आईआईटी किए हुए बच्चे भी खेती और किसानों की ओर लौटने लगे हैं। आज किसान अपने खेत में उत्साह के साथ काम करता है। उसकी फसलों में अंतर आने लगा है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, उसमें बमुश्किल एक फसल पैदा होती थी। जेनरेटर से खेती होती थी, लेकिन मैं तत्कालीन राज्य सरकार का और वर्तमान राज्य सरकार, डॉ. मोहन यादव और माननीय शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनके योगदान की वजह से, उनकी क्रियाशीलता की वजह से और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे यहां सिंचाई की परियोजना शुरू हुई। इसमें केंद्र का भी पर्याप्त सहयोग रहा।

(1925/NK/SAN)

पहले सात लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुआ करती थी, अब यह 47 लाख हेक्टेयर हो गई है और इसे 67 लाख हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य लिया गया है। एक समय पर कैपिटा इनकम केवल ग्यारह हजार रुपये थी और यह शर्म की बात हुआ करती थी। अब एक लाख चालीस हजार रुपये के ऊपर हमारी पर कैपिटा इनकम हो गई है। धीरे-धीरे मनः स्तर भी बदलते जा रहा है, हर क्षेत्र में, खेती, किसानों से लेकर जितने भी विभाग हैं, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, खेलों की बात हो, पर्यटन मंत्रालय की बात हो, आयुष मंत्रालय की बात हो, परमाणु ऊर्जा की बात हो, माननीय वित्त मंत्री जी ने नये बजट की मांग की है, हम उसका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। जो कुछ सहयोग हो सकता है, यह एक प्रक्रिया है, लोक सभा में पारित होकर ही आगे बढ़ सकता है, हम पुरजोर तरीके से उसका समर्थन कर रहे हैं।

वर्तमान में इस बजट के अनुसार, 'खरो कमावे, खोटो खावे' हमारे यहां कहावत चलती है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक आशा की किरण जगी है। वर्ष 2014 के पहले देश निराशा से

गुजर रहा था, उस निराशा को आशा में बदलने का काम किया, भारत की अर्थव्यवस्था पहले ग्यारहवीं नम्बर की थी, आज यह चौथे नम्बर की अर्थव्यवस्था बन गई है। केवल चौथे नम्बर की अर्थव्यवस्था ही नहीं बन गई, वर्ष 2047 तक इस अर्थव्यवस्था के माध्यम से भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे और स्वामी विवेकानन्द के सपने को पूरा करेंगे।

नास्त्रेदमस की घोषणा, जिसे इंटरनेट पर देखी जा सकती है, वह भी पूरी होगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। हमारे वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि एविएशन मिनिस्ट्री में काम नहीं हुआ, आप ध्यान कीजिए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय देश में केवल 74 हवाई अड्डे हुआ करते थे, लेकिन अब 170 से ऊपर हैं, इससे उत्साह पर्यटन के क्षेत्र में एक नया उत्साह आया है।

मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से आता हूं, पंचमंढी हमारा एकमात्र हिल स्टेशन है, मईया नर्मदा की गोद में हम सब बसे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी हमारे क्षेत्र को हमेशा कुछ न कुछ देने का काम किया है। हमने पिछली बार रेल लाइन मांगी, उसे दे दिया। मेरा एक और निवेदन है। हमारे क्षेत्र में फोर लेन बहुत आवश्यक है, विकास की दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से भी जरूरी है। हरदा-टिमरनी से नर्मदापुरम तक, नर्मदापुरम से पिपरिया तक होते हुए करेली तक फोर लेन हो जाएगा तो हमारे क्षेत्र का विकास द्रुत गति से दौड़ जाएगा।

हमारे क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है, आप उस पर अनुदान देने का काम करें। सामूहिक मिल बनाकर किसानों को लाभ देने का काम करें। मैं एमएसपी के लिए माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि पूरे देश में समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा खरीदी हुई है तो हमारी सरकार के कार्यकाल में हुई है, बाकी फसलों की भी समर्थन मूल्य में खरीदी हो। हमारे क्षेत्र में बासमती धान बहुत होती है, जीआई टैग की मांग की गई है, इस पर प्रॉपर एमएसपी घोषित की जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। इस बार बजट में प्राकृतिक कृषकों को अतिरिक्त राशि देने का काम किया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ रुपये देने का काम किया है। एक करोड़ किसानों को दो साल के अंदर नए प्राकृतिक कृषक बनाने का काम लक्ष्य लिया है। मेरा माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसमें गऊ माता को आधार बनाकर गऊ माता के उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए।

गऊ माता के उत्पादों को कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से जीवित करने का काम किया जाए। माननीय मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल की जो योजना दी है, आज गांव का युवा उत्साह से भर गया है, नरेन्द्र मोदी जी भारत के लिए वरदान हैं। मैं उनके लिए कहूंगा,

“एक हजार बुझे हुए दीपक एक दीपक को नहीं जला सकते,
लेकिन एक जला हुआ दीपक हजारों दीपक को जला सकता है।”

(इति)

(1930/SNT/SK)

1930 hours

DR. M. K. VISHNU PRASAD (CUDDALORE): Thank you, Chairperson Sir, for giving me an opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants.

¹(Hon. Chairperson, Sir, *vanakkam*. Since our hon. Finance Minister understands Tamil, I wish to start my speech in Tamil. There is a big businessman in our country. He is in the good books of a big leader and hence he has been engaged in several businesses. But he had a doubt. He sought an answer for a question from God, "Oh my Lord, please say who is exploiting the people so much in India?". God replied by saying "Adani". In Tamil, "Athaan Nee" means, "That is you.")

In Ramayan, when Sita was doubted by a common man, immediately Rama asked Sita to go for self-immolation. That is Rama. This is drama. This Government is very adamant in proving their honesty. It is a big opportunity for you to prove that you are honest. But this Government is very pragmatic in their approach.

As far as Supplementary Demands for Grants is concerned, I would like to say that in the recent floods in Tamil Nadu, there was record rain. We never expected it. Our hon. Prime Minister always thumps his chest and says, 'India has sent so many satellites. India is a very technically advanced country'. But unfortunately, we are ashamed to say that we cannot predict the weather because of the global warming and extreme climate condition. In future, it is going to be the order of the day. We do not know how we are going to manage. What has this Government been doing? They are not giving any warning. There is no preparedness, there is no restoration, there is no rescue, and there is no relief. There is nothing at all from this Government. Our Government has been pleading for many years, but there is no restoration and no relief package till now from the Government of India to the State of Tamil Nadu. This is a very bad state of affairs. This is only a bulldozer Government. As far as loan for agriculture, education, middle and small sectors, and small vendors is concerned, this Government is very, very biased. In spite of the uneven playing field, our students are able to clear the NEET exam. After the NEET exam, they are going for a loan. But unfortunately, they are not able to get the loan. This Government talks about Vishwakarma Scheme. Do whatever your forefathers have been doing. Does this Government not want a carpenter's son to become a scientist? Does this Government not want a tailor's son or daughter to become a judge? This is why this Government is only paper *sarkar*, a ... (*Expunged as ordered by the Chair*) and a

¹ Original in Tamil

double-engine *sarkar*. This Government has no concern about the future of India and future generations. This is a very clear display of Manu Dharma and Sanatana. In no way, Rahul ji and our CM Stalin ji will ever allow BJP to enter the State of Tamil Nadu. This is for sure.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Please come to the Supplementary Demands for Grants.

DR. M. K. VISHNU PRASAD (CUDDALORE): There is terrorism in this country.

HON. CHAIRPERSON: Please listen to what I am saying. Please come to Supplementary Demands for Grants. You are talking about something else. We have very less time.

DR. M. K. VISHNU PRASAD (CUDDALORE): This is regarding the loan, Sir. This Government has a new dimension for tax, terrorism tax. There is 18 per cent tax on almost everything. There is no five per cent tax. Almost 90 per cent of the products has got 18 per cent tax. Whereas civil aviation has got only five per cent. Anybody who wants to travel in the flight, they pay five per cent tax. But when a poor farmer or a poor weaver goes on a moped, he has to pay almost or more than 100 per cent tax. Excise duty was three per cent on petroleum products in 2015. Now, it is almost Rs. 40 per litre. Bangladesh takes our petrol. We are the second largest exporter of refined petroleum. They buy petrol from us. They give it for Rs. 80 whereas we are giving it for more than Rs. 105 rupees. This is a very sad story.

(1935/AK/KDS)

Regarding toll plaza, it is a day-light robbery. In Tamil Nadu, more number of tolls are there, especially from Cuddalore to Chidambaram a new toll has been announced. Our bus association owners are pleading, but this Government is deaf and mute.

This Government is famous for naming ceremonies. ... (*Interruptions*) Rajpath is a road, but nobody likes 'Kings' here. They immediately change it to Kartavya Path. Then, what will they do for Rajasthan? Will they name it as 'Kartavyasthan'?

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Please come to the Budget.

... (*Interruptions*)

DR. M. K. VISHNU PRASAD (CUDDALORE): Okay, Sir.

Regarding caste-based census, this Government should conduct a caste-based census immediately. There is no mention about it in the Supplementary.

1936 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

Regarding NLC, there is a Public Sector Undertaking in my Constituency called NLC, which is a Navaratna. They have promised to open a Ghatampur Thermal Station by 2020. Till now, they have not opened it. They have not given CoD and almost Rs. 6,000 crore escalation has taken place. What mechanism is this Government going to bring for the NLC issue?

Last but not least, this Government always talks big about everything, but in reality they are not bothered about the people. Poor people become poorer and rich become richer. There is economic divide and the economic divide is becoming broader. Unfortunately, this Government is mute towards the pleading and crying of the people.

Moreover, regarding my Constituency, we want a double track. My Constituency is Cuddalore. There is a double track from Chennai to Villupuram, there is a double track from Trichy to Kanyakumari, but in-between there is no double track. So, I would urge upon this Government to include the project.

We want a Vande Bharat train that should go from Chennai to Rameshwaram via Banruty, Cuddalore and Chidambaram. ... (*Interruptions*)

माननीय अयधक्ष : यह विषय डिमांड फॉर ग्रांट्स पर है।

DR. M. K. VISHNU PRASAD (CUDDALORE): But it is not included, Sir. My request is to kindly include those also as per demand, and we will be pleased to ... (*Interruptions*)

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, it is our demand for their Grant. ... (*Interruptions*)

माननीय अयधक्ष : आप विद्वान माननीय सदस्य हैं!

... (व्यवधान)

DR. M. K. VISHNU PRASAD (CUDDALORE): Yeah, that is not mentioned in the Demands. So, we are requesting it. Where else can we go for it? Whatever may be the differences, we have to ask our hon. Madam and she has to be kind enough to see Tamil Nadu with a motherly approach. Thank you very much, Sir.

(ends)

HON. SPEAKER: Thank you, Vishnu Prasad ji.

Shri Jagdambika Pal.

1938 बजे

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने अपने आसन से कहा कि यह First Batch of Supplementary Demands for Grants 2024-2025 का है। स्वाभाविक है कि बजट की एक प्रक्रिया है और जब साल का वार्षिक बजट प्रस्तुत होता है, तो उस बजट के बाद चाहे कोई सरकार हो, वह फर्स्ट सप्लीमेंट्री भी लाती है, जरूरत पड़ती है तो सेकेंड सप्लीमेंट्री भी लाती है, थर्ड सप्लीमेंट्री भी लाती है। आखिर सरकार यह क्यों लाती है? जिस समय कोई बजट तैयार होता है और उस समय किसी चीज का उस बजट में प्रावधान नहीं किया जाता है, उसका कोई एलोकेशन नहीं होता है और आगे चलकर देश हित में अति आवश्यक है कि बजट में प्रॉविजन नहीं है, लेकिन उस बजट को इस पार्लियामेंट से सैंक्शन कराकर उस कार्य के लिए खर्च करना आवश्यक है, इसलिए हम सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लाते हैं। इसीलिए हम उस समय कोई चीज फोर्स ही नहीं करते हैं। उन परिस्थितियों में हमारी वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हमारा First Batch of Supplementary Demands for Grants 2024-2025 लेकर आई हैं, जो फाइनेंशियल एडजेस्टमेंट के लिए एसेंशियल है। हमारे तमाम साथियों ने कहा कि इसमें एक तरह से जो ग्रॉस एडीशनल एक्स्पेंडिचर है, वह करीब 87 हजार 763 करोड़ रुपये का है। हमारा जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स आता है, इसका काँसेप्ट क्या है? इसके तीन काँसेप्ट हैं। एक तो cash supplementary होता है, एक टेक्निकल सप्लीमेंट्री होता है, एक टोकन सप्लीमेंट्री होता है। जब हम फर्स्ट सप्लीमेंट्री बैच को बनाते हैं, तो उसके मद्देनजर उसके पैरामिटर्स क्या हैं, तो कैश सप्लीमेंट्री में given total appropriation available in Budget Estimate is to be augmented through cash additionally and there are not enough savings available within the grants to meet additional fund requirement by way of reappropriation.

(1940/UB/MK)

Provided the savings available within one section have to be utilised in another section. अगर हम इसे एक हेड से दूसरे हेड में लेकर जाएंगे, for instance, savings in the revenue voted section has to be utilised for the capital voted section. A technical supplementary is also provided when expenditure is to be made through an increase in recovery and receipts, कि रिकवरी क्या है, रिसिप्ट्स क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है। उसके बाद, टोकन सप्लीमेंट्री होता है। टोकन सप्लीमेंट्री में, a provision of Rs. 1 lakh is made to seek

prior approval of Parliament on specific items attracting the financial limits of new services and new instrument of services. इन तीन हेड्स में जो मेजर आइटम्स हैं, चाहे वह कैश सप्लिमेंट्री हो, टेक्निकल हो या टोकन हो, वह किस-किस हेड में हमने इसमें लिया है।

आप देखिए, सबसे पहले हम विपक्ष की बात करते हैं। देश के किसानों की और किसानों के हितों की, लेकिन आज शायद वे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की तरह बोल रहे हैं। अन्यथा, आज हमारी सरकार को सबसे पहले, सत्तापक्ष का या प्रतिपक्ष का कोई भी माननीय सदस्य होता, आज हमारा जो फर्स्ट बैच आया है, उसमें हमने सबसे पहला प्रोविजन Agriculture and Farmer's Welfare के लिए किया है। किसानों के लिए और किसानों की कृषि के लिए किया है। उसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3,500 करोड़ रुपये हमारी वित्त मंत्री जी ने मांगे। पूरे सदन को इसको सर्वसम्मत से कहना चाहिए कि हम इसको करेंगे। हमने Agriculture and Farmer's Welfare के लिए 9,691.81 लाख करोड़ रुपये मांगें हैं। यह हमने जो 9,691 करोड़ रुपये मांगें हैं, इसमें 3,500 करोड़ रुपये किसान सम्मान निधि है और funds transfer to agricultural infrastructure and development fund. इसका मतलब हम किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत इसे देंगे। जब कोविड के दौरान किसानों के सामने समस्या आई तो लोग अपने घरों में कैद हो गए, लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियां आईं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक खाद्यान की समस्या आई। किस तरीके से पीएम स्वनिधि शुरू किया गया, रेहड़ी-पटरी बंद हो गई, कोविड के कारण लोगों को अपने घरों की दहलीज पर रहना पड़ा। उस समय किसानों को प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की व्यवस्था की कि साल में 6,000 रुपए 2000 की तीन किस्तों के रूप में दिए जाएं। लेकिन, आज उससे आगे बढ़कर हमारी सरकार ने तय किया कि जहां तक प्रधानमंत्री सम्मान निधि में किसानों को बुनियादी आवश्यकता, जैसे खाद, सिंचाई, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाओं की आवश्यकता है, उसके लिए हम 2,000 रुपये की तीन किस्तें दे रहे हैं। जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उसके लिए भी 6,000 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है। मैं निश्चित तौर से अपनी सरकार को बधाई देता हूँ कि उसने 9,691 करोड़ रुपये का प्रोविजन एग्रीकल्चर और फॉर्मर्स के लिए किया है।

अध्यक्ष महोदय, डिफेंस सर्विस की बात कर लीजिए। आज डिफेंस में इस सप्लिमेंट्री में एक्स-सर्विस मैन् के कंट्रीब्यूशन के लिए 8044 करोड़ रुपये मांगे हैं। मैं 'वन रैंक, वन पेंशन' की बात नहीं कर रहा हूँ। उसको हमारी सरकार ने जो वर्षों से लंबित था, उसको पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की पहली बार सरकार में आने के बाद यही प्रतिबद्धता थी।

वे हरियाणा में सैनिकों की रैली में गए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे जो सैनिक वर्षों से देश की सीमाओं की हिफाजत करते हैं, उनके लिए हम यह करेंगे। एक्स-सर्विस मैन के कंट्रीब्यूटी हैल्थ स्कीम के लिए 1,500 करोड़ रुपये, इसी तरह से हमने उनके स्टोर्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया।

ये फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी की बात कर रहे हैं। आखिर इस सप्लीमेंट्री में वित्त मंत्री जी जो लेकर आई हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, फॉर्मर्स वेलफेयर हो, डिफेंस हो या फर्टिलाइजर्स हों, फर्टिलाइजर्स में एडिशनल प्रोविजन किया गया है। पीएंडके फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम के लिए 6,593 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है।

महोदय, मैं आज रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज की बात भी कहना चाहता हूँ। मैं मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाइवेज, cashless treatment for victims of road accidents के बारे में भी कहूँगा। अभी तक रोड पर एक्सीडेंट होता था, अगर कोई उसके साथ नहीं है और वह अकेला है, तो उसकी दवा का इंतजाम किसी हॉस्पिटल में नहीं होता था। सरकार ने पहली बार यह प्रोविजन किया है कि अगर पूरे हाइवेज पर कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है, तो चाहे वह कोई भी हो, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है, उसको साथ कोई है या नहीं है, सरकार उसकी जिन्दगी बचाने के लिए अस्पताल में कैशलेस ट्रीटमेंट करेगी। उसके लिए भी हमने प्रावधान किया है।

(1945/SPS/PS)

मान्यवर, हम चाहे सप्लीमेंट्री की बात करें या हम अपने बजट की बात करें, आखिर विपक्ष हो या सत्तापक्ष हो, हम कहीं तो ईमानदारी से बात करें। टैगोर साहब, अगर आज हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में कहां खड़े हैं? किसी देश के विकास के तीन पैरामीटर्स मानते हैं। एक इन्फ्लेशन रेट क्या है। आज इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है कि महंगाई, मुद्रास्फीति पर हमारी सरकार ने कितना नियंत्रण किया है। दूसरा देश की जीडीपी क्या है, और तीसरा एफडीआई में दुनिया से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है? आज आप आलोचना कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 में इस भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 34.58 बिलियन डॉलर था और आज वर्ष 2024 में 34.58 बिलियन डॉलर से बढ़कर 667.4 बिलियन डॉलर हुआ है। इससे लगता है कि भारत के लिए पूरी दुनिया का नजरिया बदला है।

महोदय, कोविड के बाद पूरी दुनिया का सबसे फेवरेट डेस्टीनेशन चाइना था। जब चाइना से कंपनियों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट और अपने निवेश को निकालना शुरू किया तो लोग पूरी दुनिया में चाइना के बाद जापान नहीं गए, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में नहीं गए, अमेरिका नहीं गए। आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं और मैं अपनी सरकार को

बधाई दूंगा कि दुनिया का सबसे फेवरेट डेस्टीनेशन बनाने का काम एफडीआई में किया है। आज उसी का नतीजा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट 667.4 बिलियन डॉलर हुआ है। आप जीडीपी की ग्रोथ रेट देख लीजिए। आज 8.20 पर ग्रोथ रेट है। आप कम से कम इस बात को स्वीकार कीजिए कि सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है with an accelerated pace in 2024 reflecting robust policies, innovation and global confidence in India's economic framework. पूरी दुनिया में इण्डिया इकोनॉमिक फ्रेम वर्क में हमारी पॉलिसीज़, नीतियों, इनोवेशंस, इनिशिएटिव्स में पूरे विश्व का भारत में कॉन्फिडेंस बना है। इसलिए आज हमारा ग्रोथ रेट 8.20 परसेंट है। इन्फ्लेशन रेट के बारे में आप याद कीजिए कि वर्ष 2014 में महंगाई क्या थी, डबल डिजिट से कभी कम नहीं हुई। इसके बारे में वित्त मंत्री जी भी कहेंगी। जब वर्ष 2012-13 में आपकी सरकार थी तो 10.02 परसेंट थी। महंगाई डायन खाए जात है, इसे शायद आप भूले नहीं होंगे। यह गाना उसी समय बना था। उस समय 10.02 परसेंट देश की महंगाई दर थी। आज हमारी सरकार ने उस महंगाई पर नियंत्रण किया है और वह महंगाई दर 10.02 परसेंट से घटकर 3.65 परसेंट पर रह गई है। The inflation has been brought down to a historic low. पूरी दुनिया के सामने यह ऐतिहासिक गिरावट पर है। And we are demonstrating the success of measures to ensure financial stability to protect the consumers' purchasing power.

इसका फर्क कितना है। आप बात करते हैं। हम डिफेंस में छोटी-छोटी चीजों के लिए बाहर देखते थे। मैं और निशिकांत जी पीएसी के मेंबर हैं। हमारे डिफेंस के सिपाहियों के लिए हाई ऑल्टीट्यूड के लिए जूते खरीदे जाते थे। हम हाई ऑल्टीट्यूड के लिए जूते भी बाहर से इम्पोर्ट करते थे, कैप इम्पोर्ट करते थे। इस देश में डिफेंस का प्रोडक्शन वर्ष 2014-15 में 46,429 करोड़ रुपये था। प्रधान मंत्री ने यहीं पर खड़े होकर कहा था कि हम 101 आइटम्स दुनिया से इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हम खुद डिफेंस में आत्मनिर्भर बनेंगे और भारत में 101 चीजें बनाएंगे। वर्ष 2023-24 में उसका नतीजा यह हुआ कि आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख 27 हजार 265 करोड़ रुपये हुआ है, जो वर्ष 2014-15 में 46 हजार करोड़ था। यह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, चमत्कार है। आज हमने एक्सपोर्ट कितना किया है? वर्ष 2013-14 में डिफेंस में एक्सपोर्ट आस-पास के देशों में 686 करोड़ रुपये का करते थे। ... (व्यवधान) मैं अपनी बात एक-दो मिनट में खत्म कर दूंगा। आज वर्ष 2023-24 में 686 करोड़ रुपये की जगह पर 21 हजार 83 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा है। यह भारत की सक्सेस स्टोरी है, यह भारत की ग्रोथ स्टोरी है। मैं केवल सप्लीमेंट्री बजट तक ही सीमित रहना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : जगदम्बिका पाल जी में इस उम्र में भी पूरा जोश है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : जब आप बैठते हैं तो मुझे और ऊर्जा मिल जाती है।

माननीय अध्यक्ष : ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन समय नहीं मिलता है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : मैं अपनी बात अभी खत्म करता हूँ। जैसा मैंने कहा कि वर्ष 2024 में हमारी ग्रोथ 8.20 है। चाइना, जो दुनिया का सबसे बड़ा पावर बन रहा था और मैं इस बात को कह रहा हूँ तथा विपक्ष के किसी सदस्य को जवाब देना है तो दे दीजिए कि आज भारत की ग्रोथ रेट 8.20 परसेंट है।

(1950/MM/SMN)

चीन की ग्रोथ रेट पांच परसेंट है। चीन हमारी ग्रोथ रेट से क्या मुकाबला करेगा? चीन की 2.8 परसेंट ग्रोथ रेट है। यूनाइटेड किंगडम की 1.1 परसेंट है। आज इंडिया दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। India is becoming one of the fastest growing economies. टैगोर जी, कम से कम आप तारीफ तो कीजिए। भारत की विकास की कहानी नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है।

महोदय, हमारी इंफ्लेशन आज 3.5 परसेंट है। एफडीआई में हम 26 परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि चीन 29.8 परसेंट डिक्रीज कर रहा है। यह भारत की सक्सैस स्टोरी है। हमने कृषि पर भी काम किया है, मैं आपके सामने वह भी कहना चाहता हूँ ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया, अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : सर, मैं केवल दो-तीन बातें कहना चाहता हूँ।

हमने इस सप्लीमेंटरी में लिया है – Cabinet approves seven major schemes for improving farmers lives and livelihoods with a total outlay of Rs. 14,235 crore. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मैं एलोबरेट नहीं करूंगा। वह कृषि डिसिजन सपोर्ट सिस्टम के लिए है और एग्रीकल्चर स्टॉक के लिए है। इसके बाद Crop science for food and nutrition सिक्योरिटी के लिए है। उसके लिए 3979 करोड़ रुपये हैं जो वर्ष 2047 तक फूड सिक्योरिटी का काम करेगा। यह पूरे विश्व को देगा, हम जो विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं।

तीसरा, स्ट्रैंथनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज-कभी क्या कल्पना की थी कि हम एग्रीकल्चर में एजुकेशन करेंगे और मैनेजमेंट करेंगे। एफपीओ का दस हजार का लक्ष्य था। आप लोग तो आंदोलन की बात करेंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को अगर किसी ने लागू किया तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने लागू किया है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को आपने ठंडे बस्ते में डाल रखा था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद। डॉ. अमर सिंह जी।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : हॉर्टिकल्चर और सेरिकल्चर की कोई बात नहीं होती थी, केवल रबी और खरीफ की बात होती थी। हमने कृषि विज्ञान केन्द्र को भी 1202 करोड़ रुपये दिए हैं।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं भारत माला प्रोजेक्ट और प्रधान मंत्री सड़क परियोजना की बात करूंगा। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में आज 765601 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया है और गांवों को जोड़ने का काम किया है। 324186 करोड़ रुपये से देश के गांव, खेत-खलिहान और किसान की जिंदगी को बदलने का काम किया है। इसी के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

(इति)

1952 बजे

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब) : सर, मेरे बहुत सीनियर साथी कह रहे थे और यह बात सही है कि सरकार को सप्लीमेंटरी बजट लाने का अधिकार है और मेरा उस पर कोई सवाल नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : आपके रोकने से थोड़े ही न रुक जाएगा।

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब) : सर, उनको अधिकार है, लेकिन एक ही सुझाव है कि कोशिश करनी चाहिए कि जब बजट बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि सप्लीमेंटरी डिमांड न लानी पड़े। फिर भी यह सरकार का अधिकार है और मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। पिछली बार जब मैंने मैन बिल पर बोला था तो माननीय मंत्री जी ने, जो आज यहां बैठी हुई हैं, कहा था कि अमर सिंह जी अगर इकोनॉमिक पॉलिसी पर बोलते तो अच्छा होता। आप मुझे पांच-सात मिनट इकोनॉमिक पॉलिसी पर बोलने के लिए दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : पांच मिनट आपके हैं और तीन मिनट निशिकांत जी के हैं।

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब) : स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले क्वार्टर में जुलाई से सितम्बर में जीडीपी 5.4 परसेंट रही, गवर्नमेंट ने यह फिगर दी है, वह पिछले साल के 8.6 परसेंट से नीचे क्यों आ गयी है, इसके क्या कारण हैं? मैं यह जानना चाहता हूँ। दूसरा, मेरा सवाल है कि ज्यादातर फिगर्स ऑरगेनाइज्ड सेक्टर की हैं। ऑरगेनाइज्ड सेक्टर 10-15 परसेंट ही होता है, जबकि 90 परसेंट अनऑरगेनाइज्ड सेक्टर का डाटा नहीं है। इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तीसरा, यह अच्छी बात है क्योंकि हम सब भारतीय हैं कि हमारी इकोनॉमी पांच, आठ, दस या बीस ट्रिलियन की हो, यह अच्छी बात है। अगर कंट्री ऊपर की ओर जाएगी तो अच्छा लगेगा।

(1955/YSH/RP)

मैडम, मेरा आपसे एक निवेदन है कि जब भी आप जानकारी देती हैं, जब भी कंट्री ऊपर बढ़ती है तो उसमें पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी, कृपया करके उसके बारे में बता दीजिएगा। मेरे पास लेटेस्ट फिगर्स हैं, उन्हें मैं यहां पर रखना चाहता हूँ। वर्ष 2023 में हमारे देश की पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर में 2,540 थी। इसको वर्ल्ड बैंक और अन्य सारी एजेंसीज लोअर मिडिल इनकम मानती है। अपर मिडिल इनकम 4,516 यूएस डॉलर से 14,000 डॉलर है। मेरा आपसे सवाल यह है कि हम 4,500 वाला फिगर कब क्रॉस करेंगे? जीडीपी बढ़े, टोटल इकोनॉमी बढ़े, यह सब तो अच्छा है, लेकिन हम उस फिगर तक कब पहुंचेंगे?

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूँ कि हाउसहोल्ड सेविंग्स 5.1 परसेंट क्यों रह गई है? जब आप जवाब दें तो उसके कारण बता दीजिएगा। ग्रॉस फाइनेंशियल कैपिटल फार्मेशन, आपके कार्यकाल में क्यों कम हुआ है? आप इसका भी जवाब दे दीजिएगा। मैं एक सवाल का जवाब जरूर देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बार-बार कहा है कि यूपीए ने इतना दिया और एनडीए ने इतना कर दिया। मैं दो-तीन डिपार्टमेंट्स का ब्यौरा दूंगा। मैं बजट की परसेंटेज लेकर आया हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा करके जब आप जवाब दें तो आप बताइएगा कि इस साल के बजट का इतना परसेंटेज हमने दिया है और यूपीए ने इतना दिया था।

मैडम, वर्ष 2013-14 में यूपीए के समय एजुकेशन का बजट पूरे बजट का 3.16 परसेंट था और आपने वर्ष 2024-25 में 1.5 परसेंट दिया है। आपने 50 परसेंट कम कर दिया है। हाँ, ग्रॉस फिगर्स में ज्यादा होगा, क्योंकि 10-12 साल हो चुके हैं। हेल्थ में भी वही हालत है। उस वक्त यूपीए के समय करीब 2.5 परसेंट था और आपने 1.9 परसेंट दिया है। नरेगा में भी वही हालत है। उस समय नरेगा के लिए करीब-करीब 1.9 से 2 परसेंट बजट था और आपने 1.3 परसेंट दिया है। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, चूँकि बार-बार इस पर सवाल उठता है इसलिए मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूँ।

मैडम, मैं बहुत सारी बातें आपसे नहीं पूछ पाया, लेकिन मैं आपको लिखकर दे दूंगा। मैं पंजाब से श्री फतेहगढ़ साहिब का एमपी हूँ। मैं बार-बार बोलता हूँ कि पंजाब के बहुत सारे इश्यूज हैं। पंजाब की इकोनॉमी स्ट्रिजेंट है। आप बार-बार कहते हैं कि डायवर्सिफिकेशन कीजिए। यहां पर फूड मिनिस्टर साहब भी साथ बैठे हैं।

मैडम, मेरा आपसे निवेदन है कि आप डायवर्सिफिकेशन के लिए 15 से 20 हजार करोड़ रुपये पांच से सात साल पंजाब को दीजिए तो डायवर्सिफिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा किसानों का एजिटेशन चल रहा है, चूँकि बार-बार आपके लोग कहते हैं, वह ठीक है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब आपने स्वामीनाथन फार्मूला बना ही दिया है तो एमएसपी का लॉ भी बनाकर ले आते। आप उसे अगली बार कर दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. निशिकान्त दुबे जी।

... (व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब) : सर, मुझे फतेहगढ़ की बात तो कर लेने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : आठ बजे समय समाप्त होने वाला है तो उन्हें कम से कम एक मिनट तो बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, एक मिनट में आप फतेहगढ़ की बात रख दीजिए।

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब) : सर, मैं फतेहगढ़ साहिब के लिए बार-बार कहता हूँ कि यह जो दिसम्बर का महीना है, वहां छोटे साहिबजादे जिंदा चुनवा दिए गए थे। इस महीने में ही केन्द्र सरकार उसको इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट में ले ले तो अच्छा रहेगा।

(इति)

1959 बजे

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा यह कहता हूँ कि इस पार्लियामेंट में आपने जो एक नई दशा और दिशा दी है, वह मेरे लिए एक नया अनुभव है कि अध्यक्ष के नाते आप पार्लियामेंट शुरू करते हैं और हमेशा प्रयास करते हैं कि इसकी समाप्ति भी आप ही करें।

यह जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, इस पर मैं केवल छः पॉइंट्स पर अपनी बात कहूंगा। हम और आप सांसद बनें, आप राजस्थान में वर्षों तक राजनीति करते रहे, लेकिन उस समय कांग्रेस ने क्या हालात पैदा कर दिए थे? उस समय किसानों को सही समय पर खाद नहीं मिलती थी। अगर खाद मिलती भी थी तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग होती थी। उन्हें लाठी खानी पड़ती थी, गोली खानी पड़ती थी। रैक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि वहां रेल नहीं पहुंचती थी।

(2000/RAJ/NKL)

इस बजट में, सप्लीमेंट्री फॉर डिमांड्स फोर ग्रांट्स में फर्टिलाइजर सब्सिडी में माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह तय कर दिया है कि किसी कीमत पर...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब सदन का समय पांच मिनट और बढ़ाया जाता है।

...(व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, धन्यवाद।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन का समय आठ बजकर दस मिनट, पांच-सात मिनट, और तक के लिए बढ़ाया जाता है।

...(व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, आप समझें कि उनकी जो की हुई कारगुजारी थी, उनका जो किया हुआ भ्रष्टाचार था, उस पर लगाम लगाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने नीम कोटेड यूरिया और इसके बाद जो पूरी इंटरनेशनल लॉबी है, चाहे वह फास्फेट खरीदे, नाइट्रेट खरीदे, जिंक खरीदे, जिसकी हमारे यहां कमी है, उसके दाम नहीं बढ़े, उसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी आउट ऑफ द वे जा कर किसानों के लिए जो बात करते हैं, उनके लिए एक बड़ा सवाल है कि उन्होंने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी।

दूसरी बात यह है कि जो जगदम्बिका पाल जी कह रहे थे कि भारत वर्ष 1947 में स्वतंत्र हुआ। कांग्रेस 55-60 सालों तक राज करती रही। उसने किसानों को केवल एक लॉलीपॉप दिया। जब किसान मरने लगे, आत्महत्या करने लगे, तो उनके लिए कहा कि हम कृषि लोन माफ कर देंगे, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने ऐसा इनिशिएटिव लिया ताकि किसानों को आत्महत्या करने लिए मजबूर न होना पड़े, इसके लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि दिया, जिसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे थे, इस बजट में इसका जिक्र भी है।

तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि सभी लोग कहते हैं कि जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ-ईस्ट का क्या होगा? इस बजट में मैं केवल सप्लीमेंट्री ऑफ ग्रांट्स पर के बारे में कहना चाहता हूँ। अनुच्छेद 370 और 35(ए) के कारण जम्मू-कश्मीर में हमारा कानून लागू नहीं होता था। उसके कारण वहां इंडस्ट्रीज नहीं आती थी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इंडस्ट्रीज नहीं आती थी। माननीय अटल बिहारी जी ने उसके लिए कुछ नीतियां तय कीं। इस बजट के लिए मैं

वित्त मंत्री जी और उनके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इस बजट में उन्होंने एक हजार करोड़ रुपए केवल इस हिमालयन राज्य के लिए दिया, जिसके कारण वहां सुविधाएं बढ़ेंगी।

सर, चौथा यह है कि बहुत बातें होती हैं कि बहुत नक्सलवाद है, विकास नहीं है। किसी जमाने में अटक से कटक तक भारत एक हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस की नीतियों के कारण पशुपति से लेकर तिरुपति तक नक्सलवाद का पूरा का पूरा कॉरिडोर था। हम और ललन जी यहां बैठे हुए हैं। हम सभी लोग नक्सलवाद से प्रभावित रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, 140 जिले ऐसे थे, जिसमें केवल और केवल नक्सलवाद था। वहां लोग दिन में भी चल पाने की स्थिति में नहीं होते थे। ठेकेदार हो, बड़ेदार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां कुछ भी होता था। मैं इस बजट के लिए माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वर्ष 2019 के बाद जितने नक्सलवाद के जिले कम हुए, जितना पुलिस का मॉडर्नाइजेशन हुआ, साइबर सिक्योरिटी में वृद्धि हुई, आज 140 जिलों में से हार्डली 25-30 जिले बच गए हैं। जैसे कल हम लोगों ने टीबी मुक्त भारत के लिए मैच खेला है, जिसका उद्घाटन करने लिए स्पीकर महोदय आप खुद गए थे, उसी तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी का टारगेट है कि वर्ष 2025 के बाद एक भी जिला नक्सलवाद से प्रभावित नहीं रहेगा। सारे नक्सलवादियों का सफाया हो जाएगा। उसके लिए इस बजट में तकरीबन चार हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

आप बजट की बात करते हैं कि यह सप्लीमेंट्री डिमांड्स आ गया। मैंने इसी हाउस में वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक कांग्रेस की सरकार को देखा है। बजट एस्टिमेट कुछ होता था, रीवाइज्ड एस्टिमेट कुछ होता था और एक्जुअल एक्सपेंडिचर कुछ होता था। बीई, आरई और ईई में जमीन आसमान का फर्क था कि वे केवल लॉलीपॉप दिखाते थे। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट चलता था। मैं अपने यहां की बात कर रहा हूँ कि मंदार हिल से हंसडिहा होते हुए दुमका के लिए बन एक रेल लाइन रही थी। वर्ष 1995 में उसका शिलान्यास हुआ और उसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2018 में किया। जब वर्ष 2014 में वह माननीय प्रधान मंत्री बन गए तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया। उसके लिए चार साल पैसे दिए गए, लेकिन केवल लॉलीपॉप। इस साल हम लैंड एक्वायर कर रहे हैं, दूसरे साल हम पटरी बिछाएंगे, तीसरे साल एक-दो किलोमीटर पटरी बिछाएंगे। इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए जो नीति आयोग बनी है और प्रधान मंत्री जी की जो मॉनिटरिंग है, उसके लिए भी इस बजट में पैसा दिया गया है।

(2005/KN/VR)

सारे प्रोजेक्ट्स समय से पूरे हों। भारत सरकार का पैसा उसमें खर्च नहीं हो और जो लॉलीपॉप देने की संस्कृति कांग्रेस की थी, वह कैसे खत्म हो? इस बजट में प्रावधान है।

स्पीकर महोदय, इसके बाद बड़ी चर्चा चलती है कि पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? कांग्रेस के लोग बार-बार इस पर क्वेश्चन उठाते रहते हैं। सप्लीमेंट्री डिमांड्स फोर ग्रांट्स पर बात करते हुए यदि यह बात करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं? इस बजट में एक बड़ा हिस्सा हमने किसको दिया है, मॉरीशस के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे? हमने मॉरीशस को पैसा दिया है, मालदीव को पैसा दिया है, श्रीलंका को पैसा दिया है, भूटान को पैसा दिया है, नेपाल को पैसा दिया है। लैटिन अमेरिकन कंट्री,

जिसके साथ हमें व्यापार करना है। आप करंट एकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं कि करंट एकाउंट डेफिसिट हो गया, ट्रेड डेफिसिट हो गया। नई-नई मार्केट, जो बातें जगदंबिका पाल जी ने कही कि चाइना के हटने के बाद, कोरोना के बाद पूरी दुनिया, बंगलादेश में जो इस तरह का टर्मोइल आया है, इसके बाद पूरी दुनिया मैन्यूफैक्चरिंग के लिए भारत की तरफ आना चाहती है। भारत की तरफ आना चाहती है तो भारत का कैसे विकास होगा? दो चीजों के कारण विकास होगा कि उन लोगों के साथ हमारा संबंध कैसे हो? यदि श्रीलंका आज ऋण से परेशान है, ऋण के कारण पूरी दुनिया उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं है तो हम उसको पैसा देंगे। हम उसको समर्थन करेंगे, तब तो चाइना नहीं आएगा। मालदीव ने हमारे साथ संबंध खराब किए, लेकिन मालदीव के साथ हमने अच्छे संबंध बनाए। उन संबंधों का प्रतिफल यह है कि राष्ट्रपति खुद आए और राष्ट्रपति के आने के बाद उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। इस बजट में, हमने इसके अलावा एक बड़ा खर्चा किया है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां गंगा पर बंदरगाह बना है। कभी लोगों ने कल्पना की थी कि गंगा पर भी ट्रेड हो सकता है, गंगा पर बंदरगाह हो सकता है, ब्रह्मपुत्र पर बंदरगाह हो सकता है। आपको मार्केट क्या चाहिए? मार्केट यह चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट जो आपसे अलग है, मेन लैंड से जो नॉर्थ ईस्ट अलग है, यदि हमें सिंगापुर जाना है, मलेशिया जाना है, इंडोनेशिया जाना है, फिलीपींस तक जाना है तो भारत को मनीला के साथ रोड से जोड़ना पड़ेगा। कभी आपने सोचा है कि वर्ष 2014 के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी ने क्या किया? रक्सौल से हल्दिया, अभी इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया कि रक्सौल से हल्दिया बनेगा और बक्सर से भागलपुर तक रोड बनेगा। आपने कभी यह सोचा है कि यह क्यों बना? यह स्ट्रेटेजिक चीज है। यदि रक्सौल से हल्दिया बनेगा तो हम नेपाल को पोर्ट देंगे। नेपाल को यदि पोर्ट देंगे तो नेपाल जो आज चाइना के साथ जाने की कोशिश कर रहा है, वह हमारे साथ जुड़ेगा। यदि हम नॉर्थ ईस्ट में आगे बढ़ कर म्यांमार तक चार लेन का रोड बनाएंगे तो यह पूरे रोड से ... (व्यवधान) सर, मैं बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। उसके लिए पैसा है।

सर, मेरा यह कहना है कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी सप्लीमेंट्री डिमांड्स फोर ग्रांट्स लेकर आई हैं, यह 'हरि अनंत हरि कथा अनंता' है। इसके बारे में हम जितनी बात करेंगे, उतना कम होगा। मैं अपनी सरकार को बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त सदस्य हैं, उस वक्त हम सांसद हैं, जिस वक्त इस देश का नेतृत्व विकसित भारत बनाने के लिए, वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के लिए माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी का कार्यकर्ता और सांसद होने का मुझे गर्व है। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा सप्लीमेंट्री डिमांड्स फोर ग्रांट्स लेकर आई हैं।

सर, आपने मुझे वक्त दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : श्री हनुमान बेनीवाल जी, आप सप्लीमेंट्री डिमांड्स फोर ग्रांट्स पर ही बोलना। सिर्फ दो मिनट है।

2008 बजे

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं 700 किलोमीटर चलकर आया हूँ। मुझे पता है कि आप सब को बड़े मन से, आज आपका मूड भी अच्छा है। आप सब को मौका भी दे रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका समय खत्म हो जाएगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, सदन में आज वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत अनुदान की अनुपूरक मांगों पर अपनी बात रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, विभिन्न मंत्रालयों ने अतिरिक्त राशि की मांग की है। मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सहित कई राज्यों में किसान डीएपी यूरिया के लिए जूझ रहे हैं। समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए टोकन कटवाने के बावजूद किसानों की उपज की खरीद नहीं हो पा रही है। आप भी राजस्थान से ही आते हैं। वर्ष 2023-24 के आवंटित बजट का जब आठ माह बाद लेखा-जोखा देखा तो हालात सामने आए कि भारत सरकार के 15 मंत्रालयों का आवंटित बजट का एक तिहाई भी खर्च नहीं किया। मैं वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला तथा बाल विकास जैसे महकमों के लिए आवंटित बजट लैप्स होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं किसान का बेटा हूँ और मैंने किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। मैं वित्त मंत्री जी को एक बात और कहना चाहूंगा। हम समर्थन मूल्य पर खरीद तो कर रहे हैं, लेकिन आपने एक राइडर लगा रखा है कि हम 25 क्विंटल से ज्यादा खरीद नहीं करेंगे। आज भी राजस्थान के अंदर कई जगहों पर खरीद नहीं हो रही है। खरीद सेंटर बंद है। इसको आप दिखवाये। चूंकि आपने कह दिया है, इसलिए मैं राजस्थान और अपने संसदीय क्षेत्र की छोटी-मोटी बात आता हूँ। राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जा की बात हमने हमेशा की है और हम सारे मापदण्ड पूरे कर रहे हैं। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हमारा मरुस्थल, चंबल के पहाड़, अरावली की पर्वतमालाएं, और एमएसपी को कानून के दायरे में लाने के लिए बड़ा आंदोलन देश के अंदर चल रहा है।

(2010/VB/SAN)

हमारी मांग है कि एमएसपी को कानूनी दायरे के अन्दर लाया जाए। ट्रैक्टर सहित किसान... (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

2010 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 17 दिसम्बर 2024/ 26 अग्रहायण 1946 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।